



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग 2— अनुभाग 1क

PART II — Section 1A

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 3] नई दिल्ली, सोमवार, 6 नवम्बर, 2017/15 कार्तिक, 1939 (शक) [खंड LIII
NO. 3] NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 6, 2017/KARTIKA 15, 1939 (SAKA) [VOL. LIII

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधायी विभाग)

नई दिल्ली, 6 नवम्बर, 2017/15 कार्तिक, 1939 (शक)

दि शिड्यूलड कास्ट्स एंड दि शिड्यूलड ट्राईब्स (प्रिवेंशन आफ एट्रोसिटीज) अमेंडमेंट ऐक्ट 2015; (2) दि आर्बिट्रेशन एंड कनसिलिएशन (अमेंडमेंट) ऐक्ट, 2015; (3) दि नेशनल वाटरवेज ऐक्ट, 2016; (4) दि इन्फोर्समेंट आफ सिक्यूरिटी इन्टरेस्ट एंड रिकवरी आफ डैब्ट्स लाज एंड मिसलेनियस प्रोविजंस (अमेंडमेंट) ऐक्ट, 2016; (5) दि राइट आफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज ऐक्ट, 2016; (6) दि स्पेसिफाइड बैंक नोट्स (सेसेशन आफ लाइबिलिटीज) ऐक्ट, 2017; (7) दि मैटरनिटी बेनिफिट (अमेंडमेंट) ऐक्ट, 2017; (8) दि इम्प्लाईज कम्पेनसेशन (अमेंडमेंट) ऐक्ट, 2017; (9) दि इंडीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसिज टैक्स ऐक्ट, 2017; (10) दि गुड्स एंड सर्विसिज टैक्स (कम्पेनसेशन टू स्टेट्स) ऐक्ट, 2017; (11) दि कॉन्स्टीट्यूशन (शिड्यूलड कास्ट्स) आर्डर्स (अमेंडमेंट) ऐक्ट, 2017; (12) दि टैक्सेशन लाज (अमेंडमेंट) ऐक्ट, 2017; (13) दि नेशनल इंस्टीट्यूट आफ टेक्नोलाजी, साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च (अमेंडमेंट) ऐक्ट, 2017; और (14) दि कलेक्शन आफ स्टेटिस्टिक्स (अमेंडमेंट) ऐक्ट, 2017 के निम्नलिखित हिन्दी अनुवाद राष्ट्रपति के प्राधिकार से प्रकाशित किए जाते हैं और ये राजभाषा अधिनियम, 1963 (1963 का 19) की धारा 5 की उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन उनके हिन्दी में प्राधिकृत पाठ समझे जाएंगे:—

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(LEGISLATIVE DEPARTMENT)

New Delhi, November 6, 2017/Kartika 15, 1939 (Saka)

The translation in Hindi of the following, namely:—The Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Amendment Act, 2015; (2) The Arbitration and Conciliation (Amendment) Act, 2015; (3) The National Waterways Act, 2016; (4) The Enforcement of Security Interest and Recovery of Debts Laws and Miscellaneous Provisions (Amendment) Act, 2016; (5) The Rights of Persons with Disabilities Act, 2016; (6) The Specified Bank Notes (Cessation of Liabilities) Act, 2017; (7) The Maternity Benefit (Amendment) Act, 2017; (8) The Employees Compensation (Amendment) Act, 2017; (9) The Integrated Goods and Services Tax Act, 2017; (10) The Goods and Services Tax (Compensation to States) Act, 2017; (11) The Constitution (Scheduled Castes) Orders (Amendment) Act, 2017; (12) the Taxation Laws (Amendment) Act, 2017; (13) The National Institutes of Technology, Science Education and Research (Amendment) Act, 2017; and (14) The Collection of Statistics (Amendment) Act, 2017 are hereby published under the authority of the President and shall be deemed to be the authoritative texts thereof in Hindi under clause (a) of sub-section (1) of section 5 of the Official Languages Act, 1963 (19 of 1963):—

	पृष्ठ
अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधन अधिनियम, 2015 (2016 का अधिनियम संख्यांक 1)	427
The Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Amendment Act, 2015	
माध्यस्थम् और सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2015 (2016 का अधिनियम संख्यांक 3)	441
The Arbitration and Conciliation (Amendment) Act, 2015	
राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम, 2016 (2016 का अधिनियम संख्यांक 17)	457
The National Waterways Act, 2016	
प्रतिभूति हितों का प्रवर्तन और ऋण वसूली विधि तथा प्रकीर्ण उपबंध (संशोधन) अधिनियम, 2016 (2016 का अधिनियम संख्यांक 44)	473
The Enforcement of Security Interest and Recovery of Debts Laws and Miscellaneous Provisions (Amendment) Act, 2016	
दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का अधिनियम संख्यांक 49)	499
The Rights of Persons with Disabilities Act, 2016	
विनिर्दिष्ट बैंक नोट (दायित्वों की समाप्ति) अधिनियम, 2017 (2017 का अधिनियम संख्यांक 2)	537
The Specified Bank Notes (Cessation of Liabilities) Act, 2017	
प्रसूति प्रसुविधा (संशोधन) अधिनियम, 2017 (2017 का अधिनियम संख्यांक 6)	541
The Maternity Benefit (Amendment) Act, 2017	
कर्मचारी प्रतिकर (संशोधन) अधिनियम, 2017 (2017 का अधिनियम संख्यांक 11)	543
The Employees Compensation (Amendment) Act, 2017	
एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का अधिनियम संख्यांक 13)	545
The Integrated Goods and Services Tax Act, 2017	
माल और सेवा कर (राज्यों को प्रतिकर) अधिनियम, 2017 (2017 का अधिनियम संख्यांक 15)	563
The Goods and Services Tax (Compensation to States) Act, 2017	
संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2017 (2017 का अधिनियम संख्यांक 17)	571
The Constitution (Scheduled Castes) Orders (Amendment) Act, 2017	
कराधान विधि (संशोधन) अधिनियम, 2017 (2017 का अधिनियम संख्यांक 18)	573
The Taxation Laws (Amendment) Act, 2017	
राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी, विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (संशोधन) अधिनियम, 2017 (2017 का अधिनियम संख्यांक 19)	593
The National Institutes of Technology, Science Education and Research (Amendment) Act, 2017	
सांख्यिकीय संग्रहण (संशोधन) अधिनियम, 2017 (2017 का अधिनियम संख्यांक 21)	595
The Collection of Statistics (Amendment) Act, 2017	

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधन अधिनियम, 2015

(2016 का अधिनियम संख्यांक 1)

[31 दिसम्बर, 2015]

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण)
अधिनियम, 1989 का संशोधन
करने के लिए
अधिनियम

भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधन अधिनियम, 2015 है। संक्षिप्त नाम और प्रारंभ।
- (2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे।

वृहत् नाम का संशोधन।

2. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (जिसे इसमें 1989 का 33 इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) के वृहत् नाम में, “विशेष न्यायालयों” शब्दों के स्थान पर, “विशेष न्यायालयों और अनन्य विशेष न्यायालयों” शब्द रखे जाएंगे।

धारा 2 का संशोधन।

3. मूल अधिनियम की धारा 2 की उपधारा (1) में,—

(i) खंड (ख) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:—

‘(खख) “आश्रित” से पीड़ित का ऐसा पति या पत्नी, बालक, माता-पिता, भाई और बहिन अभिप्रेत हैं जो ऐसे पीड़ित पर अपनी सहायता और भरण-पोषण के लिए पूर्णतः या मुख्यतः आश्रित हैं;

(खग) “आर्थिक बहिष्कार” से निम्नलिखित अभिप्रेत है,—

(i) अन्य व्यक्ति से भाड़े पर कार्य से संबंधित संव्यवहार करने या कारबार करने से इंकार करना; या

(ii) अवसरों का प्रत्याख्यान करना जिनमें सेवाओं तक पहुंच या प्रतिफल के लिए सेवा प्रदान करने हेतु संविदाजन्य अवसर सम्मिलित हैं; या

(iii) ऐसे निबंधनों पर कोई बात करने से इंकार करना जिन पर कोई बात, कारबार के सामान्य अनुक्रम में सामान्यतया की जाएगी; या

(iv) ऐसे वृत्तिक या कारबार संबंधों से प्रविरत रहना, जो किसी अन्य व्यक्ति से रखे जाएं;

(खघ) “अनन्य विशेष न्यायालय” से इस अधिनियम के अधीन अपराधों का अनन्य रूप से विचारण करने के लिए धारा 14 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित अनन्य विशेष न्यायालय अभिप्रेत है;

(खड) “वन अधिकार” का वही अर्थ होगा, जो अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 की धारा 3 की उपधारा (1) में है; 2007 का 2

(खच) “हाथ से मैला उठाने वाले कर्मी” का वही अर्थ होगा, जो हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013 की धारा 2 की उपधारा 2013 का 25 (1) के खंड (छ) में उसका है;

(खछ) “लोक सेवक” से भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 21 के अधीन यथापरिभाषित 1860 का 45 लोक सेवक और साथ ही तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन लोक सेवक समझा गया कोई अन्य व्यक्ति अभिप्रेत है और जिनमें, यथास्थिति, केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के अधीन उसकी पदीय हैसियत में कार्यरत कोई व्यक्ति सम्मिलित है;’

(ii) खंड (ड) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:—

‘(डक) “अनुसूची” से इस अधिनियम से उपाबद्ध अनुसूची अभिप्रेत है;

(डख) “सामाजिक बहिष्कार” से कोई रूढ़िगत सेवा अन्य व्यक्ति को देने के लिए या उससे प्राप्त करने के लिए अनुज्ञात करने से इंकार करना या ऐसे सामाजिक संबंधों से प्रतिविरत रहना जो कोई व्यक्ति अन्य व्यक्ति से बनाए रखता है या अन्य व्यक्तियों से उसको अलग-थलग करना अभिप्रेत है;

(डग) “पीड़ित” से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (ग) के अधीन “अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों” की परिभाषा के भीतर आता है तथा जो इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के किए जाने के परिणामस्वरूप शारीरिक, मानसिक, मनोवैज्ञानिक, भावनात्मक या धनीय हानि या उसकी संपत्ति को हानि वहन या अनुभव करता है और जिसके अंतर्गत उसके नातेदार, विधिक संरक्षक और विधिक वारिस भी हैं;

(डघ) “साक्षी” से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो इस अधिनियम के अधीन अपराध से अंतर्वर्तित किसी दाण्डिक कार्य के अन्वेषण, जांच या विचारण के प्रयोजन के लिए तथ्यों और परिस्थितियों से परिचित है या कोई जानकारी रखता है या आवश्यक ज्ञान रखता है और जो ऐसे मामले के अन्वेषण, जांच या विचारण के दौरान जानकारी देने या कथन करने या कोई दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए अपेक्षित है या अपेक्षित हो सकेगा और जिसमें ऐसे अपराध का पीड़ित सम्मिलित है;’

(iii) खंड (च) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:—

“(च) उन शब्दों और पदों का, जो इस अधिनियम में प्रयुक्त हैं किंतु परिभाषित नहीं हैं और यथास्थिति, भारतीय दंड संहिता, 1860, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 या दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में परिभाषित हैं, वही अर्थ होना समझा जाएगा जो क्रमशः उन अधिनियमितियों में हैं।”।

1860 का 45

1872 का 1

1974 का 2

4. मूल अधिनियम की धारा 3 में,—

धारा 3 का

संशोधन।

(i) उपधारा (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

‘(1) जो कोई अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं होते हुए,—

(क) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य के मुख में कोई अखाद्य या घृणाजनक पदार्थ रखता है या ऐसे सदस्य को ऐसे अखाद्य या घृणाजनक पदार्थ पीने या खाने के लिए मजबूर करेगा;

(ख) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य द्वारा दखलकृत परिसरों में या परिसरों के प्रवेश-द्वार पर मल-मूत्र, मल, पशु-शव या कोई अन्य घृणाजनक पदार्थ इकट्ठा करेगा;

(ग) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को क्षति करने, अपमानित करने या क्षुब्ध करने के आशय से उसके पड़ोस में मल-मूत्र, कूड़ा, पशु-शव या कोई अन्य घृणाजनक पदार्थ इकट्ठा करेगा;

(घ) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को जूतों की माला पहनाएगा या नग्न या अर्ध-नग्न घुमाएगा;

(ङ) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य पर बलपूर्वक ऐसा कोई कार्य करेगा जैसे व्यक्ति के कपड़े उतारना, बलपूर्वक सिर का मुण्डन करना, मूँछे हटाना, चेहरे या शरीर को पोतना या ऐसा कोई अन्य कार्य करना, जो मानव गरिमा के विरुद्ध है;

(च) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य के स्वामित्वाधीन या उसके कब्जे में या उसको आबंटित या किसी सक्षम अधिकारी द्वारा उसको आबंटित किए जाने के लिए अधिसूचित किसी भूमि को सदोष अधिभोग में लेगा या उस पर खेती करेगा या ऐसी भूमि को अंतरित कराएगा;

(छ) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य को उसकी भूमि या परिसरों से सदोष बेकब्जा करेगा या किसी भूमि या परिसरों या जल या सिंचाई सुविधाओं पर वन अधिकारों सहित उसके अधिकारों के उपभोग में हस्तक्षेप करेगा या उसकी फसल को नष्ट करेगा या उसके उत्पाद को ले जाएगा।

स्पष्टीकरण—खंड (च) और इस खंड के प्रयोजनों के लिए, “सदोष” पद में निम्नलिखित सम्मिलित हैं,—

(अ) व्यक्ति की इच्छा के विरुद्ध;

(आ) व्यक्ति की सहमति के बिना;

(इ) व्यक्ति की सहमति से, जहां ऐसी सहमति, उस व्यक्ति या किसी ऐसे अन्य व्यक्ति को, जिससे वह व्यक्ति हितबद्ध है, मृत्यु या उपहति का भय दिखाकर, अभिप्राप्त की गई है; या

(ई) ऐसी भूमि के अभिलेखों को बनाना;

(ज) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को “बेगार” करने के लिए या सरकार द्वारा लोक प्रयोजनों के लिए अधिरोपित किसी अनिवार्य सेवा से भिन्न अन्य प्रकार के बलात्श्रम या बंधुआ श्रम करने के लिए तैयार करेगा;

(झ) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को मानव या पशु-शवों की अंत्येष्टि या ले जाने या कब्रों को खोदने के लिए विवश करेगा;

(ञ) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य को हाथ से मैला उठाने के लिए तैयार करेगा या ऐसे प्रयोजन के लिए ऐसे सदस्य का नियोजन करेगा या नियोजन को अनुज्ञात करेगा;

(ट) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की स्त्री को, किसी देवदासी के रूप में पूजा, मंदिर या किसी अन्य धार्मिक संस्थान की देवी, मूर्ति या पात्र के समर्पण को या वैसी ही किसी अन्य प्रथा का निष्पादन या संवर्धन करेगा या पूर्वोक्त कार्यों को अनुज्ञात करेगा;

(ठ) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य को,—

(अ) मतदान न करने या किसी विशिष्ट अभ्यर्थी के लिए मतदान करने या विधि द्वारा उपबंधित से भिन्न रीति से मतदान करने के लिए मजबूर या अभित्रस्त करेगा;

(आ) किसी अभ्यर्थी के रूप में नामनिर्देशन फाइल न करने या ऐसे नामनिर्देशन को प्रत्याहृत करने; या

(इ) किसी निर्वाचन में अभ्यर्थी के रूप में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य के नामनिर्देशन का प्रस्ताव या समर्थन नहीं करेंगे;

(ड) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी ऐसे सदस्य को, जो संविधान के भाग 9 के अधीन पंचायत या संविधान के भाग 9क के अधीन नगरपालिका का सदस्य या अध्यक्ष या किसी अन्य पद का धारक है, उसके सामान्य कर्तव्यों या कृत्यों के पालन में मजबूर या अभित्रस्त या बाधित करेगा;

(ढ) मतदान के पश्चात्, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को उपहति या घोर उपहति कारित करेगा या हमला करेगा या सामाजिक या आर्थिक बहिष्कार अधिरोपित करेगा या अधिरोपित करने की धमकी देगा या किसी ऐसी लोक सेवा के उपलब्ध फायदों से, निवारित करेगा, जो उसको प्राप्य हैं;

(ण) किसी विशिष्ट अभ्यर्थी के लिए मतदान करने या उसको मतदान नहीं करने या विधि द्वारा उपबंधित रीति से मतदान करने के लिए अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य के विरुद्ध इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध करेगा;

(त) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य के विरुद्ध मिथ्या, द्वेषपूर्ण या तंग करने वाला वाद या दांडिक या अन्य विधिक कार्यवाहियां संस्थित करेगा;

(थ) किसी लोक सेवक को कोई मिथ्या या तुच्छ सूचना देगा जिससे ऐसा लोक सेवक अपनी विधिपूर्ण शक्ति का प्रयोग अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को क्षति करने या क्षुब्ध करने के लिए करे;

(द) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को अवमानित करने के आशय से लोक दृष्टि में आने वाले किसी स्थान पर अपमानित या अभिन्नस्त करेगा;

(ध) लोक दृष्टि में आने वाले किसी स्थान पर जाति के नाम से अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को गाली-गलौज करेगा;

(न) अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों द्वारा सामान्यतया धार्मिक मानी जाने वाली या अति श्रद्धा से ज्ञात किसी वस्तु को नष्ट करेगा, हानि पहुंचाएगा या अपवित्र करेगा;

स्पष्टीकरण—इस खंड के प्रयोजनों के लिए “वस्तु” पद से अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत मूर्ति, फोटो और रंगचित्र है;

(प) अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के विरुद्ध शत्रुता, घृणा या वैमनस्य की भावनाओं की या तो लिखित या मौखिक शब्दों द्वारा या चिह्नों द्वारा या दृश्य रूपण द्वारा या अन्यथा, अभिवृद्धि करेगा या अभिवृद्धि करने का प्रयत्न करेगा;

(फ) अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों द्वारा अति श्रद्धा से माने जाने वाले किसी दिवंगत व्यक्ति का या तो लिखित या मौखिक शब्दों द्वारा या किसी अन्य साधन से अनादर करेगा;

(ब)(i) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की किसी स्त्री को साशय, यह जानते हुए स्पर्श करेगा कि वह अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से संबंधित है, जबकि स्पर्श करने का ऐसा कार्य, कामुक प्रकृति का है और प्राप्तिकर्ता की सहमति के बिना है;

(ii) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की किसी स्त्री के बारे में, यह जानते हुए कि वह अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से संबंधित है, कामुक प्रकृति के शब्दों, कार्यों या अंगविक्षेपों का उपयोग करेगा;

स्पष्टीकरण—उपखंड (i) के प्रयोजनों के लिए, “सहमति” पद से कोई सुस्पष्ट स्वैच्छिक करार अभिप्रेत है, जब कोई व्यक्ति शब्दों, अंगविक्षेपों या अमौखिक संसूचना के किसी रूप में विनिर्दिष्ट कार्य में भागीदारी की रजामंदी को संसूचित करता है:

परंतु अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की कोई स्त्री, जो कामुक प्रकृति के किसी कार्य में शारीरिक अवरोध नहीं करती है, केवल इस तथ्य के कारण लैंगिक क्रियाकलाप में सहमति के रूप में नहीं माना जाएगा:

परंतु यह और कि स्त्री का लैंगिक इतिहास, अपराधी के साथ लैंगिक इतिहास सहित, सहमति विवक्षित नहीं करता है या अपराध को कम नहीं करता है;

(भ) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य द्वारा सामान्यतः उपयोग किए जाने वाले किसी स्रोत, जलाशय या किसी अन्य स्रोत के जल को दूषित या गंदा करेगा जिससे वह ऐसे प्रयोजन के लिए कम उपयुक्त हो जाए जिसके लिए वह साधारणतया उपयोग किया जाता है;

(म) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को लोक समागम के किसी स्थान से गुजरने के किसी रूढ़िजन्य अधिकार से इंकार करेगा या ऐसे सदस्य को लोक समागम के ऐसे स्थान का उपयोग करने या उस पर पहुंच रखने से निवारित करने के लिए बाधा पहुंचाएगा जिसमें जनता या उसके किसी अन्य वर्ग के सदस्यों को उपयोग करने और पहुंच रखने का अधिकार है;

(य) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को उसका गृह, ग्राम या निवास का अन्य स्थान छोड़ने के लिए मजबूर करेगा या छुड़ाएगा;

परंतु इस खंड की कोई बात किसी लोक कर्तव्य के निर्वहन में की गई किसी कार्रवाई को लागू नहीं होगी;

(यक) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य को निम्नलिखित के संबंध में किसी रीति से बाधित या निवारित करेगा,—

(अ) किसी क्षेत्र के सम्मिलित संपत्ति संसाधनों का या अन्य व्यक्तियों के साथ समान रूप से कब्रिस्तान या श्मशान-भूमि का उपयोग करना या किसी नदी, सरिता स्रोत, कुंआ, तालाब, कुंड, नल या अन्य जलीय स्थान या कोई स्नान घाट, कोई सार्वजनिक परिवहन, कोई सड़क या मार्ग का उपयोग करना;

(आ) साइकिल या मोटर साइकिल आरोहण या सवारी करना या सार्वजनिक स्थानों में जूते या नए कपड़े पहनना या विवाह की शोभा यात्रा निकालना या विवाह की शोभा यात्रा के दौरान घोड़े या किसी अन्य यान पर आरोहण करना;

(इ) जनता या समान धर्म के अन्य व्यक्तियों के लिए खुले किसी पूजा स्थल में प्रविष्ट करना या जाटर्स सहित किसी धार्मिक, सामाजिक या सांस्कृतिक शोभा यात्रा में भाग लेना या उसको निकालना;

(ई) किसी शैक्षणिक संस्था, अस्पताल, औषधालय, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, दुकान या लोक मनोरंजन स्थान या किसी अन्य लोक स्थान में प्रविष्ट होने या जनता के लिए खुले किसी स्थान में सार्वजनिक उपयोग के लिए अभिप्रेत कोई उपकरण या वस्तुओं का उपयोग करना; या

(उ) किसी वृत्ति में व्यवसाय करना या किसी ऐसी उपजीविका, व्यापार, कारबार या किसी नौकरी में नियोजन करना, जिसमें जनता या उसके किसी वर्ग के अन्य लोगों को उपयोग करने या उस तक पहुंच का अधिकार है;

(यख) जादू-टोना करने या डाइन होने के अभिकथन पर अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य को शारीरिक हानि पहुंचाएगा या मानसिक यंत्रणा देगा; या

(यग) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी व्यक्ति या कुटुंब या उसके किसी समूह का सामाजिक या आर्थिक बहिष्कार करेगा या उसकी धमकी देगा,

वह कारावास से, जिसकी अवधि छह मास से कम की नहीं होगी, किंतु जो पांच वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने से, दंडनीय होगा।”।

(ii) उपधारा (2) में,—

(क) खंड (v) में, “किसी व्यक्ति या संपत्ति के विरुद्ध इस आधार पर करेगा कि ऐसा व्यक्ति अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य है या ऐसी संपत्ति ऐसे सदस्य की है,” शब्दों के स्थान पर, “किसी व्यक्ति या संपत्ति के विरुद्ध यह जानते हुए करेगा कि ऐसा व्यक्ति अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य है या ऐसी संपत्ति ऐसे सदस्य की है” शब्द रखे जाएंगे;

(ख) खंड (v) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“(vक) अनुसूची में विनिर्दिष्ट कोई अपराध किसी व्यक्ति या संपत्ति के विरुद्ध यह जानते हुए करेगा कि ऐसा व्यक्ति अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य है या वह संपत्ति ऐसे सदस्य की है, वह ऐसे अपराधों के लिए भारतीय दंड संहिता के अधीन यथा विनिर्दिष्ट दंड से दंडनीय होगा और जुर्माने का भी दायी होगा।”।

5. मूल अधिनियम की धारा 4 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

धारा 4 के स्थान पर
नई धारा का
प्रतिस्थापन।

“4. (1) कोई भी लोक सेवक, जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है, इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन उसके द्वारा पालन किए जाने के लिए अपेक्षित अपने कर्तव्यों की जानबूझकर उपेक्षा करेगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि छह मास से कम की नहीं होगी, किंतु जो एक वर्ष तक की हो सकेगी, दंडनीय होगा।

कर्तव्य उपेक्षा के
लिए दंड।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट लोक सेवक के कर्तव्यों में निम्नलिखित सम्मिलित होगा,—

(क) पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी द्वारा सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर लेने से पहले मौखिक रूप से दी गई सूचना को, सूचनाकर्ता को पढ़कर सुनाना और उसको लेखबद्ध करना;

(ख) इस अधिनियम और अन्य सुसंगत उपबंधों के अधीन शिकायत या प्रथम इत्तिला रिपोर्ट को रजिस्टर करना और अधिनियम की उपयुक्त धाराओं के अधीन उसको रजिस्टर करना;

(ग) इस प्रकार अभिलिखित की गई सूचना की एक प्रति सूचनाकर्ता को तुरंत देना;

(घ) पीड़ितों या साक्षियों के कथन को अभिलिखित करना;

(ङ) अन्वेषण करना और विशेष न्यायालय या अनन्य विशेष न्यायालय में साठ दिन की अवधि के भीतर आरोपपत्र फाइल करना तथा विलंब, यदि कोई हो, लिखित में स्पष्ट करना;

(च) किसी दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख को सही रूप से तैयार, विरचित करना तथा उसका अनुवाद करना;

(छ) इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों में विनिर्दिष्ट किसी अन्य कर्तव्य का पालन करना:

परंतु लोक सेवक के विरुद्ध इस संबंध में आरोप, प्रशासनिक जांच की सिफारिश पर दर्ज किए जाएंगे।

(3) लोक सेवक द्वारा उपधारा (2) में निर्दिष्ट कर्तव्य की अवहेलना के संबंध में संज्ञान विशेष न्यायालय या अनन्य विशेष न्यायालय द्वारा लिया जाएगा और ऐसे लोक सेवक के विरुद्ध दांडिक कार्यवाहियों के लिए निदेश दिया जाएगा।”।

6. मूल अधिनियम की धारा 8 में,—

धारा 8 का
संशोधन।

(i) खंड (क) में, “अभियुक्त व्यक्ति की या युक्तियुक्त रूप से संदेहास्पद व्यक्ति की वित्तीय सहायता की है” शब्दों के स्थान पर, “अभियुक्त व्यक्ति द्वारा या युक्तियुक्त रूप से संदेहास्पद व्यक्ति द्वारा किए गए अपराधों के संबंध में कोई वित्तीय सहायता की है” शब्द रखे जाएंगे;

(ii) खंड (क) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“(ग) अभियुक्त, पीड़ित या उसके कुटुंब का व्यक्तिगत ज्ञान रखता था, न्यायालय यह उपधारणा करेगा कि जब तक कि तत्प्रतिकूल साबित न कर दिया जाए, अभियुक्त को पीड़ित की जाति या जनजातीय पहचान का ज्ञान था।”।

7. मूल अधिनियम की धारा 10 की उपधारा (1) में,—

धारा 10 का
संशोधन।

(क) “संविधान के अनुच्छेद 244” शब्दों और अंकों के पश्चात्, “या धारा 21 की उपधारा (2) के खंड (vii) के उपबंधों के अधीन पहचान किए गए किसी क्षेत्र” शब्द, अंक और कोष्ठक अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(ख) “दो वर्ष” शब्दों के स्थान पर, “तीन वर्ष” शब्द रखे जाएंगे।

धारा 14 के स्थान पर
नई धारा का
प्रतिस्थापन।

विशेष न्यायालय
और अनन्य विशेष
न्यायालय।

8. मूल अधिनियम की धारा 14 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

“14 (1) शीघ्र विचारण का उपबंध करने के प्रयोजन के लिए, राज्य सरकार, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति की सहमति से, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, एक या अधिक जिलों के लिए एक अनन्य विशेष न्यायालय स्थापित करेगी:

परंतु ऐसे जिलों में जहां अधिनियम के अधीन कम मामले अभिलिखित किए गए हैं, राज्य सरकार, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति की सहमति से, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, ऐसे जिलों के लिए सेशन न्यायालयों को, इस अधिनियम के अधीन अपराधों का विचारण करने के लिए विशेष न्यायालय होना विनिर्दिष्ट करेगी:

परंतु यह और कि इस प्रकार स्थापित या विनिर्दिष्ट न्यायालयों को इस अधिनियम के अधीन अपराधों का सीधे संज्ञान लेने की शक्ति होगी।

(2) राज्य सरकार का, यह सुनिश्चित करने के लिए कि इस अधिनियम के अधीन मामले, यथासंभव, दो मास की अवधि के भीतर निपटाए गए हैं, पर्याप्त संख्या में न्यायालयों की स्थापना करने का कर्तव्य होगा।

(3) विशेष न्यायालय या अनन्य विशेष न्यायालय में प्रत्येक विचारण में कार्यवाहियां, दिन-प्रतिदिन के लिए तब तक जारी रहेंगी, जब तक कि उपस्थित सभी साक्षियों की परीक्षा न हो जाए, जब तक कि विशेष न्यायालय या अनन्य विशेष न्यायालय, अभिलिखित किए जाने वाले कारणों से उसको आगामी दिन से परे स्थगन करना आवश्यक नहीं पाता हो:

परंतु जब विचारण, इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध से संबंधित है, तब विचारण, यथासंभव, आरोप पत्र को फाइल करने की तारीख से दो मास की अवधि के भीतर पूरा किया जाएगा।”।

नई धारा 14क का
अंतःस्थापन।

अपीलें।

9. मूल अधिनियम की धारा 14 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

“14क. (1) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में किसी बात के होते हुए भी, किसी विशेष न्यायालय या किसी अनन्य विशेष न्यायालय के किसी निर्णय, दंडादेश या आदेश, जो अंतर्वर्ती आदेश नहीं है, के विरुद्ध अपील तथ्यों और विधि दोनों के संबंध में, उच्च न्यायालय में होगी। 1974 का 2

(2) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 378 की उपधारा (3) में किसी बात के होते हुए भी, विशेष न्यायालय या अनन्य विशेष न्यायालय के जमानत मंजूर करने या नामंजूर करने के किसी आदेश के विरुद्ध अपील उच्च न्यायालय में होगी। 1974 का 2

(3) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, इस धारा के अधीन प्रत्येक अपील, ऐसे निर्णय, दंडादेश या आदेश की तारीख से, जिससे अपील की गई है, नब्बे दिन के भीतर की जाएगी:

परंतु उच्च न्यायालय, नब्बे दिन की उक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् ऐसी अपील को ग्रहण कर सकेगा यदि उसका समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी के पास नब्बे दिन के भीतर अपील नहीं करने का पर्याप्त कारण था:

परंतु यह और कि कोई भी अपील, एक सौ अस्सी दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात् ग्रहण नहीं की जाएगी।

(4) उपधारा (1) में की गई प्रत्येक अपील का निपटारा, यथासंभव, अपील ग्रहण करने की तारीख से तीन मास की अवधि के भीतर किया जाएगा।”।

10. मूल अधिनियम की धारा 15 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

धारा 15 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन।

“15. (1) राज्य सरकार, प्रत्येक विशेष न्यायालय के लिए, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा एक लोक अभियोजक विनिर्दिष्ट करेगी या किसी ऐसे अधिवक्ता को, जिसने कम से कम सात वर्ष तक अधिवक्ता के रूप में विधि-व्यवसाय किया हो, उस न्यायालय में मामलों के संचालन के प्रयोजन के लिए विशेष लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त करेगी।

विशेष लोक अभियोजक और अनन्य लोक अभियोजक।

(2) राज्य सरकार, प्रत्येक अनन्य विशेष न्यायालय के लिए राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, अनन्य लोक अभियोजक को विनिर्दिष्ट करेगी या किसी ऐसे अधिवक्ता को, जिसने कम से कम सात वर्ष तक अधिवक्ता के रूप में विधि-व्यवसाय किया हो, उस न्यायालय में मामलों के संचालन के प्रयोजन के लिए अनन्य लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त करेगी।”

11. मूल अधिनियम के अध्याय 4 के पश्चात् निम्नलिखित अध्याय अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

नए अध्याय 4क का अंतःस्थापन।

“अध्याय 4क

पीड़ित और साक्षी के अधिकार

15क. (1) राज्य का, किसी प्रकार के अभित्रास या प्रपीड़न या उत्प्रेरणा या हिंसा या हिंसा की धमकियों के विरुद्ध पीड़ितों, उसके आश्रितों और साक्षियों के संरक्षण के लिए व्यवस्था करने का कर्तव्य और उत्तरदायित्व होगा।

पीड़ित और साक्षी के अधिकार।

(2) पीड़ित से निष्पक्षता, सम्मान और गरिमा के साथ तथा किसी ऐसी विशेष आवश्यकता के साथ, जो पीड़ित की आयु या लिंग या शैक्षणिक अलाभ या गरीबी के कारण उत्पन्न होती है, व्यवहार किया जाएगा।

(3) किसी पीड़ित या उसके आश्रित को, किसी न्यायालय की कार्यवाही की युक्तियुक्त, यथार्थ और समय से सूचना का अधिकार होगा, जिसमें जमानत प्रक्रिया सम्मिलित है और विशेष लोक अभियोजक या राज्य सरकार पीड़ित को इस अधिनियम के अधीन किन्हीं कार्यवाहियों के बारे में सूचित करेगी।

(4) किसी पीड़ित या उसके आश्रित को, यथास्थिति, विशेष न्यायालय या अनन्य विशेष न्यायालय को, किन्हीं दस्तावेजों या सामग्री, साक्षियों को प्रस्तुत करने के लिए पक्षकारों को समन करने या उपस्थित व्यक्तियों की परीक्षा करने के लिए आवेदन करने का अधिकार होगा।

(5) कोई पीड़ित या उसका आश्रित, इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही में अभियुक्त की जमानत, उन्मोचन, निर्मुक्ति, पैरोल, दोषसिद्धि या दण्डादेश या दोषसिद्धि, दोषमुक्ति या दण्डादेश पर या किसी संबद्ध कार्यवाहियों या बहसों और सिद्धदोष करने के संबंध में कोई संबद्ध कार्यवाहियां या बहसों के संबंध में किन्हीं कार्यवाहियों में सुने जाने और लिखित तर्क फाइल करने का हकदार होगा।

1974 का 2

(6) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के अधीन किसी मामले का विचारण करने वाला विशेष न्यायालय या अनन्य विशेष न्यायालय, पीड़ित, उसके आश्रित, इत्तिला देने वाले या साक्षियों को निम्नलिखित प्रदान करेगा,—

(क) न्याय प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए पूर्ण संरक्षण;

(ख) अन्वेषण, जांच और विचारण के दौरान यात्रा तथा भरण-पोषण व्यय;

(ग) अन्वेषण, जांच और विचारण के दौरान सामाजिक-आर्थिक पुनर्वास; और

(घ) पुनः अवस्थान।

(7) राज्य, संबद्ध विशेष न्यायालय या अनन्य विशेष न्यायालय को किसी पीड़ित या उसके आश्रित, इत्तिला देने वाले या साक्षियों को प्रदान किए गए संरक्षण के बारे में सूचित करेगा और ऐसा न्यायालय प्रस्थापित किए गए संरक्षण का आवधिक रूप से पुनर्विलोकन करेगा तथा समुचित आदेश पारित करेगा।

(8) उपधारा (6) के उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, संबद्ध विशेष न्यायालय या अनन्य विशेष न्यायालय उसके समक्ष इत्तिला देने वाला, किन्हीं कार्यवाहियों में किसी पीड़ित या उसके आश्रित, इत्तिला देने वाले, या साक्षी द्वारा या ऐसे पीड़ित, इत्तिला देने वाले, या साक्षी के संबंध में विशेष लोक अभियोजक द्वारा किए गए आवेदन पर या स्वप्रेरणा से ऐसे उपाय, जिनमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं, कर सकेगा,—

(क) जनता की पहुंच योग्य मामले के उसके आदेशों या निर्णयों में या किन्हीं अभिलेखों में साक्षियों के नाम और पत्तों को छुपाना;

(ख) साक्षियों की पहचान और पत्तों का अप्रकटन करने के लिए निदेश जारी करना;

(ग) पीड़ित, इत्तिला देने वाले या साक्षी के उत्पीड़न से संबंधित किसी शिकायत के संबंध में तुरंत कार्रवाई करना और उसी दिन, यदि आवश्यक हो, संरक्षण के लिए समुचित आदेश पारित करना:

परंतु खंड (ग) के अधीन प्राप्त शिकायत में जांच या अन्वेषण ऐसे न्यायालय द्वारा मुख्य मामले से पृथक् रूप से विचारित किया जाएगा और शिकायत की प्राप्ति की तारीख से दो मास की अवधि के भीतर पूरा किया जाएगा:

परंतु यह और कि जहां खंड (ग) के अधीन शिकायत किसी लोक सेवक के विरुद्ध है, वहां न्यायालय ऐसे लोक सेवक को, न्यायालय की अनुज्ञा के सिवाय, लंबित मामले से संबंधित या असंबंधित किसी विषय में, यथास्थिति, पीड़ित, इत्तिला देने वाले या साक्षी को बाधा उत्पन्न करने से अवरुद्ध करेगा।

(9) अन्वेषण अधिकारी और थाना अधिकारी का, पीड़ित इत्तिला देने वाले या साक्षियों की अभित्रास, प्रपीड़न या उत्प्रेरणा या हिंसा या हिंसा की धमकियों के विरुद्ध शिकायत को अभिलिखित करने का कर्तव्य होगा, चाहे वह मौखिक रूप से या लिखित में दी गई हो, और प्रथम इत्तिला रिपोर्ट की एक फोटो प्रति उनको तुरंत निःशुल्क दी जाएगी।

(10) इस अधिनियम के अधीन अपराधों से संबंधित सभी कार्यवाहियों की वीडियो रिकार्डिंग की जाएगी।

(11) संबद्ध राज्य का, न्याय प्राप्त करने में पीड़ितों और साक्षियों के निम्नलिखित अधिकारों और हकों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए एक समुचित स्कीम विनिर्दिष्ट करने का कर्तव्य होगा, जिससे,—

(क) अभिलिखित प्रथम इत्तिला रिपोर्ट की प्रति निःशुल्क प्रदान की जा सके;

(ख) अत्याचार से पीड़ितों या उनके आश्रितों को नकद या वस्तु रूप में तुरंत राहत प्रदान की जा सके;

(ग) अत्याचार से पीड़ितों या उनके आश्रितों और साक्षियों को आवश्यक संरक्षण प्रदान किया जा सके;

(घ) मृत्यु या उपहति या संपत्ति को नुकसान के संबंध में राहत प्रदान की जा सके;

(ङ) पीड़ितों को खाद्य या जल या कपड़े या आश्रय या चिकित्सीय सहायता या परिवहन सुविधा या दैनिक भत्तों की व्यवस्था की जा सके;

(च) अत्याचार से पीड़ितों और उनके आश्रितों को भरण-पोषण व्यय प्रदान किया जा सके;

(छ) शिकायत करने और प्रथम इत्तिला रिपोर्ट रजिस्टर करने के समय अत्याचार से पीड़ितों के अधिकारों के बारे में जानकारी प्रदान की जा सके;

(ज) अभित्रास तथा उत्पीड़न के अत्याचार से पीड़ितों या उनके आश्रितों और साक्षियों को संरक्षण प्रदान किया जा सके;

(झ) अन्वेषण और आरोपपत्र की प्रास्थिति पर अत्याचार से पीड़ितों या उनके आश्रितों या सहयुक्त संगठनों या व्यष्टियों को जानकारी प्रदान की जा सके तथा आरोपपत्र की प्रति निःशुल्क प्रदान की जा सके;

(ञ) चिकित्सीय परीक्षा के समय आवश्यक पूर्वावधानियां बरती जा सके;

(ट) राहत रकम के संबंध में अत्याचार से पीड़ितों या उनके आश्रितों या सहयुक्त संगठनों या व्यष्टियों को जानकारी प्रदान की जा सके;

(ठ) अन्वेषण और विचारण की तारीख और स्थान के बारे में अग्रिम रूप से अत्याचार से पीड़ितों या उनके आश्रितों या सहयुक्त संगठनों या व्यष्टियों को जानकारी प्रदान की जा सके;

(ड) अत्याचार से पीड़ितों या उनके आश्रितों या सहयुक्त संगठनों या व्यष्टियों के मामले पर और विचारण की तैयारी के लिए पर्याप्त टिप्पण दिया जा सके तथा उक्त प्रयोजन के लिए विधिक सहायता प्रदान की जा सके;

(ढ) इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के प्रत्येक प्रक्रम पर अत्याचार से पीड़ितों या उनके आश्रितों या सहयुक्त संगठनों या व्यष्टियों के अधिकारों का निष्पादन किया जा सके और अधिकारों के निष्पादन के लिए आवश्यक सहायता प्रदान की जा सके।

(12) अत्याचार से पीड़ितों या उनके आश्रितों का गैर-सरकारी संगठनों, सामाजिक कार्यकर्ताओं या अधिवक्ताओं से सहायता लेने का अधिकार होगा।''

12. मूल अधिनियम की धारा 23 के पश्चात् निम्नलिखित अनुसूची अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:— नई अनुसूची का अंतःस्थापन।

“अनुसूची

[धारा 3 (2) (V) देखिए]

भारतीय दंड संहिता के अधीन धारा	अपराध का नाम और दंड
120क	आपराधिक षड्यंत्र की परिभाषा।
120ख	आपराधिक षड्यंत्र का दंड।
141	विधिविरुद्ध जमाव।
142	विधिविरुद्ध जमाव का सदस्य होना।
143	विधिविरुद्ध जमाव के लिए दंड।
144	घातक आयुध से सज्जित होकर विधिविरुद्ध जमाव में सम्मिलित होना।
145	किसी विधिविरुद्ध जमाव में यह जानते हुए कि उसके बिखर जाने का समादेश दे दिया गया है, सम्मिलित होना या उसमें बने रहना।
146	बलवा करना।
147	बलवा करने के लिए दंड।
148	घातक आयुध से सज्जित होकर बलवा करना।
217	लोक सेवक द्वारा किसी व्यक्ति को दंड से या किसी संपत्ति के सम्पहरण से बचाने के आशय से विधि के निदेश की अवज्ञा।
319	उपहति।
320	घोर उपहति।
323	स्वेच्छया उपहति कारित करने के लिए दंड।
324	खतरनाक आयुधों या साधनों द्वारा स्वेच्छया उपहति कारित करना।
325	स्वेच्छया घोर उपहति कारित करने के लिए दंड।
326ख	स्वेच्छया अम्ल फेंकना या फेंकने का प्रयत्न करना।
332	लोक सेवक को अपने कर्तव्य से भयोपरत करने के लिए स्वेच्छया उपहति कारित करना।
341	सदोष अवरोध के लिए दंड।
354	स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग।
354क	लैंगिक उत्पीड़न और लैंगिक उत्पीड़न के लिए दंड।
354ख	विवस्त्र करने के आशय से स्त्री पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग।
354ग	दृश्यरतिकता।
354घ	पीछा करना।
359	व्यपहरण।
363	व्यपहरण के लिए दंड।
365	किसी व्यक्ति का गुप्त रीति से और सदोष परिरोध करने के आशय से व्यपहरण या अपहरण।
376ख	पति द्वारा अपनी पत्नी के साथ पृथक्करण के दौरान मैथुन।
376ग	प्राधिकार में किसी व्यक्ति द्वारा मैथुन।
447	आपराधिक अतिचार के लिए दंड।
506	आपराधिक अभित्रास के लिए दंड।
509	शब्द, अंग विक्षेप या कार्य जो किसी स्त्री की लज्जा का अनादर करने के लिए आशयित है।

2014 का
अध्यादेश
संख्यांक 1

13. (1) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधन अध्यादेश, 2014 को निरसन और
निरसित किया जाता है। व्यावृत्ति।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के अधीन की गई
कोई बात या कोई कार्रवाई इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन
की गई समझी जाएगी।

माध्यस्थम् और सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2015

(2016 का अधिनियम संख्यांक 3)

[31 दिसंबर, 2015]

माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 का
संशोधन करने के लिए
अधिनियम

भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम माध्यस्थम् और सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2015 है।

संक्षिप्त नाम और
प्रारंभ।

(2) यह 23 अक्टूबर, 2015 को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा।

1996 का 26

2. माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 में,—

धारा 2 का
संशोधन।

(I) उपधारा (1) में,—

(अ) खंड (ड) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:—

‘(ड) “न्यायालय” से,—

(i) अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक माध्यस्थम् से भिन्न किसी माध्यस्थम् के मामले में, किसी जिले में आरंभिक अधिकारिता वाला प्रधान सिविल न्यायालय अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत ऐसा उच्च न्यायालय भी है, जिसे अपनी मामूली आरंभिक सिविल अधिकारिता का प्रयोग करते हुए माध्यस्थम् की विषय-वस्तु वाले प्रश्नों का, यदि वे किसी वाद की विषय-वस्तु होते, विनिश्चय करने की अधिकारिता प्राप्त है, किंतु ऐसे प्रधान सिविल न्यायालय से अवर श्रेणी का कोई सिविल न्यायालय या कोई लघुवाद न्यायालय इसके अंतर्गत नहीं आता है;

(ii) अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक माध्यस्थम् के मामले में, ऐसा उच्च न्यायालय अभिप्रेत है, जिसे अपनी मामूली आरंभिक सिविल अधिकारिता का प्रयोग करते हुए माध्यस्थम् की विषय-वस्तु वाले प्रश्नों का, यदि वे किसी वाद की विषय-वस्तु होते, विनिश्चय करने की अधिकारिता प्राप्त है, और अन्य मामलों में, ऐसा उच्च न्यायालय अभिप्रेत है, जिसे उस उच्च न्यायालय से अधीनस्थ न्यायालयों की डिक्कियों के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई करने की अधिकारिता प्राप्त है;’;

(आ) खंड (च) के उपखंड (iii) में, “ऐसी कोई कंपनी या” शब्दों के स्थान पर “ऐसा कोई” शब्द रखे जाएंगे;

(II) उपधारा (2) में, निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“परन्तु तत्प्रतिकूल किसी करार के अधीन रहते हुए, धारा 9, धारा 27 और धारा 37 की उपधारा (1) के खंड (क) तथा उपधारा (3) के उपबंध अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक माध्यस्थम् को भी लागू होंगे, भले ही माध्यस्थम् का स्थान भारत के बाहर हो और ऐसे स्थान में किया गया या किया जाने वाला माध्यस्थम् पंचाट इस अधिनियम के भाग 2 के उपबंधों के अधीन प्रवर्तनीय और मान्य है।”।

धारा 7 का
संशोधन।

3. मूल अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (4) के खंड (ख) में, “या दूरसंचार के ऐसे अन्य साधनों में” शब्दों के पश्चात् “जिसके अंतर्गत इलैक्ट्रॉनिक साधनों के माध्यम से संसूचना भी है” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे।

धारा 8 का
संशोधन।

4. मूल अधिनियम की धारा 8 में,—

(i) उपधारा (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

“(1) कोई न्यायिक प्राधिकारी, जिसके समक्ष किसी ऐसे मामले में अनुयोग लाया जाता है, जो किसी माध्यस्थम् करार का विषय है, यदि माध्यस्थम् करार का कोई पक्षकार या उसके माध्यम से या उसके अधीन दावा करने वाला कोई व्यक्ति, उस तारीख तक, जो विवाद के सार पर उसका प्रथम कथन प्रस्तुत करने के पश्चात् की न हो, इस प्रकार आवेदन करता है, तो वह उच्चतम न्यायालय या किसी न्यायालय के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश के होते हुए भी, पक्षकारों को माध्यस्थम् के लिए निर्दिष्ट करेगा जब तक कि उसका यह निष्कर्ष न हो कि प्रथमदृष्ट्या कोई विधिमान्य माध्यस्थम् करार विद्यमान नहीं है;”;

(ii) उपधारा (2) में, निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“परन्तु जहां मूल माध्यस्थम् करार या उसकी कोई प्रमाणित प्रति उपधारा (1) के अधीन माध्यस्थम् के लिए निर्देश करने वाले पक्षकार के पास उपलब्ध नहीं है और उक्त करार अथवा उसकी प्रमाणित प्रति उस करार का दूसरे पक्षकार रखे हुए है, वहां इस प्रकार आवेदन करने वाला पक्षकार ऐसा आवेदन, माध्यस्थम् करार की प्रति तथा न्यायालय से इस बात की प्रार्थना करने की अर्जी के साथ फाइल करेगा कि दूसरे पक्षकार से मूल माध्यस्थम् करार या उसकी सम्यक् रूप से प्रमाणित प्रति न्यायालय के समक्ष पेश करने की अपेक्षा की जाए।”।

धारा 9 का
संशोधन।

5. मूल अधिनियम की धारा 9 को उसकी उपधारा (1) के रूप में पुनः संख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार पुनः संख्यांकित उपधारा (1) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधाराएं अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:—

“(2) जहां, माध्यस्थम् कार्यवाहियां प्रारंभ होने के पूर्व, न्यायालय उपधारा (1) के अधीन संरक्षा के किसी अंतरिम उपाय का आदेश पारित करता है, वहां माध्यस्थम् कार्यवाहियां ऐसे आदेश की

तारीख से नब्बे दिन की अवधि के भीतर या ऐसे अतिरिक्त समय के भीतर, जो न्यायालय अवधारित करे, प्रारंभ की जाएंगी।

(3) माध्यस्थम् अधिकरण का एक बार गठन हो जाने पर, न्यायालय उपधारा (1) के अधीन कोई आवेदन तब तक ग्रहण नहीं करेगा जब तक कि न्यायालय का यह निष्कर्ष न हो कि ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान हैं जिनके कारण धारा 17 के अधीन उपबंधित उपचार संभवतः प्रभावकारी न हो पाए।”

6. मूल अधिनियम की धारा 11 में,—

धारा 11 का संशोधन।

(i) उपधारा (4), उपधारा (5) और उपधारा (6) में, “मुख्य न्यायमूर्ति या उसके द्वारा पदाभिहित किसी व्यक्ति या संस्था” शब्दों के स्थान पर, जहाँ-कहीं वे आते हैं, “यथास्थिति, उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या ऐसे न्यायालय द्वारा पदाभिहित किसी व्यक्ति या संस्था” शब्द रखे जाएंगे;

(ii) उपधारा (6) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधाराएं अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:—

“(6क) उपधारा (4) या उपधारा (5) या उपधारा (6) के अधीन किसी आवेदन पर विचार करते समय, यथास्थिति, उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय, किसी न्यायालय के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश के होते हुए भी, किसी माध्यस्थम् करार के विद्यमान होने की परीक्षा करने तक ही सीमित रहेगा।

(6ख) इस धारा के प्रयोजनों के लिए, यथास्थिति, उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति या संस्था के पदाभिधान को उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा न्यायिक शक्तियों का प्रत्यायोजन नहीं माना जाएगा।”;

(iii) उपधारा (7) में, “मुख्य न्यायमूर्ति या उसके द्वारा पदाभिहित व्यक्ति या संस्था को सौंपे गए किसी विषय पर कोई विनिश्चय अंतिम होगा” शब्दों के स्थान पर “यथास्थिति, उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या ऐसे न्यायालय द्वारा पदाभिहित व्यक्ति या संस्था को सौंपे गए किसी विषय पर कोई विनिश्चय अंतिम होगा और ऐसे विनिश्चय के विरुद्ध कोई अपील, जिसके अंतर्गत लेटर्स पेटेंट अपील भी है, नहीं होगी” शब्द रखे जाएंगे;

(iv) उपधारा (8) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

“(8) किसी मध्यस्थ की नियुक्ति करने के पूर्व, यथास्थिति, उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या ऐसे न्यायालय द्वारा पदाभिहित व्यक्ति या संस्था धारा 12 की उपधारा (1) के निबंधनों के अनुसार और—

(क) पक्षकारों के करार द्वारा मध्यस्थ के लिए अपेक्षित किन्हीं अर्हताओं को; और

(ख) प्रकटन की अंतर्वस्तुओं और अन्य विचारणाओं को, जिनसे किसी स्वतंत्र और निष्पक्ष मध्यस्थ की नियुक्ति सुनिश्चित किए जाने की संभावना है,

ध्यान में रखते हुए भावी मध्यस्थ से लिखित में प्रकटन की ईप्सा करेगा;”;

(v) उपधारा (9) में, “भारत का मुख्य न्यायमूर्ति या उसके द्वारा पदाभिहित व्यक्ति या संस्था” शब्दों के स्थान पर “उच्चतम न्यायालय या उस न्यायालय द्वारा पदाभिहित व्यक्ति या संस्था” शब्द रखे जाएंगे;

(vi) उपधारा (10) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

“(10) यथास्थिति, उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय ऐसी स्कीम बना सकेगा जो उक्त न्यायालय, उपधारा (4) या उपधारा (5) या उपधारा (6) द्वारा उसे सौंपे गए विषयों के निपटारे के लिए, समुचित समझे।”;

(vii) उपधारा (11) में, “जहाँ विभिन्न उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों या उनके पदाभिहितों से उपधारा (4) या उपधारा (5) या उपधारा (6) के अधीन पहली बार अनुरोध किया गया है, वहाँ केवल वही न्यायमूर्ति या उसका पदाभिहित ही” शब्दों के स्थान पर “जहाँ विभिन्न उच्च न्यायालयों या उनके पदाभिहितों से उपधारा (4) या उपधारा (5) या उपधारा (6) के अधीन पहली बार अनुरोध किया गया है, वहाँ केवल वही उच्च न्यायालय या उसका पदाभिहित ही” शब्द रखे जाएंगे;

(viii) उपधारा (12) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

‘(12) (क) जहां उपधारा (4), उपधारा (5), उपधारा (6), उपधारा (7), उपधारा (8) और उपधारा (10) में निर्दिष्ट विषय किसी अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक माध्यस्थम् में उद्भूत होते हैं, वहां उन उपधाराओं में “यथास्थिति, उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय” के प्रति निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह “उच्चतम न्यायालय” के प्रति निर्देश है; और

(ख) जहां उपधारा (4), उपधारा (5), उपधारा (6), उपधारा (7), उपधारा (8) और उपधारा (10) में निर्दिष्ट विषय किसी अन्य माध्यस्थम् में उद्भूत होते हैं वहां उन उपधाराओं में, “यथास्थिति, उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय” के प्रति निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह ऐसे “उच्च न्यायालय” के प्रति निर्देश है जिसकी स्थानीय सीमाओं के भीतर धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (ड) में निर्दिष्ट प्रधान सिविल न्यायालय स्थित है और जहां स्वयं उच्च न्यायालय ही उस खंड में निर्दिष्ट न्यायालय है, वहां उस उच्च न्यायालय के प्रति निर्देश है।’;

(ix) उपधारा (12) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधाराएं अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:—

“(13) किसी मध्यस्थ या किन्हीं मध्यस्थों की नियुक्ति के लिए इस धारा के अधीन किए गए किसी आवेदन का निपटारा, यथास्थिति, उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या ऐसे न्यायालय द्वारा पदाभिहित किसी व्यक्ति या संस्था द्वारा यथासंभव शीघ्रता के साथ किया जाएगा और उस मामले का निपटारा विरोधी पक्षकार पर सूचना की तामील किए जाने की तारीख से साठ दिन की अवधि के भीतर करने का प्रयास किया जाएगा।

(14) माध्यस्थम् अधिकरण की फीस के और माध्यस्थम् अधिकरण को उसके संदाय की रीति के अवधारण के प्रयोजन के लिए उच्च न्यायालय चौथी अनुसूची में विनिर्दिष्ट दरों पर विचार करने के पश्चात् ऐसे विनियम विरचित कर सकेगा, जो आवश्यक हों।

स्पष्टीकरण—शंकाओं को दूर करने के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि यह उपधारा अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक माध्यस्थम् को और ऐसे मामले में जहां पक्षकार किसी माध्यस्थम् संस्था के नियमों के अनुसार फीस के अवधारण के लिए सहमत हो गए हैं, से संबंधित माध्यस्थम् (अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक माध्यस्थम् से भिन्न) में लागू नहीं होगी।”।

नई धारा 11क का
अंतःस्थापन।

चौथी अनुसूची का
संशोधन करने की
केंद्रीय सरकार की
शक्ति।

7. मूल अधिनियम की धारा 11 के पश्चात्, निम्नलिखित नई धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

“11क. (1) यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है तो वह, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, चौथी अनुसूची का संशोधन कर सकेगी और तदुपरांत चौथी अनुसूची को तदनुसार संशोधित समझा जाएगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन जारी की जाने वाली प्रस्तावित प्रत्येक अधिसूचना की प्रति संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखी जाएगी। यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी। यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस अधिसूचना के जारी किए जाने का अनुमोदन न करने के लिए सहमत हो जाएं या दोनों सदन उस अधिसूचना में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो, यथास्थिति, अधिसूचना जारी नहीं की जाएगी या केवल ऐसे परिवर्तित रूप में ही जारी की जाएगी, जिस पर संसद् के दोनों सदन सहमत हुए हैं।”।

धारा 12 का
संशोधन।

8. मूल अधिनियम की धारा 12 में,—

(i) उपधारा (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

“(1) जहां किसी व्यक्ति को किसी मध्यस्थ के रूप में उसकी संभावित नियुक्ति के संबंध में प्रस्ताव किया जाता है, वहां वह उन परिस्थितियों का,—

(क) जैसे कि किसी भी पक्षकार के साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संबंध अथवा किसी

भी पक्षकार अथवा विवादग्रस्त विषय-वस्तु के संबंध में हित होने का, चाहे वह वित्तीय, कारोबारी, वृत्तिक या किसी अन्य प्रकार का हो, जिससे कि उसकी स्वतंत्रता और निष्पक्षता के बारे में उचित शंकाएं पैदा होने की संभावनाएं हैं; और

(ख) जिनसे माध्यस्थम् के प्रति पर्याप्त समय देने की उसकी योग्यता और विशिष्टता संपूर्ण माध्यस्थम् को बारह मास की अवधि के भीतर पूरा करने की उसकी योग्यता पर प्रभाव पड़ने की संभावना है,

लिखित रूप में प्रकटन करेगा।

स्पष्टीकरण 1—पांचवीं अनुसूची में कथित आधार इस बात का अवधारण करने में मार्गदर्शन करेंगे कि क्या ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिनसे मध्यस्थ की स्वतंत्रता या निष्पक्षता के बारे में उचित संदेह पैदा होते हैं।

स्पष्टीकरण 2—यह प्रकटन उस व्यक्ति द्वारा छठी अनुसूची में विनिर्दिष्ट रूप में किया जाएगा।”;

(ii) उपधारा (4) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

“(5) तत्प्रतिकूल किसी पूर्व करार में किसी बात के होते हुए भी, ऐसा कोई व्यक्ति, जिसका पक्षकारों या काउन्सेल या विवाद की विषय-वस्तु के साथ संबंध, सातवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्रवर्गों में से किसी के अधीन आता है, मध्यस्थ के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए अपात्र होगा:

परन्तु पक्षकार, उनके बीच विवादों के उत्पन्न होने के पश्चात्, लिखित रूप में अभिव्यक्त करार द्वारा इस उपधारा के लागू होने का अधित्यजन कर सकेंगे।”।

9. मूल अधिनियम की धारा 14 की उपधारा (1) में, आरंभिक भाग में “पर्यवसित हो जाएगा यदि वह” शब्दों के स्थान पर “पर्यवसित हो जाएगा और उसके स्थान पर दूसरे मध्यस्थ को रख दिया जाएगा, यदि वह” शब्द रखे जाएंगे।

धारा 14 का संशोधन।

10. मूल अधिनियम की धारा 17 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

धारा 17 के स्थान पर नई धारा का रखा जाना।

“17. (1) कोई पक्षकार, माध्यस्थम् की कार्यवाहियों के दौरान या माध्यस्थम् पंचाट के किए जाने के पश्चात् किंतु धारा 36 के अनुसार उसे प्रवर्तित किए जाने के पूर्व, किसी समय माध्यस्थम् अधिकरण को—

माध्यस्थम् अधिकरण द्वारा आदिष्ट अंतरिम उपाय।

(i) माध्यस्थम् की कार्यवाहियों के प्रयोजनों के लिए, किसी अवयस्क या विकृत चित्त व्यक्ति के लिए संरक्षक की नियुक्ति करने के लिए; या

(ii) निम्नलिखित विषयों में से किसी के संबंध में संरक्षा के अंतरिम उपाय के लिए, अर्थात्:—

(क) ऐसे किसी माल के, जो माध्यस्थम् करार की विषय-वस्तु है, परिरक्षण, अंतरिम अभिरक्षा या विक्रय के लिए;

(ख) माध्यस्थम् में विवादित रकम को प्रतिभूत करने के लिए;

(ग) ऐसी किसी संपत्ति या वस्तु के, जो माध्यस्थम् में विवाद की विषय-वस्तु है, या जिसके बारे में उसमें कोई प्रश्न उद्भूत हो सकता है, निरोध, परिरक्षण या निरीक्षण के लिए और पूर्वोक्त प्रयोजनों में से किसी के लिए किसी व्यक्ति को किसी पक्षकार में के कब्जे में की किसी भूमि या भवन में प्रवेश करने हेतु प्राधिकृत करने के लिए अथवा ऐसे कोई नमूने

लेने या कोई संप्रेक्षण करने या किसी परीक्षण का प्रयोग करने हेतु, जो संपूर्ण जानकारी या साक्ष्य अभिप्राप्त करने के प्रयोजन के लिए आवश्यक या समीचीन हो, प्राधिकृत करने के लिए;

(घ) अंतरिम व्यादेश या रिसीवर की नियुक्ति के लिए;

(ङ) संरक्षा के ऐसे अन्य अंतरिम उपाय के लिए, जो माध्यस्थम् अधिकरण को न्यायोचित और सुगम प्रतीत हो,

आवेदन कर सकेगा और माध्यस्थम् अधिकरण को आदेश करने की वही शक्तियां प्राप्त होंगी जो न्यायालय को उसके समक्ष की किन्हीं कार्यवाहियों के प्रयोजन के लिए या उनके संबंध में प्राप्त हैं।

(2) धारा 37 के अधीन किसी अपील में पारित किन्हीं आदेशों के अधीन रहते हुए, इस धारा के अधीन माध्यस्थम् अधिकरण द्वारा जारी किए गए किसी आदेश को सभी प्रयोजनों के लिए न्यायालय का आदेश समझा जाएगा और वह सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन उसी रीति से प्रवर्तनीय होगा मानो वह न्यायालय का कोई आदेश हो।”।

1908 का 5

धारा 23 का संशोधन।

11. मूल अधिनियम की धारा 23 की उपधारा (2) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

“(2क) प्रत्यर्थी भी, अपने मामले के समर्थन में, प्रतिदावा प्रस्तुत कर सकेगा या मुजराई का अभिवाक् कर सकेगा जिसका न्यायनिर्णयन, यदि ऐसा प्रतिदावा या ऐसी मुजराई माध्यस्थम् करार की परिधि के अंतर्गत आती है, माध्यस्थम् अधिकरण द्वारा किया जाएगा।”।

धारा 24 का संशोधन।

12. मूल अधिनियम की धारा 24 की उपधारा (1) के परन्तुक के पश्चात्, निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“परन्तु यह और कि माध्यस्थम् अधिकरण यथासंभव साक्ष्य की प्रस्तुति के लिए या मौखिक बहस के लिए दिन-प्रतिदिन के आधार पर मौखिक सुनवाई करेगा और जब तक पर्याप्त हेतुक प्रस्तुत न किया जाए कोई स्थगन मंजूर नहीं करेगा तथा बिना किसी पर्याप्त कारण के स्थगन की ईप्सा करने वाले पक्षकार पर खर्च, जिनके अंतर्गत निदर्श खर्च भी है, अधिरोपित कर सकेगा।”।

धारा 25 का संशोधन।

13. मूल अधिनियम की धारा 25 के खंड (ख) में, “कार्यवाहियों को चालू रखेगा” शब्दों के पश्चात्, “और प्रत्यर्थी के ऐसे प्रतिरक्षा कथन को फाइल करने के अधिकार को इस रूप में मानने का विवेकाधिकार होगा मानो कि वह समपहृत हो गया है” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे।

धारा 28 का संशोधन।

14. मूल अधिनियम की धारा 28 की उपधारा (3) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

“(3) माध्यस्थम् अधिकरण, किसी पंचाट का विनिश्चय और उसे करते समय, सभी मामलों में, संविदा के निबंधनों और संव्यवहार को लागू व्यापार प्रथाओं को ध्यान में रखेगा।”।

नई धारा 29क और धारा 29ख का अंतःस्थापन।

15. मूल अधिनियम की धारा 29 के पश्चात्, निम्नलिखित नई धाराएं अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:—

माध्यस्थम् पंचाट की समय-सीमा।

“29क. (1) पंचाट, माध्यस्थम् अधिकरण द्वारा निर्देश ग्रहण किए जाने की तारीख से बारह मास की अवधि के भीतर किया जाएगा।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनार्थ, माध्यस्थम् अधिकरण के बारे में यह समझा जाएगा कि उसने उस तारीख को निर्देश ग्रहण कर लिया है जिसको, यथास्थिति, माध्यस्थ या सभी माध्यस्थों ने अपनी नियुक्ति की सूचना लिखित में प्राप्त कर ली है।

(2) यदि पंचाट उस तारीख से, जिसको माध्यस्थम् अधिकरण निर्देश ग्रहण करता है, छह मास की अवधि के भीतर किया जाता है, तो माध्यस्थम् अधिकरण अतिरिक्त फीस की उतनी रकम प्राप्त करने का हकदार होगा जितनी पक्षकारों के बीच करार पाई जाए।

(3) पक्षकार, सम्मति द्वारा, पंचाट करने के लिए उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट अवधि को छह मास से अनधिक की और अवधि के लिए बढ़ा सकेंगे।

(4) यदि उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट अवधि या उपधारा (3) के अधीन विनिर्दिष्ट विस्तारित अवधि के भीतर पंचाट नहीं किया जाता है तो मध्यस्थ (मध्यस्थों) का समादेश, जब तक कि न्यायालय द्वारा इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि के पूर्व या उसके पश्चात् उस अवधि को बढ़ा न दिया गया हो, पर्यवसित हो जाएगा:

परन्तु यदि इस उपधारा के अधीन अवधि बढ़ाए जाने के समय न्यायालय का निष्कर्ष यह है कि कार्यवाहियों में विलंब माध्यस्थम् अधिकरण के कारण हुआ माना जा सकता है तो वह ऐसे विलंब के प्रत्येक मास के लिए मध्यस्थ (मध्यस्थों) की फीस में पांच प्रतिशत से अनधिक तक की कमी किए जाने का आदेश कर सकेगा।

(5) उपधारा (4) में निर्दिष्ट अवधि का विस्तारण किसी भी पक्षकार के आवेदन पर किया जा सकेगा और केवल पर्याप्त कारण होने पर तथा ऐसे निबंधनों और शर्तों पर ही, जो न्यायालय द्वारा अधिरोपित की जाएं, मंजूर किया जा सकेगा।

(6) उपधारा (4) में निर्दिष्ट अवधि का विस्तारण करते हुए, न्यायालय एक या सभी मध्यस्थों को प्रतिस्थापित करने के लिए स्वतंत्र होगा और यदि एक या सभी मध्यस्थों को प्रतिस्थापित किया जाता है, तो माध्यस्थम् की कार्यवाहियां उस प्रक्रम से, जिस प्रक्रम पर वे हैं और पहले से अभिलेखगत साक्ष्य और सामग्री के आधार पर जारी रहेंगी और इस धारा के अधीन नियुक्त मध्यस्थ (मध्यस्थों) के बारे में यह समझा जाएगा कि उन्हें उक्त साक्ष्य और सामग्री प्राप्त हो गई है।

(7) इस धारा के अधीन मध्यस्थ (मध्यस्थों) के नियुक्त किए जाने की दशा में, इस प्रकार पुनर्गठित माध्यस्थम् की कार्यवाहियों को पूर्व में नियुक्त माध्यस्थम् अधिकरण की क्रमागत कार्यवाहियां समझा जाएगा।

(8) न्यायालय इस धारा के अधीन किन्हीं भी पक्षकारों पर वास्तविक या निदर्श खर्च अधिरोपित करने के लिए स्वतंत्र होगा।

(9) उपधारा (5) के अधीन फाइल किए गए आवेदन का निपटारा न्यायालय द्वारा यथासंभव शीघ्रता के साथ किया जाएगा और मामले का निपटारा विरोधी पक्षकार पर सूचना की तामील किए जाने की तारीख से साठ दिन की अवधि के भीतर करने का प्रयास किया जाएगा।

29ख. (1) इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, माध्यस्थम् करार के पक्षकार, त्वरित प्रक्रिया। माध्यस्थम् अधिकरण की नियुक्ति के पूर्व या के समय, किसी भी प्रक्रम पर, उपधारा (3) में विनिर्दिष्ट त्वरित प्रक्रिया द्वारा अपने विवाद का समाधान करने के लिए लिखित में करार कर सकेंगे।

(2) माध्यस्थम् करार के पक्षकार, त्वरित प्रक्रिया द्वारा विवाद का समाधान कराने का करार करते समय इस बात के लिए सहमत हो सकते हैं कि माध्यस्थम् अधिकरण में ऐसा एकल मध्यस्थ होगा जिसे पक्षकारों द्वारा चुना जाएगा।

(3) माध्यस्थम् अधिकरण, उपधारा (1) के अधीन माध्यस्थम् की कार्यवाहियों के संचालन के समय निम्नलिखित प्रक्रिया का अनुसरण करेगा, अर्थात्:—

(क) माध्यस्थम् अधिकरण, पक्षकारों द्वारा फाइल किए गए लिखित अभिवाकों, दस्तावेजों और निवेदनों के आधार पर विवाद का विनिश्चय किसी मौखिक सुनवाई के बिना, करेगा;

(ख) माध्यस्थम् अधिकरण को पक्षकारों से, उनके द्वारा फाइल किए गए अभिवाकों और दस्तावेजों के अलावा, कोई अतिरिक्त सूचना या स्पष्टीकरण मांगने की शक्ति होगी;

(ग) यदि सभी पक्षकार अनुरोध करें अथवा यदि माध्यस्थम् अधिकरण कतिपय मुद्दों को स्पष्ट करने के लिए मौखिक सुनवाई करना आवश्यक समझता है तो केवल तभी मौखिक सुनवाई की जा सकेगी;

(घ) यदि मौखिक सुनवाई की जाती है तो माध्यस्थम् अधिकरण किन्हीं तकनीकी औपचारिकताओं से अभिमुक्ति प्रदान कर सकेगा और ऐसी प्रक्रिया अंगीकार कर सकेगा, जो वह मामले के शीघ्र निपटारे के लिए समुचित समझे।

(4) इस धारा के अधीन पंचाट उस तारीख से, जिसको माध्यस्थम् अधिकरण द्वारा निर्देश ग्रहण किया जाता है, छह मास की अवधि के भीतर किया जाएगा।

(5) यदि पंचाट उपधारा (4) में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर नहीं किया जाता है तो धारा 29क की उपधारा (3) से उपधारा (9) के उपबंध कार्यवाहियों को लागू होंगे।

(6) मध्यस्थ को संदेय फीस और फीस के संदाय की रीति ऐसी होगी, जो मध्यस्थ और पक्षकारों के बीच करार पाई जाए।”।

धारा 31 का
संशोधन।

16. मूल अधिनियम की धारा 31 में,—

(i) उपधारा (7) के खंड (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:—

“(ख) उस राशि पर, जिसका संदाय किए जाने का माध्यस्थम् पंचाट द्वारा निदेश दिया गया है, जब तक कि पंचाट में अन्यथा निदेश न दिया गया हो, पंचाट की तारीख से उस राशि का संदाय किए जाने की तारीख तक, पंचाट की तारीख को लागू ब्याज की वर्तमान दर से दो प्रतिशत उच्चतर दर पर ब्याज लगेगा।

स्पष्टीकरण—“ब्याज की वर्तमान दर” पद का वही अर्थ है जो ब्याज अधिनियम, 1978 की धारा 2 के खंड (ख) में उसका है।” 1978 का 14

(ii) उपधारा (8) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

“(8) किसी माध्यस्थम् का खर्च माध्यस्थम् अधिकरण द्वारा धारा 31क के अनुसार नियत किया जाएगा।”।

नई धारा 31क का
अंतःस्थापन।

17. मूल अधिनियम की धारा 31 के पश्चात्, निम्नलिखित नई धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

खर्चों के लिए
शासनतंत्र।

‘31क. (1) किसी माध्यस्थम् कार्यवाही या इस अधिनियम के उपबंधों में से किसी उपबंध के अधीन माध्यस्थम् से तात्पर्यित किसी कार्यवाही के संबंध में, न्यायालय या माध्यस्थम् अधिकरण को, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, निम्नलिखित का अवधारण करने का विवेकाधिकार होगा—

1908 का 5

(क) क्या एक पक्षकार द्वारा दूसरे पक्षकार को खर्च संदेय हैं;

(ख) ऐसे खर्चों की रकम; और

(ग) ऐसे खर्चों का संदाय कब किया जाना है।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनार्थ, “खर्चों” से निम्नलिखित के संबंध में युक्तियुक्त खर्च अभिप्रेत हैं—

(i) मध्यस्थों, न्यायालयों और साक्षियों की फीस और व्यय;

(ii) विधिक फीस और व्यय;

(iii) माध्यस्थम् का पर्यवेक्षण करने वाली संस्था की कोई प्रशासनिक फीस; और

(iv) माध्यस्थम् या न्यायालय की कार्यवाहियों और माध्यस्थम् पंचाट के संबंध में उपगत कोई अन्य व्यय।

(2) यदि न्यायालय या माध्यस्थम् अधिकरण खर्चों के संदाय के बारे में कोई आदेश करने का विनिश्चय करता है तो —

(क) साधारण नियम यह है कि असफल पक्षकार को खर्चों का संदाय सफल पक्षकार को करने का आदेश दिया जाएगा; या

(ख) न्यायालय या माध्यस्थम् अधिकरण द्वारा लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से कोई भिन्न आदेश किया जा सकेगा।

(3) न्यायालय या माध्यस्थम् अधिकरण, खर्चों का अवधारण करने में सभी परिस्थितियों का ध्यान रखेगा, जिनके अंतर्गत निम्नलिखित भी हैं,—

(क) सभी पक्षकारों का आचरण;

(ख) क्या पक्षकार मामले में भागतः सफल हुआ है;

(ग) क्या ऐसा कोई तुच्छ प्रतिदावा किया गया था जिसके कारण माध्यस्थम् की कार्यवाहियों में विलंब हुआ है; और

(घ) क्या विवाद का निपटारा करने के लिए कोई युक्तियुक्त प्रस्ताव एक पक्षकार द्वारा किया गया है और दूसरे पक्षकार द्वारा उससे इंकार कर दिया गया है।

(4) न्यायालय या माध्यस्थम् अधिकरण इस धारा के अधीन कोई आदेश कर सकेगा जिसके अंतर्गत ऐसा आदेश भी है कि पक्षकार निम्नलिखित का संदाय करेगा:—

(क) दूसरे पक्षकार के कोई आनुपातिक खर्चें;

(ख) दूसरे पक्षकार के खर्चों के संबंध में कथित कोई रकम;

(ग) केवल एक निश्चित तारीख से या एक निश्चित तारीख तक के खर्चें;

(घ) कार्यवाहियों के आरंभ होने के पूर्व उपगत खर्चें;

(ङ) कार्यवाहियों में किए गए विशिष्ट उपायों से संबंधित खर्चें;

(च) कार्यवाहियों के केवल किसी सुभिन्न भाग से संबंधित खर्चें; और

(छ) एक निश्चित तारीख से या एक निश्चित तारीख तक के खर्चों पर ब्याज।

(5) ऐसा करार, जिसका प्रभाव यह है कि पक्षकार को माध्यस्थम् के संपूर्ण खर्चों या उसके भाग का किसी भी दशा में संदाय करना होगा केवल तभी विधिमान्य होगा यदि ऐसा करार प्रश्नगत विवाद के उद्भूत होने के पश्चात् किया जाता है।'

18. मूल अधिनियम की धारा 34 में,—

धारा 34 का संशोधन।

(1) उपधारा (2) के खंड (ख) में, स्पष्टीकरण के स्थान पर, निम्नलिखित स्पष्टीकरण रखे जाएंगे, अर्थात्:—

“स्पष्टीकरण 1—किसी शंका को दूर करने के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि कोई भी पंचाट भारत की लोक नीति के विरुद्ध केवल तभी होगा, यदि—

(i) पंचाट का किया जाना कपट या भ्रष्टाचार द्वारा उत्प्रेरित है या प्रभावित किया गया है अथवा वह धारा 75 या धारा 81 के अतिक्रमण में है; या

(ii) वह भारतीय विधि की मूलभूत नीति के उल्लंघन में है; या

(iii) वह नैतिकता या न्याय की अत्यंत आधारभूत धारणा के विरोध में है।

स्पष्टीकरण 2—शंका को दूर करने के लिए, इस बात की जांच कि भारतीय विधि की मूलभूत नीति का उल्लंघन हुआ है अथवा नहीं, विवाद के गुणागुण के पुनर्विलोकन को आवश्यक नहीं बनाएगी।”;

(II) उपधारा (2) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

“(2क) अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक माध्यस्थता से भिन्न माध्यस्थता से उद्भूत किसी माध्यस्थता पंचाट को भी न्यायालय द्वारा अपास्त किया जा सकेगा यदि न्यायालय का यह निष्कर्ष है कि पंचाट को देखने से ही यह प्रतीत होता है कि वह प्रकट अवैधता से दूषित है:

परन्तु किसी पंचाट को केवल विधि के गलत रूप से लागू किए जाने के आधार पर या साक्ष्य का पुनर्मूल्यांकन करके अपास्त नहीं किया जाएगा।”;

(III) उपधारा (4) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधाराएं अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:—

“(5) इस धारा के अधीन कोई आवेदन किसी पक्षकार द्वारा दूसरे पक्षकार को पूर्व सूचना जारी करने के पश्चात् ही फाइल किया जाएगा और ऐसे आवेदन के साथ आवेदक द्वारा उक्त अपेक्षा के अनुपालन का पृष्ठांकन करते हुए एक शपथपत्र संलग्न किया जाएगा।

(6) इस धारा के अधीन आवेदन का निपटारा यथाशीघ्र और किसी भी दशा में उस तारीख से, जिसको उपधारा (5) में निर्दिष्ट सूचना दूसरे पक्षकार पर तामील की जाती है, एक वर्ष की अवधि के भीतर किया जाएगा।”।

धारा 36 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन।

19. मूल अधिनियम की धारा 36 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

प्रवर्तन।

“36. (1) जहां धारा 34 के अधीन माध्यस्थता पंचाट को अपास्त करने के लिए कोई आवेदन करने का समय समाप्त हो गया है, वहां उपधारा (2) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, ऐसा पंचाट सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के उपबंधों के अनुसार उसी रीति से प्रवर्तित किया जाएगा मानो वह न्यायालय की कोई डिक्री हो। 1908 का 5

(2) जहां माध्यस्थता पंचाट को अपास्त करने के लिए कोई आवेदन न्यायालय में धारा 34 के अधीन फाइल किया गया है, वहां ऐसे किसी आवेदन के फाइल किए जाने से ही वह पंचाट तब तक अप्रवर्तनीय नहीं हो जाएगा जब तक कि न्यायालय उस प्रयोजन के लिए किए गए किसी पृथक् आवेदन पर उपधारा (3) के उपबंधों के अनुसार उक्त माध्यस्थता पंचाट के प्रवर्तन पर कोई रोकाना नहीं दे देता है।

(3) न्यायालय, माध्यस्थता पंचाट के प्रवर्तन पर रोक लगाने के लिए उपधारा (2) के अधीन कोई आवेदन फाइल किए जाने पर, ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो वह ठीक समझे, लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से ऐसे पंचाट के प्रवर्तन पर रोक मंजूर कर सकेगा:

परन्तु न्यायालय, धन के संदाय संबंधी माध्यस्थता पंचाट के मामले में रोक मंजूर करने संबंधी आवेदन पर विचार करते समय, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के उपबंधों के अधीन धन संबंधी किसी डिक्री पर रोक मंजूर किए जाने संबंधी उपबंधों का सम्यक् ध्यान रखेगा।”। 1908 का 5

धारा 37 का संशोधन।

20. मूल अधिनियम की धारा 37 की उपधारा (1) के खंड (क) और खंड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखे जाएंगे, अर्थात्:—

“(क) धारा 8 के अधीन माध्यस्थता के लिए पक्षकारों को निर्दिष्ट करने से इंकार करना;

(ख) धारा 9 के अधीन किसी उपाय को मंजूर करना या मंजूर करने से इंकार करना;

(ग) धारा 34 के अधीन माध्यस्थता पंचाट को अपास्त करना या अपास्त करने से इंकार करना।”।

21. मूल अधिनियम की धारा 47 के स्पष्टीकरण के स्थान पर, निम्नलिखित स्पष्टीकरण रखा जाएगा, धारा 47 का संशोधन।
अर्थात्:—

‘स्पष्टीकरण—इस धारा में और इस अध्याय में की आगे की धाराओं में, “न्यायालय” से ऐसा उच्च न्यायालय अभिप्रेत है, जिसे माध्यस्थ पंचाट की विषय-वस्तु वाले प्रश्नों का, यदि वे उसकी आरंभिक सिविल अधिकारिता पर किसी वाद की विषय-वस्तु होते, विनिश्चय करने की आरंभिक अधिकारिता प्राप्त है और अन्य मामलों में ऐसा उच्च न्यायालय अभिप्रेत है जिसे उक्त उच्च न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालयों की डिक्रियों के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई करने की अधिकारिता प्राप्त है।’

22. मूल अधिनियम की धारा 48 की उपधारा (2) के स्पष्टीकरण के स्थान पर, निम्नलिखित स्पष्टीकरण रखे जाएंगे, अर्थात्:— धारा 48 का संशोधन।

“स्पष्टीकरण 1—किसी शंका को दूर करने के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि कोई पंचाट भारत की लोक नीति के विरुद्ध केवल तभी होगा यदि—

(i) पंचाट का किया जाना कपट या भ्रष्टाचार द्वारा उत्प्रेरित है या प्रभावित किया गया है अथवा वह धारा 75 या धारा 81 के अतिक्रमण में है; या

(ii) वह भारतीय विधि की मूलभूत नीति के उल्लंघन में है; या

(iii) वह नैतिकता या न्याय की अत्यंत आधारभूत धारणा के विरोध में है।

स्पष्टीकरण 2—शंका को दूर करने के लिए, इस बात की जांच कि भारतीय विधि की मूलभूत नीति का उल्लंघन हुआ है अथवा नहीं, विवाद के गुणागुण के पुनर्विलोकन को आवश्यक नहीं बनाएगी।”

23. मूल अधिनियम की धारा 56 के स्पष्टीकरण के स्थान पर, निम्नलिखित स्पष्टीकरण रखा जाएगा, धारा 56 का संशोधन।
अर्थात्:—

‘स्पष्टीकरण —इस धारा में और इस अध्याय में की आगे की धाराओं में, “न्यायालय” से ऐसा उच्च न्यायालय अभिप्रेत है, जिसे माध्यस्थ पंचाट की विषय-वस्तु वाले प्रश्नों का, यदि वे उसकी आरंभिक सिविल अधिकारिता पर किसी वाद की विषय-वस्तु होते, विनिश्चय करने की आरंभिक अधिकारिता प्राप्त है और अन्य मामलों में ऐसा उच्च न्यायालय अभिप्रेत है जिसे उक्त उच्च न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालयों की डिक्रियों के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई करने की अधिकारिता प्राप्त है।’

24. मूल अधिनियम की धारा 57 की उपधारा (1) के स्पष्टीकरण के स्थान पर, निम्नलिखित स्पष्टीकरण रखे जाएंगे, अर्थात्:— धारा 57 का संशोधन।

“स्पष्टीकरण 1—किसी शंका को दूर करने के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि कोई भी पंचाट भारत की लोक नीति के विरुद्ध केवल तभी होगा यदि—

(i) पंचाट का किया जाना कपट या भ्रष्टाचार द्वारा उत्प्रेरित है या प्रभावित किया गया है अथवा वह धारा 75 या धारा 81 के अतिक्रमण में है; या

(ii) वह भारतीय विधि की मूलभूत नीति के उल्लंघन में है; या

(iii) वह नैतिकता या न्याय की अत्यंत आधारभूत धारणा के विरोध में है।

स्पष्टीकरण 2—शंका को दूर करने के लिए, इस बात की जांच कि भारतीय विधि की मूलभूत नीति का उल्लंघन हुआ है अथवा नहीं, विवाद के गुणागुण के पुनर्विलोकन को आवश्यक नहीं बनाएगी।”

नई चौथी अनुसूची,
पांचवीं अनुसूची,
छठी अनुसूची और
सातवीं अनुसूची का
अंतःस्थापन।

25. मूल अधिनियम की तीसरी अनुसूची के पश्चात्, निम्नलिखित नई अनुसूचियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:—

‘चौथी अनुसूची

[धारा 11(14) देखिए]

विवादित राशि	मॉडल फीस
5,00,000/- रुपए तक	45,000/- रुपए
5,00,000/- रुपए से ऊपर और 20,00,000/- रुपए तक	45,000/- रुपए + 5,00,000/- रुपए से अधिक की दावा रकम का 3.5 प्रतिशत
20,00,000/- रुपए से ऊपर और 1,00,00,000/- तक	97,500/- रुपए + 20,00,000/- रुपए से अधिक की दावा रकम का 3 प्रतिशत
1,00,00,000/- रुपए से ऊपर और 10,00,00,000/- रुपए तक	3,37,500/- रुपए + 1,00,00,000/- रुपए से अधिक की दावा रकम का 1 प्रतिशत
10,00,00,000/- रुपए से ऊपर और 20,00,00,000/- रुपए तक	12,37,500/- रुपए + 10,00,00,000/- रुपए से अधिक की दावा रकम का 0.75 प्रतिशत
20,00,00,000/- रुपए से ऊपर	19,87,500/- रुपए + 20,00,00,000/- रुपए, से 30,00,00,000/- रुपए की अधिकतम सीमा सहित से अधिक की दावा रकम का 0.5 प्रतिशत।

टिप्पण: यदि माध्यस्थम् अधिकरण एकल मध्यस्थ है, तो वह ऊपर वर्णित सारणी के अनुसार संदेय फीस पर पच्चीस प्रतिशत अतिरिक्त रकम का हकदार होगा।

पांचवीं अनुसूची

[धारा 12(1) (ख) देखिए]

निम्नलिखित आधार मध्यस्थों की स्वतन्त्रता या निष्पक्षता के बारे में संदेह उत्पन्न करते हैं:

मध्यस्थों का पक्षकारों या काउंसेल के साथ संबंध

1. मध्यस्थ किसी पक्षकार का कोई कर्मचारी, परामर्शी, सलाहकार है या उसका किसी पक्षकार के साथ कोई अन्य पूर्व या वर्तमान कारोबारी सम्बन्ध है।
2. मध्यस्थ वर्तमान में पक्षकारों में से किसी एक पक्षकार का प्रतिनिधित्व करता है या उसे सलाह देता है अथवा किसी एक पक्षकार का सहबद्ध है।
3. वर्तमान में, मध्यस्थ ऐसे वकील या विधि फर्म का प्रतिनिधित्व कर रहा है जो पक्षकारों में से किसी एक पक्षकार के काउंसेल के रूप में कार्य कर रही है।
4. मध्यस्थ उसी विधि फर्म का एक वकील है जो पक्षकारों में से किसी एक पक्षकार का प्रतिनिधित्व कर रही है।
5. मध्यस्थ पक्षकारों में से किसी एक पक्षकार के किसी ऐसे सहबद्ध का प्रबन्धक, निदेशक या प्रबन्धतन्त्र का एक भाग है या उसका उसमें वैसा ही नियंत्रणकारी असर है, यदि उक्त सहबद्ध मध्यस्थता में के विवादग्रस्त विषयों में प्रत्यक्ष रूप से अंतर्वलित है।
6. मध्यस्थ की विधि फर्म, मध्यस्थ द्वारा अपने को अंतर्वलित किए बिना, मामले में पूर्व में अंतर्वलित थी किंतु उसका अंतर्वलन समाप्त हो गया था।

7. मध्यस्थ की विधि फर्म का वर्तमान में पक्षकारों में से किसी के साथ या पक्षकारों में से किसी के सहबद्ध के साथ महत्वपूर्ण वाणिज्यिक संबंध है।
8. मध्यस्थ नियुक्ति पक्षकार को या नियुक्ति पक्षकार के सहबद्ध को नियमित रूप से सलाह देता है भले ही न तो मध्यस्थ और न ही उसकी फर्म को उससे कोई महत्वपूर्ण वित्तीय आय व्युत्पन्न होती है।
9. मध्यस्थ के पक्षकारों में से किसी के साथ और कंपनियों की दशा में कंपनी के प्रबंधन और नियंत्रण में के व्यक्तियों के साथ निकट के कौटुम्बिक संबंध हैं।
10. मध्यस्थ के निकट के कौटुम्बिक सदस्य का पक्षकारों में से किसी में या पक्षकारों के किसी सहबद्ध में महत्वपूर्ण वित्तीय हित है।
11. मध्यस्थ ऐसे किसी अस्तित्व का, जो माध्यस्थम् में एक पक्षकार है, विधिक प्रतिनिधि है।
12. मध्यस्थ पक्षकारों में से किसी में प्रबंधक, निदेशक या प्रबंधतंत्र का एक भाग है या उसका उसमें वैसा ही नियंत्रणकारी असर है।
13. मध्यस्थ का पक्षकारों में से किसी में या मामले के निर्णय में महत्वपूर्ण वित्तीय हित है।
14. मध्यस्थ नियुक्ति पक्षकार को या नियुक्ति पक्षकार के सहबद्ध को नियमित रूप से सलाह देता है और मध्यस्थ या उसकी फर्म को उससे महत्वपूर्ण वित्तीय आय व्युत्पन्न होती है।

मध्यस्थ का विवाद से संबंध

15. मध्यस्थ ने विवाद के संबंध में किसी पक्षकार या पक्षकारों में से किसी के सहबद्ध को विधिक सलाह दी है या विशेषज्ञ राय प्रदान की है।
16. मध्यस्थ मामले में पूर्ववर्ती रूप से अंतर्वलित है।

मध्यस्थ का विवाद में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हित होना

17. मध्यस्थ पक्षकारों में से किसी में या पक्षकारों में से किसी एक के सहबद्ध में प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः शेर धारण करता है अर्थात् प्राइवेट रूप से धारित किए हुए है।
18. मध्यस्थ के निकट के कौटुम्बिक सदस्य का विवाद के निर्णय में महत्वपूर्ण वित्तीय हित है।
19. मध्यस्थ या मध्यस्थ के निकट के कौटुम्बिक सदस्य का ऐसे अन्य पक्षकार के साथ, जो विवाद में के असफल पक्षकार की ओर से सहारा लेने के लिए दायी हो सकता है, निकट के संबंध हैं।

पक्षकारों में से किसी एक पक्षकार के लिए मामले में पूर्ववर्ती रूप से सेवाएं या अन्य अंतर्वलन

20. मध्यस्थ ने पिछले तीन वर्षों के भीतर पक्षकारों में से किसी के या पक्षकारों में से किसी एक के सहबद्ध के काउन्सेल के रूप में कार्य किया है या पूर्व में किसी असंबंधित मामले में नियुक्ति करके पक्षकार या पक्षकार के सहबद्ध को पूर्व में सलाह दी है या उसके द्वारा उससे परामर्श किया गया है; किंतु मध्यस्थ और पक्षकार या पक्षकार के सहबद्ध के बीच अब कोई संबंध नहीं है।
21. मध्यस्थ ने पिछले तीन वर्षों के भीतर पक्षकारों में से किसी के या पक्षकारों में से किसी एक के सहबद्ध के विरुद्ध किसी असंबद्ध मामले में काउन्सेल के रूप में कार्य किया है।
22. मध्यस्थ को पिछले तीन वर्षों के भीतर पक्षकारों में से किसी एक या पक्षकारों में से एक के सहबद्ध द्वारा दो या अधिक अवसरों पर मध्यस्थ के रूप में नियुक्त किया गया है।
23. मध्यस्थ की विधि फर्म ने पिछले तीन वर्षों के भीतर मध्यस्थ को अंतर्वलित किए बिना, पक्षकारों में से एक या पक्षकारों में से एक के सहबद्ध के लिए किसी असंबंधित मामले में कार्य किया है।

24. मध्यस्थ वर्तमान में किसी अन्य माध्यस्थम् में किसी संबंधित विवादक पर, जिसमें पक्षकारों में से एक या पक्षकारों में से एक का सहबद्ध अंतर्वलित है, मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है या उसने पिछले तीन वर्षों के भीतर कार्य किया है।

मध्यस्थ और अन्य मध्यस्थ या काउन्सेल के बीच संबंध

25. मध्यस्थ और कोई अन्य मध्यस्थ उसी विधि फर्म में वकील हैं।
26. मध्यस्थ पिछले तीन वर्षों के भीतर किसी अन्य मध्यस्थ या उसी माध्यस्थम् में किसी काउन्सेल का भागीदार था या अन्यथा उससे सहबद्ध था।
27. मध्यस्थ की विधि फर्म में का वकील ऐसे किसी अन्य विवाद में मध्यस्थ है जिसमें वही पक्षकार या वे ही पक्षकार अथवा पक्षकारों में से एक का सहबद्ध अंतर्वलित है।
28. मध्यस्थ का निकट का कौटुम्बिक सदस्य उस विधि फर्म का भागीदार या कर्मचारी है जो पक्षकारों में से एक का प्रतिनिधित्व कर रही है किंतु विवाद में सहायता प्रदान नहीं कर रही है।
29. मध्यस्थ को पिछले तीन वर्षों के भीतर उसी काउन्सेल या उसी विधि फर्म द्वारा तीन से अधिक मनोनयन प्राप्त हुए हैं।

मध्यस्थ और पक्षकार तथा माध्यस्थम् में अंतर्वलित अन्यो के बीच संबंध

30. मध्यस्थ की फर्म इस समय पक्षकारों में से एक अथवा पक्षकारों में से एक के सहबद्ध के प्रतिकूल कार्य कर रही है।
31. मध्यस्थ पिछले तीन वर्षों के भीतर किसी पक्षकार या पक्षकारों में से एक के सहबद्ध के साथ व्यवसायिक हैसियत में जैसे कि पूर्व कर्मचारी या भागीदार के रूप में सहयोजित रहा है।

अन्य परिस्थितियां

32. मध्यस्थ के, संख्या या अंकित मूल्य के कारण, जिनसे कि पक्षकारों में से एक में या पक्षकारों में से एक के सहबद्ध में तात्विक धृति का गठन होता है, सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध की जाती है प्रत्यक्षतया या अप्रत्यक्षतया शेयर धारण करता है।
33. मध्यस्थ किसी माध्यस्थम् संस्था में विवाद के विषय में नियुक्ति प्राधिकारी की हैसियत धारण करता है।
34. मध्यस्थ पक्षकारों में से किसी एक पक्षकार के सहबद्ध में कोई प्रबंधक, निदेशक या प्रबंधतंत्र का एक भाग है या उसका उसमें वैसा ही नियंत्रणकारी असर है, जहां कि वह सहबद्ध मध्यस्थता में के विवादग्रस्त विषयों में प्रत्यक्ष रूप से अंतर्वलित नहीं है।

स्पष्टीकरण 1—“निकट का कौटुम्बिक सदस्य” पद पति/पत्नी, सहोदर, बालक, माता/पिता या जीवन साथी के प्रति निर्देश करता है।

स्पष्टीकरण 2—“सहबद्ध” पद के अंतर्गत कंपनियों के एक समूह में सभी कंपनियां, जिनके अंतर्गत मूल कंपनी भी है, आती हैं।

स्पष्टीकरण 3—शंकाओं को दूर करने के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि माध्यस्थम् के कतिपय विनिर्दिष्ट रूपों में, जैसे कि सामुद्रिक या वस्तु संबंधी माध्यस्थम् रूप में लघु, विशेषज्ञ पूल से मध्यस्थों को लेने के लिए एक पद्धति हो सकती है। यदि इन क्षेत्रों में पक्षकारों के लिए प्रायः उसी मध्यस्थ को भिन्न-भिन्न मामलों में नियुक्त करने की रूढ़ि और पद्धति है, तो उपर्युक्त नियत नियमों को लागू करते समय सुसंगत तथ्य को विचार में लिया जाना होगा।

छठी अनुसूची

[धारा 12(1)(ख) देखिए]

नाम:

संपर्क के ब्यौरे:

पूर्व अनुभव (जिसके अंतर्गत माध्यस्थों का अनुभव भी है):

चल रहे माध्यस्थों की संख्या:

वे परिस्थितियाँ जिनसे पक्षकारों में से किसी में या विवादग्रस्त विषय-वस्तु के संबंध में कोई पूर्व या वर्तमान संबंध या हित है, चाहे वह वित्तीय, कारोबारी या अन्य प्रकार का हो, जिससे उसकी स्वतंत्रता या निष्पक्षता के बारे में उचित शंकाएँ पैदा होने की संभावना है (सूची दें):

वे परिस्थितियाँ जिनसे माध्यस्थ के प्रति पर्याप्त समय देने की आपकी योग्यता और विशिष्टता संपूर्ण माध्यस्थ को बारह मास की अवधि के भीतर पूरा करने की आपकी योग्यता पर प्रभाव पड़ने की संभावना है (सूची दें)।

सातवीं अनुसूची

[धारा 12(5) देखिए]

मध्यस्थ का पक्षकारों या काउंसेल के साथ संबंध

1. मध्यस्थ किसी पक्षकार का कोई कर्मचारी, परामर्शी, सलाहकार है या उसका किसी पक्षकार के साथ कोई अन्य पूर्ववर्ती या वर्तमान कारोबारी सम्बन्ध है।
2. मध्यस्थ वर्तमान में पक्षकारों में से किसी एक पक्षकार अथवा किसी एक पक्षकार के सहबद्ध का प्रतिनिधित्व करता है या उसे सलाह देता है।
3. वर्तमान में, मध्यस्थ ऐसे वकील या विधि फर्म का प्रतिनिधित्व कर रहा है जो पक्षकारों में से किसी एक पक्षकार के काउंसेल के रूप में कार्य कर रही है।
4. मध्यस्थ उसी विधि फर्म का एक वकील है जो पक्षकारों में से किसी एक पक्षकार का प्रतिनिधित्व कर रही है।
5. मध्यस्थ पक्षकारों में से किसी एक पक्षकार के सहबद्ध में कोई प्रबंधक, निदेशक या प्रबन्धतन्त्र का एक भाग है या उसका उसमें वैसा ही नियंत्रणकारी असर है, जहां कि वह सहबद्ध मध्यस्थता में के विवादग्रस्त विषयों में प्रत्यक्ष रूप से अन्तर्वलित है।
6. मध्यस्थ की विधि फर्म, मध्यस्थ द्वारा अपने को अंतर्वलित किए बिना, मामले में पूर्व में अंतर्वलित थी किंतु ऐसा अंतर्वलन समाप्त हो गया था।
7. मध्यस्थ की विधि फर्म का वर्तमान में पक्षकारों में से किसी के साथ या पक्षकारों में से किसी सहबद्ध के साथ महत्वपूर्ण वाणिज्यिक संबंध है।
8. मध्यस्थ नियुक्ति पक्षकार को या नियुक्ति पक्षकार के सहबद्ध को नियमित रूप से सलाह देता है भले ही न तो मध्यस्थ और न ही उसकी फर्म को उससे कोई महत्वपूर्ण वित्तीय आय व्युत्पन्न हुई है।
9. मध्यस्थ के पक्षकारों में से किसी के साथ और कंपनियों की दशा में कंपनी के प्रबंधन और नियंत्रण में के व्यक्तियों के साथ निकट के कौटुम्बिक संबंध हैं।
10. मध्यस्थ के निकट के कौटुम्बिक सदस्य का पक्षकारों में से किसी में या पक्षकारों के किसी सहबद्ध में महत्वपूर्ण वित्तीय हित है।
11. मध्यस्थ ऐसे किसी अस्तित्व का, जो माध्यस्थ में एक पक्षकार है, विधिक प्रतिनिधि है।
12. मध्यस्थ पक्षकारों में से किसी में कोई प्रबंधक, निदेशक या प्रबंधतंत्र का एक भाग है या उसका उसमें वैसा ही नियंत्रणकारी असर है।

13. मध्यस्थ का पक्षकारों में से किसी में या मामले के निर्णय में महत्वपूर्ण वित्तीय हित है।
14. मध्यस्थ नियुक्ति पक्षकार को या नियुक्ति पक्षकार के सहबद्ध को नियमित रूप से सलाह देता है और मध्यस्थ या उसकी फर्म को उससे महत्वपूर्ण वित्तीय आय व्युत्पन्न होती है।

मध्यस्थ का विवाद से संबंध

15. मध्यस्थ ने विवाद के संबंध में किसी पक्षकार या पक्षकारों में से किसी के सहबद्ध को विधिक सलाह दी है या विशेषज्ञ राय प्रदान की है।
16. मध्यस्थ मामले में पूर्ववर्ती रूप से अंतर्वलित है।

मध्यस्थ का विवाद में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हित होना

17. मध्यस्थ पक्षकारों में से किसी में या पक्षकारों में से किसी एक के सहबद्ध में प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः शेयर धारण करता है अर्थात् प्राइवेट रूप से धारित किए हुए है।
18. मध्यस्थ के निकट के कौटुम्बिक सदस्य का विवाद के निर्णय में महत्वपूर्ण वित्तीय हित है।
19. मध्यस्थ या मध्यस्थ के निकट के कौटुम्बिक सदस्य का ऐसे अन्य पक्षकार के साथ, जो विवाद में के असफल पक्षकार की ओर से सहारा लेने के लिए दायी हो सकता है, निकट के संबंध हैं।

स्पष्टीकरण 1— “निकट का कौटुम्बिक सदस्य” पद पति/पत्नी, सहोदर, बालक, माता/पिता या जीवन साथी के प्रति निर्देश करता है।

स्पष्टीकरण 2— “सहबद्ध” पद के अंतर्गत कंपनियों के एक समूह में सभी कंपनियां, जिनके अंतर्गत मूल कंपनी भी है, आती हैं।

स्पष्टीकरण 3— शंकाओं को दूर करने के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि माध्यस्थम् के कतिपय विनिर्दिष्ट रूपों में, जैसे कि सामुद्रिक या वस्तु संबंधी माध्यस्थम् रूप में, लघु, विशेषज्ञ पूल से मध्यस्थों को लेने के लिए एक पद्धति हो सकती है। यदि इन क्षेत्रों में पक्षकारों के लिए प्रायः उसी मध्यस्थ को भिन्न-भिन्न मामलों में नियुक्त करने की रुढ़ि और पद्धति है, तो उपर्युक्त नियत नियमों को लागू करते समय सुसंगत तथ्य को विचार में लिया जाना होगा।’।

अधिनियम का लंबित माध्यस्थम् कार्यवाहियों को लागू न होना।

26. इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट कोई बात, इस अधिनियम के प्रारंभ से पूर्व मूल अधिनियम की धारा 21 के उपबंधों के अनुसार प्रारंभ की गई माध्यस्थम् कार्यवाहियों को तब तक लागू नहीं होगी, जब तक कि पक्षकार अन्यथा सहमत न हों, किन्तु यह अधिनियम, इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख को या उसके पश्चात् प्रारंभ की गई माध्यस्थम् कार्यवाहियों को लागू होगा।

निरसन और व्यावृत्ति।

27. (1) माध्यस्थम् और सुलह (संशोधन) अध्यादेश, 2015 इसके द्वारा निरसित किया जाता है।
(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के अधीन की गई कोई बात या कोई कार्रवाई इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के तत्संबंधी उपबंधों के अधीन की गई समझी जाएगी।

2015 का अध्यादेश संख्यांक 9

राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम, 2016

(2016 का अधिनियम संख्यांक 17)

[25 मार्च, 2016]

विद्यमान राष्ट्रीय जलमार्गों और कतिपय अंतर्देशीय जलमार्गों को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित करने का उपबंध करने तथा पोत परिवहन और नौ परिवहन के प्रयोजनों के लिए उक्त जलमार्गों के विनियमन और विकास का तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का भी उपबंध करने के लिए
अधिनियम

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम, 2016 है।

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में, अधिसूचना द्वारा, नियत करे।

2. (1) अनुसूची के क्रम संख्यांक 1 से 5 में तथा उसके स्तंभ (3) में दी गई उनकी सीमाओं के साथ विनिर्दिष्ट विद्यमान राष्ट्रीय जलमार्ग, जिन्हें धारा 5 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट अधिनियमों के अधीन उस रूप में घोषित किया गया है, पोत परिवहन और नौ परिवहन के प्रयोजनों के लिए, इस अधिनियम के अधीन राष्ट्रीय जलमार्ग इस अधिनियम के अधीन किए गए उपांतरणों के अधीन रहते हुए बने रहेंगे।

विद्यमान राष्ट्रीय जलमार्ग तथा कतिपय अंतर्देशीय जलमार्गों की राष्ट्रीय जलमार्गों के रूप में घोषणा।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट उन जलमार्गों का विनियमन और विकास, जो केन्द्रीय सरकार के नियंत्रण के अधीन रहा है, उसी रूप में बना रहेगा यदि उक्त जलमार्गों को इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में घोषित कर दिया जाता है।

(3) अनुसूची में क्रम संख्यांक 6 से 111 में विनिर्दिष्ट अंतर्देशीय जलमार्गों के बारे में इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि वे उसके स्तंभ (3) में दी गई उनकी सीमाओं के साथ पोत परिवहन और नौ परिवहन के प्रयोजनों के लिए राष्ट्रीय जलमार्ग होंगे।

संघ द्वारा कतिपय प्रयोजनों के लिए अनुसूची में विनिर्दिष्ट जलमार्गों के नियंत्रण और विकास की समीचीनता के बारे में घोषणा।

3. धारा 2 की उपधारा (1) और उपधारा (2) में जैसा उपबंधित है, उसके सिवाय, यह घोषित किया जाता है कि लोकहित में यह समीचीन है कि संघ, पोत-परिवहन और नौ परिवहन के प्रयोजनों के लिए अनुसूची में विनिर्दिष्ट जलमार्गों के विनियमन और विकास को भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1985 में उपबंधित विस्तार तक अपने नियंत्रण में ले ले।

1985 का 82

1985 के अधिनियम सं० 82 की धारा 2 का संशोधन।

4. भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1985 की धारा 2 के खंड (ज) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:—

‘(ज) “राष्ट्रीय जलमार्ग” से ऐसा अंतर्देशीय जलमार्ग अभिप्रेत है जिसे राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम, 2016 की धारा 2 द्वारा राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया जाए।

स्पष्टीकरण—यदि संसद, विधि द्वारा, किसी अन्य जलमार्ग को राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में घोषित करती है तो उस तारीख से, जिसको ऐसी घोषणा प्रभावी होती है, ऐसा अन्य जलमार्ग भी—

(i) इस खंड के अर्थान्तर्गत राष्ट्रीय जलमार्ग समझा जाएगा; और

(ii) इस अधिनियम के उपबंध, आवश्यक उपांतरणों सहित (जिसके अंतर्गत इस अधिनियम के प्रारंभ के प्रति किसी निर्देश का पूर्वोक्त तारीख के प्रति निर्देश करने के रूप में अर्थान्वयन करने संबंधी उपांतरण भी हैं) ऐसे राष्ट्रीय जलमार्ग को लागू होंगे;’।

कतिपय अधिनियमितियों का निरसन और व्यावृत्ति।

5. (1) निम्नलिखित अधिनियमितियां, अर्थात्:—

(क) राष्ट्रीय जलमार्ग (गंगा-भागीरथी-हुगली नदी इलाहाबाद-हल्दिया खंड) अधिनियम, 1982; 1982 का 49

(ख) राष्ट्रीय जलमार्ग (ब्रह्मपुत्र नदी का सदिया-धुबरी खंड) अधिनियम, 1988; 1988 का 40

(ग) राष्ट्रीय जलमार्ग (पश्चिमी तट नहर तथा चंपकरा और उद्योग मंडल नहरों का कोल्लम-कोट्टपुरम खंड) अधिनियम, 1992; 1992 का 25

(घ) राष्ट्रीय जलमार्ग (नदियों का तलचर-धमरा खंड, पूर्वी तट नहर का गोंखली-चरबतिया खंड, माताई नदी का चरबतिया-धामरा खंड और महानदी डेल्टा नदियां) अधिनियम, 2008; 2008 का 23

(ङ) राष्ट्रीय जलमार्ग (नहरों और कालूवेली जलाशय का काकीनाडा-पुडुचेरी खंड, गोदावरी नदी का भद्राचलम-राजामुंदरी खंड और कृष्णा नदी का वजीराबाद-विजयवाड़ा खंड) अधिनियम, 2008, 2008 का 24

इसके द्वारा निरसित की जाती है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अधिनियमों के अधीन की गई कोई बात या कोई कार्रवाई, जहां तक वह इस अधिनियम के उपबंधों के अनुरूप है, के बारे में यह समझा जाएगा कि वह इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन की गई है या उसके किए जाने का लोप किया गया है या की गई है अथवा नहीं की गई है।

अनुसूची
(धारा 2 देखिए)

क्रम सं०	राष्ट्रीय जलमार्ग	राष्ट्रीय जलमार्गों की सीमाएं
(1)	(2)	(3)
1.	राष्ट्रीय जलमार्ग 1	<p>गंगा-भागीरथी-हुगली नदियों का इलाहाबाद-हल्दिया खंड, निम्नलिखित सीमाओं सहित अर्थात्:—</p> <p>बड़ाटोला नदी के, जिसे सामान्यतः चैनल क्रीक कहा जाता है, प्रवेश पर सं० 1 रिफ्यूज हाउस के बीच अंकित लाइन से हुगली नदी के ज्वारीय जल पर अंतर्देशीय जलमार्ग सीमा तक त्रिवेणी पर गंगा और यमुना नदी के संगम की ऊपरी धारा से लगभग दो किलोमीटर गंगा नदी के आर-पार इलाहाबाद में सड़क पुल से सागर प्रकाश स्तंभ के ठीक दक्षिण में 2.5 किलोमीटर की स्थिति पर और बाद में गंगा नदी के माध्यम से हिजली या बसूलपुर नदी के प्रवेश पर दाएं या दक्षिणी किनारे को जोड़ती है, फरक्का पर लाक नहर और संभरक नहर, भागीरथी नदी और हुगली नदी।</p>
2.	राष्ट्रीय जलमार्ग 2	<p>ब्रह्मपुत्र नदी का सदिया-धुबरी खंड, निम्नलिखित सीमाओं सहित अर्थात्:—</p> <p>सदिया के निकट ब्रह्मपुत्र नदी के साथ उसके संगम पर कुंडिल नदी के उत्तरी किनारे पर बिंदु से ब्रह्मपुत्र नदी के पार तक खींची गई रेखा से नदी द्वीप मजुली के प्रारंभ तक और वहां से नदी द्वीप मजुली के दोनों किनारों पर ब्रह्मपुत्र नदी की सभी वाहिकाओं से होकर नदी द्वीप मजुली के अंत तक और उसके आगे धुबरी सरिता के बहाव की दिशा में अंतर्राष्ट्रीय सीमा तक।</p>
3.	राष्ट्रीय जलमार्ग 3	<p>पश्चिमी तट नहर तथा चंपकरा और उद्योगमंडल नहरों के कोल्लम-कोझिकोड खंड, निम्नलिखित सीमाओं सहित, अर्थात्:—</p> <p>पश्चिमी तट नहर की उत्तरी सीमा, अक्षांश 11°13'39" उत्तरी, रेखांश 75°46'44" पूर्वी कोझिकोड होगी और दक्षिणी सीमा कोल्लम जेटी के दक्षिण में 100 मीटर की दूरी पर अष्टमुडी कायल के आर-पार खींची गई रेखा होगी।</p> <p>चंपकरा नहर पश्चिमी तट नहर के साथ के संगम से प्रारंभ होती है और फर्टिलाइजर्स एंड कैमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड, नौका द्रोणी के निकट रेल पुल (कोचीन आयल रिफाइनरी की रेल साइडिंग) पर समाप्त होती है।</p> <p>उद्योगमंडल नहर पश्चिमी तट नहर के साथ के संगम से प्रारंभ होती है और पडलम सड़क पुल (एलूर-एडयार) पर समाप्त होती है।</p>
4.	राष्ट्रीय जलमार्ग 4	<p>नहरों और कालूवेली जलाशय का काकीनाडा-पुडुचेरी खंड, गोदावरी नदी का नाशिक-भद्राचलम-राजामुंदरी खंड और कृष्णा नदी के ग्राम गालागाली-वजीराबाद-विजयवाड़ा खंड के निकट पुल:—</p> <p>काकीनाडा-पुडुचेरी नहर:</p> <p>(वह नहर प्रणाली जिसमें काकीनाडा नहर, ईलूरू नहर, कोमामूर नहर और उत्तरी बकिंधम नहर समाविष्ट है, उत्तरी और दक्षिणी बकिंधम नहरों को जोड़ने वाली कूवम नदी का भाग, दक्षिणी बकिंधम नहर और कालूवेली जलाशय)</p> <p>उत्तरी सीमा : अक्षांश 16° 56' 24" उत्तर, रेखांश 82° 14' 20" पूर्व पर जगन्नाधपुरम सड़क पुल, काकीनाडा के समानांतर काकीनाडा नहर के आर-पार, अनुप्रवाही 500 मीटर की दूरी पर खींची गई रेखा।</p>

(1)	(2)	(3)
		<p>दक्षिणी सीमा : पूर्वी तट राजमार्ग और कनकचेट्टीकुलम पर चिन्नाकालावरी-कनकचेट्टीकुलम सड़क का संधिस्थान जो अक्षांश 20° 0' 07" उत्तर, रेखांश 79° 52' 12" पूर्व पर कालूवेली जलाशय की कृत्रिम नहर श्रृंखला का अंतिम स्थल।</p> <p>गोदावरी नदी:</p> <p>पश्चिमी सीमा : अक्षांश 20° 0' 07" उत्तर, रेखांश 73° 48' 12" पूर्व पर गोदावरी नदी के आर-पार नाशिक में मुंबई-आगरा राजमार्ग।</p> <p>पूर्वी सीमा : अक्षांश 16° 56' 05" उत्तर, रेखांश 81° 45' 32" पूर्व पर डोलिसवरम, राजामुंदरी में गोदावरी नदी के आर-पार सर आर्थर कॉटन बराज।</p> <p>कृष्णा नदी:</p> <p>पश्चिमी सीमा : अक्षांश 16° 25' 28" उत्तर, रेखांश 75° 26' 19" पूर्व पर गालागाली ग्राम के निकट पुल।</p>
5.	राष्ट्रीय जलमार्ग 5	<p>ब्रह्मणि-खरसुआ-तांतिघई-पंडुआ नाला-दुधई नाला-कानि-धामरा नदी प्रणाली का तलचर-धामरा खंड, पूर्वी तट नहर का गोंखली-चरबतिया खंड, माताई नदी का चरबतिया-धामरा खंड और महानदी डेल्टा नदियां, निम्नलिखित सीमाओं सहित, अर्थात्:—</p> <p>पूर्वी तट नहर और माताई नदी (जिसमें पुरानी हिंजली ज्वारीय नहर, उड़ीसा तट नहर और माताई नदी समाविष्ट हैं)।</p> <p>उत्तरी सीमा : गोंखली पर हुगली नदी और हिजली ज्वारीय नहर का अक्षांश 22° 12' 20" उत्तर, रेखांश 88° 03' 07" पूर्व पर संगम स्थल।</p> <p>दक्षिणी सीमा : धामरा मात्सयिकी पत्तन के निकट माताई नदी और धामरा नदी का अक्षांश 20° 47' 42" उत्तर, रेखांश 86° 53' 03" पूर्व पर संगम स्थल।</p> <p>ब्रह्मणि-खरसुआ-धामरा नदी प्रणाली (जिसमें ब्रह्मणि-खरसुआ-तांताघई-पंडुआ नाला-दुधई नाला-कानि-धामरा नदियां हैं)।</p> <p>उत्तरी-पश्चिमी सीमा : अक्षांश 21° 04' 26" उत्तर, रेखांश 86° 08' 05" पूर्व पर ब्रह्मणि नदी के आर-पार सामल बराज, तलचर।</p> <p>दक्षिणी-पूर्वी सीमा : चांदनीपाल के निकट कालीभंज डियान आरक्षित वन के पूर्वी किनारे पर धामरा नदी के आर-पार अक्षांश 20° 46' 26" उत्तर, रेखांश 86° 57' 15" पूर्व पर खींची गई एक काल्पनिक रेखा।</p> <p>महानदी डेल्टा नदियां (जिसमें हुंसुआ नदी, आथराबांकी संकरी खाड़ी, नूना नाला, गोबरी नाला, खरनासी नदी और महानदी हैं)।</p> <p>(अनुकल्पी मार्ग-हंसुआ नदी बंगाल की खाड़ी में आभासी बिंदु खाड़ी के उत्तरी किनारे से प्रवेश करती है तत्पश्चात् आभासी बिंदु खाड़ी के दक्षिणी सिरे पर खरनासी नदी में प्रवेश करती है, आथराबांकी नदी, महानदी नदी की उत्तरी वितरक नदी समाविष्ट है)।</p> <p>उत्तरी सीमा : अक्षांश 20° 36' 55" उत्तर, रेखांश 86° 45' 05" पूर्व पर रामचंद्रपुर पर ब्रह्मणि नदी के साथ खरसुआ नदी का संगम।</p> <p>दक्षिणी सीमा : पाराद्वीप पत्तन पर प्रवेश जलसरणी के आर-पार उत्तरी तरंग रोध जल संरचना की सतत में, काल्पनिक रेखा अक्षांश 20° 15' 38" उत्तर, रेखांश 86° 40' 55" पूर्व।</p>

(1)	(2)	(3)
6.	राष्ट्रीय जलमार्ग 6	आई नदी : अक्षांश 26° 33' 32" उत्तर, रेखांश 90° 34' 01" पूर्व से आदालगुड़ी संख्या 3 पर पुल से धारा के प्रतिकूल अक्षांश 26° 12' 50" उत्तर, रेखांश 90° 36' 24" पूर्व (जोगीघोपा में नारायणन सेतु पर 4.7 किमी धारा के प्रतिकूल) पर ब्रह्मपुत्र नदी के साथ संगम तक।
7.	राष्ट्रीय जलमार्ग 7	अजोय (अजेय) नदी: कतवा पर अक्षांश 23° 36' 56" उत्तर, रेखांश 87° 31' 58" पूर्व से इलमबाजार पर मोरग्राम-पानागढ़ राज्य राजमार्ग संख्या 14 पर पुल से अक्षांश 23° 39' 23" उत्तर, रेखांश 88° 07' 57" पूर्व पर अजोय नदी के भागीरथी नदी के संगम तक।
8.	राष्ट्रीय जलमार्ग 8	अलप्पुझा-चंगनासेरी नहर: अक्षांश 9° 30' 03" उत्तर, रेखांश 76° 20' 37" पूर्व पर नौका जैटी अलप्पुझा से अक्षांश 9° 26' 42" उत्तर, रेखांश 76° 31' 42" पूर्व चंगनासेरी जैटी तक।
9.	राष्ट्रीय जलमार्ग 9	अलप्पुझा-कोट्टायम-अथीरमपुझा नहर: अक्षांश 9° 30' 03" उत्तर, रेखांश 76° 20' 37" पूर्व पर नौका जैटी अलप्पुझा पर अक्षांश 9° 40' 04" उत्तर, रेखांश 76° 31' 54" पूर्व अथीरमपुझा बाजार तक।
10.	राष्ट्रीय जलमार्ग 10	अंबा नदी: अक्षांश 18° 50' 15" उत्तर, रेखांश 72° 56' 31" पूर्व पर अरब सागर, धरमतार क्रीक नजदीक ग्राम रेवास से अक्षांश 18° 32' 20" उत्तर रेखांश 73° 08' 0" पूर्व पर नागोथाने एसटी स्टैंड के निकट पुल तक।
11.	राष्ट्रीय जलमार्ग 11	अरुणावती अरेन नदी प्रणाली: अक्षांश 20° 13' 33" उत्तर, रेखांश 77° 33' 23" पूर्व पर राज्य राजमार्ग संख्या 211 पर रतनापुर ग्राम के निकट अरुणावती और अरेन नदियों के संगम से अक्षांश 19° 59' 31" उत्तर, रेखांश 78° 09' 38" पूर्व पर अरेन और पेणगंगा नदियों के संगम से छिमाता ग्राम के निकट अक्षांश 19° 54' 08" उत्तर, रेखांश 78° 12' 36" पूर्व तक।
12.	राष्ट्रीय जलमार्ग 12	असी नदी: अक्षांश 25° 17' 19" उत्तर, रेखांश 83° 0' 25" पूर्व से अस्सी घाट, वाराणसी में गंगा नदी के संगम से अक्षांश 25° 16' 37" उत्तर, रेखांश 82° 58' 18" पूर्व पर निकट नवादा, वाराणसी तक।
13.	राष्ट्रीय जलमार्ग 13	एवीएम नहर: अक्षांश 08° 18' 30" उत्तर, रेखांश 77° 04' 45" पूर्व से पूवर नदी तट पर अक्षांश 08° 14' 54" उत्तर, रेखांश 77° 09' 34" पूर्व पर अरियूमथूराई बस स्टाप तक।
14.	राष्ट्रीय जलमार्ग 14	बैतरणी नदी: अक्षांश 20° 51' 45" उत्तर, रेखांश 86° 33' 30" पूर्व पर दत्तापुर ग्राम से अक्षांश 20° 45' 13" उत्तर रेखांश 86° 49' 15" पूर्व पर लक्ष्मी प्रसाद दिया के निकट धर्मा नदी के संगम तक।
15.	राष्ट्रीय जलमार्ग 15	बकरेश्वर मयूराक्षी नदी प्रणाली: अक्षांश 23° 49' 31" उत्तर, रेखांश 87° 24' 59" पूर्व पर बकरेश्वर नदी पर नील निरंजन बांध से अक्षांश 23° 51' 58" उत्तर, रेखांश 88° 02' 21" पूर्व पर तेलग्राम ग्राम के निकट बकरेश्वर और मयूराक्षी नदियों के संगम तक ;

(1)	(2)	(3)
		अक्षांश 23° 58' 22" उत्तर, रेखांश 88° 09' 21" पूर्व पर तेलग्राम ग्राम मयूराक्षी नदी से दक्षिण हिजाल ग्राम के निकट द्वारका नदी के संगम तक ।
16.	राष्ट्रीय जलमार्ग 16	बराक नदी: अक्षांश 24° 47' 18" उत्तर, रेखांश 93° 01' 16" पूर्व पर लखीपुर फेरी घाट से अक्षांश 24° 52' 34" उत्तर, रेखांश 92° 29' 21" पूर्व पर तुकेर ग्राम तक ।
17.	राष्ट्रीय जलमार्ग 17	व्यास नदी: अक्षांश 31° 57' 22" उत्तर, रेखांश 75° 53' 37" पूर्व पर तलवाडा बराज से अक्षांश 31° 09' 09" उत्तर, रेखांश 74° 58' 08" पूर्व पर हरकी के निकट व्यास और सतलुज नदियों के संगम तक ।
18.	राष्ट्रीय जलमार्ग 18	बेकी नदी: अक्षांश 26° 38' 37" उत्तर, रेखांश 90° 59' 02" पूर्व पर इलेनगमरी से अक्षांश 26° 14' 24" उत्तर, रेखांश 90° 47' 21" पूर्व पर ब्रह्मपुत्र संगम तक ।
19.	राष्ट्रीय जलमार्ग 19	बेतवा नदी: अक्षांश 25° 54' 17" उत्तर, रेखांश 79° 45' 06" पूर्व पर रिरवा बुजुर्ग दरिया से अक्षांश 25° 55' 11" उत्तर, रेखांश 80° 13' 08" पूर्व पर मीरपुर दरिया ग्राम के निकट बेतवा और यमुना नदियों के संगम तक ।
20.	राष्ट्रीय जलमार्ग 20	भवानी नदी: अक्षांश 11° 28' 16" उत्तर, रेखांश 77° 06' 49" पूर्व पर भवानी सागर बांध, सत्यामंगलम से अक्षांश 11° 25' 54" उत्तर, रेखांश 77° 41' 02" पूर्व पर सलेम-कोयम्बटूर राजमार्ग पर कावेरी नदी पुल पर भवानी और कावेरी नदियों के संगम तक ।
21.	राष्ट्रीय जलमार्ग 21	भीमा नदी: अक्षांश 17° 09' 05" उत्तर, रेखांश 76° 46' 34" पूर्व पर बराज (हिप्पार्गी ग्राम से लगभग 1 किलोमीटर) से अक्षांश 16° 24' 28" उत्तर, रेखांश 77° 17' 13" पूर्व पर गंदलूर में भीमा और कृष्णा नदियों के संगम तक ।
22.	राष्ट्रीय जलमार्ग 22	विरूपा बड़ी गंगूती ब्रह्मणी नदी प्रणाली: अक्षांश 20° 30' 49" उत्तर, रेखांश 85° 55' 20" पूर्व पर चौदवार पर विरूपा बराज से अक्षांश 20° 37' 36" उत्तर, रेखांश 86° 24' 19" पूर्व पर ऊपरकाई पाडा ग्राम के निकट विरूपा और ब्रह्मणी नदियों के संगम तक, जिसके अंतर्गत अक्षांश 20° 35' 41" उत्तर, रेखांश 86° 06' 32" पूर्व पर समसपुर ग्राम से अक्षांश 20° 38' 28" उत्तर, रेखांश 86° 17' 32" पूर्व पर खडकपुर ग्राम के निकट वैकल्पिक मार्ग भी है । अक्षांश 20° 37' 36" उत्तर, रेखांश 86° 24' 19" पूर्व पर ऊपरकाई पाडा ग्राम के नजदीक विरूपा और ब्रह्मणी नदियों के संगम से अक्षांश 20° 39' 26" उत्तर, रेखांश 86° 44' 53" पूर्व पर कटना में ब्रह्मणी नदी तक ।
23.	राष्ट्रीय जलमार्ग 23	बूढ़ा बलंगा नदी: अक्षांश 21° 38' 13" उत्तर, रेखांश 86° 50' 53" पूर्व पर बराज (पतलीपुरा ग्राम से लगभग 300 मीटर) से अक्षांश 21° 28' 12" उत्तर, रेखांश 87° 04' 12" पूर्व पर चांदीपुर मत्स्य पत्तन पर बंगाल की खाड़ी के साथ बूढ़ा बलंगा नदी के संगम तक ।

(1)	(2)	(3)
24.	राष्ट्रीय जलमार्ग 24	चंबल नदी: अक्षांश 26° 41' 56" उत्तर, रेखांश 78° 56' 09" पूर्व राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-92 पर चंबल सड़क पुल पर अक्षांश 26° 29' 30" उत्तर, रेखांश 79° 15' 01" पूर्व पर चरकपुर ग्राम में चंबल और यमुना नदियों के संगम तक।
25.	राष्ट्रीय जलमार्ग 25	छपोरा नदी: अक्षांश 15° 42' 47" उत्तर, रेखांश 73° 57' 23" पूर्व पर राज्य राजमार्ग संख्या 124 (मनेरी ग्राम से 1 किलोमीटर) पर पुल से अक्षांश 15° 36' 33" उत्तर, रेखांश 73° 44' 01" पूर्व पर मोरजिम में अरब सागर के छपोरा नदी के संगम तक।
26.	राष्ट्रीय जलमार्ग 26	चेनाब नदी: अक्षांश 33° 05' 07" उत्तर, रेखांश 74° 48' 06" पूर्व पर चेनाब सड़क पुल से अक्षांश 32° 48' 12" उत्तर, रेखांश 74° 34' 53" पूर्व पर भरदा कलां के निकट पुल तक।
27.	राष्ट्रीय जलमार्ग 27	कंबरजुआ नदी: अक्षांश 15° 24' 40" उत्तर, रेखांश 73° 54' 48" पूर्व पर कोर्टेलिम फेरी टर्मिनल के निकट कंबरजुआ और जुवारी नदियों के संगम से अक्षांश 15° 31' 26" उत्तर, रेखांश 73° 55' 34" पूर्व पर साओ मार्टियास विधान परिषद् के निकट कंबरजुआ और मानदोबी नदियों के संगम तक।
28.	राष्ट्रीय जलमार्ग 28	दाभोल संकरी खाड़ी वशिष्ठी नदी: अक्षांश 17° 34' 51" उत्तर, रेखांश 73° 09' 18" पूर्व अरब सागर, दाभोल से अक्षांश 17° 32' 39" उत्तर, रेखांश 73° 30' 36" पूर्व पेढे पर पुल तक।
29.	राष्ट्रीय जलमार्ग 29	दामोदर नदी: अक्षांश 23° 12' 40" उत्तर, रेखांश 87° 50' 54" पूर्व पर राज्य राजमार्ग संख्या 8 पर क्रिष्क सेतु, बर्द्धमान से अक्षांश 22° 21' 01" उत्तर, रेखांश 88° 05' 19" पूर्व पर पूर्वा बासुदेवपुर के निकट हुगली नदी के संगम तक।
30.	राष्ट्रीय जलमार्ग 30	देहिंग नदी: अक्षांश 27° 19' 25" उत्तर, रेखांश 95° 18' 45" पूर्व पर मार्बिल माजुली संख्या 1 पर रेल पुल से अक्षांश 27° 15' 10" उत्तर, रेखांश 94° 40' 01" पूर्व पर लक्षण ग्राम के निकट देहिंग और ब्रह्मपुत्र नदी के संगम तक।
31.	राष्ट्रीय जलमार्ग 31	धनश्री/चाथे नदी: अक्षांश 26° 24' 41" उत्तर, रेखांश 93° 53' 47" पूर्व पर मोरोंगी टीई ग्राम के निकट पुल अक्षांश 26° 42' 01" उत्तर, रेखांश 93° 35' 15" पूर्व पर नुमालीगढ़ तक।
32.	राष्ट्रीय जलमार्ग 32	दीखु नदी: अक्षांश 26° 55' 18" उत्तर, रेखांश 94° 44' 27" पूर्व पर राज्य राजमार्ग संख्या 1 पर नजारिया में पुल से अक्षांश 26° 59' 58" उत्तर, रेखांश 94° 27' 42" पूर्व पर दीखु और ब्रह्मपुत्र नदियों के संगम तक।
33.	राष्ट्रीय जलमार्ग 33	दोयांश नदी: अक्षांश 26° 10' 47" उत्तर, रेखांश 93° 59' 10" पूर्व पर सीयालमढ़ी के निकट पुल से अक्षांश 26° 26' 53" उत्तर, रेखांश 93° 57' 12" पूर्व पर दोयांश और सुबानसिरी नदियों के संगम तक।

(1)	(2)	(3)
34.	राष्ट्रीय जलमार्ग 34	डीवीसी नहर: अक्षांश 23° 28' 47" उत्तर, रेखांश 87° 18' 19" पूर्व पर दुर्गापुर बराज से अक्षांश 23° 0' 31" उत्तर, रेखांश 88° 24' 55" पूर्व पर त्रिवेणी के निकट डीवीसी नहर के हुगली नदी के संगम तक।
35.	राष्ट्रीय जलमार्ग 35	द्वारकेश्वर नदी: अक्षांश 23° 06' 55" उत्तर, रेखांश 87° 18' 47" पूर्व पर अवंतिका के निकट पुल से अक्षांश 22° 40' 17" उत्तर, रेखांश 87° 46' 43" पूर्व पर प्रतापपुर में द्वारकेश्वर और सिलाई नदियों के संगम तक।
36.	राष्ट्रीय जलमार्ग 36	द्वारका नदी: अक्षांश 24° 06' 58" उत्तर, रेखांश 87° 47' 51" पूर्व पर तारापीठ में पुल से अक्षांश 23° 43' 53" उत्तर, रेखांश 88° 10' 51" पूर्व पर माओग्राम ग्राम के निकट भागीरथी नदी के संगम तक।
37.	राष्ट्रीय जलमार्ग 37	गंडक नदी: अक्षांश 27° 26' 22" उत्तर, रेखांश 83° 54' 24" पूर्व पर त्रिवेणी घाट के निकट भाईसासलोताल बराज से अक्षांश 25° 39' 18" उत्तर, रेखांश 85° 10' 28" पूर्व पर हाजीपुर में गंडक और गंगा नदियों के संगम तक।
38.	राष्ट्रीय जलमार्ग 38	गंगाधर नदी: अक्षांश 26° 27' 30" उत्तर, रेखांश 89° 51' 25" पूर्व पर राष्ट्रीय राजमार्ग-31सी पर पकरीगुडी पुल से अक्षांश 26° 0' 32" उत्तर, रेखांश 89° 49' 57" पूर्व पर बीनाछारा बिन्दु 3 पर बांग्लादेश सीमा तक।
39.	राष्ट्रीय जलमार्ग 39	गनोल नदी: अक्षांश 25° 31' 47" उत्तर, रेखांश 89° 51' 24" पूर्व पर बांग्लादेश सीमा से अक्षांश 25° 34' 20" उत्तर, रेखांश 90° 03' 46" पूर्व पर डोलबारी के निकट पुल तक।
40.	राष्ट्रीय जलमार्ग 40	घाघरा नदी: अक्षांश 26° 47' 51" उत्तर, रेखांश 82° 06' 46" पूर्व पर फैजाबाद से अक्षांश 25° 44' 13" उत्तर, रेखांश 84° 42' 03" पूर्व पर मांझी घाट में घाघरा और गंगा नदियों के संगम तक।
41.	राष्ट्रीय जलमार्ग 41	घटप्रभा नदी: अक्षांश 16° 20' 01" उत्तर, रेखांश 75° 11' 23" पूर्व पर मलाली के निकट बराज से अक्षांश 16° 20' 13" उत्तर, रेखांश 75° 47' 54" पूर्व पर चिकसनगाम में कृष्णा नदी के संगम तक।
42.	राष्ट्रीय जलमार्ग 42	गोमती नदी: अक्षांश 26° 52' 21" उत्तर, रेखांश 80° 54' 58" पूर्व पर बड़ा इमामबाड़ा, लखनऊ से अक्षांश 25° 30' 31" उत्तर, रेखांश 83° 10' 17" पूर्व पर गोमती नदी के गंगा नदी के संगम तक।
43.	राष्ट्रीय जलमार्ग 43	गुरुपुर नदी: अक्षांश 12° 50' 44" उत्तर, रेखांश 74° 49' 45" पूर्व पर नेतरावती संगम से अक्षांश 12° 55' 35" उत्तर, रेखांश 74° 49' 37" पूर्व पर मंगलोर पत्तन पुल संगम तक।

(1)	(2)	(3)
44.	राष्ट्रीय जलमार्ग 44	इच्छामती नदी: अक्षांश 22° 53' 50" उत्तर, रेखांश 88° 53' 49" पूर्व पर बांग्लादेश सीमा के निकट सीमा मुख्य मार्ग पर पुल से अक्षांश 22° 39' 07" उत्तर, रेखांश 88° 55' 35" पूर्व पर बांसझाड़ी मल्लिकपुर में बांग्लादेश सीमा के निकट तक।
45.	राष्ट्रीय जलमार्ग 45	इंदिरा गांधी नहर: अक्षांश 31° 08' 33" उत्तर, रेखांश 74° 56' 57" पूर्व पर हरकी बराज से अक्षांश 27° 18' 37" उत्तर, रेखांश 71° 09' 10" पूर्व पर मोहनगढ़ के निकट तक।
46.	राष्ट्रीय जलमार्ग 46	इंडस नदी: अक्षांश 33° 49' 43" उत्तर, रेखांश 77° 48' 56" पूर्व पर उपसी ग्राम में राजमार्ग पर पुल से अक्षांश 34° 03' 35" उत्तर, रेखांश 77° 38' 33" पूर्व पर शे ग्राम के निकट शे-चुचोल पर पुल तक।
47.	राष्ट्रीय जलमार्ग 47	जलांगी नदी: अक्षांश 23° 47' 47" उत्तर, रेखांश 88° 27' 09" पूर्व पर पलासीपाड़ा के निकट राज्य राजमार्ग संख्या 14 पर पुल से अक्षांश 23° 24' 39" उत्तर, रेखांश 88° 22' 48" पूर्व पर नवाद्वीप में जलांगी के हुगली/भागीरथी नदियों के संगम तक।
48.	राष्ट्रीय जलमार्ग 48	जवाई-लुनी नदियां और कच्छ-रण: अक्षांश 25° 20' 37" उत्तर, रेखांश 72° 41' 09" पूर्व पर जालौर से जवाई नदी से अक्षांश 23° 32' 54" उत्तर, रेखांश 68° 22' 27" पूर्व पर गांधव कच्छ रण से गांधव ग्राम के निकट लुनी नदी तक।
49.	राष्ट्रीय जलमार्ग 49	झेलम नदी: अक्षांश 33° 49' 26" उत्तर, रेखांश 75° 03' 50" पूर्व पर राजमार्ग पर पुल से अक्षांश 34° 21' 37" उत्तर, रेखांश 74° 36' 36" पूर्व पर वुलर झील, श्रीनगर तक।
50.	राष्ट्रीय जलमार्ग 50	जिंजीराम नदी: अक्षांश 25° 51' 51" उत्तर, रेखांश 89° 58' 57" पूर्व पर ब्रह्मपुत्र नदी के संगम से अक्षांश 25° 44' 15" उत्तर, रेखांश 89° 52' 53" पूर्व पर ब्रह्मपुत्र नदी पर फुलेरचर बिंदु 3 तक।
51.	राष्ट्रीय जलमार्ग 51	कबीनी नदी: अक्षांश 11° 58' 25" उत्तर, रेखांश 76° 21' 10" पूर्व पर कबीनी बांध से अक्षांश 11° 56' 10" उत्तर, रेखांश 76° 14' 18" पूर्व पर बीरामबल्ली तक।
52.	राष्ट्रीय जलमार्ग 52	काली नदी: अक्षांश 14° 55' 08" उत्तर, रेखांश 74° 32' 07" पूर्व पर कोडासल्ली बांध से अक्षांश 14° 50' 31" उत्तर, रेखांश 74° 07' 21" पूर्व पर सदाशिवगाड पुल के निकट काली नदी के अरब सागर के संगम तक।
53.	राष्ट्रीय जलमार्ग 53	कल्याण-ठाणे-मुंबई जलमार्ग, वसई संकरी खाड़ी और उल्हास नदी: अक्षांश 18° 55' 50" उत्तर, रेखांश 72° 53' 22" पूर्व पर उल्हास नदी की और से नवी मुम्बई पर अरब सागर से अक्षांश 19° 02' 38" उत्तर, रेखांश 73° 19' 54" पूर्व पर मालेगांव टी० वरेडी के निकट राज्य राजमार्ग संख्या 76 पर उल्हास नदी पर पुल तक;

(1)	(2)	(3)
		अक्षांश 19° 14' 06" उत्तर, रेखांश 73° 08' 49" पूर्व पर कल्याण में कल्याण रेलवे यार्ड के नजदीक कल्याण-बदलापुर मार्ग पर पुल से अक्षांश 19° 15' 53" रेखांश 73° 09' 28" पूर्व पर कल्याण तक:
		अक्षांश 19° 18' 54" उत्तर, रेखांश 72° 47' 30" पूर्व बसई संकरी खाड़ी से अक्षांश 19° 13' 23" उत्तर, रेखांश 73° 0' 21" पूर्व पर कशेली तक।
54.	राष्ट्रीय जलमार्ग 54	करमनासा नदी: अक्षांश 25° 18' 11" उत्तर, रेखांश 83° 31' 38" पूर्व पर ककरेत में पुल से अक्षांश 25° 31' 06" उत्तर, रेखांश 83° 52' 47" पूर्व पर कुतुबपुर में करमनासा और गंगा नदियों के संगम तक।
55.	राष्ट्रीय जलमार्ग 55	कावेरी कोल्लीदाम नदी: अक्षांश 11° 29' 03" उत्तर, रेखांश 77° 42' 14" पूर्व पर उरातचिकोत्ताई बराज से अक्षांश 11° 21' 38" उत्तर, रेखांश 79° 49' 53" पूर्व पर पजहायार पर कोल्लीदाम नदी के बंगाल की खाड़ी के संगम तक।
56.	राष्ट्रीय जलमार्ग 56	खेरकाई नदी अक्षांश 22° 45' 12" उत्तर, रेखांश 86° 05' 09" पूर्व पर गंगिया ग्राम के नजदीक बांध से अक्षांश 22° 50' 13" उत्तर, रेखांश 86° 09' 37" पूर्व पर जमशेदपुर में सुबर्णरेखा नदी के संगम तक।
57.	राष्ट्रीय जलमार्ग 57	कोपीली नदी: अक्षांश 26° 10' 41" उत्तर, रेखांश 92° 13' 05" पूर्व पर बनथाई गांव तिनाली बस स्टॉप से अक्षांश 26° 15' 07" उत्तर, रेखांश 91° 56' 49" पूर्व पर चन्द्रपुर सं० 2 पर ब्रह्मपुत्र नदी के संगम तक।
58.	राष्ट्रीय जलमार्ग 58	कोसी नदी: अक्षांश 26° 31' 40" उत्तर, रेखांश 86° 55' 29" पूर्व पर हनुमान नगर पर कोसी बराज से अक्षांश 25° 24' 40" उत्तर, रेखांश 87° 15' 14" पूर्व पर कुरसेला पर कोसी के गंगा नदी के संगम तक।
59.	राष्ट्रीय जलमार्ग 59	कोट्यायम-वायकम नहर: अक्षांश 9° 34' 39" उत्तर, रेखांश 76° 31' 08" पूर्व पर काडिमठ के निकट, कोट्यायम से अक्षांश 9° 40' 0" उत्तर, रेखांश 76° 24' 11" पूर्व पर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 को जोड़ने वाले वेच्चूर तक।
60.	राष्ट्रीय जलमार्ग 60	कुमारी नदी: अक्षांश 23° 06' 37" उत्तर, रेखांश 86° 15' 51" पूर्व पर अमरूहासा ग्राम के निकट बांध से अक्षांश 22° 57' 18" उत्तर, रेखांश 86° 44' 43" पूर्व पर चियादा में मुकुटमणिपुर बांध तक।
61.	राष्ट्रीय जलमार्ग 61	कियांसी नदी: अक्षांश 25° 12' 07" उत्तर, रेखांश 91° 15' 21" पूर्व पर मावपील्लम के निकट बंगलादेश सीमा से अक्षांश 25° 19' 35" उत्तर, रेखांश 91° 04' 07" पूर्व पर नोघिल्लम-मवैट सड़क पर पुल तक।
62.	राष्ट्रीय जलमार्ग 62	लोहित नदी: अक्षांश 27° 52' 40" उत्तर, रेखांश 96° 21' 40" पूर्व पर परशुराम कुंड से अक्षांश 27° 47' 49" रेखांश 95° 38' 14" पूर्व शेखोवाघाट, सदिया तक।

(1)	(2)	(3)
63.	राष्ट्रीय जलमार्ग 63	<p>लूनी नदी:</p> <p>अक्षांश 26° 13' 35" उत्तर, रेखांश 73° 41' 20" पूर्व पर जसवन्तपुरा स्थित बांध से अक्षांश 24° 57' 04" पूर्व, रेखांश 71° 38' 02" पूर्व मलिपुरा के निकट बराज तक।</p>
64.	राष्ट्रीय जलमार्ग 64	<p>महानदी नदी:</p> <p>अक्षांश 21° 27' 34" उत्तर, रेखांश 83° 57' 50" पूर्व पर संबल बराज से अक्षांश 20° 19' 38" उत्तर, रेखांश 86° 40' 17" पूर्व पारादीप तक।</p>
65.	राष्ट्रीय जलमार्ग 65	<p>महानंदा नदी:</p> <p>अक्षांश 25° 26' 41" उत्तर, रेखांश 88° 05' 26" पूर्व पर गोसाईपुर के निकट पुल से अक्षांश 24° 57' 17" उत्तर, रेखांश 88° 10' 59" पूर्व पर आदमपुर के निकट बंगलादेश सीमा तक।</p>
66.	राष्ट्रीय जलमार्ग 66	<p>माही नदी:</p> <p>अक्षांश 23° 18' 22" उत्तर, रेखांश 73° 49' 37" पूर्व पर कदाना बांध से अक्षांश 22° 10' 35" उत्तर, रेखांश 72° 30' 36" पूर्व कवि रेल स्टेशन के निकट खंभात की खाड़ी तक।</p>
67.	राष्ट्रीय जलमार्ग 67	<p>मलप्रभा नदी:</p> <p>अक्षांश 15° 49' 51" उत्तर, रेखांश 75° 38' 54" पूर्व पर जकानुरू से अक्षांश 16° 12' 30" उत्तर, रेखांश 76° 04' 16" पूर्व तक कुदालासंगम पर कृष्णा नदी के निकट संगम तक।</p>
68.	राष्ट्रीय जलमार्ग 68	<p>मन्दोवीर नदी:</p> <p>अक्षांश 15° 26' 42" उत्तर, रेखांश 74° 03' 12" पूर्व पर उसगाँव पर पुल से अक्षांश 15° 28' 32" उत्तर, रेखांश 73° 46' 46" पूर्व तक रेईश मेगोस पर अरब सागर के साथ मन्दोवीर नदी के संगम तक।</p>
69.	राष्ट्रीय जलमार्ग 69	<p>मणिमथारू नदी:</p> <p>अक्षांश 08° 39' 14" उत्तर, रेखांश 77° 24' 27" पूर्व पर मणिमथारू बांध से अक्षांश 08° 41' 03" उत्तर, रेखांश 77° 26' 07" पूर्व पर अलादियर के निकट ताम्र प्राणी नदी के संगम तक।</p>
70.	राष्ट्रीय जलमार्ग 70	<p>मंजारा नदी:</p> <p>अक्षांश 17° 44' 58" उत्तर, रेखांश 77° 55' 41" पूर्व पर सिंगूर बाँध से अक्षांश 18° 49' 07" उत्तर, रेखांश 77° 52' 20" पूर्व पर कन्दाकुर्थी पर गोदावरी नदी के संगम तक।</p>
71.	राष्ट्रीय जलमार्ग 71	<p>मपुसा/मोइदे नदी:</p> <p>अक्षांश 15° 35' 21" उत्तर, रेखांश 73° 49' 17" पूर्व पर मपुसा राष्ट्रीय राजमार्ग-17 पर पुल से पोरवोरिण अक्षांश 15° 30' 20" उत्तर, रेखांश 73° 50' 42" पूर्व पर मपुसा और मन्दोवी नदियों के संगम बिन्दु तक।</p>
72.	राष्ट्रीय जलमार्ग 72	<p>नाग नदी:</p> <p>अक्षांश 21° 06' 17" उत्तर, रेखांश 79° 06' 03" पूर्व एन आई टी कालोनी, नागपुर के निकट पुल से अक्षांश 21° 05' 38" उत्तर, रेखांश 79° 27' 54" पूर्व पर स्वांगी ग्राम के निकट कान्हा नदी के संगम तक।</p>
73.	राष्ट्रीय जलमार्ग 73	<p>नर्मदा नदी:</p> <p>अक्षांश 21° 57' 10" उत्तर, रेखांश 74° 08' 27" पूर्व पर पंधाड़िया से अक्षांश 21° 38' 27" उत्तर, रेखांश 72° 33' 28" पूर्व खम्भात की खाड़ी में अरब सागर के साथ नर्मदा के संगम तक।</p>

(1)	(2)	(3)
74.	राष्ट्रीय जलमार्ग 74	<p>नेत्रावती नदी:</p> <p>अक्षांश 12° 57' 55" उत्तर, रेखांश 75° 22' 10" पूर्व पर नेत्रावती बांध, धर्मशाला से अक्षांश 12° 50' 43" उत्तर, रेखांश 74° 49' 29" पूर्व बेंगरी पर अरब सागर के संगम तक।</p>
75.	राष्ट्रीय जलमार्ग 75	<p>पालार नदी:</p> <p>अक्षांश 12° 56' 14" उत्तर, रेखांश 79° 07' 30" पूर्व पर विरदमपट्ट, वेल्लोर में रेल पुल से अक्षांश 12° 27' 52" उत्तर, रेखांश 80° 09' 13" पूर्व सादुरंगापट्टिनम पर बंगाल की खाड़ी के संगम तक।</p>
76.	राष्ट्रीय जलमार्ग 76	<p>पंचगनगवली (पंचगंगोली) नदी:</p> <p>अक्षांश 13° 38' 01" उत्तर, रेखांश 74° 40' 08" पूर्व पर गंगोली पत्तन से अक्षांश 13° 44' 50" उत्तर, रेखांश 74° 39' 15" पूर्व पर बड़केरे में पुल तक।</p>
77.	राष्ट्रीय जलमार्ग 77	<p>पजयार नदी:</p> <p>अक्षांश 08° 13' 49" उत्तर, रेखांश 77° 26' 27" पूर्व पर वीरानारायण मंगलम ग्राम के निकट पुल से अक्षांश 08° 05' 15" उत्तर, रेखांश 77° 29' 08" पूर्व पर मानाकुदी में अरब सागर के संगम तक।</p>
78.	राष्ट्रीय जलमार्ग 78	<p>पेनगंगा वर्धा नदी प्रणाली:</p> <p>अक्षांश 19° 54' 08" उत्तर, रेखांश 78° 12' 36" पूर्व पर चिमाता ग्राम के निकट आरन और पेनगंगा नदियों का संगम से अक्षांश 19° 33' 59" उत्तर, रेखांश 79° 49' 0" पूर्व पर रेवल्ली ग्राम के निकट वर्धा तथा प्रणहिता नदी के संगम तक।</p>
79.	राष्ट्रीय जलमार्ग 79	<p>पेन्नार नदी:</p> <p>अक्षांश 14° 28' 08" उत्तर, रेखांश 79° 59' 09" पूर्व पर पेन्ना बराज, पोथिरेड्डी पलेम से अक्षांश 14° 35' 37" उत्तर, रेखांश 80° 11' 31" पूर्व पर कुदीथिपलेम के निकट बंगाल की खाड़ी के साथ संगम तक।</p>
80.	राष्ट्रीय जलमार्ग 80	<p>पोन्नियार नदी:</p> <p>अक्षांश 12° 11' 0" उत्तर, रेखांश 78° 51' 01" पूर्व पर सथानूर बांध से अक्षांश 11° 46' 22" उत्तर, रेखांश 79° 47' 42" पूर्व पर बंगाल की खाड़ी के संगम पर कुडालोर तक।</p>
81.	राष्ट्रीय जलमार्ग 81	<p>पुनपुन नदी:</p> <p>अक्षांश 25° 29' 50" उत्तर, रेखांश 85° 06' 19" पूर्व पर पारकी ग्राम के निकट राष्ट्रीय राजमार्ग-83 पुल से अक्षांश 25° 30' 50" उत्तर, रेखांश 85° 18' 17" पूर्व पर फतुहा पर गंगा नदी के संगम तक।</p>
82.	राष्ट्रीय जलमार्ग 82	<p>पुथिमरी नदी:</p> <p>अक्षांश 26° 22' 01" उत्तर, रेखांश 91° 39' 11" पूर्व पर ग्राम घोपला के निकट राष्ट्रीय राजमार्ग-31 पर पुल से अक्षांश 26° 15' 28" उत्तर, रेखांश 91° 20' 35" पूर्व पर बामुनबोरी के निकट ब्रह्मपुत्र नदी के साथ संगम तक।</p>
83.	राष्ट्रीय जलमार्ग 83	<p>राजपुरी संकरी खाड़ी:</p> <p>अक्षांश 18° 18' 03" उत्तर, रेखांश 72° 56' 43" पूर्व पर राजपुरी पर अरब सागर से अक्षांश 18° 08' 15" उत्तर, रेखांश 73° 06' 45" पूर्व पर महसला तक।</p>

(1)	(2)	(3)
84.	राष्ट्रीय जलमार्ग 84	रावी नदी: अक्षांश 32° 35' 51" उत्तर, रेखांश 75° 59' 05" पूर्व पर गांधीयार बांध से 32° 26' 36" उत्तर, रेखांश 75° 43' 45" पूर्व पर बसौली में रणजीत सागर बांध तक।
85.	राष्ट्रीय जलमार्ग 85	रेवाडांडा संकरी खाड़ी—कुंडालिका नदी प्रणाली: अक्षांश 18° 32' 20" उत्तर, रेखांश 72° 55' 33" पूर्व पर रेवाडांडा अरब सागर से अक्षांश 18° 26' 32" उत्तर, रेखांश 73° 07' 11" पूर्व पर रोहा नगर के निकट रोहा- अष्टमी रोड पर पुल तक।
86.	राष्ट्रीय जलमार्ग 86	रूप नारायण नदी: अक्षांश 22° 40' 17" उत्तर, रेखांश 87° 46' 43" पूर्व पर प्रतापपुर पर द्वारकेश्वर और सिलाई नदियों का संगम से अक्षांश 22° 12' 42" उत्तर, रेखांश 88° 03' 14" पूर्व पर गिओखाली पर हुगली नदी के संगम तक।
87.	राष्ट्रीय जलमार्ग 87	साबरमती नदी: अक्षांश 23° 26' 50" उत्तर, रेखांश 72° 48' 35" पूर्व पर साडोलिया के निकट बराज से अक्षांश 22° 09' 18" उत्तर रेखांश 72° 27' 28" पूर्व खम्भात के निकट खम्भात की खाड़ी के संगम तक।
88.	राष्ट्रीय जलमार्ग 88	साल नदी: अक्षांश 15° 13' 11" उत्तर, रेखांश 73° 57' 30" पूर्व पर ओरलिम डेंउसा पुल से अक्षांश, 15° 08' 32" उत्तर, रेखांश 73° 57' 0" पूर्व पर मोबार पर अरब सागर के संगम तक।
89.	राष्ट्रीय जलमार्ग 89	सावित्री नदी (बेंकोट संकरी खाड़ी): अक्षांश 18° 05' 54" उत्तर, रेखांश 73° 20' 09" पूर्व पर सापे के निकट पुल से अक्षांश, 17° 58' 47" उत्तर, रेखांश 73° 01' 45" पूर्व पर बेंकोट अरब सागर तक।
90.	राष्ट्रीय जलमार्ग 90	सरावती नदी: अक्षांश 14° 17' 56" उत्तर, रेखांश 74° 25' 27" पूर्व पर हौन्नावर पत्तन समुद्र मोहाना से अक्षांश 14° 14' 15" उत्तर, रेखांश 74° 39' 06" पूर्व पर गैरसोपा में राजमार्ग के संपर्क तक।
91.	राष्ट्रीय जलमार्ग 91	शास्त्री नदी, जयगढ़ संकरी खाड़ी: अक्षांश 17° 11' 16" उत्तर, रेखांश 73° 33' 03" पूर्व पर संगमेश्वर से अक्षांश, 17° 19' 12" उत्तर, रेखांश 73° 12' 39" पूर्व पर जयगढ़ में अरब सागर के संगम तक।
92.	राष्ट्रीय राजमार्ग 92	सिलाबती नदी: अक्षांश 22° 34' 53" उत्तर, रेखांश 87° 38' 31" पूर्व पर शिमुलिया ग्राम के निकट बराज से अक्षांश 22° 40' 17" उत्तर, रेखांश 87° 46' 43" पूर्व पर प्रतापपुर में द्वारकेश्वर और सिलाई नदियों के संगम तक।
93.	राष्ट्रीय जलमार्ग 93	सिमसांग नदी: अक्षांश 25° 11' 05" उत्तर, रेखांश 90° 39' 25" पूर्व पर बंगलादेश सीमा से अक्षांश 25° 27' 20" उत्तर, रेखांश 90° 42' 22" पूर्व पर नोगलबिब्रा के निकट राष्ट्रीय राजमार्ग-62 पर पुल तक।
94.	राष्ट्रीय जलमार्ग 94	सोन नदी: अक्षांश 24° 50' 14" उत्तर, रेखांश 84° 08' 03" पूर्व पर डेहरी के निकट सोन बराज से अक्षांश 25° 42' 15" उत्तर, रेखांश 84° 52' 02" पूर्व पर सोन और गंगा नदियों के संगम तक।
95.	राष्ट्रीय जलमार्ग 95	सुबनसिरी नदी: अक्षांश 27° 27' 03" उत्तर, रेखांश 94° 15' 16" पूर्व पर गेरुकामुख से अक्षांश 26° 52' 25" उत्तर, रेखांश 93° 54' 31" पूर्व पर ब्रह्मपुत्र संगम तक।

(1)	(2)	(3)
96.	राष्ट्रीय जलमार्ग 96	<p>सुबर्णरेखा नदी:</p> <p>अक्षांश 22° 58' 29" उत्तर, रेखांश 86° 01' 14" पूर्व पर चांदिल बांध से अक्षांश 21° 33' 29" उत्तर, रेखांश 87° 22' 59" पूर्व पर बंगाल की खाड़ी के संगम तक।</p>
97.	राष्ट्रीय जलमार्ग 97	<p>सुन्दरबन जलमार्ग:</p> <p>(i) अक्षांश 21° 45' 46" उत्तर, रेखांश 88° 13' 06" पूर्व पर नमखाना से अक्षांश 21° 56' 57" उत्तर, रेखांश 89° 05' 32" पूर्व पर अथारा बांकी खाल तक।</p> <p>(ii) बिंद्या नदी: अक्षांश 21° 54' 43" उत्तर, रेखांश 88° 41' 08" पूर्व पर लाट सं 124 से अक्षांश 22° 11' 48" उत्तर, रेखांश 88° 51' 55" पूर्व पर उत्तर डांगा के निकट तक।</p> <p>(iii) छोटा कालागाची (छोटो कालेगाची) नदी: अक्षांश 22° 19' 57" उत्तर, रेखांश 88° 54' 21" पूर्व पर राजनी पार नौका घाट के निकट से अक्षांश 22° 26' 05" उत्तर, रेखांश 88° 50' 12" पूर्व पर नजात के निकट तक।</p> <p>(iv) गोमर नदी: अक्षांश 22° 11' 53" उत्तर, रेखांश 88° 44' 42" पूर्व पर रामकृष्णपुर के निकट से अक्षांश 22° 10' 05" उत्तर, रेखांश 88° 47' 37" पूर्व पर गोसाबा खेया घाट के निकट तक।</p> <p>(v) हरिभांगा नदी: अक्षांश 21° 53' 19" उत्तर, रेखांश 89° 01' 24" पूर्व पर बंगलादेश सीमा से अक्षांश 21° 58' 18" उत्तर, रेखांश 88° 55' 08" पूर्व पर झिला नदी के संगम तक।</p> <p>(vi) होगला (होगल) — पठानखाली नदी: अक्षांश 22° 12' 22" उत्तर, रेखांश 88° 40' 43" पूर्व पर परंदर के निकट से अक्षांश 22° 21' 12" उत्तर, रेखांश 88° 52' 48" पूर्व पर संदेशखाई नौका घाट के निकट तक।</p> <p>(vii) कालिंदी (कालंदी) नदी: अक्षांश 22° 28' 08" उत्तर, रेखांश 88° 59' 46" पूर्व पर हिंमालगंज पर बंगलादेश सीमा से अक्षांश 22° 24' 41" उत्तर, रेखांश 88° 58' 21" पूर्व पर खोसबास के निकट बंगलादेश सीमा तक।</p> <p>(viii) कटाखाली नदी: अक्षांश 22° 30' 31" उत्तर, रेखांश 88° 58' 25" पूर्व पर बरुणहाट के निकट बंगलादेश सीमा से अक्षांश 22° 21' 45" उत्तर, रेखांश 88° 57' 30" पूर्व पर लेबूखली नौका घाट तक।</p> <p>(ix) माल्टा नदी: अक्षांश 21° 33' 04" उत्तर, रेखांश 88° 38' 26" पूर्व पर बंगाल की खाड़ी से अक्षांश 22° 18' 39" उत्तर, रेखांश 88° 40' 43" पूर्व पर केनिंग नौका घाट तक।</p> <p>(x) मुरी गंगा (बारातला) नदी: अक्षांश 21° 37' 52" उत्तर, रेखांश 88° 10' 0" पूर्व पर बिसालक्ष्मी पुर के निकट बंगाल की खाड़ी से अक्षांश 21° 52' 17" उत्तर, रेखांश 88° 09' 08" पूर्व पर काकद्वीप के निकट तक।</p> <p>(xi) रायमंगल नदी: अक्षांश 22° 11' 41" उत्तर, रेखांश 88° 58' 01" पूर्व पर हेमनगर से अक्षांश 22° 33' 57" उत्तर, रेखांश 88° 56' 17" पूर्व पर राजनगर तक।</p> <p>(xii) साहिबखाली (साहेबखाली) नदी : अक्षांश 22° 17' 52" उत्तर, रेखांश 88° 56' 35" पूर्व पर रामपुर के निकट से अक्षांश 22° 24' 41" उत्तर रेखांश 88° 58' 21" पूर्व पर बंगलादेश सीमा के निकट खोसबास तक।</p> <p>(xiii) सप्तमुखी नदी : अक्षांश 21° 34' 57" उत्तर, रेखांश 88° 19' 08" पूर्व पर बंगाल की खाड़ी में हेनरी द्वीप से अक्षांश 21° 51' 14" उत्तर, रेखांश 88° 18' 41" पूर्व पर चिंतामणिपुर के निकट तक।</p>

(1)	(2)	(3)
		(xiv) ठकुरान नदी : अक्षांश 21°33'32" उत्तर, रेखांश 88°27'45" पूर्व पर बंगाल की खाड़ी से अक्षांश 22°02'52" उत्तर, रेखांश 88°33'28" पूर्व पर माधवपुर तक।
98.	राष्ट्रीय जलमार्ग 98	सतलुज नदी : अक्षांश 31°14'45" उत्तर, रेखांश 77°07'34" पूर्व पर सुन्नी सड़क पुल से अक्षांश 31°08'33" उत्तर, रेखांश 74°56'57" पूर्व पर हरिके बांध तक।
99.	राष्ट्रीय जलमार्ग 99	तामारापारानी नदी : अक्षांश 08°43'43" उत्तर, रेखांश 77°42'54" पूर्व पर सुलोचना मुदालियर पुल, तिरुनेलवेली से, अक्षांश 08°38'25" उत्तर, रेखांश 78°07'38" पूर्व पर पुनईकायल के निकट बंगाल की खाड़ी के संगम तक।
100.	राष्ट्रीय जलमार्ग 100	तापी नदी : अक्षांश 21°04'22" उत्तर, रेखांश 75°56'45" पूर्व पर मंगलवाड़ी के निकट हटनूर बांध से अक्षांश 21°02'16" उत्तर, रेखांश 72°39'30" पूर्व पर खंवात की खाड़ी (अरब सागर) तक।
101.	राष्ट्रीय जलमार्ग 101	तिजु और झुंगकी नदियां : अक्षांश 25°46'12" उत्तर, रेखांश 94°44'35" पूर्व पर लोंगमातरा से अक्षांश 25°35'03" उत्तर, रेखांश 94°53'06" पूर्व पर म्यांमार सीमा पर अवानघखु तक और अक्षांश 25°48'26" उत्तर, रेखांश 94°46'36" पूर्व पर पुल से झुंगकी नदी में अक्षांश 25°46'58" उत्तर, देशांतर रेखांश 94°45'21" पूर्व पर से झुंगकी और तिजु नदियों के संगम तक।
102.	राष्ट्रीय जलमार्ग 102	तलवांग (धालेश्वरी नदी) : अक्षांश 23°55'22" उत्तर, रेखांश 92°39'08" पूर्व पर राष्ट्रीय राजमार्ग-54 के निकट खमरांग से अक्षांश 24°17'19" उत्तर, रेखांश 92°31'0" पूर्व पर राष्ट्रीय राजमार्ग-154 पर पुल तक।
103.	राष्ट्रीय जलमार्ग 103	टोंस नदी : अक्षांश 25°02'05" उत्तर, रेखांश 81°43'45" पूर्व पर चाकघाट के निकट राष्ट्रीय राजमार्ग-27 पर पुल से अक्षांश 25°16'32" उत्तर, रेखांश 82°05'0" पूर्व पर सिरसा में गंगा संगम तक।
104.	राष्ट्रीय जलमार्ग 104	तुंगभद्रा नदी : अक्षांश 15°24'33" उत्तर, रेखांश 76°35'13" पूर्व पर चिक्का जनताकाल ग्राम के निकट राज्य राजमार्ग संख्या 29 पर पुल से अक्षांश 15°57'20" उत्तर, रेखांश 78°14'30" पूर्व पर मुरवा कौंडा ग्राम के निकट कृष्णा नदी के संगम तक।
105.	राष्ट्रीय जलमार्ग 105	उदयवारा नदी : अक्षांश 13°20'57" उत्तर, रेखांश 74°41'28" पूर्व पर मालपे में अरब सागर मुहाना से अक्षांश 13°17'33" उत्तर, रेखांश 74°46'26" पूर्व पर मनिपुरा के निकट पुल तक।
106.	राष्ट्रीय जलमार्ग 106	उमनगोत (डाकी) नदी : अक्षांश 25°11'07" उत्तर, रेखांश 92°0'54" पूर्व पर लारबामोंन के निकट बंगलादेश सीमा से अक्षांश 25°19'05" उत्तर, रेखांश 92°02'20" पूर्व पर नौगरिंगकोह तक।
107.	राष्ट्रीय जलमार्ग 107	वैगई नदी : अक्षांश 10°05'19" उत्तर, रेखांश 77°51'10" पूर्व पर अनाई पट्टी के निकट बराज से अक्षांश 9°53'52" उत्तर, रेखांश 78°10'34" पूर्व पर विरागनूर बांध तक।

(1)	(2)	(3)
108.	राष्ट्रीय जलमार्ग 108	वरुणा नदी : अक्षांश 25°23'15" उत्तर, रेखांश 82°44'07" पूर्व पर कुरु के निकट सड़क पुल से अक्षांश 25°19'45" उत्तर, रेखांश 83°02'41" पूर्व पर गंगा संगम सराय मोहना, वाराणसी तक।
109.	राष्ट्रीय जलमार्ग 109	बाणगंगा - परानाहिता नदी प्रणाली : अक्षांश 20°0'30" उत्तर, रेखांश 79°47'08" पूर्व पर चंदापुर ग्राम के निकट पुल से अक्षांश 18°49'33" उत्तर, रेखांश 79°54'33" पूर्व पर कालेश्वरम में गोदावरी नदी के संगम तक।
110.	राष्ट्रीय जलमार्ग 110	यमुना नदी : अक्षांश 28°45'28" उत्तर, रेखांश 77°13'50" पूर्व पर जगतपुर (वजीराबाद बराज से 6 किलोमीटर धारा प्रतिकूल) दिल्ली से अक्षांश 25°25'24" उत्तर, रेखांश 81°53'20" पूर्व पर संगम इलाहाबाद में गंगा और यमुना के संगम तक।
111.	राष्ट्रीय जलमार्ग 111	जुआरी नदी : अक्षांश 15°16'15" उत्तर, रेखांश 74°07'11" पूर्व पर सनवरदम पुल से अक्षांश 15°25'55" उत्तर, रेखांश 73°48'13" पूर्व पर मरम्गांव तक।

प्रतिभूति हितों का प्रवर्तन और ऋण वसूली विधि तथा प्रकीर्ण उपबंध (संशोधन) अधिनियम, 2016

(2016 का अधिनियम संख्यांक 44)

[12 अगस्त, 2016]

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन
अधिनियम, 2002, बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध ऋण वसूली
अधिनियम, 1993, भारतीय स्टॉप अधिनियम, 1899
और निक्षेपागार अधिनियम, 1996 का और
संशोधन तथा उससे संसक्त और उसके
आनुषंगिक विषयों के लिए
अधिनियम

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

अध्याय 1

प्रारंभिक

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम प्रतिभूति हितों का प्रवर्तन और ऋण वसूली विधि तथा प्रकीर्ण उपबंध (संशोधन) अधिनियम, 2016 है।
(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे:

संक्षिप्त नाम और
प्रारंभ।

परंतु इस अधिनियम के भिन्न-भिन्न उपबंधों के लिए भिन्न-भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी और ऐसे किसी उपबंध में इस अधिनियम के प्रारंभ के प्रति निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह उस उपबंध के प्रवृत्त होने के प्रति निर्देश है।

अध्याय 2

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 का संशोधन

वृहत् नाम का संशोधन।

2. वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) के वृहत् नाम के स्थान पर, निम्नलिखित वृहत् नाम रखा जाएगा, अर्थात्:—

“वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हितों के प्रवर्तन को विनियमित करने तथा संपत्ति अधिकारों पर सृजित प्रतिभूति हित के केन्द्रीय आंकड़ों का उपबंध करने तथा उससे संसक्त और उनके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए अधिनियम”।

कतिपय पदों के प्रतिनिर्देशों के स्थान पर अन्य पदों का रखा जाना।

3. संपूर्ण मूल अधिनियम में,—

(i) “प्रतिभूतिकरण कंपनी”, “पुनर्गठन कंपनी”, “प्रतिभूतिकरण या पुनर्गठन कंपनी”, “प्रतिभूतिकरण कंपनी या पुनर्गठन कंपनी”, या “प्रतिभूतिकरण कंपनी या कोई पुनर्गठन कंपनी” शब्दों के स्थान पर, “आस्ति पुनर्गठन कंपनी” शब्द रखे जाएंगे;

(ii) “प्रतिभूतिकरण कंपनियां या पुनर्गठन कंपनियां” जहां-जहां वे आते हैं, शब्दों के स्थान पर, “आस्ति पुनर्गठन कंपनियां” शब्द रखे जाएंगे;

(iii) “अर्हक संस्थागत क्रेता” शब्दों के स्थान पर जहां-कहीं वे आते हैं, “अर्हक क्रेता” शब्द रखे जाएंगे;

(iv) “अर्हक संस्थागत क्रेताओं” शब्दों के स्थान पर जहां-कहीं वे आते हैं, “अर्हक क्रेताओं” शब्द रखे जाएंगे।

धारा 2 का संशोधन।

4. मूल अधिनियम की धारा 2 की उपधारा (1) में,—

(i) खंड (ख) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“(खक) “आस्ति पुनर्गठन कंपनी” से ऐसी कोई कंपनी अभिप्रेत है, जो आस्ति पुनर्गठन या प्रतिभूतिकरण या दोनों के कारबार को संचालित करने के प्रयोजन के लिए इस अधिनियम की धारा 3 के अधीन रिजर्व बैंक के पास रजिस्ट्रीकृत है;”;

(ii) खंड (च) के अन्त में “के फलस्वरूप उधार लेने वाला हो जाता है” शब्दों के पश्चात् “या जो ऋण प्रतिभूतियां जारी करने के माध्यम से निधि जुटाता है” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(iii) खंड (छ) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“(छक) “कंपनी” से कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 के खंड (20) में यथा परिभाषित कोई कंपनी अभिप्रेत है;”;

(iv) खंड (जक) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:—

“(जक) “ऋण” का वही अर्थ होगा जो बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋण वसूली अधिनियम, 1993 की धारा 2 के खंड (छ) में है और जिसके अंतर्गत निम्नलिखित भी हैं—

(i) किराए या वित्तीय पट्टे या सशर्त विक्रय या किसी अन्य संविदा के अधीन दी गई किसी मूर्त आस्ति की क्रय कीमत का असंदत्त भाग;

2002 का 54

2013 का 18

1993 का 51

(ii) ऐसी किसी अमूर्त आस्ति पर कोई अधिकार, हक या हित या ऐसी अमूर्त आस्ति की अनुज्ञप्ति या समनुदेशन, जो ऐसी अमूर्त आस्ति की क्रय कीमत के किसी असंदत्त भाग के संदाय की बाध्यता या किसी उधार लेने वाले को अमूर्त आस्ति के अर्जन या ऐसी आस्ति की अनुज्ञप्ति अभिप्राप्त करने में समर्थ बनाने के लिए उपगत बाध्यता या अन्यथा विस्तारित प्रत्यय को प्रतिभूत करता है;’;

(v) खंड (झ) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

1992 का 15

‘(झक) “ऋण प्रतिभूतियाँ” से भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 के अधीन बोर्ड द्वारा बनाए गए विनियमों के अनुसार सूचीबद्ध ऋण प्रतिभूतियाँ अभिप्रेत हैं;’;

(vi) खंड (ज) के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

‘(ज) “व्यतिक्रम” से निम्नलिखित अभिप्रेत हैं,—

(i) किसी उधार लेने वाले द्वारा किसी प्रतिभूत लेनदार को संदेय किसी ऋण या किसी अन्य रकम का असंदाय जिसके परिणामस्वरूप प्रतिभूत लेनदार की लेखा बहियों में ऐसे उधार लेने वाले के खाते को गैर-निष्पादनीय आस्ति के रूप में वर्गीकृत किया जाता है; या

(ii) ऋण प्रतिभूतियों के संबंध में किसी उधार लेने वाले व्यक्ति द्वारा, डिबेंचर न्यासी या ऐसे किसी अन्य प्राधिकरण द्वारा जिसके पक्ष में ऐसी ऋण प्रतिभूतियों के धारक के फायदे के लिए प्रतिभूति हित का सृजन किया गया है, उधार लेने वाले व्यक्ति पर देयों के संदाय की मांग करने वाली नब्बे दिनों की सूचना के पश्चात् भी किसी ऋण या किसी अन्य संदेय रकम का असंदाय;’;

(vii) खंड (ट) में, “प्रत्यय सुविधा अभिप्रेत है”, शब्दों के पश्चात् निम्नलिखित शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:—

“जिसके अंतर्गत किसी मूर्त आस्ति को किराए या वित्तीय पट्टे या सशर्त विक्रय पर या किसी अन्य संविदा के अधीन अर्जन या किसी अमूर्त आस्ति के समनुदेशन या अनुज्ञप्ति अभिप्राप्त करने या ऋण प्रतिभूतियों के प्रयोजन के क्रय के लिए उपलब्ध कराई गई निधियाँ भी हैं।”;

(viii) खंड (ठ) में, उपखंड (v) के पश्चात् निम्नलिखित उपखंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:—

“(vक) किराया या वित्तीय पट्टों या सशर्त विक्रय पर या किसी अन्य संविदा के अधीन दी गई किसी मूर्त आस्ति में कोई फायदाप्रद अधिकार, हक या हित जो ऐसी आस्ति की क्रय कीमत के किसी असंदत्त भाग के संदाय की बाध्यता या ऐसी मूर्त आस्ति अर्जित करने के लिए उधार लेने वाले को समर्थ बनाने के लिए उपगत बाध्यता या अन्यथा उपलब्ध प्रत्यय को प्रतिभूत करते हैं; या

(vख) किसी अमूर्त आस्ति में कोई अधिकार, हक या हित या ऐसी अमूर्त आस्ति की अनुज्ञप्ति या समनुदेशन जो ऐसी अमूर्त आस्ति की क्रय-कीमत के किसी असंदत्त भाग के संदाय की बाध्यता या ऐसी अमूर्त आस्ति अर्जित करने अथवा अमूर्त आस्ति की अनुज्ञप्ति अभिप्राप्त करने के लिए उधार लेने वाले को समर्थ बनाने के लिए उपगत किसी बाध्यता या अन्यथा विस्तारित प्रत्यय को प्रतिभूत करते हैं; या”;

(ix) खंड (ड) में उपखंड (iii) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:—

“(iiiक) बोर्ड के पास रजिस्ट्रीकृत और प्रतिभूत ऋण प्रतिभूतियों के लिए नियुक्त कोई डिबेंचर न्यासी;

(iiiख) आस्ति पुनर्गठन कंपनी चाहे वह इस हैसियत से कार्य कर रही है अथवा यथास्थिति, प्रतिभूतिकरण या आस्ति पुनर्गठन के प्रयोजन के लिए सृजित किसी न्यास का प्रबंध कर रही है।”;

(x) खंड (ड) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

‘(डक) “वित्तीय पट्टा” से मूर्त आस्ति के परक्राम्य लिखत या परक्राम्य दस्तावेज से भिन्न किसी पट्टा करार के अधीन आवधिक रूप से सहमत हुई रकम के संदाय के प्रतिफल के रूप में कतिपय समय के लिए पट्टेदार को पट्टाकर्ता के अधिकार के अंतरण के लिए कोई पट्टा अभिप्रेत है और जहां पट्टेदार, यथास्थिति, पट्टे की अवधि की समाप्ति पर या सहमत हुई शेष रकम के संदाय पर ऐसी आस्ति का स्वामी हो जाता है;’;

(xi) खंड (ढ) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

‘(ढक) “परक्राम्य दस्तावेज” से ऐसा कोई दस्तावेज अभिप्रेत है जिसमें मूर्त आस्ति के परिदान का अधिकार सन्निविष्ट होता है और जो तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन परक्राम्यता के लिए अपेक्षाओं की, जिसके अंतर्गत कोई भांडागार रसीद और कोई वहन पत्र भी है, पूर्ति करता है;’;

(xii) खंड (न) के उपखंड (v) में “इसी प्रकृति का कोई अन्य कारबार या वाणिज्यिक अधिकार” शब्दों के पश्चात् “जिसे केन्द्रीय सरकार द्वारा रिजर्व बैंक के परामर्श से विहित किया जाए” शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे;

(xiii) खंड (प) में “रजिस्ट्रीकृत कोई विदेशी संस्थागत विनिधानकर्ता” शब्दों के पश्चात् “गैर-संस्थागत विनिधानकर्ताओं का कोई प्रवर्ग, जिसे धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन रिजर्व बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(xiv) उपधारा (1) में खंड (फ) का लोप किया जाएगा;

(xv) उपधारा (1) में खंड (यक) का लोप किया जाएगा;

(xvi) खंड (यघ) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:—

‘(यघ) “प्रतिभूत लेनदार” से निम्नलिखित अभिप्रेत है,—

(i) कोई बैंक या वित्तीय संस्था या बैंकों या वित्तीय संस्थाओं का कोई संघ या समूह, जो खंड (ठ) में यथाविनिर्दिष्ट किसी मूर्त आस्ति या अमूर्त आस्ति पर कोई अधिकार, हक या हित धारण करता है;

(ii) किसी बैंक या वित्तीय संस्था द्वारा नियुक्त कोई डिबेंचर न्यासी; या

(iii) कोई आस्ति पुनर्गठन कंपनी, चाहे वह इस हैसियत से कार्य कर रही हो या यथास्थिति, प्रतिभूतिकरण या पुनर्गठन के लिए ऐसी आस्ति पुनर्गठन कंपनी द्वारा स्थापित किसी न्यास का प्रबंध कर रही हो; या

(iv) प्रतिभूत ऋण प्रतिभूतियों के लिए किसी कंपनी द्वारा नियुक्त बोर्ड के पास रजिस्ट्रीकृत डिबेंचर न्यासी; या

(v) किसी बैंक या वित्तीय संस्था की ओर से प्रतिभूतियों को धारण करने वाला कोई अन्य न्यासी,

जिसके पक्ष में किसी उधार लेने वाले द्वारा किसी वित्तीय सहायता के सम्यक् प्रतिसंदाय के लिए प्रतिभूति हित का सृजन किया गया है।’;

(xvii) उपधारा (1) में खंड (यच) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:—

‘(यच) “प्रतिभूति हित” से किसी संपत्ति पर किसी प्रतिभूत लेनदार के पक्ष में सृजित धारा 31 में विनिर्दिष्ट से भिन्न किसी भी प्रकार का कोई अधिकार, हक या हित अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत,—

(i) किराए पर दी गई या वित्तीय पट्टा या सशर्त विक्रय या किसी अन्य संविदा के अधीन दी गई संपत्ति के स्वामी के रूप में प्रतिभूत लेनदार द्वारा प्रतिधारित मूर्त आस्ति पर

कोई बंधक, भार, आडमान, समनुदेशन या किसी भी प्रकार का कोई अधिकार, हक या हित जो आस्ति की क्रय कीमत के किसी असंदत भाग के संदाय की बाध्यता या मूर्त आस्ति के अर्जन के लिए उधार लेने वाले को समर्थ बनाने के लिए उपगत किसी बाध्यता या उपलब्ध प्रत्यय को प्रतिभूत करता है; या

(ii) किसी अमूर्त आस्ति में ऐसे अधिकार, हक या हित या ऐसी अमूर्त आस्ति का समनुदेशन या अनुज्ञप्ति जो अमूर्त आस्ति की क्रय कीमत के किसी असंदत भाग के संदाय की बाध्यता या अमूर्त आस्ति के अर्जन या अमूर्त आस्ति की अनुज्ञप्ति के लिए उधार लेने वाले को समर्थ बनाने के लिए उपगत बाध्यता या उपलब्ध किसी प्रत्यय को प्रतिभूत करता है।”।

5. मूल अधिनियम की धारा 3 में,—

धारा 3 का संशोधन।

(i) उपधारा (1) के खंड (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:—

“(ख) दो करोड़ रुपए से अन्यून की स्वयं की निधि या ऐसी अन्य उच्चतर रकम जो रिजर्व बैंक अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे;”

(ii) उपधारा (3) में,—

(क) खंड (च) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:—

“(च) आस्ति पुनर्गठन कंपनी का कोई प्रायोजक ऐसे मानदंडों के अनुसार कोई योग्य या उपयुक्त व्यक्ति है जो रिजर्व बैंक द्वारा ऐसे व्यक्तियों के लिए जारी दिशानिर्देशों में विनिर्दिष्ट किए जाएं;”

(ख) खंड (घ) का लोप किया जाएगा;

(iii) उपधारा (6) में,—

(क) “किसी सारवान् परिवर्तन के लिए” शब्दों के पश्चात् “जिसके अंतर्गत आस्ति पुनर्गठन कंपनी के निदेशक बोर्ड के किसी निदेशक या प्रबंध निदेशक या मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति भी है” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(ख) स्पष्टीकरण में, “शेयरों के अंतरण द्वारा या” शब्दों के पश्चात् “शेयरों के अंतरण के द्वारा कंपनी में प्रायोजन को प्रभावित करने वाला परिवर्तन” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे।

6. मूल अधिनियम की धारा 5 में,—

धारा 5 का संशोधन।

(i) उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

“(1क) उपधारा (1) के अधीन किसी बैंक या वित्तीय संस्था द्वारा ऐसी आस्ति पुनर्गठन कंपनी, जो आस्ति पुनर्गठन या प्रतिभूतिकरण के प्रयोजनों के लिए वित्तीय आस्तियों का अर्जन कर रही है, के पक्ष में निष्पादित किसी दस्तावेज को भारतीय स्टॉप अधिनियम, 1899 की धारा 8च के उपबंधों के अनुसार स्टॉप शुल्क से छूट प्राप्त होगी:

परन्तु इस उपधारा के उपबंध वहां लागू नहीं होंगे जहां आस्ति पुनर्गठन कंपनी द्वारा वित्तीय आस्तियों का अर्जन आस्ति पुनर्गठन या प्रतिभूतिकरण से भिन्न प्रयोजनों के लिए किया गया है।”;

(ii) उपधारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

“(2क) यदि बैंक या वित्तीय संस्था, ऐसी आस्ति की क्रय-कीमत के किसी असंदत भाग के संदाय या उधार लेने वाले व्यक्ति को मूर्त आस्ति या अमूर्त आस्ति के समनुदेशन या अनुज्ञप्ति के अर्जन में समर्थ बनाने के लिए उपगत किसी बाध्यता या अन्यथा उपलब्ध प्रत्यय को प्रतिभूत करने के लिए किसी मूर्त आस्ति या अमूर्त आस्ति पर कोई अधिकार, हक या हित रखती है तो उपधारा (1) के अधीन ऐसी आस्तियों के अर्जन पर ऐसा अधिकार, हक या हित पुनर्गठन कंपनी में निहित होगा।”।

धारा 7 का संशोधन।

7. मूल अधिनियम की धारा 7 में, उपधारा (1) में, “(जनसाधारण को की गई प्रस्थापना से भिन्न)” कोष्ठकों और शब्दों के स्थान पर “या विनिधानकर्ता का ऐसा अन्य कोई प्रवर्ग जिसके अंतर्गत ऐसे गैर-संस्थागत विनिधानकर्ता भी हैं, जो समय-समय पर बोर्ड के परामर्श से रिजर्व बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं” शब्द रखे जाएंगे।

धारा 9 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन।

8. मूल अधिनियम की धारा 9 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

आस्तियों के पुनर्गठन के लिए उपाय।

“9. (1) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी उपबंध के अधीन रहते हुए, कोई आस्ति पुनर्गठन कंपनी, आस्ति पुनर्गठन के प्रयोजन के लिए निम्नलिखित एक या अधिक उपायों का उपबंध कर सकेगी, अर्थात्:—

(क) उधार लेने वाले के कारबार के प्रबंध तंत्र में परिवर्तन या प्रबंध-ग्रहण द्वारा उधार लेने वाले के कारबार का उचित प्रबंध;

(ख) उधार लेने वाले के संपूर्ण कारबार या उसके भाग का विक्रय या पट्टा;

(ग) उधार लेने वाले द्वारा संदेय ऋणों के संदाय का समय परिवर्तन;

(घ) इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार प्रतिभूति हित का प्रवर्तन;

(ङ) उधार लेने वाले द्वारा संदेय शोध्यों का परिनिर्धारण;

(च) इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार प्रतिभूत आस्तियों का कब्जा लेना;

(छ) ऋण के किसी भाग का उधार लेने वाली किसी कंपनी के शेयरों में संपरिवर्तन;

परंतु ऋण के किसी भाग के उधार लेने वाली कंपनी के शेयरों में संपरिवर्तन को सदैव से ऐसे विधिमान्य समझा जाएगा मानो कि इस खंड के उपबंध सभी तात्त्विक समयों पर प्रवृत्त थे।

(2) रिजर्व बैंक, उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए नीति का अवधारण करेगा और आवश्यक निर्देश जारी करेगा जिसके अंतर्गत उधार लेने वाले के कारबार के प्रबंध के विनियमन के लिए निर्देश और प्रभारित की जाने वाली फीस भी है।

(3) आस्ति पुनर्गठन कंपनी उपधारा (2) के अधीन रिजर्व बैंक द्वारा अवधारित नीतियों और निर्देशों के अनुसार उपधारा (1) के अधीन उपाय करेगी।”।

धारा 12 का संशोधन।

9. मूल अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) के खंड (ख) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:—

“(ग) फीस और अन्य प्रभार जो किसी आस्ति पुनर्गठन कंपनी द्वारा अर्जित वित्तीय आस्तियों के प्रबंधन के लिए प्रभारित या उपगत किए जा सकेंगे;

(घ) अर्हक क्रेताओं को जारी प्रतिभूति प्राप्तियों का अंतरण।”।

नई धारा 12ख का अंतःस्थापन।

10. मूल अधिनियम की धारा 12क के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

रिजर्व बैंक की, संपरीक्षा और निरीक्षण करने की शक्ति।

“12ख. (1) रिजर्व बैंक, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, समय-समय पर किसी आस्ति पुनर्गठन कंपनी की संपरीक्षा और निरीक्षण करेगा या कराएगा।

(2) किसी आस्ति पुनर्गठन कंपनी और इसके अधिकारियों का यह कर्तव्य होगा कि वह उपधारा (1) के अधीन रिजर्व बैंक द्वारा किए जाने वाले संपरीक्षा या निरीक्षण में सहायता और सहयोग प्रदान करें।

(3) जहां रिजर्व बैंक का संपरीक्षा या निरीक्षण पर या अन्यथा समाधान हो जाता है कि आस्ति पुनर्गठन कंपनी का कारबार, लोक हित या ऐसी आस्ति पुनर्गठन कंपनी द्वारा जारी प्रतिभूति प्राप्तियों में विनिधानकर्ताओं के हितों के लिए हानिकर रूप में संचालित हो रहा है, वहां रिजर्व बैंक किसी आस्ति पुनर्गठन कंपनी का उचित प्रबंध सुनिश्चित करने के लिए आदेश द्वारा—

(क) आस्ति पुनर्गठन कंपनी के अध्यक्ष या किसी निदेशक को हटा सकेगा या निदेशक बोर्ड में अतिरिक्त निदेशकों की नियुक्ति कर सकेगा; या

(ख) अपने किसी अधिकारी को ऐसी पुनर्गठन कंपनी के निदेशक बोर्ड के कार्यकरण का संप्रेक्षण करने के लिए प्रेक्षक के रूप में नियुक्त कर सकेगा:

परंतु खंड (क) के अधीन अध्यक्ष या निदेशक को हटाने के लिए कोई आदेश उसे सुनवाई का कोई अवसर प्रदान किए बिना नहीं किया जाएगा।

(4) आस्ति पुनर्गठन कंपनी के प्रत्येक निदेशक या अन्य अधिकारी या कर्मचारी का यह कर्तव्य होगा कि वह उपधारा (1) के अधीन किसी संपरीक्षा या निरीक्षण करने वाले किसी व्यक्ति के समक्ष अपनी अभिरक्षा या नियंत्रण में के सभी ऐसी लेखा बहियां, लेखे और अन्य दस्तावेज प्रस्तुत करें और आस्ति पुनर्गठन कंपनी के मामलों से संबंधित ऐसे विवरण तथा जानकारी उपलब्ध कराए जो ऐसे व्यक्ति द्वारा उसके द्वारा विनिर्दिष्ट नियत समय के भीतर अपेक्षित हो।”।

11. मूल अधिनियम की धारा 13 में,—

धारा 13 का संशोधन।

(i) उपधारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“परंतु—

(i) इस उपधारा के अधीन गैर-निष्पादनीय आस्ति के रूप में प्रतिभूत ऋण के वर्गीकरण की अपेक्षा किसी ऐसे उधार लेने वाले को लागू नहीं होगी जिसने ऋण प्रतिभूतियों को जारी करके निधि जुटाई है; और

(ii) व्यतिक्रम की दशा में, डिबेंचर न्यासी, डिबेंचर न्यासी के पक्ष में प्रतिभूति दस्तावेजों के निबंधनों और शर्तों के अनुसार ऐसे उपांतरणों, जो आवश्यक समझे जाएं, के साथ इस धारा के अधीन यथा उपबंधित समान रीति में प्रतिभूति हित के प्रवर्तन का हकदार होगा।”;

(ii) उपधारा (8) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

“(8) जहां प्रतिभूत लेनदार को शोध्य रकम, उसके द्वारा उपगत सभी लागत प्रभारों और व्ययों सहित, प्रतिभूत आस्तियों की लोक नीलामी या जनता से उसके लिए कोटेशन या निविदाएं आमंत्रित करने या पट्टे, समनुदेशन या विक्रय के माध्यम से अंतरण हेतु निजी संधि के लिए सूचना के प्रकाशन की तारीख से पहले किसी भी समय प्रतिभूत लेनदार को दे दी जाती है वहां,—

(i) प्रतिभूत लेनदार द्वारा प्रतिभूत आस्तियों को पट्टे समनुदेशन या विक्रय के माध्यम से अंतरित नहीं किया जाएगा; और

(ii) उस दशा में, जब ऐसी रकम दिए जाने से पहले इस उपधारा के अधीन आस्तियों के पट्टे या समनुदेशन या विक्रय के माध्यम से अंतरण के लिए ऐसे प्रतिभूत लेनदार द्वारा कोई कदम उठा लिया गया है, तो ऐसी प्रतिभूत आस्तियों के पट्टे या समनुदेशन या विक्रय के माध्यम से अंतरण के लिए ऐसे प्रतिभूत लेनदार द्वारा कोई और कदम नहीं उठाया जाएगा।”।

12. मूल अधिनियम की धारा 14 की उपधारा (1) में,—

धारा 14 का संशोधन।

(i) दूसरे परंतुक में “आस्तियों को कब्जे में लेने के प्रयोजन के लिए” शब्दों के पश्चात् “आवेदन की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर” शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे;

(ii) दूसरे परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“परंतु यह भी कि यदि मुख्य मेट्रोपालिटन मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट द्वारा, उसके नियंत्रण से परे किन्हीं कारणों से तीस दिन की अवधि के भीतर कोई आदेश पारित नहीं किया जाता है तो वह उसके लिए कारण लेखबद्ध करने के पश्चात् ऐसी और अवधि के भीतर, जो कुल मिलाकर साठ दिन से अधिक नहीं होगी, आदेश पारित कर सकेगा।”।

धारा 15 का संशोधन।

13. मूल अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (4) में निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“परंतु यदि कोई प्रतिभूत लेनदार संयुक्त रूप से अन्य प्रतिभूत लेनदारों या किसी आस्ति पुनर्गठन कंपनी या वित्तीय संस्था या किसी अन्य समनुदेशिनी के साथ अपने ऋण को किसी उधार देने वाली कंपनी के शेयरों में भागतः परिवर्तित कर देता है और उसके द्वारा उधार लेने वाली कंपनी में नियंत्री हित अर्जित कर लेता है, तो ऐसे प्रतिभूत लेनदार ऐसे उधार लेने वाले के कारबार के प्रबंध को प्रत्यावर्तित करने के दायी नहीं होंगे।”।

धारा 17 का संशोधन।

14. मूल अधिनियम की धारा 17 में,—

(i) “अपील करने का अधिकार” पार्श्व शीर्ष के स्थान पर, “प्रतिभूत ऋणों को वसूल करने के उपायों के विरुद्ध आवेदन” शब्द रखे जाएंगे;

(ii) उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

“(1क) उपधारा (1) के अधीन आवेदन ऐसे ऋण वसूली अधिकरण के समक्ष जिसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमा के भीतर—

(क) वाद हेतुक पूर्णतः या भागतः उत्पन्न होता है; या

(ख) जहां प्रतिभूत आस्ति अवस्थित है;

(ग) बैंक या वित्तीय संस्था की कोई शाखा या कोई अन्य कार्यालय ऐसा कोई खाता बनाए रखते हैं जिसमें दावा किया गया ऋण तत्समय बकाया है,

फाइल किया जाएगा।”;

(iii) उपधारा (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

“(3) यदि ऋण वसूली अधिकरण, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों तथा पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य की परीक्षा करने के पश्चात् इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि प्रतिभूत लेनदार द्वारा धारा 13 की उपधारा (4) में निर्दिष्ट किया गया कोई उपाय इस अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार नहीं है और उधार लेने वाले व्यक्ति या अन्य व्यथित व्यक्ति के लिए प्रतिभूत आस्तियों के प्रबंधन की पुनःस्थापना या प्रतिभूत आस्तियों के कब्जे का प्रत्यावर्तन अपेक्षित है, तो वह आदेश द्वारा,—

(क) प्रतिभूत लेनदार द्वारा धारा 13 की उपधारा (4) में निर्दिष्ट किए गए एक या अधिक उपायों के अवलंब को अविधिमान्य घोषित कर सकेगा; और

(ख) यथास्थिति, ऐसे किसी उधार लेने वाले व्यक्ति या अन्य व्यथित व्यक्ति को, जिसने उपधारा (1) के अधीन आवेदन किया है, प्रतिभूत आस्तियों का कब्जा प्रत्यावर्तित कर देगा या प्रतिभूत आस्तियों के प्रबंध को पुनः स्थापित कर सकेगा; और

(ग) ऐसा अन्य निदेश जारी कर सकेगा, जिसे वह उचित समझता है और जो धारा 13 की उपधारा (4) के अधीन प्रतिभूत लेनदार द्वारा लिए गए किसी अवलंब के संबंध में आवश्यक समझे।”;

(iv) उपधारा (4) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

“(4क) जहां,—

(i) कोई व्यक्ति उपधारा (1) के अधीन किसी आवेदन में किसी प्रतिभूत आस्ति पर किसी अभिधृति या पट्टाधृति अधिकारों का दावा करता है तो ऋण वसूली अधिकरण के पास, मामले के तथ्यों और ऐसे दावों के संबंध में पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य की परीक्षा करने के पश्चात्, प्रतिभूत हित के प्रवर्तन के प्रयोजनों के लिए यह परीक्षा करने की अधिकारिता होगी कि क्या पट्टे या अभिधृति,—

1882 का 4

(क) का अवसान हो गया है या अवधारण हो गया है; या

(ख) संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882 की धारा 65क के प्रतिकूल है; या

(ग) बंधक के निबंधनों के प्रतिकूल है; या

(घ) का सृजन, बैंक द्वारा अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (2) के अधीन व्यतिक्रम और मांग सूचना जारी करने के पश्चात् किया गया है; और

(ii) ऋण वसूली अधिकरण का यह समाधान हो गया है कि प्रतिभूत आस्ति में अभिवृत्ति अधिकार या पट्टा धृति अधिकारों का दावा खंड (i) के उपखंड (क) या उपखंड (ख) या उपखंड (ग) या उपखंड (घ) के अन्तर्गत आता है तो तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी ऋण वसूली अधिकरण ऐसा आदेश पारित कर सकेगा, जिसे वह इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार उचित समझता है।”।

15. मूल अधिनियम की धारा 19 में, “प्रतिभूत लेनदारों को संबंधित उधार लेने वालों को” शब्दों के स्थान पर “प्रतिभूत लेनदारों को या ऐसे अन्य व्यक्तित्व व्यक्ति को, जिसने यथास्थिति, धारा 17 या धारा 17क के अधीन आवेदन फाइल किया है या धारा 18 या धारा 18क के अधीन अपील फाइल की है, संबंधित उधार लेने वालों को या ऐसे अन्य व्यक्ति को” शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे। धारा 19 का संशोधन।

16. मूल अधिनियम की धारा 20 के पश्चात्, निम्नलिखित नई धाराएं अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:— नई धारा 20क और 20ख का अंतःस्थापन।

“20क. (1) केन्द्रीय सरकार, किसी राज्य सरकार या किसी संपत्ति पर अधिकारों के अभिलेखीकरण या ऐसी संपत्ति पर किसी प्रतिभूति हित के सृजन, उपांतरण या समाधान के लिए रजिस्ट्रीकरण प्रणाली संचालित करने वाले अन्य प्राधिकरणों के परामर्श से धारा 20 के अधीन स्थापित केन्द्रीय रजिस्ट्री के अभिलेखों के साथ ऐसी रजिस्ट्रीकरण प्रणालियों के रजिस्ट्रीकरण अभिलेखों का ऐसी रीति में एकीकरण कर सकेगी, जो विहित की जाए। केन्द्रीय रजिस्ट्री में रजिस्ट्रीकरण प्रणाली का एकीकरण।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजन के लिए, रजिस्ट्रीकरण अभिलेख के अंतर्गत कंपनी अधिनियम, 2013, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908, वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958, मोटरयान अधिनियम, 1988, पेटेंट अधिनियम, 1970, डिजाइन अधिनियम, 2000 या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन अन्य ऐसे अभिलेख भी हैं।

2013 का 18
1908 का 16
1958 का 44
1988 का 59
1970 का 39
2000 का 16

(2) केन्द्रीय सरकार केन्द्रीय रजिस्ट्री के साथ उपधारा (1) में निर्दिष्ट विभिन्न रजिस्ट्रीकरण प्रणालियों के अभिलेखों के एकीकरण के पश्चात्, अधिसूचना द्वारा रजिस्ट्रीकरण प्रणालियों के एकीकरण की तारीख और ऐसी तारीख जिसको ऐसे एकीकृत अभिलेख उपलब्ध होंगे, घोषित करेगी, तथा ऐसी तारीख से ऐसी संपत्तियों पर, जो उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी रजिस्ट्रीकरण प्रणाली के अधीन रजिस्ट्रीकृत हैं, प्रतिभूति हितों को इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए केन्द्रीय रजिस्ट्री के पास रजिस्ट्रीकृत समझा जाएगा।

20ख. केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा केन्द्रीय रजिस्ट्री के स्थापन, प्रचालन और विनियमन के संबंध में इस अध्याय के अधीन इसकी शक्तियों और कृत्यों को रिजर्व बैंक को ऐसे निबंधनों और शर्तों के अधीन प्रत्यायोजित कर सकेगी जो विहित की जाए।”। शक्तियों का प्रत्यायोजन।

17. मूल अधिनियम में,—

धारा 23 का संशोधन।

(i) धारा 23 को उसकी उपधारा (1) के रूप में पुनः संख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार पुनः संख्यांकित उपधारा (1) में,—

(क) “यथास्थिति, प्रतिभूतिकरण कंपनी या पुनर्गठन कंपनी या प्रतिभूत लेनदार द्वारा ऐसे प्रतिभूति के संव्यवहार या सृजन की तारीख के पश्चात् तीस दिन के भीतर” शब्दों का लोप किया जाएगा;

(ख) पहले परंतुक का लोप किया जाएगा;

(ग) दूसरे परंतुक में, “परंतु” शब्द के पश्चात् आने वाले “यह और कि” शब्दों का लोप किया जाएगा।

(ii) धारा 23 में, इस प्रकार पुनःसंख्यांकित उपधारा (1) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधाराएं अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:—

“(2) केंद्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा केन्द्रीय रजिस्ट्री के पास विभिन्न प्रकार की संपत्ति पर सृजित, विभिन्न प्रकार के प्रतिभूति हित से संबंधित संव्यवहार के रजिस्ट्रीकरण की अपेक्षा कर सकेगी।

(3) केन्द्रीय सरकार, नियमों द्वारा, इस धारा के अधीन विभिन्न प्रकार के प्रतिभूति हित के रजिस्ट्रीकरण के लिए प्ररूप और ऐसे रजिस्ट्रीकरण पर प्रभारित की जाने वाली फीस विहित कर सकेगी।”।

नए अध्याय 4क का
अंतःस्थापन।

18. मूल अधिनियम की धारा 26क के पश्चात्, निम्नलिखित अध्याय अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“अध्याय 4क

प्रतिभूत लेनदारों और अन्य लेनदारों द्वारा रजिस्ट्रीकरण

प्रतिभूत लेनदारों और
अन्य लेनदारों द्वारा
रजिस्ट्रीकरण।

26ख. (1) केंद्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा उधार लेने वाले ऐसे लेनदार द्वारा अनुदत्त किसी वित्तीय सहायता के सम्यक् प्रतिसंदाय को प्रतिभूत करने के प्रयोजन के लिए उधार लेने वाले की किसी संपत्ति पर किसी प्रतिभूति हित का सृजन, उपांतरण या उसकी तुष्टि के लिए केंद्रीय रजिस्ट्री से संबंधित अध्याय 4 के उपबंधों को धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (घ) में यथा परिभाषित प्रतिभूत लेनदारों से भिन्न सभी लेनदारों तक विस्तारित कर सकेगी।

(2) उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना की तारीख से, कोई लेनदार, जिसके अन्तर्गत प्रतिभूत लेनदार भी है, ऐसे प्ररूप और रीति में, जो विहित की जाए, केंद्रीय रजिस्ट्री को किसी प्रतिभूति हित के सृजन, उपांतरण या तुष्टि करने वाले संव्यवहार की विशिष्टियां फाइल कर सकेगा।

(3) अपने पक्ष में सृजित संपत्तियों पर प्रतिभूति हित का सृजन, उपांतरण और तुष्टि के संव्यवहारों की विशिष्टियां फाइल करने वाला प्रतिभूत लेनदार से भिन्न कोई लेनदार इस अधिनियम के अधीन प्रतिभूतियों के प्रवर्तन संबंधी किसी अधिकार का प्रयोग करने का हकदार नहीं होगा।

(4) केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकरण का ऐसा प्रत्येक प्राधिकारी या अधिकारी, जिसे कर या अन्य सरकारी शोध्यों की वसूली और कर या सरकारी शोध्यों का संदाय करने के लिए दायी किसी व्यक्ति की किसी संपत्ति की कुर्की का कोई आदेश जारी करने का कृत्य सौंपा गया है, केन्द्रीय रजिस्ट्री के पास, ऐसे प्ररूप में और रीति से, जो विहित की जाए, ऐसा कुर्की आदेश, निर्धारित की विशिष्टियों और ऐसी तारीख से, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित की जाए, कर या अन्य सरकारी शोध्यों के व्यौरों के साथ, फाइल करेगा।

(5) यदि कोई व्यक्ति, जिसका किसी उधार लेने वाले के विरुद्ध कोई दावा है, किसी न्यायालय या अन्य प्राधिकारी से, जो कुर्की आदेश जारी करने के लिए सशक्त है, संपत्ति की कुर्की के आदेश अभिप्राप्त कर लेता है तो ऐसा व्यक्ति ऐसे कुर्की आदेश की विशिष्टियां, केंद्रीय रजिस्ट्री के पास ऐसे प्ररूप में और रीति से तथा ऐसी फीस का संदाय करने पर, जो विहित की जाए, फाइल कर सकेगा।

संव्यवहारों के
रजिस्ट्रीकरण का
प्रभाव।

26ग. (1) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, इस अध्याय के उपबंधों के अधीन किसी प्रतिभूत लेनदार या किसी अन्य लेनदार द्वारा प्रतिभूत हित का सृजन, उपांतरण या तुष्टि के संव्यवहारों का कोई भी रजिस्ट्रीकरण या कुर्की आदेशों का फाइल किया जाना, केन्द्रीय रजिस्ट्री के पास, यथास्थिति, ऐसे प्रतिभूत हित के सृजन, उपांतरण या तुष्टि के ऐसे संव्यवहार की विशिष्टियां या कुर्की आदेश फाइल किए जाने की तारीख और समय से सार्वजनिक सूचना दिया जाना समझा जाएगा।

(2) जहां अध्याय 4 और इस अध्याय के उपबंधों के अधीन प्रतिभूत लेनदार या किसी अन्य लेनदार के पक्ष में किसी संपत्ति पर प्रतिभूति हित या कुर्की आदेश रजिस्ट्रीकरण के प्रयोजन के लिए फाइल किया जाता है, वहां कुर्की आदेश धारण करने वाले ऐसे प्रतिभूत लेनदार या अन्य लेनदार के दावे को ऐसी संपत्ति पर सृजित किसी पश्चात्तर्ती प्रतिभूति हित पर पूर्विकता प्राप्त होगी और ऐसे रजिस्ट्रीकरण के पश्चात् ऐसी संपत्ति का किसी विक्रय, पट्टा, समनुदेशन या अनुज्ञप्ति के द्वारा अंतरण अथवा कुर्की आदेश ऐसे दावे के अध्यक्षीन होगा:

परंतु इस उपधारा में अंतर्विष्ट कोई बात उधार लेने वाले द्वारा कारबार के सामान्य अनुक्रम में किए गए संव्यवहारों को लागू नहीं होगी।

26घ. तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इस अध्याय के उपबंधों के प्रारंभ की तारीख से ही, कोई भी प्रतिभूत लेनदार अध्याय 3 के अधीन प्रतिभूतियों के प्रवर्तन के अधिकारों का तब तक प्रयोग करने का हकदार नहीं होगा जब तक उधार लेने वाले द्वारा उसके पक्ष में सृजित प्रतिभूति हित केंद्रीय रजिस्ट्री के साथ रजिस्ट्रीकृत न कर दिया गया हो।

प्रतिभूतियों के प्रवर्तन का अधिकार।

26ङ. तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, प्रतिभूति हित के रजिस्ट्रीकरण के पश्चात् किसी प्रतिभूत लेनदार को, देय ऋणों का संदाय केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी को संदेय सभी अन्य ऋणों और सभी राजस्वों, करों, उपकरों और अन्य रेंटों पर पूर्विकता देकर किया जाएगा।

प्रतिभूत लेनदारों को पूर्विकता।

2016 का 31

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के प्रारंभ पर या उसके पश्चात्, ऐसे मामलों में जहां उधार लेने वाले व्यक्ति की प्रतिभूत आस्तियों के संबंध में दिवाला या शोधन अक्षमता कार्यवाहियां लंबित हैं, वहां ऋण के संदाय में प्रतिभूत लेनदारों को दी जाने वाली पूर्विकता उस संहिता के उपबंधों के अध्यक्षीन होगी।”।

19. धारा 27 में निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

धारा 27 का संशोधन।

“परन्तु इस धारा के उपबंध, प्रतिभूति हित का प्रवर्तन और ऋण वसूली विधि तथा प्रकीर्ण उपबंध (संशोधन) अधिनियम, 2016 द्वारा यथा संशोधित इस अध्याय और धारा 23 के उपबंधों के प्रवर्तन में आने की तारीख से लोप हुए समझे जाएंगे।”।

20. मूल अधिनियम की धारा 28 का लोप किया जाएगा।

धारा 28 का लोप।

21. मूल अधिनियम की धारा 30 के पश्चात्, निम्नलिखित धाराएं अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:—

नई धारा 30क, धारा 30ख, धारा 30ग और धारा 30घ का अंतःस्थापन।

‘30क. (1) जहां कोई आस्ति पुनर्गठन कंपनी या कोई व्यक्ति, इस अधिनियम के अधीन रिजर्व बैंक द्वारा जारी किसी निदेश का अनुपालन करने में असफल रहता है, तो न्यायनिर्णायक प्राधिकारी, आदेश द्वारा, ऐसी व्यतिक्रमी कंपनी या व्यक्ति पर, एक करोड़ रुपए से अनधिक रकम या ऐसी चूक में अंतर्वर्तित रकम, जहां ऐसी रकम परिमेय है, की दुगुनी रकम, इनमें से जो भी अधिक हो, और जहां ऐसी चूक जारी रहती है, वहां ऐसी अतिरिक्त शास्ति, जो प्रथम दिन के पश्चात् ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान ऐसी चूक जारी रहती है, एक लाख रुपए तक की हो सकेगी, अधिरोपित कर सकेगा।

न्यायनिर्णायक प्राधिकारी की शास्ति अधिरोपित करने की शक्ति।

(2) उपधारा (1) के अधीन शास्ति अधिरोपित करने के प्रयोजन के लिए, न्यायनिर्णायक प्राधिकारी व्यतिक्रमी आस्ति पुनर्गठन कंपनी या व्यक्ति पर सूचना की तामील करेगा, जिसमें ऐसी कंपनी या व्यक्ति से इस बात का कारण बताने की अपेक्षा की जाएगी कि सूचना में विनिर्दिष्ट रकम को शास्ति के रूप में अधिरोपित क्यों नहीं किया जाना चाहिए और ऐसे व्यक्ति को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किया जाएगा।

(3) इस धारा के अधीन अधिरोपित कोई शास्ति, उपधारा (2) के अधीन जारी सूचना की तारीख से तीस दिन के भीतर संदेय होगी।

(4) जहां आस्ति पुनर्गठन कंपनी उपधारा (3) के अधीन विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर शास्ति का संदाय करने में असफल रहती है, वहां न्यायनिर्णायक प्राधिकारी, आदेश द्वारा उसके रजिस्ट्रीकरण को रद्द कर सकेगा:

परन्तु रजिस्ट्रीकरण को रद्द किए जाने से पूर्व ऐसी आस्ति पुनर्गठन कंपनी को सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाएगा।

(5) किसी व्यतिक्रमी व्यक्ति के विरुद्ध किसी न्यायालय में उपधारा (1) के अधीन किसी ऐसी चूक से संबंधित कोई परिवाद फाइल नहीं किया जाएगा, जिसके संबंध में कोई शास्ति इस धारा के अधीन रिजर्व बैंक द्वारा अधिरोपित और वसूल की गई है।

(6) जहां अधिकारिता रखने वाले किसी न्यायालय में व्यतिक्रमी व्यक्ति के विरुद्ध किसी असफलता के संबंध में कोई परिवाद फाइल किया गया है, वहां उस व्यक्ति के विरुद्ध इस धारा के अधीन शास्ति अधिरोपित किए जाने की कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी।

स्पष्टीकरण—इस धारा और धारा 30ख, धारा 30ग तथा धारा 30घ के प्रयोजनों के लिए,—

(i) “न्यायनिर्णायक प्राधिकारी” से रिजर्व बैंक का ऐसा अधिकारी या अधिकारियों की कोई समिति अभिप्रेत है, जो रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड द्वारा समय-समय पर अधिसूचना द्वारा उस हैसियत से अभिहित की जाए;

(ii) “व्यतिक्रमी व्यक्ति” से ऐसी आस्ति पुनर्गठन कंपनी या कोई व्यक्ति, जिसने इस अधिनियम के अधीन कोई भी चूक, उल्लंघन या व्यतिक्रम किया है और ऐसी कंपनी का, यथास्थिति, कोई भारसाधक व्यक्ति या ऐसा अन्य व्यक्ति, ऐसी कंपनी या व्यक्ति द्वारा की गई किसी चूक या उल्लंघन या व्यतिक्रम के लिए धारा 33 के अधीन कार्यवाही किए जाने के दायित्वाधीन और दंडनीय होगा।

शास्तियों के विरुद्ध
अपील।

30ख. धारा 30क की उपधारा (4) के अधीन पारित आदेश से व्यथित व्यतिक्रमी व्यक्ति, उस तारीख से, जिसको वह आदेश पारित किया जाता है, तीस दिन की अवधि के भीतर अपील प्राधिकारी को अपील कर सकेगा:

परन्तु अपील प्राधिकारी तीस दिन की उक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् अपील ग्रहण कर सकेगा, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि उस अवधि के भीतर उसे फाइल न करने का पर्याप्त हेतुक था।

अपील प्राधिकारी।

30ग. (1) रिजर्व बैंक का केन्द्रीय बोर्ड, ऐसे अधिकारी या अधिकारियों की समिति को अभिहित कर सकेगा जो अपील प्राधिकारी की शक्ति का प्रयोग करने के लिए ठीक समझे।

(2) अपील प्राधिकारी को, व्यतिक्रमी व्यक्ति को सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् ऐसा आदेश पारित करने की शक्ति होगी, जो वह ठीक समझे।

(3) अपील प्राधिकारी, आदेश द्वारा, ऐसे निबंधनों और शर्तों के अधीन रहते हुए, जो वह ठीक समझे, धारा 30क के अधीन न्यायनिर्णायक प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश के प्रवर्तन को रोक सकेगा।

(4) जहां व्यतिक्रमी व्यक्ति, किसी युक्तियुक्त कारण के बिना उपधारा (3) के अधीन पारित आदेश द्वारा अधिरोपित निबंधनों और शर्तों का अनुपालन करने में असफल रहता है वहां अपील प्राधिकारी अपील को खारिज कर सकेगा।

शास्तियों की वसूली।

30घ. (1) धारा 30क के अधीन अधिरोपित कोई शास्ति “वसूलीय राशि” के रूप में वसूल की जाएगी और वह उस तारीख से, जिसको व्यतिक्रमी व्यक्ति पर वसूलीय राशि के संदाय की मांग करने संबंधी सूचना की तारीख की जाती है, तीस दिन की अवधि के भीतर संदेय होगी और ऐसी अवधि के भीतर उस व्यक्ति द्वारा उसका संदाय करने में असफल रहने की दशा में रिजर्व बैंक, वसूली के प्रयोजन के लिए,—

(क) व्यतिक्रमी व्यक्ति द्वारा रिजर्व बैंक के पास चालू खाते में से, यदि कोई हो, विकलन करके या ऐसे व्यक्ति द्वारा रिजर्व बैंक की पुस्तकों में जमा रखी गई प्रतिभूतियों के, यदि कोई हों, परिसमापन द्वारा कर सकेगा;

(ख) ऐसे व्यक्ति को, जिससे कोई रकम व्यतिक्रमी व्यक्ति को शोध्य है, उस व्यक्ति से उसके द्वारा जो रकम व्यतिक्रमी व्यक्ति को संदेय है, में से ऐसी राशि की, जो वसूलीय राशि की

रकम के बराबर है, कटौती करके और उसका रिजर्व बैंक को संदाय करने की अपेक्षा करते हुए, सूचना जारी कर सकेगा।

(2) उपधारा (4) में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन जारी सूचना ऐसे प्रत्येक व्यक्ति पर, आबद्धकर होगी, जिसे यह जारी की जाती है और जहां ऐसी सूचना किसी डाकघर, बैंक या किसी बीमा कंपनी को जारी की जाती है, वहां किसी प्रतिकूल नियम, पद्धति या अपेक्षा के होते हुए भी, संदाय किए जाने के पूर्व उसकी किसी प्रविष्टि या पृष्ठांकन के प्रयोजन के लिए कोई पास बुक, जमा रसीद, पालिसी या किसी अन्य दस्तावेज का प्रस्तुत किया जाना आवश्यक नहीं होगा।

(3) ऐसी किसी रकम के संबंध में ऐसा कोई दावा, जो उपधारा (1) के अधीन सूचना जारी होने की तारीख के पश्चात् उद्भूत हुआ है, सूचना में अंतर्विष्ट मांग के विरुद्ध शून्य होगा।

(4) कोई व्यक्ति, जिसे उपधारा (1) के अधीन सूचना भेजी जाती है, शपथ पर यह कथन करते हुए ऐसी सूचना के प्रति यह आक्षेप करता है कि मांगी गई राशि या उसका कोई भाग व्यतिक्रमी व्यक्ति के प्रति शोध्य नहीं है या वह व्यतिक्रमी व्यक्ति की ओर से या उसके मद्दे कोई धनराशि धारित नहीं करता है, तो इस धारा में अंतर्विष्ट कोई बात ऐसे व्यक्ति से, यथास्थिति, ऐसी रकम या उसके भाग का संदाय करने की उससे अपेक्षा करने वाली नहीं समझी जाएगी।

(5) जहां यह पता चलता है कि उपधारा (4) के अधीन व्यक्ति द्वारा किया गया कथन किसी तात्त्विक विशिष्टि में मिथ्या है वहां ऐसा व्यक्ति, सूचना की तारीख को व्यतिक्रमी व्यक्ति के प्रति अपने स्वयं के दायित्व की सीमा तक या रिजर्व बैंक को व्यतिक्रमी व्यक्ति द्वारा संदेय वसूलीय राशि की सीमा तक, इनमें से जो भी कम हो, रिजर्व बैंक के प्रति व्यक्तिगत रूप से दायी होगा।

(6) रिजर्व बैंक, किसी भी समय उपधारा (1) के अधीन जारी किसी सूचना का संशोधन कर सकेगा या उसे वापस ले सकेगा या ऐसी सूचना के अनुसरण में संदाय करने के समय को बढ़ा सकेगा।

(7) रिजर्व बैंक, इस धारा के अधीन जारी सूचना के अनुपालन में उसे संदत्त किसी रकम की रसीद देगा और इस प्रकार संदाय करने वाला व्यक्ति, इस प्रकार संदत्त रकम की सीमा तक व्यतिक्रमी व्यक्ति के प्रति अपने दायित्व से पूर्णतया उन्मोचित हो जाएगा।

(8) व्यतिक्रमी व्यक्ति के प्रति किसी दायित्व का निर्वहन करने वाला कोई व्यक्ति इस खंड के अधीन कोई सूचना प्राप्त होने के पश्चात्,—

(क) व्यतिक्रमी व्यक्ति के प्रति इस प्रकार निर्वहन किए गए अपने स्वयं के दायित्व की सीमा तक; या

(ख) व्यतिक्रमी व्यक्ति द्वारा रिजर्व बैंक को संदेय वसूलीय राशि की सीमा तक,

इनमें से जो भी कम हो, रिजर्व बैंक के प्रति व्यक्तिगत रूप से दायी होगा।

(9) जहां ऐसा व्यक्ति, जिसे इस धारा के अधीन सूचना भेजी गई है, रिजर्व बैंक को उसके अनुसरण में संदाय करने में असफल रहता है तो उसे सूचना में विनिर्दिष्ट रकम के संबंध में व्यतिक्रमी व्यक्ति समझा जाएगा और रकम की वसूली के लिए उसके विरुद्ध इस धारा में उपबंधित रीति में कार्रवाई या कार्यवाहियां की जा सकेंगी या संस्थित की जा सकेंगी।

(10) रिजर्व बैंक, उस क्षेत्र पर जहां व्यतिक्रमी व्यक्ति का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय, प्रधान कार्यालय या कारबार का मुख्य स्थान या ऐसे व्यक्ति का सामान्य निवास स्थान स्थित है, अधिकारिता रखने वाले प्रधान सिविल न्यायालय के माध्यम से वसूलीय राशि की वसूली इस प्रकार प्रवर्तित कर सकेगा, मानो रिजर्व बैंक द्वारा जारी सूचना न्यायालय की कोई डिक्री हो।

(11) इस निमित्त रिजर्व बैंक के किसी प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रधान सिविल न्यायालय को यह प्रमाणित करते हुए कि व्यतिक्रमी व्यक्ति वसूलीय राशि का संदाय करने में असफल रहा है, किए गए आवेदन के सिवाय, उपधारा 10 के अधीन वसूली प्रवर्तित नहीं की जाएगी।'

धारा 31 का
संशोधन।

22. मूल अधिनियम की धारा 31 के खंड (ड) का लोप किया जाएगा।

धारा 31क का
संशोधन।

23. मूल अधिनियम की धारा 31क की उपधारा (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधाराएं रखी जाएंगी, अर्थात्:—

“(2) उपधारा (1) के अधीन जारी किए जाने के लिए प्रस्तावित प्रत्येक अधिसूचना की एक प्रति, प्रारूप रूप में, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखी जाएगी और यदि दोनों सदन उस अधिसूचना के जारी किए जाने का अनुमोदन करने के लिए सहमत हो जाएं या दोनों सदन अधिसूचना में उपांतरण करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह अधिसूचना, यथास्थिति, जारी नहीं की जाएगी या ऐसे उपांतरित रूप में जारी की जाएगी जिन पर दोनों सदन सहमत हों।

(3) उपधारा (2) में यथानिर्दिष्ट तीस दिन की ऐसी अवधि की संगणना करने में किसी ऐसी अवधि को हिसाब में नहीं लिया जाएगा जिसके दौरान उपधारा (2) में निर्दिष्ट सदन लगातार चार दिन से अधिक के लिए सत्रावसित या स्थगित रहता है।

(4) इस धारा के अधीन जारी प्रत्येक अधिसूचना की प्रतियां, उसके जारी किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जाएंगी।”।

धारा 32 का संशोधन।

24. मूल अधिनियम की धारा 32 में, “किसी प्रतिभूत लेनदार या प्रतिभूत लेनदार के किन्हीं अधिकारों का प्रयोग करने वाले उसके किसी अधिकारी या प्रबंधक या उधार लेने वाले” शब्दों के स्थान पर, “रिजर्व बैंक या केन्द्रीय रजिस्ट्री या प्रतिभूत लेनदार या उसके किन्हीं अधिकारियों” शब्द रखे जाएंगे।

धारा 38 का
संशोधन।

25. मूल अधिनियम की धारा 38 की उपधारा (2) में,—

(i) खंड (क) को खंड (कक) के रूप में संख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार पुनःसंख्यांकित (कक) से पूर्व निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“(क) धारा 2 के खंड (न) के अधीन समान प्रकृति के अन्य कारबार या वाणिज्यिक अधिकार;”;

(ii) खंड (खग) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:—

“(खगक) धारा 20क की उपधारा (1) के अधीन केन्द्रीय रजिस्ट्री के अभिलेखों में विभिन्न रजिस्ट्रीकरण प्रणालियों के अभिलेखों को समाकलित करने की रीति;

(खगख) धारा 20ख के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा रिजर्व बैंक को शक्तियां प्रत्यायोजित करने के निबंधन और शर्तें;”;

(iii) खंड (घ) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“(घक) धारा 23 की उपधारा (3) के अधीन विभिन्न प्रकार के प्रतिभूति हितों के रजिस्ट्रीकरण का प्ररूप और उसकी फीस;”;

(iv) खंड (च) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:—

“(चक) धारा 26ख की उपधारा (2) के अधीन संव्यवहारों की विशिष्टियां फाइल करने का प्ररूप और रीति;

(चख) धारा 26ख की उपधारा (4) के अधीन केन्द्रीय रजिस्ट्री के पास कुर्की आदेश फाइल करने का प्ररूप और रीति तथा तारीख;

(चग) धारा 26ख की उपधारा (5) के अधीन केन्द्रीय रजिस्ट्री के पास कुर्की आदेश की विशिष्टियां फाइल करने का प्ररूप और रीति तथा फीस;”।

अध्याय 3

बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋण वसूली अधिनियम, 1993

1993 का 51

26. बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋण वसूली अधिनियम, 1993 की (जिसे इस अध्याय में इसके धारा 2 का संशोधन। पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 में,—

(i) खंड (छ) में “वैद्य रूप से वसूल किए जाने योग्य हो” आने वाले शब्दों के पश्चात् निम्नलिखित शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:—

“और इसके अंतर्गत ऐसे प्रतिभूति ऋणों के प्रति कोई दायित्व भी है, जिसका, डिबेंचर न्यासी या ऐसे किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा, जिसके पक्ष में प्रतिभूति ऋण धारकों के फायदे के लिए प्रतिभूति हित का सृजन हुआ है, उधार लेने वाले पर नब्बे दिन की सूचना की तामील के पश्चात् भी पूर्ण रूप से या भागतः संदाय नहीं किया गया है; या”;

(ii) खंड (छ) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

1992 का 15

‘(छक) “ऋण प्रतिभूतियों” से भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 3 के अधीन भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड द्वारा बनाए गए विनियमों के अनुसार सूचीबद्ध ऋण प्रतिभूतियां अभिप्रेत हैं;’;

(iii) खंड (ज) के उपखंड (i) के पश्चात्, निम्नलिखित उपखंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“(iख) बोर्ड के पास रजिस्ट्रीकृत और प्रतिभूत ऋण प्रतिभूतियों के लिए नियुक्त कोई डिबेंचर न्यासी।”;

(iv) खंड (ज) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

‘(जक) “वित्तीय पट्टे” से आवधिक रूप से करार पाई गई रकम के संदाय के प्रतिफलस्वरूप कतिपय समय के लिए पट्टेदार को उसमें पट्टेकर्ता के अधिकार के अंतरण के लिए, परक्राम्य लिखत या परक्राम्य दस्तावेज से भिन्न मूर्त आस्ति के पट्टा करार के अधीन और जहां, यथास्थिति, पट्टेदार पट्टे की अवधि की समाप्ति पर या करार पाई गई शेष रकम के संदाय पर ऐसी आस्तियों का स्वामी हो जाता है, पट्टा अभिप्रेत हैं;’;

(v) खंड (जक) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

‘(जख) “संपत्ति” से निम्नलिखित अभिप्रेत हैं,—

(क) स्थावर संपत्ति;

(ख) जंगम संपत्ति;

(ग) कोई ऋण या धन का, चाहे प्रतिभूत हो या अप्रतिभूत, संदाय प्राप्त करने का कोई अधिकार;

(घ) प्राप्त किए जाने योग्य शोध्य, चाहे विद्यमान हो, या भावी;

(ङ) अमूर्त आस्तियां, व्यवहार ज्ञान, पेटेंट, प्रतिलिप्यधिकार, व्यापार चिह्न, लाइसेंस, मताधिकार या इसी प्रकृति का ऐसा कोई अन्य कारबार या वाणिज्यिक अधिकार, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा रिजर्व बैंक के परामर्श से विहित किया जाए;’;

(iv) खंड (ठ) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:—

‘(ठक) “प्रतिभूत लेनदार” का वही अर्थ होगा, जो उसका वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (यघ) में है;

2002 का 54

(ठख) “प्रतिभूति हित” से किसी संपत्ति पर, किसी बैंक या वित्तीय संस्था के पक्ष में सृजित कोई बंधक, भार, आडमान, समनुदेशन या सम्पत्ति पर किसी बैंक या वित्तीय संस्था के पक्ष में सृजित कोई अन्य अधिकार, हक या हित चाहे वह किसी प्रकार का हो, अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत—

(क) ऐसी मूर्त आस्ति पर, जो किराए या वित्तीय पट्टे या सशर्त विक्रय पर दी गई हो, बैंक या वित्तीय संस्था द्वारा संपत्ति के स्वामी के रूप में प्रतिधारित किसी प्रकार का ऐसा कोई अधिकार, हक या हित भी है, जो आस्ति की क्रय कीमत या उपगत बाध्यता या किसी ऐसे उधार के, जो उधार लेने वाले को मूर्त आस्ति अर्जित करने में समर्थ बनाने के लिए दिया गया हो, किसी असंदत्त भाग का संदाय करने की बाध्यता को प्रतिभूत करता है; या

(ख) किसी अमूर्त आस्ति या अमूर्त आस्ति के लाइसेंस में का कोई ऐसा अधिकार, हक या हित भी है, जो अमूर्त आस्ति की क्रय कीमत या उपगत बाध्यता या किसी ऐसे उधार के, जो उधार लेने वाले को अमूर्त आस्ति या अमूर्त आस्ति का लाइसेंस अर्जित करने में समर्थ बनाने के लिए विस्तारित कर दिया गया हो, किसी असंदत्त भाग का संदाय करने की बाध्यता को प्रतिभूत करता है;’।

धारा 4 का संशोधन।

27. मूल अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

“(2) उपधारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, केन्द्रीय सरकार,—

(क) तत्समय प्रवृत्त अन्य किसी विधि के अधीन स्थापित किसी अन्य अधिकरण के पीठासीन अधिकारी को, उसके उस अधिकरण के पीठासीन अधिकारी होने के अतिरिक्त, इस अधिनियम के अधीन ऋण वसूली अधिकरण के पीठासीन अधिकारी के कृत्यों का निर्वहन करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगी; या

(ख) तत्समय प्रवृत्त अन्य किसी विधि के अधीन स्थापित किसी अन्य अधिकरण में उस रूप में पद धारण करने वाले न्यायिक सदस्य को उसके उस अधिकरण के न्यायिक सदस्य होने के अतिरिक्त, इस अधिनियम के अधीन ऋण वसूली अधिकरण के पीठासीन अधिकारी के कृत्यों का निर्वहन करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगी।”।

धारा 6 का संशोधन।

28. मूल अधिनियम की धारा 6 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

पीठासीन अधिकारी की पदावधि।

“6. अधिकरण का पीठासीन अधिकारी अपने पद ग्रहण करने की तारीख से, पांच वर्ष की अवधि के लिए अपना पद धारण करेगा और पुनः नियुक्ति के लिए पात्र होगा:

परंतु कोई व्यक्ति पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के पश्चात् अधिकरण के पीठासीन अधिकारी के रूप में पद धारण नहीं करेगा।”।

धारा 8 का संशोधन।

29. मूल अधिनियम की धारा 8 में, उपधारा (1) में, निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“परन्तु केन्द्रीय सरकार, तत्समय प्रवृत्त अन्य किसी विधि के अधीन स्थापित किसी अन्य अपील अधिकरण के अध्यक्ष को, उसके उस अपील अधिकरण का अध्यक्ष होने के अतिरिक्त, इस अधिनियम के अधीन ऋण वसूली अपील अधिकरण का अध्यक्ष प्राधिकृत कर सकेगी।”।

धारा 11 का संशोधन।

30. मूल अधिनियम की धारा 11 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

अपील अधिकरण के अध्यक्ष की पदावधि।

“11. अपील अधिकरण का अध्यक्ष अपने पदग्रहण करने की तारीख से, पांच वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा और पुनः नियुक्ति के लिए पात्र होगा:

परंतु कोई व्यक्ति सत्तर वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के पश्चात् अपील अधिकरण के अध्यक्ष के रूप में पद धारण नहीं करेगा।”।

31. मूल अधिनियम की धारा 17क में, उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधाराएं अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:—

धारा 17क का संशोधन।

“(1क) अध्यक्ष, उपधारा (1) के अधीन अधिकरणों पर अधीक्षण और नियंत्रण की साधारण शक्तियों के प्रयोग के प्रयोजन के लिए, —

2002 का 54

(i) इस अधिनियम और वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002, दोनों के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन लंबित मामलों से संबंधित जानकारी, निपटाए गए मामलों की संख्या, फाइल किए गए नए मामलों की संख्या और ऐसी अन्य जानकारी, जो अध्यक्ष द्वारा आवश्यक समझी जाए, ऐसे प्ररूप में, ऐसे अंतरालों पर और ऐसे समय के भीतर प्रस्तुत करने के लिए अधिकरणों को निदेश दे सकेगा;

(ii) उनके निष्पादन का आवधिक रूप से पुनर्विलोकन करने के लिए अधिकरणों के पीठासीन अधिकारियों की बैठक आहूत कर सकेगा।

(1ख) जहां अधिकरण के किसी पीठासीन अधिकारी के कार्य निष्पादन के मूल्यांकन किए जाने पर, या अन्यथा अध्यक्ष की यह राय है कि कदाचार या अक्षमता के लिए ऐसे पीठासीन अधिकारी के विरुद्ध जांच आरंभ की जानी अपेक्षित है वहां वह धारा 15 के अधीन ऐसे पीठासीन अधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई, यदि कोई हो, की सिफारिश करते हुए और उसके लिए कारण लेखबद्ध करते हुए केन्द्रीय सरकार को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।”

32. मूल अधिनियम की धारा 19 में,—

धारा 19 का संशोधन।

(i) उपधारा (1) में खंड (क) को खंड (कक) के रूप में पुनर्संख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार पुनर्संख्यांकित खंड (कक) से पहले निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“(क) बैंक या वित्तीय संस्था की शाखा या कोई अन्य कार्यालय कोई ऐसा खाता रख रहा है जिसमें दावाकृत ऋण तत्समय बकाया है; या”;

(ii) उपधारा (3) के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

“(3) उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन प्रत्येक आवेदन, ऐसे प्ररूप में होगा जो विहित किया जाए और इसके साथ ऐसी फीस जो विहित की जाए, सहित दावे के समर्थन में विश्वास किए गए सभी दस्तावेजों की शुद्ध प्रतियां संलग्न होंगी।”;

(iii) उपधारा (3) में, दूसरे परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

1891 का 18

“स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, दस्तावेजों के अंतर्गत बैंककार बही साक्ष्य अधिनियम, 1891 के अधीन सम्यक्तः प्रमाणित बैंककारों की बही में लेखा का विवरण या कोई प्रविष्टि भी है।”;

(iv) उपधारा (3) के पश्चात् उपधारा (3क) को उपधारा (3ख) के रूप में पुनर्संख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार पुनर्संख्यांकित उपधारा (3ख) से पूर्व निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

“(3क) ऋण की वसूली के लिए उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन फाइल किए गए किसी आवेदन में प्रत्येक आवेदक,—

(क) प्रतिवादियों में से किसी प्रतिवादी की संपत्तियों या आस्तियों पर प्रतिभूति हित द्वारा प्रतिभूत ऋण और ऐसी प्रतिभूतियों के प्राक्कलित मूल्य की विशिष्टियों का कथन करेगा;

(ख) यदि प्रतिभूतियों का प्राक्कलित मूल्य दावाकृत ऋण को चुकाने के लिए पर्याप्त नहीं है तो प्रतिवादियों में से किसी प्रतिवादी के स्वामित्वाधीन किसी अन्य संपत्ति या आस्तियों, यदि कोई हो, की विशिष्टियों का कथन करेगा; और

(ग) यदि ऐसी अन्य आस्तियों का प्राक्कलित मूल्य ऋण को वसूल करने के लिए पर्याप्त नहीं है तो प्रतिवादियों के स्वामित्वाधीन अन्य संपत्तियों या आस्तियों की विशिष्टियां अधिकरण को प्रकटित करने के लिए प्रतिवादी को निदेश देने वाले आदेश की मांग करेगा।”;

(v) उपधारा (4) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

“(4) उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन आवेदन प्राप्त किए जाने पर अधिकरण प्रतिवादी को निम्नलिखित निदेशों के साथ समन जारी करेगा,—

(i) वह समनों की तामील के तीस दिन के भीतर कारण बताए कि प्रार्थना अनुतोष क्यों न प्रदान किया जाए;

(ii) उपधारा (3क) के खंड (क) और खंड (ख) के अधीन आवेदक द्वारा विनिर्दिष्ट संपत्तियों और आस्तियों से भिन्न संपत्तियों या आस्तियों की विशिष्टियां प्रकटित करने के लिए प्रतिवादी को निदेश देने के लिए;

(iii) संपत्ति कुर्की के लिए आवेदन की सुनवाई और निपटान के लंबित रहने तक उपधारा (3क) के खंड (ग) के अधीन प्रकटित ऐसी आस्तियों और संपत्तियों के संबंध में व्यौहार करने या उनका व्ययन करने से प्रतिवादी को अवरुद्ध करने के लिए।”;

(vi) उपधारा (4) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

“(4क) संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882 की धारा 65क में किसी बात के होते हुए भी, 1882 का 4 समनों के तामील पर प्रतिवादी अपनी किन्हीं आस्तियों को, जिन पर प्रतिभूति हित सृजित किया गया है या उपधारा (3क) के अधीन विनिर्दिष्ट या प्रकटित ऐसी अन्य संपत्तियों को और आस्तियों को अपने कारबार के सामान्य अनुक्रम के सिवाय अधिकरण के पूर्व अनुमोदन के बिना विक्रय, पट्टा या अन्यथा के रूप में अंतरित नहीं करेगा:

परंतु अधिकरण आवेदक बैंक या वित्तीय संस्था को कारण बताने के लिए सूचना दिए बिना ऐसा अनुमोदन प्रदान नहीं करेगा कि प्रार्थना किया गया अनुमोदन क्यों नहीं प्रदान किया जाए:

परंतु यह और कि प्रतिवादी कारबार के मामूली अनुक्रम में प्रतिभूत आस्तियों के विक्रय द्वारा वसूल किए गए विक्रय आगमों का लेखा-जोखा देने के लिए दायी होगा और ऐसी आस्तियों पर प्रतिभूति हित धारण करने वाले बैंक या वित्तीय संस्था के रखे गए खाते में ऐसे विक्रय आगमों को जमा करेगा।”;

(vii) उपधारा (5) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

“(5) (i) प्रतिवादी समनों की तामील की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर उपधारा (6) के अधीन मुजरा के लिए दावे सहित अपनी प्रतिरक्षा का लिखित कथन या उपधारा (8) के अधीन प्रतिदावा, यदि कोई हो, प्रस्तुत करेगा और ऐसे लिखित कथन के साथ अपनी प्रतिरक्षा में लिखित विवरणी प्रस्तुत करेगा और ऐसी लिखित विवरणी के साथ प्रतिवादी द्वारा अपनी प्रतिरक्षा में विश्वास किए गए मूल दस्तावेज या अधिकरण की इजाजत से उनकी शुद्ध प्रतियां संलग्न होंगी:

परंतु जहां प्रतिवादी तीस दिन की उक्त अवधि के भीतर लिखित कथन फाइल करने में असफल रहता है वहां पीठासीन अधिकारी आपवादिक मामलों और विशेष परिस्थितियों में, जो लेखबद्ध की जाएं, उक्त अवधि को अपनी प्रतिरक्षा की लिखित विवरणी फाइल करने के लिए पंद्रह दिन से अनधिक ऐसी और अतिरिक्त अवधि तक बढ़ा सकेगा।

(ii) जहां प्रतिवादी, अधिकरण द्वारा पारित आदेशों के अनुसरण में किसी संपत्ति या आस्ति का प्रकटन करता है वहां इस धारा की उपधारा (4क) के उपबंध ऐसी संपत्ति या आस्ति को लागू होंगे।

(iii) उपधारा (4) के खंड (ii) के अधीन किए गए किसी आदेश के अनुपालन की दशा में पीठासीन अधिकारी आदेश द्वारा यह निदेश दे सकेगा कि ऐसे व्यक्ति या अधिकारी को, जो व्यतिक्रम करता है, तीन मास से अनधिक की अवधि के लिए सिविल कारागार में परिरुद्ध तब तक कर लिया जाए जब तक कि इस बीच पीठासीन अधिकारी उसको छोड़ने का आदेश न दे दे:

परंतु पीठासीन अधिकारी इस खंड के अधीन कोई आदेश ऐसे व्यक्ति या अधिकारी को सुनवाई का अवसर दिए बिना पारित नहीं करेगा।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजन के लिए, ‘ऐसा अधिकारी जो व्यतिक्रम करता है’ पद से ऐसा अधिकारी अभिप्रेत है जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 के खंड (60) में परिभाषित है।’;

(viii) उपधारा (5क) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

“(5क) प्रतिरक्षा का लिखित कथन प्राप्त हो जाने पर या लिखित कथन फाइल करने के लिए अधिकरण द्वारा प्रदान किए गए समय की समाप्ति पर, अधिकरण कार्यवाहियों के पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों को स्वीकार करने के लिए या प्रत्याख्यान के लिए उपधारा (4) के अधीन पारित अंतरिम आदेश को बनाए रखने के लिए या उसको बातिल करने के लिए भी सुनवाई की तारीख नियत करेगा।

(5ख) जहां प्रतिवादी बैंक या वित्तीय संस्था को देय ऋण की रकम को पूर्णतः या भागतः स्वीकार करता है वहां अधिकरण प्रतिवादी को स्वीकृति की सीमा तक ऐसी रकम का ऐसे आदेश की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर संदाय करने का आदेश करेगा जिसके न हो सकने पर अधिकरण उपधारा (22) के उपबंधों के अनुसार प्रतिवादी द्वारा स्वीकार किए गए देय ऋण की रकम की सीमा तक प्रमाणपत्र जारी कर सकेगा।”;

(ix) उपधारा (6) में, “मुजरा किए जाने के लिए चाहे गए ऋण” शब्दों के स्थान पर “आवेदक के विरुद्ध मूल दस्तावेज और किसी अभिनिश्चित धनराशि के मुजरा के दावे के समर्थन में निर्भर किए गए अन्य साक्ष्य सहित मुजरा किए जाने के लिए चाहे गए ऋण” शब्द रखे जाएंगे;

(x) उपधारा (10) में, “जो अधिकरण द्वारा नियत की जाए” शब्दों के स्थान पर “जो विहित की जाए” शब्द रखे जाएंगे;

(xi) उपधारा (10) के पश्चात् निम्नलिखित उपधाराएं अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:—

“(10क) उपधारा (3) के अधीन प्रत्येक आवेदन या उपधारा (5) के अधीन प्रतिवादी का लिखित कथन या उपधारा (6) के अधीन मुजरे का दावा या प्रतिवादी द्वारा उपधारा (8) के अधीन कोई प्रतिदावा या उपधारा (10) के अधीन प्रतिदावा के उत्तर में आवेदक द्वारा लिखित कथन या कोई अन्य अभिवचन, वह जो भी हो, यथास्थिति, सभी तथ्यों और अभिवचनों, आवेदन से उपाबद्ध दस्तावेजों का अभिवचन करने वाले कथन और अन्य दस्तावेजी साक्ष्य या मुजरा या प्रतिदावे का लिखित कथन या उत्तर सत्यापन करने वाले आवेदक या प्रतिवादी द्वारा शपथ लिए गए शपथ-पत्र से समर्थित होगा:

परंतु यदि किसी पक्षकार द्वारा नेतृत्व किए जाने वाले साक्षियों का कोई साक्ष्य है, तो ऐसे साक्षियों के शपथ-पत्र उपधारा (10क) के अधीन फाइल किए गए आवेदन या लिखित कथन या उत्तरों के साथ-साथ पक्षकार द्वारा फाइल किए जाएंगे।

(10ख) यदि आवेदन या लिखित कथन में किन्हीं तथ्यों पर अभिवचनों को उपधारा (10क) के अधीन उपबंधित रीति में सत्यापित नहीं किया जाता है तो कार्यवाहियों के पक्षकार को उसमें उपवर्णित साक्ष्य या किसी विषय के रूप में ऐसे तथ्यों या अभिवचनों पर निर्भर करने के लिए अनुज्ञा नहीं दी जाएगी।”;

(xii) उपधारा (11) के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

“(11) जहां प्रतिवादी कोई प्रतिदावा लिखित कथन में प्रस्तुत करता है और आवेदक ऐसे दावे के उत्तर में यह प्रतिवाद करता है कि उसके द्वारा उठाया गया दावा, प्रतिदावे के रूप में न

निपटया जाए किंतु एक स्वतंत्र कार्रवाई के रूप में निपटया जाए तो अधिकरण ऐसे मुद्दे का विनिश्चय ऋण की वसूली के लिए आवेदक के दावे के साथ करेगा।”;

(xiii) विद्यमान धारा 12 का लोप किया जाएगा;

(xiv) उपधारा (13) (क) में, “अधिकरण का शपथ-पत्र द्वारा या अन्यथा यह समाधान हो जाता है” शब्दों के स्थान पर, “अधिकरण का कुर्क की जाने वाली संपत्ति की विशिष्टियों और उसके प्राक्कलित मूल्य सहित आवेदक द्वारा किए गए आवेदन पर या अन्यथा यह समाधान हो जाता है” शब्द रखे जाएंगे;

(xv) उपधारा (14) का लोप किया जाएगा;

(xvi) उपधारा (15) में “उपधारा (14)” शब्द, कोष्ठकों और अंकों के स्थान पर “उपधारा (13)” शब्द, कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे;

(xvii) उपधारा (19) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

“(19) जहां कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन यथा परिभाषित कंपनी के विरुद्ध वसूली प्रमाणपत्र जारी किया जाता है और ऐसी कंपनी परिसमापनाधीन है वहां अधिकरण आदेश द्वारा यह निदेश दे सकेगा कि ऐसी कंपनी की प्रतिभूत आस्तियों के विक्रय आगम कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 326 में यथा उपबंधित उसी रीति में या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन वितरित की जाए।”;

(xviii) उपधारा (20) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

“(20) अधिकरण सभी दावों, मुजरा या प्रतिदावों, यदि कोई हों और ऐसे दावों पर ब्याज के संबंध में आवेदक और प्रतिवादी को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् सुनवाई के समाप्त होने की तारीख से तीस दिन के भीतर ऐसा अंतरिम या अंतिम आदेश पारित कर सकेगा जो वह ठीक समझे, जिसके अंतर्गत उस तारीख से जिसको ऐसी रकम का संदाय शोध पाया जाता है, वसूली या वास्तविक संदाय की तारीख तक ब्याज के संदाय का आदेश भी है।”;

(xix) उपधारा (20क) के पश्चात् निम्नलिखित उपधाराएं अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:—

“(20क) उपधारा (20) के अधीन अंतिम आदेश पारित करते समय अधिकरण, उधार लेने वाले की उन आस्तियों को स्पष्टतः विनिर्दिष्ट करेगा जिन पर किसी बैंक या वित्तीय संस्थाओं के पक्ष में वित्तीय हित सृजित किया जाता है और वसूली अधिकारियों को उपधारा (20कख) में यथा उपबंधित ऐसी आस्तियों के विक्रय आगमों को वितरित करने का निदेश देगा।

(20कख) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, प्रतिभूत आस्तियों के विक्रय से प्राप्त आगम पूर्विकता के निम्नलिखित क्रम में वितरित किए जाएंगे, अर्थात्:—

(i) प्रतिभूत आस्तियों के परिरक्षण और संरक्षण के लिए उपगत खर्चों, मूल्यांकन के खर्च, कब्जे और नीलामी के लिए लोक सूचना और आस्तियों के विक्रय के लिए अन्य व्ययों का पूर्णतः संदाय किया जाएगा;

(ii) ऐसे बैंक या वित्तीय संस्था के देय ऋण।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजन के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के प्रारंभ होने पर या उसके पश्चात्, उन मामलों में जहां उधार लेने वालों की प्रतिभूत आस्तियों के संबंध में दिवाला और शोधन अक्षमता प्रक्रियाएं लंबित हैं, वहां प्रतिभूत आस्तियों के विक्रय के आगमों का वितरण उक्त संहिता में यथा उपबंधित पूर्विकता के क्रम के अधीन होगा।”।

(xx) उपधारा (21) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

“(21) (i) अधिकरण, आवेदक और प्रतिवादी को अपनी अंतिम आदेश और वसूली प्रमाणपत्र की एक प्रति भेजेगा।

(ii) आवेदक और प्रतिवादी, ऐसी फीस के संदाय किए जाने पर जो विहित की जाए, अधिकरण द्वारा पारित किसी आदेश की प्रति अभिप्राप्त कर सकेगा।”;

(xxi) उपधारा (22) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

“(22) पीठासीन अधिकारी प्रमाणपत्र में विनिर्दिष्ट ऋण की रकम की वसूली के लिए वसूली अधिकारी को अपने हस्ताक्षर से ब्याज सहित ऋण के संदाय के लिए अंतिम आदेश सहित उपधारा (20) के अधीन वसूली प्रमाणपत्र जारी करेगा।”;

(xxii) उपधारा (22) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

“(22क) उपधारा (22) के अधीन पीठासीन अधिकारी द्वारा जारी कोई वसूली प्रमाणपत्र, यथास्थिति, कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन रजिस्ट्रीकृत कंपनी, या सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2008 के अधीन रजिस्ट्रीकृत सीमित दायित्व भागीदारी के विरुद्ध परिसमापन कार्यवाहियां या किसी अन्य विधि के अधीन किसी व्यक्ति या भागीदारी फर्म के विरुद्ध दिवाला कार्यवाहियां प्रारंभ करने के प्रयोजनों के लिए न्यायालय की डिक्री या आदेश समझा जाएगा।”;

(xxiii) उपधारा (24) में आवेदन प्राप्त करने की तारीख से एक सौ अस्सी दिन के भीतर “उसके द्वारा आवेदन को अंतिम रूप से निपटाने का प्रयास किया जाएगा,” शब्दों के स्थान पर “दो सुनवाईयों में कार्यवाहियों को पूरा करने और आवेदन प्राप्त करने की तारीख से एक सौ अस्सी दिन के भीतर उसके द्वारा आवेदन को अंतिम रूप से निपटाने का प्रत्येक प्रयास किया जाएगा,” शब्द रखे जाएंगे।

33. मूल अधिनियम की धारा 19 के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

“19क. (1) केन्द्रीय सरकार इस अधिनियम में अंतर्विष्ट तत्प्रतिकूल किसी बात के होते हुए भी और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 6 में अंतर्विष्ट उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना नियमों द्वारा यह उपबंध कर सकेगी कि ऐसी तारीख से और ऐसे अधिकरण तथा अपील अधिकरण के समक्ष जो अधिसूचित किए जाएं,—

(क) फाइल किए जाने के लिए अपेक्षित आवेदन या लिखित कथन या कोई अन्य अभिवचन और उनके साथ उपाबद्ध किए जाने वाले दस्तावेज इलैक्ट्रॉनिक रूप में प्रस्तुत किए जाएंगे और आवेदक, प्रतिवादी या किसी अन्य याची के अंकीय हस्ताक्षर के साथ ऐसे रूप और रीति में जो विहित की जाए, अधिप्रमाणित किए जाएंगे;

(ख) कोई समन सूचना या संसूचना या प्रज्ञापना जो इस अधिनियम के अधीन तामील की जानी या परिदत्त की जानी अपेक्षित हो, इलैक्ट्रॉनिक रूप में अभिवचनों और दस्तावेजों के पारेषण द्वारा तामील या परिदत्त की जा सकेगी और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, अधिप्रमाणित की जा सकेगी।

(2) ऐसे अधिकरण या अपील अधिकरण की वेबसाइट पर प्रदर्शित अधिकरण या अपील अधिकरण द्वारा पारित किसी अंतरिम या अंतिम आदेश को ऐसे आदेश की लोक सूचना समझा जाएगा और कार्रवाई के पक्षकारों के रजिस्ट्रीकृत पते पर इलैक्ट्रॉनिक मेल द्वारा ऐसे आदेश का पारेषण ऐसे पक्षकार पर तामील किया गया समझा जाएगा।

(3) केन्द्रीय सरकार नियमों द्वारा यह उपबंध कर सकेगी कि इस धारा में विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिए इलैक्ट्रॉनिक रूप अनन्य या अनुकल्पतः उसके भौतिक रूप के अतिरिक्त होगा।

(4) इलैक्ट्रॉनिक फाइलिंग को अंगीकृत करने के प्रयोजन के लिए उपधारा (1) के अधीन अधिसूचित अधिकरण या अपील अधिकरण अपनी स्वयं की वेबसाइट या अन्य अधिकरणों और अपील अधिकरण के साथ सामान्य वेबसाइट या इलैक्ट्रॉनिक सूचना की ऐसी अन्य सार्वभौमिक रूप से पहुंच योग्य भंडार बनाए रखेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि अधिकरण या अपील अधिकरण द्वारा जारी किए गए सभी आदेश या निदेश अधिकरण या अपील अधिकरण की वेबसाइट पर ऐसी रीति में जो विहित की जाए, प्रदर्शित किए जाते हैं।

नई धारा 19क का अंतःस्थापन।

इलैक्ट्रॉनिक रूप में वसूली आवेदनों, दस्तावेजों और लिखित कथनों का फाइल किया जाना।

2013 का 18
2008 का 9

2000 का 21

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजन के लिए—

(क) 'अंकीय हस्ताक्षर' से सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 2 के खंड (त) 2000 का 21 के अधीन यथा परिभाषित अंकीय हस्ताक्षर अभिप्रेत है;

(ख) किसी सूचना या किसी दस्तावेज के प्रतिनिर्देश से 'इलैक्ट्रॉनिक रूप' से सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 2 के खंड (द) के अधीन यथा परिभाषित इलैक्ट्रॉनिक रूप 2000 का 21 अभिप्रेत है।”।

धारा 20 का संशोधन।

34. मूल अधिनियम की धारा 20 की उपधारा (3) में “पैंतालीस दिन” शब्दों के स्थान पर, दोनों स्थानों पर, जहां-जहां वे आते हैं, “तीस दिन” शब्द रखे जाएंगे।

धारा 21 का संशोधन।

35. मूल अधिनियम में,—

(i) धारा 21 में, “पचहत्तर प्रतिशत” शब्दों के स्थान पर “पचास प्रतिशत” शब्द रखे जाएंगे;

(ii) परंतुक में, “रकम का अधित्यजन कर सकेगा या उसे बढ़ा सकेगा” शब्दों के स्थान पर “का अधित्यजन रकम को ऐसी रकम में से जो ऐसी देय ऋण की रकम का पच्चीस प्रतिशत से अन्यून नहीं होगी घटा सकेगा” शब्द रखे जाएंगे।

धारा 22 का संशोधन।

36. मूल अधिनियम की धारा 22 में उपधारा (3) के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

“(4) बैंककार बहियों में किसी प्रविष्टि के सबूत के प्रयोजन के लिए, बैंककार बही साक्ष्य अधिनियम, 1891 के उपबंध अधिकरण या अपील अधिकरण के समक्ष सभी कार्यवाहियों को लागू होंगे।”। 1891 का 18

नई धारा 22 का अंतःस्थापन। कार्यवाहियां संचालित करने के लिए एक समान प्रक्रिया। धारा 25 का संशोधन।

37. मूल अधिनियम में धारा 22 के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

“22क. केन्द्रीय सरकार, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए नियमों द्वारा अधिकरणों और अपील अधिकरणों के समक्ष कार्यवाहियां संचालित करने के लिए इस अधिनियम के उपबंधों से संगत एक समान प्रक्रिया अधिकथित कर सकेगी।”।

38. मूल अधिनियम की धारा 25 में,—

(i) खंड (क) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“(कक) ऐसी संपत्ति का, जिस पर प्रतिभूति हित सृजित किया जाता है या प्रतिवादी की किसी अन्य संपत्ति का, कब्जा लेना और ऐसी संपत्ति के लिए और उसका विक्रय करने के लिए रिसीवर नियुक्त करना।”।

(ii) खंड (ग) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“(घ) वसूली की कोई अन्य पद्धति जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए।”।

धारा 27 का संशोधन।

39. मूल अधिनियम की धारा 27 में उपधारा (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधाराएं रखी जाएंगी, अर्थात्:—

“(1) यह होते हुए भी कि किसी रकम की वसूली के लिए वसूली अधिकारी को प्रमाणपत्र जारी किया गया है, पीठासीन अधिकारी आदेश द्वारा रकम के संदाय के लिए समय मंजूर कर सकेगा, परंतु यह तब जब प्रतिवादी, दावा की गई रकम से कम पच्चीस प्रतिशत रकम का नकद संदाय करता है और युक्तियुक्त समय के भीतर अतिशेष का संदाय करने का अशर्त वचनबंध करता है, जो वसूली प्रमाणपत्र धारण करने वाले आवेदक बैंक या वित्तीय संस्था को स्वीकार्य है।

(1क) वसूली अधिकारी उपधारा (1) के अधीन पारित आदेश के प्राप्त हो जाने के पश्चात् इस प्रकार मंजूर किए गए समय की समाप्ति तक कार्यवाहियों पर रोक लगाएगा।

(1ख) जहां प्रतिवादी वसूली प्रमाणपत्र में विनिर्दिष्ट रकम का संदाय करने के लिए सहमत हो जाता है और कार्यवाहियों पर वसूली अधिकारी द्वारा रोक लगा दी जाती है वहां प्रतिवादी अधिकरण के आदेशों के विरुद्ध अपील फाइल करने के अधिकार को समपहत करेगा।

(1ग) जहां प्रतिवादी उपधारा (1) के अधीन रकम के संदाय में कोई व्यतिक्रम करता है वहां वसूली कार्यवाहियों की रोक वापस हो जाएगी और वसूली अधिकारी शेष शोध्य और संदेय ऋण की रकम की वसूली के लिए कदम उठाएगा।”।

40. मूल अधिनियम में, धारा 30 के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

धारा 30क का
अंतःस्थापन।

“30क. जहां किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा, जिससे बैंक को या वित्तीय संस्था को या बैंकों या वित्तीय संस्थाओं के संघ को ऋण की रकम शोध्य है, धारा 30 के अधीन वसूली अधिकारी के किसी आदेश के विरुद्ध कोई अपील की जाती है वहां ऐसी अपील, अधिकरण द्वारा तब तक ग्रहण नहीं की जाएगी जब तक कि ऐसे व्यक्ति ने अधिकरण के पास अधिकरण द्वारा यथा अवधारित ऐसे शोध्य ऋण की रकम की पचास प्रतिशत रकम जमा नहीं कर दी हो।”।

वसूली अधिकारी के आदेश के विरुद्ध अपील फाइल करने के लिए शोध्य ऋण की रकम का निक्षेप।

41. मूल अधिनियम में, धारा 31क के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

धारा 31ख का
अंतःस्थापन।

“31ख. तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, प्रतिभूत लेनदारों को, ऐसी आस्तियों के, जिन पर प्रतिभूति हित सृजित किया जाता है, विक्रय द्वारा उनको शोध्य और संदेय प्रतिभूत ऋणों को वसूल करने के अधिकारों को पूर्विकता प्राप्त होगी और केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकरण को शोध्य अन्य सभी ऋण और सरकारी शोध्य जिनमें राजस्व, कर, उपकर या रेट भी हैं, पर पूर्विकता के क्रम में संदत्त किए जाएंगे।

प्रतिभूत लेनदारों की पूर्विकता।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के प्रारंभ पर या उसके पश्चात्, ऐसे मामलों में जहां उधार लेने वाले व्यक्ति की प्रतिभूत आस्तियों के संबंध में दिवाला या शोधन अक्षमता कार्यवाहियां लंबित हैं, ऋण के संदाय में प्रतिभूत लेनदारों को दी जाने वाली पूर्विकता उस संहिता के उपबंधों के अध्वधीन होगी।”।

42. मूल अधिनियम की धारा 36 की उपधारा (2) में,—

धारा 36 का
संशोधन।

(i) खंड (क) को खंड (कक) के रूप में पुनः संख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार पुनः संख्यांकित (कक) से पूर्व निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“(क) धारा 2 के खंड (जख) के अधीन समान प्रकृति के अन्य कारबार या वाणिज्यिक अधिकार;”;

(ii) खंड (ग) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“(गक) धारा 19 की उपधारा (3) के अधीन आवेदन फाइल करने के लिए प्ररूप और फीस;”;

(iii) खंड (गग) में “(3क)” कोष्ठकों, अंक और अक्षर के स्थान पर, “(3ख)” कोष्ठक, अंक और अक्षर रखे जाएंगे;

(iv) खंड (गग) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:—

“(गगक) धारा 19 की उपधारा (10) के अधीन लिखित कथन फाइल करने की अवधि;

(गगख) धारा 19 की उपधारा (21) के अधीन अधिकरण के आदेश की प्रति अभिप्राप्त करने के लिए फीस;

(गगग) धारा 19क की उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन अंकीय हस्ताक्षर को अधिप्रमाणित करने का प्ररूप और रीति और खंड (ख) के अधीन अभिवचनों और दस्तावेजों की तामिल या परिदान को अधिप्रमाणित करने की रीति;

(गगघ) धारा 19क की उपधारा (1) के अधीन इलैक्ट्रानिक रूप में आवेदन और अन्य दस्तावेज फाइल करने का प्ररूप और उपधारा (4) के अधीन अधिकरण और अपील अधिकरण के आदेशों के प्रदर्शन की रीति;”;

(v) खंड (घ) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:—

“(घक) धारा 22क के अधीन अधिकरणों और अपील अधिकरणों के समक्ष कार्यवाहियां संचालित करने के लिए एक समान प्रक्रिया के नियम;

(घख) धारा 25 के खंड (घ) के अधीन वसूली की कोई अन्य पद्धति।”।

1899 का
अधिनियम
संख्यांक 2 का
संशोधन।

43. भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899, पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट रीति में संशोधित किया जाएगा।

1996 का
अधिनियम
संख्यांक 22 का
संशोधन।

44. निक्षेपागार अधिनियम, 1996, दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट रीति में संशोधित किया जाएगा।

पहली अनुसूची

(धारा 43 देखिए)

भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 का संशोधन

(1899 का 2)

धारा 8ड के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

वित्तीय आस्तियों के
अंतरण या उसमें के
अधिकारों अथवा
हित के समनुदेशन के
लिए करार या
दस्तावेज का स्टाम्प
ड्यूटी के लिए दायी
न होना।

“8च. इस अधिनियम में या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (खक) में यथा परिभाषित किसी आस्ति पुनर्संनिर्माण कंपनी के पक्ष में, उक्त अधिनियम की धारा 5 के अधीन बैंकों या वित्तीय संस्थाओं की वित्तीय आस्तियों में अधिकारों या हित के अंतरण या समनुदेशन के लिए करार या अन्य दस्तावेज इस अधिनियम के अधीन शुल्क के लिए दायी नहीं होंगे।

2002 का 54

दूसरी अनुसूची

(धारा 44 देखिए)

निक्षेपागार अधिनियम, 1996 का संशोधन

(1996 का 22)

धारा 7 में, उपधारा (1) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधाराएं अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:—

“(1क) किसी प्रतिभागी से सूचना की प्राप्ति पर प्रत्येक निक्षेपागार, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (खक) में यथा परिभाषित आस्ति पुनर्संनिर्माण कंपनी के पक्ष में प्रतिभूति का कोई अंतरण उस अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) के अधीन किसी बैंक या वित्तीय संस्था की वित्तीय आस्ति के अंतरण या समनुदेशन के साथ या उसके परिणामस्वरूप रजिस्टर करता है।

2002 का 54

(1ख) किसी प्रतिभागी से सूचना की प्राप्ति पर प्रत्येक निक्षेपागार, कंपनी और बैंक या वित्तीय संस्था या आस्ति पुनर्संनिर्माण कंपनी के बीच करार पाए गए कंपनी के ऋणों के पुनर्संनिर्माण के अनुसरण में शेयरों में अपने ऋण के भाग के संपरिवर्तन द्वारा यथास्थिति किसी बैंक या वित्तीय संस्था या आस्ति पुनर्संनिर्माण कंपनी और ऐसे बैंक या वित्तीय संस्था या आस्ति पुनर्संनिर्माण कंपनी के पक्ष में नए शेयरों के किसी पुरोधरण को रजिस्टर करता है।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजन के लिए “बैंक” और “वित्तीय संस्था” तथा “आस्ति पुनर्संनिर्माण कंपनी” पदों के वही अर्थ होंगे जो उनके वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति

2002 का 54

हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (खक), खंड (ग) और खंड (ड) में हैं।”।

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016

(2016 का अधिनियम संख्यांक 49)

[27 दिसम्बर, 2016]

दिव्यांगजनों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय और
उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों को
प्रभावी बनाने के लिए
अधिनियम

संयुक्त राष्ट्र महासभा ने, 13 दिसम्बर, 2006 को दिव्यांगजनों के अधिकारों पर उसके अभिसमय को
अंगीकृत किया था;

और पूर्वोक्त अभिसमय दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए निम्नलिखित सिद्धांत अधिकथित करता
है:—

(क) अंतर्निहित गरिमा, वैयक्तिक स्वायत्तता के लिए आदर, जिसके अंतर्गत किसी व्यक्ति की
स्वयं की पसंद की स्वतंत्रता और व्यक्तियों की स्वतंत्रता भी है;

(ख) अविभेद;

(ग) समाज में पूर्ण और प्रभावी भागीदारी और सम्मिलित होना;

(घ) मानवीय भेदभाव और मानवता के भाग के रूप में दिव्यांगजनों की भिन्नता के लिए आदर
और उनका ग्रहण;

(ड) अवसर की समानता;

(च) पहुंच;

(छ) पुरुषों और स्त्रियों के बीच समता;

(ज) दिव्यांग बालकों की बढ़ती हुई क्षमता के लिए आदर और दिव्यांग बालकों की पहचान परिरक्षित करने के उनके अधिकार के लिए आदर;

और भारत उक्त अभिसमय का एक हस्ताक्षरकर्ता है;

और भारत ने, 1 अक्टूबर, 2007 को उक्त अभिसमय का अनुसमर्थन किया था;

और पूर्वोक्त अभिसमय को कार्यान्वित करना आवश्यक समझा जाता है।

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

अध्याय 1

प्रारंभिक

संक्षिप्त नाम,
विस्तार और प्रारंभ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 है।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे।

परिभाषाएं।

2. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) “अपील प्राधिकारी” से, यथास्थिति, धारा 14 की उपधारा (3) या धारा 53 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचित या धारा 59 की उपधारा (1) के अधीन अभिहित प्राधिकारी अभिप्रेत है;

(ख) “समुचित सरकार” से,—

(i) केन्द्रीय सरकार या उस सरकार द्वारा पूर्णतः या पर्याप्त रूप से वित्तपोषित किसी स्थापन या छावनी अधिनियम, 2006 के अधीन गठित किसी छावनी बोर्ड के संबंध में, केन्द्रीय सरकार; 2006 का 41

(ii) कोई राज्य सरकार या उस सरकार द्वारा पूर्णतः या सारवान् रूप से वित्तपोषित किसी स्थापन या छावनी बोर्ड से भिन्न किसी स्थानीय प्राधिकारी के संबंध में, राज्य सरकार,

अभिप्रेत है;

(ग) “रोध” से ऐसा कोई कारक अभिप्रेत है जिसमें संसूचनात्मक, सांस्कृतिक, आर्थिक, पर्यावरणात्मक, संस्थागत, राजनैतिक, सामाजिक, भाव संबंधी या अवसरचरणात्मक कारक सम्मिलित हैं जो समाज में दिव्यांगजनों की पूर्ण और प्रभावी भागीदारी को रोकते हैं;

(घ) “देख-रेख कर्ता” से माता-पिता और कुटुंब के अन्य सदस्यों सहित ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो संदाय करने पर या उसके बिना, किसी दिव्यांगजन को देख-रेख, सहारा या सहायता देता है;

(ड) “प्रमाणकर्ता प्राधिकारी” से धारा 57 की उपधारा (1) के अधीन अभिहित प्राधिकारी अभिप्रेत है;

(च) “संसूचना” में संसूचना के उपाय और रूप विधान, भाषाएं, पाठ का प्रदर्श, उत्कीर्ण लेख, स्पर्शनीय संसूचना, संकेत, बड़ा मुद्रण, पहुंच योग्य मल्टीमीडिया, लिखित, श्रव्य, विडियो, दृश्य, प्रदर्शन, संकेत भाषा, सरल भाषा, ह्यूमन-रीडर, संवर्धित तथा अनुकल्पी पद्धति और पहुंच योग्य जानकारी और संसूचना प्रौद्योगिकी सम्मिलित हैं;

(छ) “सक्षम प्राधिकारी” से धारा 49 के अधीन नियुक्त कोई प्राधिकारी अभिप्रेत है;

(ज) दिव्यांगता के संबंध में “विभेद” से दिव्यांगता के आधार पर कोई विभेद, अपवर्जन, निर्बन्धन अभिप्रेत है जो राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, सिविल या किसी अन्य क्षेत्र में सभी मानव

अधिकारों और मूलभूत स्वतंत्रताओं के संबंध में अन्य व्यक्तियों के साथ किसी सामान्य आधार पर मान्यता, उपभोग या प्रयोग ह्रासित करने या अकृत करने का प्रयोजन या प्रभाव है और जिसके अंतर्गत सभी प्रकार के विभेद और युक्तियुक्त सुविधाओं का प्रत्याख्यान भी है;

(झ) “स्थापन” के, अंतर्गत कोई सरकारी और प्राइवेट स्थापन भी है;

(ञ) “निधि” से धारा 86 के अधीन गठित राष्ट्रीय निधि अभिप्रेत है;

2013 का 18

(ट) “सरकारी स्थापन” से केन्द्रीय अधिनियम या राज्य अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित कोई निगम या सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी या कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 में यथा परिभाषित किसी सरकारी कंपनी के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन या सहायता प्राप्त कोई प्राधिकरण या निकाय अभिप्रेत है और जिसमें सरकार का कोई विभाग भी सम्मिलित है;

(ठ) “उच्च सहायता” से शारीरिक, मानसिक और अन्यथा ऐसी गहन सहायता अभिप्रेत है जो दैनिक क्रियाकलाप के लिए संदर्भित दिव्यांगजन द्वारा जीवन के सभी क्षेत्रों में जिसके अंतर्गत शिक्षा, नियोजन, कुटुंब और सामुदायिक जीवन और व्यवहार तथा रोगोपचार भी हैं, पहुंच सुविधाएं और भागीदारी के लिए स्वतंत्र और बुद्धिमान विनिश्चय लेने के लिए अपेक्षित हो सकेगी;

(ड) “सम्मिलित शिक्षा” से ऐसी शिक्षा पद्धति अभिप्रेत है जिसमें दिव्यांगता और दिव्यांगता रहित छात्र एक साथ विद्या ग्रहण करते हैं और शिक्षण और विद्या की पद्धति, विभिन्न प्रकार के दिव्यांग छात्रों की विद्या की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उचित रूप से अनुकूलित की गई है;

(ढ) “सूचना और संचार प्रौद्योगिकी” के अंतर्गत सूचना और प्रौद्योगिकी से संबंधित सभी सेवा और नव परिवर्तन भी हैं जिसके अंतर्गत टेलीकाम सेवाएं, वेब आधारित सेवाएं, इलैक्ट्रॉनिक और मुद्रण सेवाएं, डिजिटल और परोक्ष सेवाएं भी हैं;

(ण) “संस्था” से दिव्यांगजनों के लिए प्रवेश, देख-रेख, संरक्षण, शिक्षा, प्रशिक्षण, पुनर्वास और किसी अन्य क्रियाकलाप के लिए कोई संस्था अभिप्रेत है;

2006 का 41

(त) “स्थानीय प्राधिकरण” से संविधान के अनुच्छेद 243त के खंड (ड) और खंड (च) में यथापरिभाषित नगरपालिका या पंचायत; छावनी अधिनियम, 2006 के अधीन गठित छावनी बोर्ड; और नागरिक क्रियाकलापों का प्रशासन करने के लिए संसद् या किसी राज्य विधान-मंडल के अधिनियम के अधीन स्थापित कोई अन्य प्राधिकरण अभिप्रेत है;

(थ) “अधिसूचना” से राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत है और “अधिसूचित करना” या “अधिसूचित” पद का अर्थ तदनुसार लगाया जाएगा;

(द) “संदर्भित दिव्यांगजन” से प्रमाणकर्ता प्राधिकारी द्वारा यथाप्रमाणीकृत, विनिर्दिष्ट दिव्यांगता के चालीस प्रतिशत से अन्यून का व्यक्ति अभिप्रेत है, जहां विनिर्दिष्ट दिव्यांगता अध्यापयी निबंधनों में परिभाषित नहीं की गई है और इसमें ऐसा दिव्यांगजन भी सम्मिलित है जहां विनिर्दिष्ट दिव्यांगता, प्रमाणकर्ता प्राधिकारी द्वारा यथाप्रमाणीकृत अध्यापयी निबंधनों में परिभाषित की गई है;

(ध) “दिव्यांगजन” से ऐसी दीर्घकालिक शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक या संवेदी हानि वाला व्यक्ति अभिप्रेत है जिससे बाधाओं का सामना करने में अन्य व्यक्तियों के साथ समान रूप से समाज में पूर्ण और प्रभावी भागीदारी में रुकावट उत्पन्न होती है;

(न) “उच्च सहायता की आवश्यकताओं वाला दिव्यांगजन” से धारा 58 की उपधारा (2) के खंड (क) के अधीन प्रमाणित संदर्भित दिव्यांगजन अभिप्रेत है, जिसे उच्च सहायता की आवश्यकता है;

(प) “विहित” से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;

(फ) “प्राइवेट स्थापन” से कोई कंपनी, फर्म, सहकारी या अन्य सोसाइटी, संगम, न्यास, अभिकरण, संस्था, संगठन, संघ, कारखाना या ऐसा कोई अन्य स्थापन जो समुचित सरकार अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे;

(ब) “सार्वजनिक भवन” से कोई सरकारी या निजी भवन जो अत्यधिक जनता द्वारा उपयोग किया जाता है या उनकी पहुंच में है, जिसके अंतर्गत शैक्षिक या व्यावसायिक प्रयोजनों के कार्य स्थल, वाणिज्यिक क्रियाकलापों, सार्वजनिक सुविधाओं, धार्मिक, सांस्कृतिक, अवकाश या मनोरंजन क्रियाकलापों, चिकित्सीय या स्वास्थ्य सेवाओं, विधि प्रवर्तन अभिकरणों, सुधारात्मक या न्यायिक फोरम, रेलवे स्टेशनों या प्लेटफार्मों, सड़क परिवहन बस स्टैंडों या टर्मिनल, विमानपत्तनों या जलमार्गों के लिए उपयोग किए जाने वाले भवन भी हैं;

(भ) “सार्वजनिक सुविधाओं और सेवाओं” के अंतर्गत वृहत् स्तर पर जनता को सेवाएं प्रदान करने के सभी रूप आते हैं जिसके अंतर्गत आवास, शिक्षा या वृत्तिक प्रशिक्षण, नियोजन और वृत्तिक उन्नयन, विक्रय स्थल या विपणन केन्द्र, धार्मिक, सांस्कृतिक, अवकाश या मनोरंजन, चिकित्सा, स्वास्थ्य और पुनर्वास, बैंकारी, वित्त और बीमा, संचार, डाक और सूचना, न्याय तक पहुंच, सार्वजनिक उपयोगिताएं, परिवहन भी हैं;

(म) “युक्तियुक्त आवासन” से दिव्यांगजनों के लिए अन्य व्यक्तियों के समान अधिकारों के उपभोग या उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए, किसी विशिष्ट दशा में, अनुपातिक या असम्यक् बोझ अधिरोपित किए बिना, आवश्यक और समुचित उपांतरण तथा समायोजन अभिप्रेत हैं;

(य) “रजिस्ट्रीकृत संगठन” से संसद् या किसी राज्य विधान-मंडल के अधिनियम के अधीन सम्यक् रूप से रजिस्ट्रीकृत दिव्यांगजनों का कोई संगम या दिव्यांगजन संगठन, दिव्यांगजनों के माता-पिता का संगम, दिव्यांगजनों और कुटुंब के सदस्यों का संगम या स्वैच्छिक या गैर-सरकारी या पूर्ण संगठन या न्यास, सोसाइटी या दिव्यांगजनों के कल्याण के लिए कार्य करने वाली अलाभकारी कंपनी अभिप्रेत है;

(यक) “पुनर्वास” से दिव्यांगजनों को, अनुकूलतम, शारीरिक, संवेदी, बौद्धिक, मनोवैज्ञानिक, पर्यावरणीय या सामाजिक कार्य के स्तरों को प्राप्त करने और उनको बनाए रखने में समर्थ बनाने के उद्देश्य से कोई प्रक्रिया निर्दिष्ट है;

(यख) “विशेष रोजगार कार्यालय” से—

(i) ऐसे व्यक्ति के संबंध में जो दिव्यांगजनों में से कर्मचारियों को लगाना चाहते हैं;

(ii) ऐसे संदर्भित दिव्यांगजन के संबंध में जो नियोजन चाहते हैं;

(iii) ऐसी रिक्तियों के संबंध में जिन पर संदर्भित दिव्यांगजन नियोजन चाहते हैं, नियुक्त किए जा सकेंगे,

रजिस्टर रखते हुए या अन्यथा सूचना एकत्रित करने या सूचना देने के लिए सरकार द्वारा स्थापित या अनुरक्षित कोई कार्यालय या स्थान अभिप्रेत है;

(यग) “विनिर्दिष्ट दिव्यांगता” से अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट दिव्यांगताएं अभिप्रेत हैं;

(यघ) “परिवहन प्रणाली” के अंतर्गत सड़क परिवहन, रेल परिवहन, वायु परिवहन, जल परिवहन, अंतिम मील तक संबद्धता के लिए सह-अभिवहन प्रणाली, सड़क और गली अवसंरचना आते हैं;

(यड) “सर्वव्यापी डिजाइन” से सभी लोगों द्वारा अनुकूलन या विशिष्ट डिजाइन की आवश्यकता के बिना अधिकतम संभव सीमा तक उपयोग किए जाने वाले उत्पादों, वातावरणों, कार्यक्रमों की डिजाइन और सेवाएं अभिप्रेत हैं और जो दिव्यांगजनों के विशिष्ट समूह के लिए उन्नत प्रौद्योगिकियों सहित सहायक युक्तियों पर लागू होंगी।

अध्याय 2

अधिकार और हकदारियां

समता और अविभेद।

3. (1) समुचित सरकार, यह सुनिश्चित करेगी कि दिव्यांगजन अन्य व्यक्तियों के समान, समता, गरिमा के साथ जीवन के और उसकी सत्यनिष्ठा के लिए सम्मान के अधिकार का उपभोग करे।

(2) समुचित सरकार, समुचित वातावरण प्रदान करके दिव्यांगजनों की क्षमता का उपयोग करने के लिए उपाय करेगी।

(3) किसी दिव्यांगजन के साथ दिव्यांगता के आधार पर तब तक विभेद नहीं किया जाएगा जब तक कि यह दर्शित नहीं कर दिया जाता है कि आक्षेपित कृत्य या लोप, विधिसंगत उद्देश्य को प्राप्त करने का आनुपातिक साधन है।

(4) कोई व्यक्ति केवल दिव्यांगता के आधार पर उसकी वैयक्तिक स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा।

(5) समुचित सरकार दिव्यांगजनों के लिए युक्तियुक्त आवासन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक उपाय करेगी।

4. (1) समुचित सरकार और स्थानीय प्राधिकारी यह सुनिश्चित करने का उपाय करेंगे कि दिव्यांग स्त्री और बालक अन्य लोगों की भांति समान रूप से अपने अधिकारों का उपभोग करें। दिव्यांग महिला और बालक।

(2) समुचित सरकार और स्थानीय प्राधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी दिव्यांग बालकों को उनको प्रभावित करने वाले सभी विषयों पर अपने दृष्टिकोण व्यक्त करने का किसी समान आधार पर अधिकार होगा और उनकी आयु और दिव्यांगता को दृष्टि में रखते हुए उनको समुचित सहायता प्रदान की जाएगी।

5. (1) दिव्यांग व्यक्ति को समुदाय में जीने का अधिकार होगा। सामुदायिक जीवन।

(2) समुचित सरकार यह प्रयास करेगी कि दिव्यांग व्यक्ति को,—

(क) किसी विशिष्ट जीवन व्यवस्था में जीने के लिए बाध्य नहीं किया जाए; और

(ख) किसी ऐसे गृह, आवास की श्रेणी और अन्य समुदाय सहारा सेवाओं में, जिनमें आयु और लिंग पर सम्यक् ध्यान देते हुए, जीवन को सहारे के लिए आवश्यक व्यक्तिगत सहायता सम्मिलित है, पहुंच प्रदान की गई है।

6. (1) समुचित सरकार, दिव्यांगजन को प्रताड़ना, क्रूर, अमानवीय या अपमानजनक व्यवहार के होने से संरक्षित करने के लिए उपाय करेगी। क्रूरता और अमानवीय व्यवहार से संरक्षा।

(2) कोई दिव्यांगजन,—

(i) संसूचना की पहुंच योग्य पद्धतियों, साधनों और रूपविधानों के माध्यम से अभिप्राप्त उसकी स्वतंत्र और सूचित सम्मति के बिना; और

(ii) समुचित सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिए विहित रीति से गठित ऐसी दिव्यांगता पर अनुसंधान के लिए समिति की पूर्व अनुमति, जिसमें आधे से अन्यून सदस्य उसमें से या तो दिव्यांगजन या धारा 2 के खंड (यक) के अधीन यथावर्णित रजिस्ट्रीकृत संगठनों के सदस्य होंगे, के बिना,

किसी अनुसंधान की प्रयोग वस्तु नहीं होगा।

7. (1) समुचित सरकार, दिव्यांगजनों को दुरुपयोग, हिंसा और शोषण के सभी रूपों से संरक्षित करने के लिए उपाय करेगी और उनको रोकने के लिए वह,— दुरुपयोग, हिंसा और शोषण से संरक्षण।

(क) दुरुपयोग, हिंसा और शोषण की घटनाओं का संज्ञान लेगी तथा ऐसी घटनाओं के विरुद्ध उपलब्ध विधिक उपचार उपलब्ध कराएगी;

(ख) ऐसी घटनाओं से बचने के लिए उपाय करेगी और उनकी रिपोर्ट किए जाने के लिए प्रक्रिया विहित करेगी;

(ग) ऐसी घटनाओं के पीड़ितों का बचाव, संरक्षण और पुनर्वास करने के लिए उपाय करेगी; और

(घ) जागृति पैदा करेगी तथा जनता को सूचनाएं उपलब्ध कराएगी।

(2) ऐसा कोई व्यक्ति या रजिस्ट्रीकृत संगठन, जिसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि दुरुपयोग, हिंसा या शोषण का कोई कृत्य किसी दिव्यांगजन के विरुद्ध हुआ है या हो रहा है या उसके किए जाने की संभावना है तो वह ऐसे कार्यपालक मजिस्ट्रेट को, जिसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर ऐसी घटनाएं होती हैं, उसके बारे में सूचना दे सकेगा।

(3) कार्यपालक मजिस्ट्रेट, ऐसी सूचना की प्राप्ति पर, यथास्थिति, उसके होने को रोकने या उसको निवारित करने के लिए तुरंत उपाय करेगा या ऐसे दिव्यांगजन के संरक्षण के लिए ऐसा आदेश पारित करेगा, जो

वह ठीक समझे, जिसके अंतर्गत,—

(क) यथास्थिति, पुलिस या दिव्यांगजनों के लिए कार्य कर रहे किसी संगठन को ऐसे व्यक्ति की, यथास्थिति, सुरक्षित अभिरक्षा या उनके पुनर्वास, या दोनों की, व्यवस्था करने के लिए प्राधिकृत करते हुए ऐसे कार्य से पीड़ित का बचाव करने;

(ख) यदि ऐसा व्यक्ति ऐसी वांछ करे तो दिव्यांगजन के लिए संरक्षित अभिरक्षा उपलब्ध कराने;

(ग) ऐसे दिव्यांगजनों को भरणपोषण उपलब्ध कराने,

संबंधी कोई आदेश भी है।

(4) कोई पुलिस अधिकारी, दिव्यांगजन के दुरुपयोग, हिंसा या अत्याचार की कोई शिकायत प्राप्त करता है या अन्यथा जानकारी प्राप्त करता है तो, व्यथित व्यक्ति को निम्नलिखित की जानकारी देगा,—

(क) उपधारा (2) के अधीन संरक्षण के लिए आवेदन करने के उसके अधिकार की और सहायता प्रदान करने की अधिकारिता रखने वाले कार्यपालक मजिस्ट्रेट की विशिष्टियों की;

(ख) दिव्यांगजनों के पुनर्वास के लिए कार्य कर रहे निकटतम संगठन या संस्था की विशिष्टियों की;

(ग) निःशुल्क विधिक सहायता के अधिकार की; और

(घ) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन या ऐसे अपराध से निपटने वाली किसी अन्य विधि के अधीन शिकायत फाइल करने के अधिकार की;

परंतु इस धारा की किसी बात का अर्थ किसी भी रीति में पुलिस अधिकारी को किसी संज्ञेय अपराध के कारित होने पर सूचना की प्राप्ति पर विधि के अनुसार कार्यवाही करने के कर्तव्य से मुक्त करने के लिए नहीं लगाया जाएगा।

(5) यदि कार्यपालक मजिस्ट्रेट यह पाता है कि अभिकथित कृत्य या व्यवहार भारतीय दंड संहिता के 1860 का 45 अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन कोई अपराध गठित करता है तो वह इस प्रभाव की शिकायत को, उस विषय में अधिकारिता रखने वाले यथास्थिति, न्यायिक या महानगर मजिस्ट्रेट को अग्रप्रेषित करेगा।

संरक्षण और सुरक्षा।

8. (1) दिव्यांगजनों को जोखिम, सशस्त्र संघर्ष, मानवीय आपात स्थितियों और प्राकृतिक आपदाओं की दशाओं में समान संरक्षण और सुरक्षा प्राप्त होगी।

(2) राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण अपने आपदा प्रबंधन कार्यकलाप, जैसा कि आपदा प्रबंध अधिनियम, 2005 की धारा 2 के खंड (ड) के अधीन परिभाषित है, में 2005 का 53 दिव्यांगजनों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए दिव्यांगजनों को सम्मिलित किया जाना सुनिश्चित करने के लिए समुचित उपाय करेंगे।

(3) आपदा प्रबंध अधिनियम, 2005 की धारा 25 के अधीन गठित जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण जिले 2005 का 53 में दिव्यांगजनों के व्यौरों का अभिलेख रखेगा और ऐसे व्यक्तियों को जोखिम की किन्हीं स्थितियों से सूचित करने के लिए समुचित उपाय करेगा जिससे आपदा तैयारियों को बढ़ाया जा सके।

(4) जोखिम, सशस्त्र संघर्ष या प्राकृतिक आपदाओं की स्थितियों के पश्चात् पुनः निर्माण कार्यकलापों में 2005 का 53 लागू हुए प्राधिकरण दिव्यांगजनों की पहुंच अपेक्षाओं के अनुसार संबंधित राज्य आयुक्त के परामर्श से ऐसे कार्यकलापों का जिम्मा लेंगे।

गृह और कुटुंब।

9. (1) किसी दिव्यांग बालक को दिव्यांगता के आधार पर सिवाय किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के, यदि बालक के सर्वोत्तम हित में अपेक्षित हो, उसके अभिभावकों से पृथक् नहीं किया जाएगा।

(2) जहां अभिभावक दिव्यांग बालक की देखभाल करने में असमर्थ हैं, तो सक्षम न्यायालय ऐसे बालक को उसके नजदीकी नातेदारों के पास रखेगा और ऐसा न हो पाने पर कौटुम्बिक परिवेश में, समुदाय में या आपवादिक दशाओं में, यथापेक्षित, समुचित सरकार या गैर-सरकारी संगठनों द्वारा चलाए जा रहे आश्रय स्थलों में रखेगा।

प्रजनन अधिकार।

10. (1) समुचित सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि दिव्यांगजन की प्रजनन और परिवार नियोजन के बारे में समुचित जानकारी तक पहुंच हो।

(2) किसी दिव्यांगजन को ऐसी चिकित्सा प्रक्रिया के अधीन नहीं किया जाएगा जिसका परिणाम उसकी संसूचित सहमति के बिना बांझपन होता है।

11. भारत निर्वाचन आयोग और राज्य निर्वाचन आयोग यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी मतदान केन्द्र दिव्यांगजनों की पहुंच में हों और निर्वाचन प्रक्रिया से संबंधित सभी सामग्री उनके लिए सहजता से समझने योग्य और उनकी पहुंच में हो। मतदान में पहुंच।

12. (1) समुचित सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि दिव्यांगता के आधार पर विभेद के बिना किसी न्यायालय, अधिकरण, प्राधिकरण, आयोग या कोई अन्य न्यायिक या अर्धन्यायिक या अन्वेषण शक्तियां रखने वाले निकाय तक दिव्यांगजन अपनी पहुंच के अधिकार का प्रयोग करने के लिए समर्थ हों। न्याय तक पहुंच।

(2) समुचित सरकार दिव्यांगजनों के लिए विशेषतया जो कुटुंब से बाहर रहते हैं और ऐसे दिव्यांगजन जिन्हें विधिक अधिकारों के प्रयोग के लिए अधिक सहायता की अपेक्षा है, समुचित सहायता उपायों को करने के लिए कदम उठाएगी।

1987 का 39

(3) विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के अधीन गठित राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण यह सुनिश्चित करने के लिए कि दिव्यांगजन की अन्य व्यक्तियों के समान ही प्रस्तावित किसी स्कीम, कार्यक्रम, सुविधा या सेवा तक पहुंच हों, जिसके अन्तर्गत युक्तियुक्त आवासन भी है, उपबंध करेंगे।

(4) समुचित सरकार निम्नलिखित उपाय करेगी,—

(क) यह सुनिश्चित करेगी कि उनके सभी लोक दस्तावेज सुगम रूप विधान में हैं;

(ख) यह सुनिश्चित करेगी कि फाइल करने वाले विभागों, रजिस्ट्री या किसी अन्य अभिलेख कार्यालय में, सुगम रूप विधान में, दस्तावेजों और साक्ष्य को फाइल करने, भंडार में रखने और निर्दिष्ट करने में समर्थ बनाने के लिए आवश्यक उपस्कर की पूर्ति कर दी गई है; और

(ग) दिव्यांगजनों द्वारा उनकी अधिमानी भाषा और उनकी संसूचना के माध्यमों में दिए गए परिसाक्ष्य, बहस या मत के अभिलेखीकरण को सुकर बनाने के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं और उपस्कर उपलब्ध कराएगी।

13. (1) समुचित सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि दिव्यांगजन अन्य व्यक्तियों के समान रूप से स्थावर या जंगम, संपत्ति का स्वामित्व या विरासत, उनके वित्तीय मामलों के नियंत्रण का अधिकार रखेंगे और बैंक ऋण, बंधक और वित्तीय प्रत्यय के अन्य रूपों तक पहुंच रखेंगे। विधिक सामर्थ्य।

(2) समुचित सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि दिव्यांगजन जीवन से सभी पहलुओं में अन्य व्यक्तियों के समान आधार पर विधिक सामर्थ्य का उपभोग करे और विधि के समक्ष अन्य व्यक्तियों के रूप में समान मान्यता का अधिकार रखें।

(3) जब सहायता प्रदान करने वाले किसी व्यक्ति और किसी दिव्यांगजन के मध्य विशिष्टतया वित्तीय, सांपत्तिक या किसी अन्य आर्थिक संव्यवहार को लेकर हितों का कोई विरोध उत्पन्न हो जाता है, तब ऐसी सहायता प्रदान करने वाला व्यक्ति उक्त संव्यवहार में दिव्यांगजन को सहायता प्रदान करने से प्रविरत रहेगा:

परंतु हितों के विरोध की कोई उपधारणा इस आधार पर ही नहीं होगी कि सहायता देने वाला व्यक्ति, दिव्यांगजन का रक्त, विवाह संबंध या दत्तक ग्रहण से नातेदार है।

(4) कोई दिव्यांगजन किसी सहायता संबंधी ठहराव को परिवर्तित, उपांतरित या समाप्त कर सकेगा और किसी दूसरे की सहायता प्राप्त कर सकेगा:

परंतु ऐसा परिवर्तन, उपांतरण या समाप्ति भविष्यलक्षी प्रकृति की होगी और उपर्युक्त सहायता संबंधी ठहराव में दिव्यांगजन द्वारा किए गए किसी तीसरे पक्षकार के संव्यवहार को अकृत नहीं करेंगे।

(5) दिव्यांगजन को सहायता प्रदान करने वाला कोई व्यक्ति असम्यक् असर का प्रयोग नहीं करेगा और उसकी स्वायत्तता, गरिमा और निजता का सम्मान करेगा।

संरक्षकता के लिए
उपबंध।

14. (1) इस अधिनियम के आरंभ होने की तारीख से ही, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कोई जिला न्यायालय या राज्य सरकार द्वारा यथा अधिसूचित कोई अभिहित प्राधिकारी पाता है कि कोई दिव्यांगजन जिसे पर्याप्त और समुचित सहायता प्रदान की गई थी किंतु वह विधिक रूप से आबद्धकर विनिश्चयों को लेने में असमर्थ है तो ऐसे व्यक्ति के परामर्श से ऐसी रीति में जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाए, उसकी ओर से विधिक रूप से आबद्धकर विनिश्चय लेने के लिए सीमित संरक्षक की और सहायता प्रदान की जा सकेगी:

परंतु, यथास्थिति, जिला न्यायालय या अभिहित प्राधिकारी ऐसी सहायता की अपेक्षा रखने वाले दिव्यांगजन के लिए पूर्ण सहायता प्रदान कर सकेंगे या जहां सीमित संरक्षकता बार-बार प्रदान की जानी है उस दशा में दी जाने वाली सहायता की प्रकृति और रीति का अवधारण करने के लिए, दी जाने वाली सहायता की बाबत विनिश्चय का यथास्थिति, न्यायालय या अभिहित प्राधिकारी द्वारा पुनर्विलोकन किया जाएगा।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए “सीमित संरक्षकता” से संयुक्त विनिश्चय की एक प्रणाली अभिप्रेत है जो संरक्षक और दिव्यांगजन के मध्य पारस्परिक समझदारी और भरोसे पर प्रचालित है जो विनिर्दिष्ट अवधि और विनिर्दिष्ट विनिश्चय तथा स्थिति तक सीमित होगी और दिव्यांगजन की इच्छानुसार कार्य करेगी।

(2) इस अधिनियम के आरंभ होने की तारीख से ही दिव्यांगजन के लिए तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के किसी उपबंध के अधीन नियुक्त प्रत्येक संरक्षक को, सीमित संरक्षक के रूप में कार्य करने के लिए समझा जाएगा।

(3) किसी विधिक संरक्षक की नियुक्ति करने के, अभिहित प्राधिकारी के विनिश्चय द्वारा व्यथित कोई दिव्यांगजन ऐसे अपीलीय प्राधिकारी को अपील कर सकेगा जिसे इस प्रयोजन के लिए राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए।

सहायता के लिए
प्राधिकारियों के
पदाभिधान।

15. (1) समुचित सरकार दिव्यांगजनों के विधिक सामर्थ्य के प्रयोग करने में उनकी सहायता करने के लिए समुदाय को गतिशील करने और सामाजिक जागरूकता सृजित करने के लिए एक या अधिक प्राधिकारियों को अभिहित करेगी।

(2) उपधारा (1) के अधीन अभिहित प्राधिकारी संस्थान में रहने वाले और जिन्हें अधिक सहायता की आवश्यकता है दिव्यांगजनों द्वारा विधिक सामर्थ्य के प्रयोग के लिए उपयुक्त सहायता संबंधी ठहरावों की स्थापना करने के लिए उपाय करेगा और कोई अन्य उपाय, जो अपेक्षित हो, करेगा।

अध्याय 3

शिक्षा

शिक्षण संस्थानों का
कर्तव्य।

16. समुचित सरकार और स्थानीय प्राधिकारी प्रयास करेंगे कि उनके द्वारा सभी वित्तपोषित व मान्यताप्राप्त शिक्षण संस्थाएं दिव्यांग बालकों के लिए सम्मिलित शिक्षा प्रदान करें और इस संबंध में निम्नलिखित उपाय करेंगी,—

- (i) उन्हें बिना किसी विभेद के प्रवेश देना और अन्य व्यक्तियों के समान खेल और आमोद-प्रमोद गतिविधियों के लिए अवसर प्रदान करना;
- (ii) भवन, परिसर और विभिन्न सुविधाओं तक पहुंच बनाना;
- (iii) व्यक्तिगत अपेक्षाओं के अनुसार युक्तियुक्त वास सुविधा प्रदान करना;
- (iv) ऐसे वातावरण में, जो पूर्ण समावेशन के ध्येय के संगत शैक्षणिक और सामाजिक विकास को उच्चतम सीमा तक बढ़ाते हैं, व्यक्तिपरक या अन्यथा आवश्यकता सहायता प्रदान करना;
- (v) यह सुनिश्चित करना कि ऐसे व्यक्ति को, जो अंधा या बधिर या दोनों हैं, संसूचना की समुचित भाषाओं और रीतियों तथा साधनों में शिक्षा प्रदान करना;
- (vi) बालकों में विनिर्दिष्ट विद्या दिव्यांगताओं का शीघ्रतम पता लगाना और उन पर काबू पाने के लिए उपयुक्त शैक्षणिक और अन्य उपाय करना;
- (vii) प्रत्येक दिव्यांग छात्र के संबंध में शिक्षा के प्राप्ति स्तरों और पूर्णता के रूप में उसकी भागीदारी, प्रगति को मानीटर करना;
- (viii) दिव्यांग बालकों और उच्च सहायता की आवश्यकता वाले दिव्यांग बालकों के परिचर के लिए भी परिवहन सुविधाएं उपलब्ध कराना।

17. समुचित सरकार और स्थानीय प्राधिकारी धारा 16 के प्रयोजन के लिए निम्नलिखित उपाय करेंगे, अर्थात्:—

सम्मिलित शिक्षा को संवर्धित करने और सुकर बनाने के लिए विनिर्दिष्ट उपाय।

(क) दिव्यांग बालकों की पहचान करने के लिए उनकी विशेष आवश्यकताओं को अभिनिश्चित करने और उस परिमाण के संबंध में जहां तक उन्हें वह पूरा कर लिया गया है, स्कूल जाने वाले बालकों के लिए हर पांच वर्ष में सर्वेक्षण करना;

परंतु पहला सर्वेक्षण इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर किया जाएगा;

(ख) पर्याप्त संख्या में शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं को स्थापित करना;

(ग) शिक्षकों को, जिसके अंतर्गत दिव्यांग अध्यापक भी हैं जो सांकेतिक भाषा और ब्रेल में अर्हित हैं और ऐसे शिक्षकों को भी, जो बौद्धिक रूप में दिव्यांग बालकों के अध्यापन में प्रशिक्षित हैं, प्रशिक्षित और नियोजित करना;

(घ) स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों पर सम्मिलित शिक्षा में सहायता करने के लिए वृत्तिकों और कर्मचारिवृंद को प्रशिक्षित करना;

(ङ) स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों पर शैक्षिक संस्थाओं की सहायता के लिए संसाधन केन्द्रों को पर्याप्त संख्या में स्थापित करना;

(च) वाक्शक्ति, संप्रेषण या भाषा दिव्यांगता वाले व्यक्तियों के दैनिक संप्रेषण की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किसी की स्वयं की वाक्शक्ति के उपयोग की अनुपूर्ति के लिए संप्रेषण, ब्रेल और सांकेतिक भाषा के साधनों और रूपविधानों सहित समुचित संवर्धी और अनुकल्पी पद्धतियों के प्रयोग का संवर्धन करना;

(छ) संदर्भित दिव्यांग छात्रों को अठारह वर्ष की आयु तक पुस्तकें, अन्य विद्या सामग्री और समुचित सहायक युक्तियां निःशुल्क उपलब्ध कराना;

(ज) संदर्भित दिव्यांग छात्रों के समुचित मामलों में छात्रवृत्ति प्रदान करना;

(झ) दिव्यांग छात्रों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए पाठ्यक्रम और परीक्षा प्रणाली में उपयुक्त उपांतरण करना जैसे परीक्षा पत्र को पूरा करने के लिए अधिक समय, एक लिपिक या लेखक की सुविधा, दूसरी और तीसरी भाषा के पाठ्यक्रमों से छूट;

(ञ) विद्या में सुधार के लिए अनुसंधान को बढ़ावा देना; और

(ट) कोई अन्य उपाय, जो अपेक्षित हों।

18. समुचित सरकार या स्थानीय प्राधिकारी प्रौढ़ शिक्षा में दिव्यांगजनों की भागीदारी को संवर्धित, संरक्षित और सुनिश्चित करने के लिए और अन्य व्यक्तियों के समान शिक्षा कार्यक्रम जारी रखने के लिए उपाय करेंगे। प्रौढ़ शिक्षा।

अध्याय 4

कौशल विकास और नियोजन

19. (1) समुचित सरकार दिव्यांगजनों के लिए नियोजन, विशेषकर उनके व्यावसायिक प्रशिक्षण और स्वनियोजन को सुकर बनाने और उसमें सहायता करने के लिए, जिसके अंतर्गत रियायती दरों पर ऋण उपलब्ध कराना भी है, स्कीम और कार्यक्रम बनाएगी। व्यावसायिक प्रशिक्षण और स्वनियोजन।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट स्कीमों और कार्यक्रमों में निम्नलिखित उपबंध होंगे,—

(क) सभी मुख्य धारा के औपचारिक और गैर-औपचारिक वृत्तिक और कौशल प्रशिक्षण स्कीम और कार्यक्रमों में दिव्यांगजनों को सम्मिलित किया जाना;

(ख) यह सुनिश्चित करना कि किसी दिव्यांगजन को विनिर्दिष्ट प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए पर्याप्त सहायता और सुविधाएं प्राप्त हैं;

(ग) ऐसे दिव्यांगजनों के लिए जो विकासात्मक, बौद्धिक, बहुविध दिव्यांगता स्वपरायणता वाले हैं, अनन्य कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम बनाना, जिनका प्रभावी संयोजन बाजार के साथ हों;

(घ) रियायती दर पर ऋण, जिसके अंतर्गत सूक्ष्म उधार भी है;

(ङ) दिव्यांगजनों द्वारा बनाए गए उत्पादों का विपणन; और

(च) कौशल प्रशिक्षण और स्वनियोजन में की गई प्रगति पर असंकलित डाटा बनाए रखना जिसके अंतर्गत दिव्यांगजन भी हैं।

नियोजन में विभेद न करना।

20. (1) कोई भी सरकारी स्थापन नियोजन से संबंधित किसी मामले में किसी दिव्यांगजन के विरुद्ध विभेद नहीं करेगा:

परंतु समुचित सरकार किसी स्थापन में किए जाने वाले कार्यों के प्रकार को ध्यान में रखते हुए अधिसूचना द्वारा और ऐसे निबंधनों के अधीन रहते हुए, यदि कोई हो, इस धारा के उपबंधों से किसी स्थापन को छूट प्रदान कर सकेगी।

(2) प्रत्येक स्थापन दिव्यांग कर्मचारियों को युक्तियुक्त आवासन और समुचित अवरोध मुक्त तथा सहायक वातावरण उपलब्ध कराएगा।

(3) केवल दिव्यांगता के आधार पर किसी व्यक्ति को प्रोन्नति से इंकार नहीं किया जाएगा।

(4) कोई सरकारी स्थापन, किसी ऐसे कर्मचारी को, जो अपनी सेवा के दौरान कोई दिव्यांगता ग्रहण करता है, उसे अभिमुक्त या उसके रैंक में कमी नहीं करेगा:

परंतु यदि कोई कर्मचारी, दिव्यांगता ग्रहण करने के पश्चात् उस पद के लिए उपयुक्त नहीं रह जाता है जिसे वह धारित करता है तो उसे समान वेतनमान और सेवा के फायदों के साथ किसी अन्य पद पर स्थानान्तरित किया जाएगा:

परंतु यह और कि यदि कर्मचारी को किसी अन्य पद पर समायोजित करना संभव नहीं है तो वह उपयुक्त पद उपलब्ध होने तक या अधिवर्षिता की आयु प्राप्त होने तक इनमें से जो पूर्ववर्ती हो, किसी अधिसंख्या पद पर रखा जा सकेगा।

(5) समुचित सरकार दिव्यांग कर्मचारियों की तैनाती और स्थानांतरण के लिए नीति बना सकेगी।

समान अवसर नीति।

21. (1) प्रत्येक स्थापन इस अध्याय के उपबंधों के अनुसरण में उसके द्वारा किए जाने वाले प्रस्तावित समान अवसर नीति से संबंधित उपायों को ऐसी रीति में, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए, अधिसूचित करेगा।

(2) प्रत्येक स्थापन, यथास्थिति, मुख्य आयुक्त या राज्य आयुक्त के पास उक्त नीति की एक प्रति रजिस्टर करेगा।

अभिलेखों का रखा जाना।

22. (1) प्रत्येक स्थापन, इस अध्याय के उपबंधों के अनुपालन में उपलब्ध कराए गए नियोजन, सुविधाओं के मामलों के संबंध में दिव्यांग व्यक्तियों के अभिलेख रखेगा और अन्य आवश्यक जानकारी ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति में, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए, रखेगा।

(2) प्रत्येक रोजगार कार्यालय रोजगार चाहने वाले दिव्यांग व्यक्तियों के अभिलेख रखेगा।

(3) उपधारा (1) के अधीन रखे गए अभिलेख, ऐसे व्यक्तियों द्वारा जो समुचित सरकार द्वारा उनके निमित्त प्राधिकृत किए जाएं सभी युक्तियुक्त समयों पर निरीक्षण के लिए खुले रहेंगे।

शिकायत प्रतितोष अधिकारी की नियुक्ति।

23. (1) प्रत्येक सरकारी स्थापन, धारा 19 के प्रयोजन के लिए एक शिकायत प्रतितोष अधिकारी नियुक्त करेगा और यथास्थिति, मुख्य आयुक्त या राज्य आयुक्त को ऐसे अधिकारी की नियुक्ति के बारे में सूचना देगा।

(2) धारा 20 के उपबंधों के अनुपालन से व्यथित कोई व्यक्ति शिकायत प्रतितोष अधिकारी को शिकायत फाइल कर सकेगा जो उसका अन्वेषण करेगा और सुधार कार्रवाई के लिए स्थापन से मामले को विचार में लेगा।

(3) शिकायत प्रतितोष अधिकारी शिकायतों का एक रजिस्टर ऐसी रीति में रखेगा, जिसे केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित किया जाए और प्रत्येक शिकायत की, इसके रजिस्ट्रीकरण के दो सप्ताह के भीतर जांच की जाएगी।

(4) यदि व्यथित व्यक्ति का उसकी शिकायत पर की गई कार्रवाई से समाधान नहीं होता है तो वह जिला स्तर दिव्यांगता समिति के पास जा सकेगा या सकेगी।

अध्याय 5

सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य, पुनर्वास और आमोद-प्रमोद

24. (1) समुचित सरकार, उसकी आर्थिक क्षमता और विकास की सीमा के भीतर उनके स्वतंत्र रूप से या समुदाय में रहने के लिए उन्हें समर्थ बनाने के लिए पर्याप्त जीवन स्तर के लिए दिव्यांगजनों के अधिकारों की सुरक्षा और संवर्धन के लिए आवश्यक स्कीमों और कार्यक्रम बनाएगी: सामाजिक सुरक्षा।

परंतु ऐसी स्कीमों और कार्यक्रमों के अधीन दिव्यांगजनों को सहायता का परिमाण अन्य व्यक्तियों के लिए लागू उन्हीं स्कीमों से कम से कम पच्चीस प्रतिशत अधिक होगा।

(2) समुचित सरकार, इन स्कीमों और कार्यक्रमों को बनाने के समय दिव्यांगता, लिंग, आयु और सामाजिक-आर्थिक प्रास्थिति की विविधता पर सम्यक् विचार करेगी।

(3) उपधारा (1) के अधीन स्कीमों में निम्नलिखित के लिए उपबंध होंगे,—

(क) सुरक्षा, स्वच्छता, स्वास्थ्य देख-रेख और परामर्श के रूप में अच्छी जीवन परिस्थितियों सहित सामुदायिक केन्द्र;

(ख) ऐसे व्यक्तियों के लिए जिसके अंतर्गत दिव्यांग बालक भी हैं, जिनका कुटुंब नहीं है या जो परित्यक्त या बिना आश्रय या जीवन निर्वाह के हैं, सुविधाएं;

(ग) प्राकृतिक या मानव निर्मित आपदा के दौरान और संघर्ष के क्षेत्र में सहायता;

(घ) दिव्यांग महिलाओं के जीवन निर्वाह के लिए और उनके बालकों के पालन-पोषण के लिए सहायता;

(ङ) सुरक्षित पेय जल और समुचित तथा पहुंच में स्वच्छता सुविधाएं विशेषतया नगरीय गंदी-बस्ती और ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंच;

(च) ऐसी आय की सीमा, जो अधिसूचित की जाए, के साथ दिव्यांग व्यक्तियों को निःशुल्क सहायता और साधित्र, ओषधियां और नैदानिक सेवाएं तथा सुधारात्मक शल्यचिकित्सा उपलब्ध कराना;

(छ) ऐसी आय की सीमा, जो अधिसूचित की जाए, के अधीन रहते हुए दिव्यांग व्यक्तियों को दिव्यांगता पेंशन;

(ज) दो वर्ष से अधिक की अवधि के लिए विशेष रोजगार कार्यालय में रजिस्ट्रीकृत ऐसे दिव्यांग व्यक्तियों को बेरोजगारी भत्ता, जिन्हें लाभपूर्ण व्यवसाय में नहीं रखा जा सका था;

(झ) उच्च सहायता की आवश्यकताओं वाले दिव्यांगजनों के लिए देख-रेख प्रदाता भत्ता;

(ञ) ऐसे दिव्यांगजनों के लिए व्यापक बीमा स्कीम जो राज्य कर्मचारी बीमा स्कीम या किसी अन्य कानूनी या सरकार द्वारा प्रायोजित बीमा स्कीम के अंतर्गत नहीं आते हैं;

(ट) कोई अन्य विषय जिसे समुचित सरकार ठीक समझे।

स्वास्थ्य देख-रेख।

25. (1) समुचित सरकार और स्थानीय प्राधिकारी दिव्यांगजनों को निम्नलिखित उपलब्ध कराने के लिए उपाय करेगी,—

(क) ऐसी कुटुंब आय, जो अधिसूचित की जाए, के अधीन रहते हुए, आसपास विशेषतया ग्रामीण क्षेत्रों में निःशुल्क स्वास्थ्य देख-रेख;

(ख) सरकार के सभी भागों और निजी अस्पतालों तथा अन्य स्वास्थ्य देख-रेख संस्थाओं और केन्द्रों में बाधा रहित पहुँच;

(ग) परिचर्या और उपचार में पूर्विक्ता।

(2) समुचित सरकार और स्थानीय प्राधिकारी स्वास्थ्य देख-रेख की अभिवृद्धि और दिव्यांगता की घटनाओं को रोकने के लिए उपाय करेंगे और स्कीम या कार्यक्रम बनाएंगे और उक्त प्रयोजनों के लिए निम्नलिखित करेंगे,—

(क) दिव्यांगता की घटनाओं के कारणों से संबंधित सर्वेक्षण, अन्वेषण और अनुसंधान करना या कराना;

(ख) दिव्यांगता को रोकने के लिए विभिन्न पद्धतियों को प्रोन्नत करना;

(ग) “जोखिम के” मामलों की पहचान करने के प्रयोजन के लिए वर्ष में कम से कम एक बार सभी बालकों की जाँच करना;

(घ) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर कर्मचारिवृंद को प्रशिक्षण के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराना;

(ङ) जागरुकता अभियान प्रायोजित करना या कराना और साधारण आरोग्य, स्वास्थ्य और स्वच्छता के लिए जानकारी का प्रसार करना या कराना;

(च) माता और बालक की प्रसवपूर्व, प्रसव के दौरान और प्रसव के पश्चात् देख-रेख के लिए उपाय करना;

(छ) पूर्वस्कूल, स्कूल, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, ग्राम स्तर कार्यकर्ताओं और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के माध्यम से जनता को शिक्षित करना;

(ज) दिव्यांगता के कारणों और अंगीकृत किए जाने वाले निरोधात्मक उपायों को टेलीविजन, रेडियो और अन्य जन संचार साधनों के माध्यम से जनता के मध्य जागरुकता उत्पन्न करना;

(झ) प्राकृतिक आपदाओं और अन्य जोखिम की स्थितियों के समय के दौरान स्वास्थ्य देख-रेख;

(ञ) जीवनरक्षक आपात उपचार और प्रक्रियाओं के लिए आवश्यक चिकित्सीय सुविधाएं; और

(ट) विशेषतया दिव्यांग स्त्रियों के लिए लैंगिक और प्रजनक स्वास्थ्य देख-रेख।

बीमा स्कीमें।

26. समुचित सरकार, अधिसूचना द्वारा दिव्यांग कर्मचारियों के लिए बीमा स्कीमें बनाएगी।

पुनर्वास।

27. (1) समुचित सरकार और स्थानीय प्राधिकारी सभी दिव्यांगजनों के लिए विशिष्टतया स्वास्थ्य, शिक्षा और नियोजन के क्षेत्रों में उनकी आर्थिक क्षमता और विकास के भीतर सेवाओं और पुनर्वास के कार्यक्रमों की जिम्मेवारी लेंगे या जिम्मेवारी दिलाएंगे।

(2) उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए समुचित सरकार और स्थानीय प्राधिकारी, गैर-सरकारी संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान कर सकेंगे।

(3) समुचित सरकार और स्थानीय प्राधिकारी, पुनर्वास स्कीम पुनर्वास नीतियों की विरचना के समय दिव्यांगजनों के लिए कार्यरत गैर-सरकारी संगठनों से परामर्श करेंगे।

अनुसंधान और विकास।

28. समुचित सरकार ऐसे मुद्दों पर व्यष्टियों या संस्थाओं के माध्यम से जिनसे आवास और पुनर्वास और ऐसे अन्य मुद्दे जो दिव्यांगजनों के लाभ के लिए आवश्यक समझे जाएं, के माध्यम से अनुसंधान और विकास आरंभ करेगी या कराएगी।

29. समुचित सरकार और स्थानीय प्राधिकारी, सभी दिव्यांगजनों के अधिकारों के संवर्धन, संरक्षण और अन्य व्यक्तियों के समान आमोद-प्रमोद गतिविधियों में भागीदारी के उपाय करेंगे, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित भी हैं:—

(क) दिव्यांग कलाकारों और लेखकों को उनकी अभिरुचि और प्रतिभा को बढ़ाने के लिए सुविधा, सहायता और प्रायोजन;

(ख) दिव्यांगता इतिहास संग्रहालय की स्थापना जो दिव्यांगजनों के ऐतिहासिक अनुभवों को लिपिबद्ध और उनका निर्वचन करते हैं;

(ग) दिव्यांगजनों तक कला को सुगम बनाना;

(घ) आमोद-प्रमोद केन्द्रों और अन्य सामाजिक गतिविधियों का संवर्धन करना;

(ङ) बालचर, नृत्य, कला कक्षाएं, बाहरी कैप और रोमांचक गतिविधियों में भागीदारी को सुकर बनाना;

(च) दिव्यांगजनों के लिए पहुंच और भागीदारी को समर्थ बनाने के लिए सांस्कृतिक और कला विषयों के पाठ्यक्रमों को पुनः डिजाइन करना;

(छ) आमोद-प्रमोद गतिविधियों में दिव्यांगजनों के लिए पहुंच और उनको सम्मिलित करने को सुकर बनाने के लिए तकनीकी सहायक युक्तियां और उपस्करों का विकास करना; और

(ज) सुनिश्चित करना कि श्रवणशक्ति के ह्रास के व्यक्ति सांकेतिक भाषांतरण या उपशीर्षक सहित टेलीविजन कार्यक्रमों तक पहुंच कर सकें।

30. (1) समुचित सरकार दिव्यांगजनों की खेलकूद गतिविधियों में प्रभावी भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए उपाय करेगी।

(2) खेलकूद प्राधिकारी खेलकूदों में भागीदारी के लिए दिव्यांगजनों के अधिकारों को सम्यक् मान्यता देंगे और उनकी खेलकूद प्रतिभा के संवर्धन और विकास के लिए अपनी स्कीमों और कार्यक्रमों में दिव्यांगजनों को सम्मिलित करने के लिए सम्यक् उपबंध करेंगे।

(3) उपधारा (1) और उपधारा (2) में अन्तर्विष्ट उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना समुचित सरकार और खेल प्राधिकारी निम्नलिखित उपाय करेंगे,—

(क) सभी खेलकूद गतिविधियों में दिव्यांगजनों की पहुंच, समावेशन और उनकी भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए पाठ्यक्रमों और कार्यक्रमों की पुनर्संरचना;

(ख) दिव्यांगजनों के लिए सभी खेलकूद गतिविधियों और अवसंरचनात्मक सुविधाओं का पुनः डिजाइन और उसमें सहायता;

(ग) सभी दिव्यांगजनों के लिए अंतःशक्ति, प्रतिभा, सामर्थ्य और योग्यता बढ़ाने के लिए तकनीक का विकास;

(घ) सभी दिव्यांगजनों के लिए प्रभावी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए सभी खेलकूद गतिविधियों में बहुसंवेदी आवश्यकताएं और विशेषताएं प्रदान करना;

(ङ) दिव्यांगजनों के प्रशिक्षण के लिए अत्याधुनिक खेलकूद सुविधाओं के विकास के लिए निधियों का आर्बंटन करना;

(च) दिव्यांगजनों के लिए दिव्यांगता विनिर्दिष्ट खेलकूद आयोजनों को संवर्धित करना और आयोजित करना तथा ऐसे खेलकूद प्रतियोगिताओं के विजेताओं और अन्य भागीदारों को भी पुरस्कार देने को सुकर बनाना।

संस्कृति और
आमोद-प्रमोद।

खेलकूद
गतिविधियां।

अध्याय 6

संदर्भित दिव्यांगजनों के लिए विशेष उपबंध

संदर्भित दिव्यांग
बालकों को
निःशुल्क शिक्षा।

31. (1) निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी छह वर्ष से अठारह वर्ष तक का संदर्भित प्रत्येक दिव्यांग बालक का निकटवर्ती विद्यालय या उसकी पसंद की किसी विशेष विद्यालय में निःशुल्क शिक्षा का अधिकार होगा। 2009 का 35

(2) समुचित सरकार और स्थानीय प्राधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि संदर्भित प्रत्येक दिव्यांग बालक को अठारह वर्ष की आयु प्राप्त होने तक समुचित वातावरण में निःशुल्क शिक्षा की पहुंच हो।

उच्च शिक्षा संस्थाओं
में आरक्षण।

32. (1) उच्च शिक्षा की सभी सरकारी संस्थाएं और सरकार से सहायता प्राप्त कर रही अन्य शिक्षा संस्थाएं संदर्भित दिव्यांगजनों के लिए कम से कम पांच प्रतिशत स्थानों को आरक्षित रखेंगी।

(2) उच्च शिक्षा संस्थाओं में प्रवेश के लिए संदर्भित दिव्यांगजनों को ऊपरी आयु सीमा में पांच वर्ष तक शिथिलता दी जाएगी।

आरक्षण के लिए
पदों की पहचान।

33. समुचित सरकार,—

(i) स्थापन में ऐसे पदों की पहचान करेगी जिन्हें धारा 34 के उपबंधों के अनुसार आरक्षित रिक्तियों की बाबत संदर्भित दिव्यांगजनों से संबंधित प्रवर्ग के व्यक्तियों द्वारा धारण किया जा सकता है;

(ii) ऐसे पदों की पहचान करने के लिए संदर्भित दिव्यांगजनों के प्रतिनिधित्व के साथ विशेषज्ञ समिति का गठन करेगी;

(iii) पहचाने गए पदों का तीन वर्ष से अनधिक अंतराल पर आवधिक पुनर्विलोकन करेगी।

आरक्षण।

34. (1) प्रत्येक समुचित सरकार, प्रत्येक सरकारी स्थापन में नियुक्ति के लिए संदर्भित दिव्यांगजनों द्वारा भरे जाने के लिए आशयित पदों के प्रत्येक समूह से प्रवर्ग में कुल रिक्तियों की संख्या का चार प्रतिशत संदर्भित दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित करेगी,—

(क) अंध और निम्न दृष्टि;

(ख) बधिर और श्रवणशक्ति में ह्रास;

(ग) चलन दिव्यांगता जिसके अंतर्गत प्रमस्तिष्क घात, रोगमुक्त कुष्ठ, बौनापन, तेजाब आक्रमण के पीड़ित और पेशीय दुष्पोषण भी है;

(घ) स्वपरायणता, बौद्धिक दिव्यांगता, विशिष्ट अधिगम दिव्यांगता और मानसिक रुग्णता;

(ङ) प्रत्येक दिव्यांगता के लिए पहचान किए गए पदों में खंड (क) से खंड (घ) के अधीन व्यक्तियों में से बहुदिव्यांगता जिसके अंतर्गत बधिर, अंधता भी है:

परंतु यह कि प्रोन्नति में आरक्षण ऐसे अनुदेशों के अनुसार होगा जो समय-समय पर समुचित सरकार द्वारा जारी किए जाते हैं:

परंतु यह और कि समुचित सरकार, यथास्थिति, मुख्य आयुक्त या राज्य आयुक्त के परामर्श से किसी सरकारी स्थापन में कार्य करने के प्रकार को ध्यान में रखते हुए अधिसूचना द्वारा और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, यदि कोई हो, जो ऐसी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाएं, किसी सरकारी स्थापन को इस धारा के उपबंधों से छूट प्रदान कर सकेगी।

(2) जहां कोई रिक्ति किसी भर्ती वर्ष में उपयुक्त संदर्भित दिव्यांगजन की गैर-उपलब्धता के कारण या कोई अन्य पर्याप्त कारण से भरी नहीं जा सकेगी ऐसी रिक्ति पश्चात्पूर्व भर्ती वर्ष में अग्रणीत होगी और यदि पश्चात्पूर्व भर्ती वर्ष में भी उपयुक्त संदर्भित दिव्यांगजन उपलब्ध नहीं होता है तो पहले यह पांच प्रवर्गों में से अदला-बदली द्वारा हो सकेगी और केवल जब उक्त वर्ष में भी पद के लिए दिव्यांगजन उपलब्ध नहीं होता है तो नियोक्ता किसी दिव्यांगजन से भिन्न किसी व्यक्ति की नियुक्ति द्वारा रिक्ति को भर सकेगा:

परंतु यदि किसी स्थापन में रिक्तियों की प्रकृति ऐसी है कि दिए गए प्रवर्गों के व्यक्तियों को नियोजित नहीं किया जा सकता तो रिक्तियों की समुचित सरकार के पूर्व अनुमोदन से पांच प्रवर्गों में अदला-बदली की जा सकेगी।

(3) समुचित सरकार, अधिसूचना द्वारा संदर्भित दिव्यांगजनों के नियोजन के लिए ऊपरी आयु सीमा में ऐसा शिथिलीकरण प्रदान कर सकेगी जैसा वह ठीक समझे।

35. समुचित सरकार और स्थानीय प्राधिकारी, अपनी आर्थिक क्षमता और विकास की सीमा के भीतर यह सुनिश्चित करने के लिए कि उनके कार्यबल में कम से कम पांच प्रतिशत संदर्भित दिव्यांगजन प्राइवेट सेक्टरों में नियोजक को प्रोत्साहन प्रदान करेंगे।

प्राइवेट सेक्टर में नियोजकों को प्रोत्साहन।

36. समुचित सरकार, अधिसूचना द्वारा यह अपेक्षा कर सकेगी कि ऐसी तारीख से, प्रत्येक स्थापन में नियोजक, दिव्यांगजनों के लिए नियत ऐसी रिक्तियों के संबंध में, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाएं जो उस स्थापन में हुई है या होने वाली है, ऐसे विशेष रोजगार कार्यालय को, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए, ऐसी जानकारी या विवरणी भेजेगी और स्थापन उस पर ऐसी अध्यपेक्षा का पालन करेगा।

विशेष रोजगार कार्यालय।

37. समुचित सरकार और स्थानीय प्राधिकारी, अधिसूचना द्वारा संदर्भित दिव्यांगजन के पक्ष में निम्नलिखित उपबंध करने के लिए स्कीमें बनाएंगे,—

विशेष स्कीमें और विकास कार्यक्रम।

(क) संदर्भित दिव्यांग स्त्रियों की समुचित पूर्विकता के साथ सभी सुसंगत स्कीमों और विकास कार्यक्रमों में, कृषि भूमि और आवासन के आबंटन में पांच प्रतिशत आरक्षण;

(ख) संदर्भित दिव्यांग स्त्रियों की पूर्विकता के साथ सभी निर्धनता उपशमन और विभिन्न विकासशील स्कीमों में पांच प्रतिशत आरक्षण;

(ग) रियायती दर पर भूमि के आबंटन में पांच प्रतिशत आरक्षण जहां ऐसी भूमि का उपयोग, आवासन, आश्रय, उपजीविका के गठन, कारबार, उद्यम, आमोद-प्रमोद केन्द्रों, उत्पादन केन्द्रों के संवर्धन के प्रयोजन के लिए किया जाता है।

अध्याय 7

उच्च सहायता की आवश्यकताओं वाले दिव्यांगजनों के लिए विशेष उपबंध

38. (1) संदर्भित कोई दिव्यांगजन जो स्वयं उच्च सहायता की आवश्यकता समझता है या उसकी ओर से कोई व्यक्ति या संगठन, अधिक सहायता प्रदान किए जाने के लिए अनुरोध करते हुए समुचित सरकार द्वारा अधिसूचित होने वाले प्राधिकारी को आवेदन कर सकेगा।

उच्च सहायता की आवश्यकता वाले दिव्यांगजनों के लिए विशेष उपबंध।

(2) उपधारा (1) के अधीन किसी आवेदन की प्राप्ति पर, प्राधिकारी, इसे ऐसे व्यक्तियों से मिलकर बनने वाले निर्धारित बोर्ड को भेजेगा जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित किया जाए।

(3) निर्धारण बोर्ड, उपधारा (1) के अधीन इसे निर्दिष्ट किए गए मामले का ऐसी रीति में निर्धारण करेगा जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित किया जाए और अधिक सहायता की आवश्यकता और इसकी प्रकृति को प्रमाणित करके, अधिकारी को रिपोर्ट भेजेगा।

(4) उपधारा (3) के अधीन रिपोर्ट की प्राप्ति पर, प्राधिकारी, रिपोर्ट के अनुसार और इस निमित्त समुचित सरकार की सुसंगत स्कीमों और आदेशों के अधीन सहायता प्रदान करने के लिए उपाय करेगा।

अध्याय 8

समुचित सरकारों के कर्तव्य और उत्तरदायित्व

39. (1) समुचित सरकार, यथास्थिति, मुख्य आयुक्त या राज्य आयुक्त से परामर्श करके इस अधिनियम के अधीन दिव्यांगजनों को दिए गए अधिकारों के संरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए जागरूकता अभियानों और सुग्राह्यता कार्यक्रमों का संचालन, प्रोत्साहन, उसमें सहायता या संवर्धन करेगी।

जागरूकता अभियान।

(2) उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट ऐसे कार्यक्रमों और अभियानों में निम्नलिखित भी किया जाएगा,—

(क) समावेशन, सहनशीलता, समानुभूति के मूल्यों का संवर्धन और विविधता के लिए आदर;

(ख) दिव्यांगजनों के कौशल, गुणों और योग्यताओं की अग्रिम पहचान और कार्यबल, श्रम बाजार में उनका योगदान और वृत्तिक फीस;

(ग) पारिवारिक जीवन, नातेदारियों, बालकों के वहन और पालन-पोषण से संबंधित सभी विषयों पर दिव्यांगजनों द्वारा किए गए विनिश्चयों के लिए आदर का पोषण;

(घ) दिव्यांगता की मानवीय दशा पर विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय और वृत्तिक प्रशिक्षण स्तर तथा दिव्यांगजनों के अधिकारों पर अभिसंस्करण करना और सुग्राही बनाना;

(ङ) दिव्यांगता की दशाओं और नियोजकों, प्रशासकों और सहकर्मियों के प्रति दिव्यांगजनों के अधिकारों पर अभिसंस्करण और सुग्राह्यता प्रदान करना;

(च) यह सुनिश्चित करना कि विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों और स्कूलों के पाठ्यक्रमों में दिव्यांगजनों के अधिकार सम्मिलित हैं।

पहुंच।

40. केन्द्रीय सरकार, मुख्य आयुक्त के परामर्श से समुचित प्रौद्योगिकियों और प्रणालियों तथा शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में जनता को प्रदान की गई सुविधाओं और सेवाओं सहित भौतिक वातावरण, परिवहन, जानकारी और संसूचना के लिए पहुंच के मानकों को अधिकथित करते हुए दिव्यांगजनों के लिए विनियम विरचित करेगा।

परिवहन तक पहुंच।

41. (1) समुचित सरकार, निम्नलिखित का उपबंध करने के लिए उपयुक्त उपाय करेगी,—

(क) बस अड्डे और रेलवे स्टेशनों तथा हवाई अड्डों पर दिव्यांगजनों के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करना जो पार्किंग स्थलों, प्रसाधनों, टिकट खिड़कियों और टिकट मशीनों से संबंधित पहुंच मानकों के अनुरूप हों;

(ख) परिवहन के सभी ढंगों तक पहुंच प्रदान करना जो परिवहन के पश्च फिटिंग पुराने ढंगों सहित डिजाइन मानकों के अनुरूप हों, जहां कभी वे दिव्यांगजनों के लिए प्रौद्योगिक रूप से संभाव्य और सुरक्षित हों, आर्थिक रूप में व्यवहार्य हों और डिजाइन में मुख्य संरचना के परिवर्तन में भार डाले बिना हों;

(ग) दिव्यांगजनों के लिए आवश्यक गतिशीलता के समाधान के लिए पहुंच योग्य सड़कें।

(2) समुचित सरकार, निम्नलिखित के लिए उपबंध करने के लिए वहन करने योग्य लागत पर दिव्यांगजनों की वैयक्तिक गतिशीलता के संवर्धन के लिए स्कीमों, कार्यक्रमों को विकसित करेगी,—

(क) प्रोत्साहन और रियायतें;

(ख) वाहनों की पश्च फिटिंग; और

(ग) वैयक्तिक गतिशीलता सहायता।

सूचना और संचार प्रौद्योगिकी तक पहुंच।

42. समुचित सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए उपाय करेगी कि,—

(i) श्रव्य, प्रिंट और इलैक्ट्रॉनिक मीडिया में उपलब्ध सभी अंतर्वस्तुएं पहुंच योग्य फार्मेट में हैं;

(ii) श्रव्य वर्णन, संकेत भाषा निर्वचन और क्लोज्ड कैप्शनिंग, उपलब्ध कराके दिव्यांगजनों की इलैक्ट्रॉनिक मीडिया तक पहुंच है;

(iii) इलैक्ट्रॉनिक माल और उपस्कर जो प्रतिदिन उपयोग के लिए सर्वव्यापी डिजाइन में उपलब्ध कराए जाने के लिए आशयित हैं।

उपभोक्ता माल।

43. समुचित सरकार दिव्यांगजनों के साधारण उपयोग के लिए सर्वव्यापी रूप से डिजाइन किए गए उपभोक्ता उत्पादों और उपसाधनों के विकास, उत्पादन और वितरण के संवर्धन के लिए उपाय करेगी।

पहुंच सन्निधियों का आज्ञापक रूप से अनुपालन।

44. (1) किसी स्थापन को किसी संरचना के निर्माण की मंजूरी नहीं दी जाएगी यदि भवन योजना में धारा 40 के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाए गए विनियमों का पालन नहीं किया जाता है।

(2) किसी स्थापन को तब तक पूर्णता प्रमाणपत्र जारी नहीं किया जाएगा या भवन का अधिभोग करने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा जब तक वह केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाए गए विनियमों का पालन नहीं करता है।

45. (1) ऐसे विनियमों की अधिसूचना की तारीख से पांच वर्ष से अनधिक अवधि के भीतर केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाए गए विनियमों के अनुसार सभी विद्यमान सार्वजनिक भवन सुगम्य बनाए जाएंगे:

परंतु केन्द्रीय सरकार राज्यों को इस उपबंध के पालन के लिए मामला दर मामला आधार पर उनकी तैयारी की अवस्था और अन्य संबंधित पैमानों पर निर्भर रहते हुए समय का विस्तार मंजूर कर सकेगी।

(2) समुचित सरकार और स्थानीय प्राधिकारी उनके सभी भवनों और स्थानों में आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाले जैसे प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सिविल/जिला अस्पताल, विद्यालय, रेलवे स्टेशन और बस अड्डा जैसी सभी तक, पहुंच प्रदान करने के लिए पूर्विकता पर आधारित कार्ययोजना बनाएंगे और प्रकाशित करेंगे।

46. सेवा प्रदाता चाहे सरकारी हो या प्राइवेट, केन्द्रीय सरकार द्वारा धारा 40 के अधीन पहुंच पर बनाए गए नियमों के अनुसार ऐसे नियमों की अधिसूचना की तारीख से दो वर्ष की कालावधि के भीतर सेवाएं प्रदान करेगा:

परंतु केन्द्रीय सरकार मुख्य आयुक्त के परामर्श से उक्त नियमों के अनुसार कतिपय प्रवर्ग की सेवाएं प्रदान करने के लिए समय का विस्तार मंजूर कर सकेगी।

1992 का 34

47. (1) भारतीय पुनर्वास परिषद् अधिनियम, 1992 के अधीन गठित भारतीय पुनर्वास परिषद् के किसी कृत्य और शक्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, समुचित सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए मानव संसाधन का विकास करने के लिए प्रयास करेगी और उस ध्येय के लिए निम्नलिखित करेगी—

(क) पंचायती राज सदस्यों, विधायकों, प्रशासकों, पुलिस पदधारियों, न्यायाधीशों, वकीलों के प्रशिक्षण के लिए सभी पाठ्यक्रमों में दिव्यांगता के अधिकारों पर आज्ञापक प्रशिक्षण;

(ख) विद्यालयों, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों के अध्यापकों, चिकित्सकों, नर्सों, अर्धचिकित्सा कर्मिकों, सामाजिक कल्याण अधिकारियों, ग्रामीण विकास अधिकारियों, आशा कार्यकर्ताओं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, इंजीनियरों, वास्तुविदों, अन्य वृत्तिकों और सामुदायिक कार्यकर्ताओं के लिए सभी शैक्षिक पाठ्यक्रमों के लिए दिव्यांगता का घटक के रूप में समावेश कराना;

(ग) स्वावलम्बी जीवन में प्रशिक्षण और परिवारों के लिए सामुदायिक संबंधों, समुदाय के सदस्यों और अन्य पणधारियों और देख-रेख करने और सहायता करने पर देख-रेख प्रदाता सहित क्षमता निर्माण कार्यक्रम आरंभ करना;

(घ) पारस्परिक योगदान और आदर पर समुदाय संबंधों का निर्माण करने के लिए दिव्यांगजनों के लिए स्वतंत्र प्रशिक्षण सुनिश्चित करना;

(ङ) क्रीड़ा, खेलकूद, रोमांचकारी गतिविधियों पर ध्यान देने के साथ क्रीड़ा अध्यापकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन करना;

(च) कोई अन्य क्षमता विकास के उपाय, जो आवश्यक हों।

(2) सभी विश्वविद्यालय ऐसे अध्ययनों के लिए अध्ययन केन्द्रों की स्थापना सहित दिव्यांगता संबंधी अध्ययनों में शिक्षण और अनुसंधान का संवर्धन करेंगे।

(3) उपधारा (1) में कथित बाध्यता को पूरा करने के लिए, समुचित सरकार, प्रत्येक पांच वर्ष में आवश्यकता आधारित विश्लेषण करेंगी और भर्ती, प्रवेश, सुग्राह्यता अभिसंस्करण और इस अधिनियम में विभिन्न उत्तरदायित्वों के निर्वाह के लिए उपयुक्त कर्मिकों के प्रशिक्षण के लिए योजनाएं बनाएगी।

48. समुचित सरकार दिव्यांगजनों वाली सभी साधारण स्कीमों और कार्यक्रमों की सामाजिक लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित करने के लिए करेगी कि स्कीम और कार्यक्रम दिव्यांगजनों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालते हैं और दिव्यांगजनों की अपेक्षाओं और चिंताओं के लिए आवश्यक हैं।

विद्यमान अवसरचना और सुगम्य परिसर बनाने के लिए समय-सीमा तथा उस प्रयोजन के लिए कार्रवाई।

सेवा प्रदाताओं द्वारा पहुंच के लिए समय-सीमा।

मानव संसाधन विकास।

सामाजिक लेखा परीक्षा।

अध्याय 9

दिव्यांगजनों के लिए संस्थाओं का रजिस्ट्रीकरण और ऐसी संस्थाओं को अनुदान

सक्षम प्राधिकारी।

49. राज्य सरकार, ऐसे प्राधिकारी को नियुक्त करेगी जो वह इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए सक्षम प्राधिकारी होने के लिए ठीक समझे।

रजिस्ट्रीकरण।

50. इस अधिनियम के अधीन जैसा अन्यथा उपबंधित है उसके सिवाय, कोई भी व्यक्ति दिव्यांगजनों के लिए किसी संस्था की स्थापना या उसका अनुरक्षण इस निमित्त सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र के अनुसार ही करेगा अन्यथा नहीं:

परंतु मानसिक रूप से रुग्ण व्यक्तियों की देख-रेख के लिए कोई संस्था जो मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम, 1987 की धारा 8 या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियम के अधीन विधिमान्य अनुज्ञप्ति धारित करती है, उसे इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत किए जाने की आवश्यकता नहीं होगी। 1987 का 14

आवेदन और
रजिस्ट्रीकरण
प्रमाणपत्र की
मंजूरी।

51. (1) रजिस्ट्रीकरण के प्रमाणपत्र के लिए प्रत्येक आवेदन सक्षम प्राधिकारी को ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति में किया जाएगा जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाए।

(2) उपधारा (1) के अधीन किसी आवेदन की प्राप्ति पर, सक्षम प्राधिकारी ऐसी जांच करेगा जो वह ठीक समझे और यह समाधान हो जाने पर कि आवेदक ने इस अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए नियमों की अपेक्षाओं का अनुपालन किया है, वह आवेदन की प्राप्ति के 90 दिन की अवधि के भीतर आवेदक को रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र मंजूर करेगा और यदि उसका समाधान नहीं होता है तो सक्षम प्राधिकारी, आदेश द्वारा आवेदन किए गए प्रमाणपत्र को मंजूर करने से इंकार कर देगा:

परंतु सक्षम प्राधिकारी प्रमाणपत्र मंजूर करने से इंकार करने वाला कोई आदेश करने से पूर्व आवेदक को सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर देगा और प्रमाणपत्र मंजूर करने से इंकार का प्रत्येक आदेश आवेदक को लिखित में संसूचित करेगा।

(3) उपधारा (2) के अधीन रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र तब तक मंजूर नहीं किया जाएगा जब तक संस्था जिसके बारे में आवेदन किया गया है, ऐसी सुविधाएं प्रदान करने और ऐसे मानक जो राज्य सरकार द्वारा विहित किए जाएं, को पूरा करने की स्थिति में न हो।

(4) उपधारा (2) के अधीन मंजूर किया गया रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र,—

(क) जब तक धारा 52 के अधीन प्रतिसंहृत नहीं होता ऐसी अवधि के लिए जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाए, प्रवृत्त बना रहेगा;

(ख) वैसी ही अवधि के लिए समय-समय पर नवीकृत किया जा सकेगा; और

(ग) ऐसे प्ररूप में होगा और ऐसी शर्तों के अध्वधीन होगा जो राज्य सरकार द्वारा विहित किया जाए।

(5) रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र के नवीकरण के लिए कोई आवेदन विधिमान्यता की अवधि की समाप्ति के कम से कम साठ दिन पूर्व किया जाएगा।

(6) रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र की एक प्रति, संस्था द्वारा सहजदृश्य स्थान पर प्रदर्शित की जाएगी।

(7) उपधारा (1) या उपधारा (5) के अधीन किए गए प्रत्येक आवेदन का निपटारा, सक्षम प्राधिकारी द्वारा ऐसी अवधि के भीतर किया जाएगा जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाए।

रजिस्ट्रीकरण का
प्रतिसंहरण।

52. (1) सक्षम प्राधिकारी, यदि उसका विश्वास करने का यह कारण है कि धारा 51 की उपधारा (2) के अधीन मंजूर किए गए रजिस्ट्रीकरण के प्रमाणपत्र के धारक ने,—

(क) प्रमाणपत्र के जारी करने या नवीकरण के लिए किसी आवेदन के संबंध में ऐसा कथन किया है जो गलत है या तात्त्विक विशिष्टियों में मिथ्या है; और

(ख) नियमों या किन्हीं ऐसी शर्तों को भंग किया है या भंग करवाया है जिनके अधीन प्रमाणपत्र मंजूर किया गया था,

वह ऐसी जांच करने के पश्चात् जो वह ठीक समझे, आदेश द्वारा प्रमाणपत्र को प्रतिसंहत कर सकेगा:

परन्तु ऐसा कोई आदेश तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि प्रमाणपत्र के धारक को इस बात का कारण बताने का अवसर न प्रदान कर दिया हो कि रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र प्रतिसंहत क्यों न कर दिया जाए।

(2) जहां किसी संस्था के संबंध में उपधारा (1) के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र का प्रतिसंहरण किया गया है वहां ऐसी संस्था, ऐसे प्रतिसंहरण की तारीख से कार्य करना बन्द कर देगी:

परन्तु जहां प्रतिसंहरण आदेश के विरुद्ध धारा 53 के अधीन कोई अपील होती है, वहां ऐसी संस्था निम्नलिखित दशाओं में कार्य करना बन्द कर देगी,—

(क) जहां ऐसी अपील फाइल करने के लिए विहित अवधि के अवसान पर तुरंत अपील नहीं की गई है; या

(ख) जहां ऐसी कोई अपील की गई है, किन्तु अपील के आदेश की तारीख से प्रतिसंहरण आदेश को मान्य ठहराया गया है।

(3) किसी संस्था की बाबत रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र के प्रतिसंहरण पर, सक्षम प्राधिकारी निदेश दे सकेगा कि कोई दिव्यांगजन जो ऐसे प्रतिसंहरण की तारीख को, ऐसी संस्था में अन्तःवासी है,—

(क) यथास्थिति, उसे उसके माता-पिता, पति या पत्नी या विधिक संरक्षक की अभिरक्षा में प्रत्यावर्तित कर दिया जाएगा, या

(ख) सक्षम प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट किसी अन्य संस्था को स्थानांतरित कर दिया जाएगा।

(4) प्रत्येक संस्था, जो रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र धारण करता है जिसका इस धारा के अधीन प्रतिसंहरण कर लिया गया है, ऐसे प्रतिसंहरण के तुरंत पश्चात् ऐसे प्रमाणपत्र को सक्षम प्राधिकारी को अभ्यर्पित कर देगी।

53. (1) प्रमाणपत्र प्रदान करने से इंकार करने या प्रमाणपत्र का प्रतिसंहरण करने के सक्षम प्राधिकारी के आदेश से व्यथित व्यक्ति, राज्य सरकार द्वारा यथाविहित अवधि के भीतर, ऐसे आदेश के विरुद्ध, ऐसे अपील प्राधिकारी को जो राज्य सरकार द्वारा अपील प्राधिकारी के रूप में अधिसूचित किया जाए, अपील कर सकेगा।

(2) ऐसी अपील पर अपील प्राधिकारी का आदेश अंतिम होगा।

54. इस अध्याय में अंतर्विष्ट कोई बात केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा दिव्यांगजनों के लिए स्थापित या अनुरक्षित किसी संस्था को लागू नहीं होगी।

अधिनियम का केन्द्रीय या राज्य सरकार द्वारा स्थापित या अनुरक्षित संस्थाओं को लागू न होना।

55. समुचित सरकार उसकी आर्थिक क्षमता और विकास की सीमाओं के भीतर रजिस्ट्रीकृत संस्थाओं को, सेवा प्रदान करने के लिए और इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसरण में स्कीमों और कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने के लिए, वित्तीय सहायता प्रदान कर सकेगी।

रजिस्ट्रीकृत संस्थाओं को सहायता।

अध्याय 10

विनिर्दिष्ट दिव्यांगताओं का प्रमाणन

56. केन्द्रीय सरकार किसी व्यक्ति में विनिर्दिष्ट दिव्यांगता की सीमा का निर्धारण करने के प्रयोजन के लिए मार्गदर्शक सिद्धांतों को अधिसूचित करेगी।

विनिर्दिष्ट दिव्यांगताओं के निर्धारण के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत।

57. (1) समुचित सरकार अपेक्षित अर्हताएं और अनुभव रखने वाले व्यक्तियों को प्रमाणकर्ता प्राधिकारियों के रूप में पदाभिहित करेगी, जो दिव्यांगता प्रमाणपत्र जारी करने के लिए सक्षम होंगे।

प्रमाणकर्ता प्राधिकारियों के पदाभिधान।

(2) समुचित सरकार उस अधिकारिता को और उन निबंधनों और शर्तों को भी अधिसूचित करेगी जिनके अधीन रहते हुए प्रमाणकर्ता प्राधिकारी अपने प्रमाणकारी कृत्यों का पालन करेगा।

प्रमाण की प्रक्रिया।

58. (1) कोई विनिर्दिष्ट दिव्यांगजन अधिकारिता रखने वाले प्रमाणकर्ता प्राधिकारी को ऐसी रीति में जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए, दिव्यांगता का प्रमाणपत्र जारी करने के लिए आवेदन कर सकेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन आवेदन की प्राप्ति पर, प्रमाणकर्ता प्राधिकारी, धारा 56 के अधीन अधिसूचित सुसंगत मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार संबंधित व्यक्ति की दिव्यांगता का निर्धारण करेगा और ऐसे निर्धारण के पश्चात् यथास्थिति—

(क) ऐसे व्यक्ति को ऐसे प्ररूप में जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित किया जाए, दिव्यांगता का एक प्रमाणपत्र जारी करेगा;

(ख) उसे लिखित में सूचित करेगा कि उसको कोई विनिर्दिष्ट दिव्यांगता नहीं है।

(3) इस धारा के अधीन जारी दिव्यांगता का प्रमाणपत्र संपूर्ण देश में मान्य होगा।

प्रमाणकर्ता प्राधिकारी के विनिश्चय के विरुद्ध अपील।

59. (1) प्रमाणकर्ता प्राधिकारी के विनिश्चय से व्यथित कोई व्यक्ति, ऐसे विनिश्चय के विरुद्ध ऐसे समय और ऐसी रीति में जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाए, इस प्रयोजन के लिए राज्य सरकार द्वारा यथा पदाभिहित अपील प्राधिकारी को अपील कर सकेगा।

(2) किसी अपील की प्राप्ति पर अपील प्राधिकारी अपील का ऐसी रीति में, जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाए, विनिश्चय करेगा।

अध्याय 11

केन्द्रीय और राज्य दिव्यांगता सलाहकार बोर्ड तथा जिला स्तर समिति

केन्द्रीय दिव्यांगता सलाहकार बोर्ड का गठन।

60. (1) केन्द्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा केन्द्रीय दिव्यांगता सलाहकार बोर्ड के नाम से ज्ञात एक निकाय का गठन, इस अधिनियम के अधीन उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने के लिए और सौंपे गए कृत्यों का निर्वहन करने के लिए करेगी।

(2) केन्द्रीय दिव्यांगता सलाहकार बोर्ड निम्नलिखित से मिलकर बनेगा,—

(क) केन्द्रीय सरकार के दिव्यांगता कार्य विभाग का प्रभारी मंत्री—पदेन अध्यक्ष;

(ख) केन्द्रीय सरकार के दिव्यांगता कार्य मंत्रालय में दिव्यांगता कार्य विभाग से संबंधित प्रभारी राज्य मंत्री—पदेन उपाध्यक्ष;

(ग) तीन सांसद, जिनमें से दो का निर्वाचन लोक सभा द्वारा और एक का राज्य सभा द्वारा किया जाएगा—पदेन सदस्य;

(घ) सभी राज्यों के दिव्यांगता कार्य के प्रभारी मंत्री और संघ राज्यक्षेत्रों के प्रशासक/उपराज्यपाल—पदेन सदस्य;

(ङ) दिव्यांगता कार्य, सामाजिक न्याय और अधिकारिता, स्कूल शिक्षा और साक्षरता तथा उच्चतर शिक्षा, महिला और बाल विकास, व्यय, कार्मिक और प्रशिक्षण, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, ग्रामीण विकास, पंचायती राज, औद्योगिक नीति और संवर्धन, शहरी विकास, आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी, विधि कार्य, लोक उद्यम, युवा कार्य और खेल, सड़क परिवहन और राजमार्ग, नागर विमानन मंत्रालयों या विभागों के भारसाधक सचिव, भारत सरकार—पदेन सदस्य;

(च) सचिव, नेशनल इन्स्टीट्यूट आफ ट्रांसफार्मिंग इन्डिया (नीति) आयोग—पदेन सदस्य;

(छ) अध्यक्ष, भारतीय पुनर्वास परिषद्—पदेन सदस्य;

(ज) अध्यक्ष, राष्ट्रीय स्वलीनता, प्रमस्तिष्क घात, स्वपरायणता, मानसिक मंदता और बहुदिव्यांगता कल्याण न्यास—पदेन सदस्य;

- (झ) अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, राष्ट्रीय दिव्यांग वित्त विकास निगम—पदेन सदस्य;
- (ञ) अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, कृत्रिम अंग विनिर्माण निगम—पदेन सदस्य;
- (ट) अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड—पदेन सदस्य;
- (ठ) महानिदेशक, नियोजन और प्रशिक्षण, श्रम और रोजगार मंत्रालय—पदेन सदस्य;
- (ड) निदेशक, राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्—पदेन सदस्य;
- (ढ) अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्—पदेन सदस्य;
- (ण) अध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग—पदेन सदस्य;
- (त) अध्यक्ष, भारतीय चिकित्सा परिषद्—पदेन सदस्य;
- (थ) निम्नलिखित संस्थानों के निदेशक पदेन सदस्य होंगे,—

- (i) राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान, देहरादून;
- (ii) राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान, सिकन्दराबाद;
- (iii) पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय शारीरिक दिव्यांगजन संस्थान, नई दिल्ली;
- (iv) अली यावर जंग राष्ट्रीय वाक् एवं श्रवण दिव्यांगजन संस्थान, मुम्बई;
- (v) राष्ट्रीय गतिशील दिव्यांगजन संस्थान, कोलकाता;
- (vi) राष्ट्रीय पुनर्वास प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, कटक;
- (vii) राष्ट्रीय बहु दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान, चेन्नई;
- (viii) राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और विज्ञान संस्थान, बैंगलोर;
- (ix) इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर, दिल्ली;

- (द) केंद्रीय सरकार द्वारा नामनिर्देशित किए जाने वाले सदस्य,—

- (i) पांच व्यक्ति जो दिव्यांगता और पुनर्वास के क्षेत्र में विशेषज्ञ हैं;
- (ii) दिव्यांगता से संबंधित गैर-सरकारी संगठनों या दिव्यांगजन संगठनों का प्रतिनिधित्व करने के लिए जहां तक व्यवहार्य हो, ऐसे दस व्यक्ति, जो दिव्यांगजन हों:

परंतु नामनिर्दिष्ट दस व्यक्तियों में से कम से कम पांच महिलाएं होंगी और कम से कम एक-एक व्यक्ति अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति में से होगा;

- (iii) राष्ट्रीय स्तर के वाणिज्य और उद्योग-मंडल में से तीन प्रतिनिधि तक;

(ध) दिव्यांगता नीति के विषय से संबंधित भारत सरकार का संयुक्त सचिव—पदेन सदस्य सचिव।

61. (1) इस अधिनियम के अधीन अन्यथा उपबंधित के सिवाय, धारा 60 की उपधारा (2) के खंड (द) के अधीन नामनिर्दिष्ट केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड का कोई सदस्य उसके नामनिर्देशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा: सदस्यों की सेवा के निबंधन और शर्तें।

परंतु ऐसा सदस्य उसकी पदावधि की समाप्ति के होते हुए भी तब तक अपने पद पर रहेगा जब तक कि उसका उत्तरवर्ती पद ग्रहण नहीं कर लेता है।

(2) केन्द्रीय सरकार, यदि वह ठीक समझे तो धारा 60 की उपधारा (2) के खंड (द) के अधीन नामनिर्दिष्ट किसी सदस्य को उसकी पदावधि की समाप्ति से पूर्व उसे हेतुक उपदर्शित करने का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् पद से हटा सकेगी।

(3) धारा 60 की उपधारा (2) के खंड (द) के अधीन नामनिर्दिष्ट कोई सदस्य केन्द्रीय सरकार को संबोधित अपने हस्ताक्षर से किसी भी समय अपना पद त्याग सकेगा और तत्पश्चात् उक्त सदस्य का पद रिक्त हो जाएगा।

(4) केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड में किसी आकस्मिक रिक्ति को नए नामनिर्देशन द्वारा भरा जाएगा और रिक्ति को भरने के लिए नामनिर्दिष्ट व्यक्ति केवल उस सदस्य की शेष अवधि के लिए पद धारण करेगा, जिसके स्थान पर वह इस प्रकार नामनिर्दिष्ट किया गया था।

(5) धारा 60 की उपधारा (2) के खंड (द) के उपखंड (i) या उपखंड (iii) के अधीन नामनिर्दिष्ट कोई सदस्य पुनः नामनिर्देशन के लिए पात्र होगा।

(6) धारा 60 की उपधारा (2) के खंड (द) के उपखंड (i) और उपखंड (ii) के अधीन नामनिर्दिष्ट सदस्य ऐसे भत्ते प्राप्त करेंगे जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित किए जाएं।

निरहता।

62. (1) कोई व्यक्ति केंद्रीय सलाहकार बोर्ड का सदस्य नहीं होगा,—

(क) जो दिवालिया है या जिसे किसी समय दिवालिया न्यायनिर्णीत किया गया है या उसने अपने ऋणों के संदाय को निलंबित किया है या अपने लेनदारों के साथ उपशमन किया है, या

(ख) जो विकृतचित्त है और उसे सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित किया गया है, या

(ग) जो ऐसे किसी अपराध के लिए सिद्धदोष है या ठहराया गया है, जिसमें केन्द्रीय सरकार की राय में नैतिक अधमता अंतर्वलित है, या

(घ) जो इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए सिद्धदोष है या जिसे किसी समय सिद्धदोष ठहराया गया है, या

(ङ) जिसने केन्द्रीय सरकार की राय में सदस्य के रूप में अपने पद का ऐसा दुरुपयोग किया है जो उसके पद पर बने रहने को साधारण जनता के हितों के प्रतिकूल ठहराता है।

(2) इस धारा के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा हटाए जाने का कोई आदेश तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि संबद्ध सदस्य को उसके विरुद्ध हेतुक उपदर्शित करने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान नहीं कर दिया जाता है।

(3) धारा 61 की उपधारा (1) या उपधारा (5) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इस धारा के अधीन पद से हटाया गया कोई सदस्य, सदस्य के रूप में पुनः नामनिर्देशन के लिए पात्र नहीं होगा।

सदस्यों द्वारा स्थानों की रिक्ति।

63. यदि केंद्रीय सलाहकार बोर्ड का कोई सदस्य, धारा 62 में विनिर्दिष्ट निरहताग्रस्त हो जाता है तो उसका स्थान रिक्त हो जाएगा।

केन्द्रीय दिव्यांगता सलाहकार बोर्ड की बैठकें।

64. केंद्रीय सलाहकार बोर्ड प्रत्येक छह मास में कम से कम एक बैठक करेगा और अपनी बैठकों में कारबार के संव्यवहार के लिए ऐसे नियमों और प्रक्रिया का अनुपालन करेगा जो विहित की जाए।

केन्द्रीय दिव्यांगता सलाहकार बोर्ड के कृत्य।

65. (1) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए केंद्रीय दिव्यांगता सलाहकार बोर्ड, दिव्यांगता विषयों पर राष्ट्रीय स्तर का परामर्शदाता और सलाहकार निकाय होगा और दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण और अधिकारों के पूर्ण उपयोग के लिए समग्र नीति के सतत् विकास को सुकर बनाएगा।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, केंद्रीय दिव्यांगता सलाहकार बोर्ड निम्नलिखित कृत्यों का पालन करेगा, अर्थात्:—

(क) केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों को दिव्यांगता के बारे में नीतियों, कार्यक्रमों, विधान और परियोजनाओं पर सलाह देना;

(ख) दिव्यांगजनों से संबंधित मुद्दों पर ध्यान देने के लिए एक राष्ट्रीय नीति का विकास करना;

(ग) सरकार के सभी विभागों तथा सरकारी और अन्य गैर-सरकारी संगठनों के, जो दिव्यांगजनों से संबंधित मामलों से संबंधित हैं, कार्यकलापों का पुनर्विलोकन और समन्वयन करना;

(घ) राष्ट्रीय योजनाओं में दिव्यांगजनों के लिए स्कीमों और परियोजनाओं का उपबंध करने की दृष्टि से संबंधित प्राधिकारियों और अंतरराष्ट्रीय संगठनों के साथ दिव्यांगजनों के मामलों पर विचार करना;

(ङ) सूचना, सेवाओं के प्रति दिव्यांगजनों की पहुंच, युक्तियुक्त वास और भेदभावहीनता को सुनिश्चित करने के लिए और उसके लिए वातावरण तैयार करना तथा सामाजिक जीवन में उनकी भागीदारी के लिए उपायों की सिफारिश करना;

(च) दिव्यांगजनों की संपूर्ण भागीदारी की सफलता के लिए विधियों, नीतियों और कार्यक्रमों के प्रभाव की मानीटरी और मूल्यांकन करना; और

(छ) ऐसे अन्य कृत्य करना जो समय-समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा सौंपे जाएं।

66. (1) प्रत्येक राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा राज्य दिव्यांगता सलाहकार बोर्ड के नाम से ज्ञात एक निकाय का गठन इस अधिनियम के अधीन उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने के लिए और सौंपे गए कृत्यों का निर्वहन करने के लिए करेगी। राज्य दिव्यांगता सलाहकार बोर्ड।

(2) राज्य सलाहकार बोर्ड निम्नलिखित से मिलकर बनेगा—

(क) राज्य सरकार के दिव्यांगता मामलों से संबंधित विभाग का प्रभारी मंत्री—अध्यक्ष पदेन;

(ख) राज्य सरकार के दिव्यांगता मामलों से संबंधित विभाग यदि कोई है, का प्रभारी राज्य मंत्री या उपमंत्री—उपाध्यक्ष पदेन;

(ग) दिव्यांगता कार्य, स्कूल शिक्षा और साक्षरता तथा उच्चतर शिक्षा, महिला और बाल विकास, वित्त, कार्मिक और प्रशिक्षण, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, ग्रामीण विकास, पंचायती राज, औद्योगिक नीति और संवर्धन, श्रम और रोजगार, शहरी विकास, आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी, लोक उद्यम, युवा कार्य और खेल, सड़क परिवहन और कोई अन्य विभाग जिसे राज्य सरकार आवश्यक समझे, के भारसाधक राज्य सरकार के सचिव—पदेन सदस्य;

(घ) राज्य विधान-मंडल के तीन सदस्य जिनमें से दो का निर्वाचन विधान सभा द्वारा और एक सदस्य का विधान परिषद्, यदि कोई हो, द्वारा किया जाएगा और जहां कोई विधान परिषद् नहीं है, वहां तीनों सदस्यों का निर्वाचन विधान सभा द्वारा किया जाएगा—सदस्य पदेन;

(ङ) राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले सदस्य—

(i) पांच सदस्य जो दिव्यांगता और पुनर्वास के क्षेत्र में विशेषज्ञ हैं;

(ii) जिलों का ऐसी रीति में जो विहित की जाए, प्रतिनिधित्व करने के लिए चक्रानुक्रम में राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले पांच सदस्य;

परंतु इस उपखंड के अधीन कोई नामनिर्देशन सिवाय संबंधित जिला प्रशासन की सिफारिश के नहीं किया जाएगा;

(iii) गैर-सरकारी संगठनों या संगमों जो दिव्यांगता से संबद्ध हैं, का प्रतिनिधित्व करने के लिए जहां तक व्यवहार्य हो, ऐसे दस व्यक्ति, जो दिव्यांगजन हों;

परंतु इस खंड के अधीन नामनिर्दिष्ट दस व्यक्तियों में से कम से कम पांच महिलाएं होंगी और कम से कम एक-एक व्यक्ति अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति में से होगा;

(iv) राज्य वाणिज्य और उद्योग मंडल में से तीन से अनधिक प्रतिनिधि;

(च) राज्य सरकार में दिव्यांगता विषयों से संबंधित विभाग में ऐसा अधिकारी जो संयुक्त सचिव की पंक्ति से नीचे की पंक्ति का न हो—पदेन सदस्य-सचिव।

67. (1) इस अधिनियम के अधीन अन्यथा उपबंधित के सिवाय, धारा 66 की उपधारा (2) के खंड (ङ) के अधीन नामनिर्दिष्ट राज्य सलाहकार बोर्ड का सदस्य उसके नामनिर्देशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा: सदस्यों की सेवा के निबंधन और शर्तें।

परंतु ऐसा सदस्य उसकी पदावधि की समाप्ति के होते हुए भी तब तक अपने पद पर बना रहेगा जब तक कि उसका उत्तरवर्ती पदग्रहण नहीं कर लेता है।

(2) राज्य सरकार यदि वह ठीक समझे तो धारा 66 की उपधारा (2) के खंड (ड) के अधीन नामनिर्दिष्ट किसी सदस्य को उसकी पदावधि की समाप्ति से पूर्व उसे हेतुक उपदर्शित करने का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् पद से हटा सकेंगी।

(3) धारा 66 की उपधारा (2) के खंड (ड) के अधीन नामनिर्दिष्ट कोई सदस्य राज्य सरकार को संबोधित अपने हस्ताक्षर से किसी भी समय अपना पद त्याग सकेगा और तत्पश्चात् उक्त सदस्य का पद रिक्त हो जाएगा।

(4) राज्य सलाहकार बोर्ड में किसी आकस्मिक रिक्ति को नए नामनिर्देशन द्वारा भरा जाएगा और रिक्ति को भरने के लिए नामनिर्दिष्ट व्यक्ति केवल उस सदस्य की शेष अवधि के लिए पद धारण करेगा जिसके स्थान पर वह इस प्रकार नामनिर्दिष्ट किया गया था।

(5) धारा 66 की उपधारा (2) के खंड (ड) के उपखंड (i) या उपखंड (iii) के अधीन नामनिर्दिष्ट कोई सदस्य पुनः नामनिर्देशन के लिए पात्र होगा।

(6) धारा 66 की उपधारा (2) के खंड (ड) के उपखंड (i) और उपखंड (ii) के अधीन नामनिर्दिष्ट सदस्य ऐसे भत्ते प्राप्त करेगा जो राज्य सरकार द्वारा विहित किए जाएं।

निरहता।

68. (1) कोई व्यक्ति राज्य सलाहकार बोर्ड का सदस्य नहीं होगा—

(क) जो दिवालिया है या जिसे किसी समय दिवालिया न्यायनिर्णीत किया गया है या उसने अपने ऋणों के संदाय को निलंबित किया है या अपने लेनदारों के साथ उपशमन किया है, या

(ख) जो विकृतचित्त है या उसे सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित किया गया है, या

(ग) जो किसी अपराध के लिए सिद्धदोष है या ठहराया गया है जिसमें राज्य सरकार की राय में नैतिक अधमता अंतर्वर्लित है, या

(घ) जो इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए सिद्धदोष है या जिसे किसी समय सिद्धदोष ठहराया गया है, या

(ड) जिसने राज्य सरकार की राय में सदस्य के रूप में अपने पद का ऐसा दुरुपयोग किया है जिससे उसका राज्य सलाहकार बोर्ड में बने रहना साधारण जनता के हितों के लिए हानिकर है।

(2) इस धारा के अधीन राज्य सरकार द्वारा पद से हटाने का कोई आदेश तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि संबंधित सदस्य को, उसके विरुद्ध हेतुक दर्शित करने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान नहीं कर दिया जाता है।

(3) धारा 67 की उपधारा (1) या उपधारा (5) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कोई सदस्य जो इस धारा के अधीन हटाया गया है, सदस्य के रूप में पुनः नामनिर्देशन के लिए पात्र नहीं होगा।

स्थानों का रिक्त होना।

69. यदि राज्य सलाहकार बोर्ड का कोई सदस्य धारा 68 में विनिर्दिष्ट निरहता ग्रस्त हो जाता है तो उसका स्थान रिक्त हो जाएगा।

राज्य दिव्यांगता सलाहकार बोर्ड की बैठकें।

70. राज्य सलाहकार बोर्ड प्रत्येक छह मास में कम से कम एक बैठक करेगा और अपनी बैठकों में कारबार के संव्यवहार के ऐसे नियमों या प्रक्रिया का अनुपालन करेगा जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाए।

राज्य दिव्यांगता सलाहकार बोर्ड के कृत्य।

71. (1) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, राज्य सलाहकार बोर्ड दिव्यांगता मामलों पर एक राज्यस्तरीय परामर्शदाता और सलाहकार निकाय होगा तथा दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण और अधिकारों के पूर्ण उपभोग के लिए समग्र नीति के सतत् विकास को सुकर बनाएगा।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, राज्य दिव्यांगता सलाहकार बोर्ड निम्नलिखित कृत्यों का पालन करेगा, अर्थात्:—

(क) राज्य सरकार को दिव्यांगता की बाबत नीतियों, कार्यक्रमों, विधान और परियोजनाओं पर सलाह देना;

(ख) दिव्यांगजनों से संबंधित मुद्दों पर ध्यान देने के लिए एक राज्य नीति का विकास करना;

(ग) राज्य सरकार के सभी विभागों और अन्य सरकारी और गैर-सरकारी संगठनों के, जो दिव्यांगजनों से संबंधित मामलों से संबंधित हैं, कार्यकलापों का पुनर्विलोकन और समन्वय करना;

(घ) राज्य योजनाओं में दिव्यांगजनों के लिए स्कीमों और परियोजनाओं का उपबंध करने की दृष्टि से संबंधित प्राधिकारियों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ दिव्यांगजनों के मामलों पर विचार करना;

(ङ) दिव्यांगजनों के लिए पहुंच, युक्तियुक्त रूप से वास, भेदभावहीनता सेवाओं को सुनिश्चित करने के लिए उपाय करना और वातारण तैयार करना तथा अन्य व्यक्तियों के समान आधार पर सामाजिक जीवन में उनकी भागीदारी करना;

(च) दिव्यांगजनों की संपूर्ण भागीदारी की सफलता के लिए विधियों, नीतियों और डिजाइन किए गए कार्यक्रमों के प्रभाव की मानीटरी और मूल्यांकन करना; और

(छ) ऐसे अन्य कृत्य करना जो समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा सौंपे जाएं।

72. राज्य सरकार, ऐसे कृत्य जो विहित किए जाएं, का पालन करने के लिए जिला स्तर दिव्यांगता समितियों का गठन करेगी।

जिला स्तर दिव्यांगता समिति।

73. केन्द्रीय दिव्यांगता सलाहकार बोर्ड, राज्य दिव्यांगता सलाहकार बोर्ड या जिला स्तर दिव्यांगता समिति का कोई कार्य या कार्यवाही केवल इस आधार पर प्रश्नगत नहीं होगी कि यथास्थिति, ऐसे बोर्ड या समिति में कोई रिक्ति है या गठन में कोई त्रुटि है।

रिक्तियों से कार्यवाहियों का अविधिमान्य न होना।

अध्याय 12

दिव्यांगजनों के लिए मुख्य आयुक्त और राज्य आयुक्त

74. (1) केन्द्रीय सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अधिसूचना द्वारा दिव्यांगजनों के लिए मुख्य आयुक्त (जिसे इसमें इसके पश्चात् “मुख्य आयुक्त” कहा गया है) नियुक्त कर सकेगी।

मुख्य आयुक्त और आयुक्तों की नियुक्ति।

(2) केन्द्रीय सरकार मुख्य आयुक्त की सहायता करने के लिए अधिसूचना द्वारा दो आयुक्तों की नियुक्ति कर सकेगी, जिनमें से एक आयुक्त दिव्यांगजन होगा।

(3) कोई व्यक्ति मुख्य आयुक्त या आयुक्त के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए तब तक अर्हित नहीं होगा जब तक कि उसे पुनर्वास से संबंधित विषयों के संबंध में विशेष जानकारी या व्यावहारिक अनुभव न हो।

(4) मुख्य आयुक्त और आयुक्तों को संदेय वेतन और भत्ते तथा सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें (जिसके अंतर्गत पेंशन, उपदान और अन्य सेवानिवृत्ति फायदे भी हैं) वे होंगे, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित किए जाएं।

(5) केन्द्रीय सरकार मुख्य आयुक्त की उसके कृत्यों के निर्वहन में सहायता करने के लिए अपेक्षित अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की प्रकृति तथा प्रवर्गों का अवधारण करेगी और मुख्य आयुक्त को उतने ऐसे अधिकारी और अन्य कर्मचारी उपलब्ध कराएगी, जो वह ठीक समझे।

(6) मुख्य आयुक्त को उपलब्ध कराए गए अधिकारी और कर्मचारी मुख्य आयुक्त के साधारण अधीक्षण और नियन्त्रण के अधीन अपने कृत्यों का निर्वहन करेंगे।

(7) अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन और भत्ते तथा सेवा की अन्य शर्तें वे होंगी, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाएं।

(8) मुख्य आयुक्त की एक सलाहकार समिति द्वारा सहायता की जाएगी, जो विभिन्न दिव्यांगताओं के क्षेत्र से ग्यारह से अन्तून सदस्यों से ऐसी रीति में, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए, मिलकर बनेगी।

75. (1) मुख्य आयुक्त,—

मुख्य आयुक्त के कृत्य।

(क) स्वप्रेरणा से या अन्यथा किसी विधि के उपबंध या नीति, कार्यक्रम और प्रक्रियाओं की पहचान करेगा, जो इस अधिनियम से असंगत हैं और आवश्यक सुधारकारी उपायों की सिफारिश करेगा;

(ख) स्वप्रेरणा से या अन्यथा दिव्यांगजनों को अधिकारों से वंचित करने और उन विषयों के संबंध में उन्हें उपलब्ध सुरक्षापायों की जांच करेगा जिनके लिए केन्द्रीय सरकार समुचित सरकार है और सुधारकारी कार्रवाई के लिए समुचित प्राधिकारियों के पास मामले को उठाएगा;

(ग) इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा दिव्यांगजनों के अधिकारों के संरक्षण के लिए उपलब्ध सुरक्षापायों का पुनर्विलोकन करेगा और उनके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए उपायों की सिफारिश करेगा;

(घ) उन कारकों का पुनर्विलोकन करेगा, जो दिव्यांगजनों के अधिकारों का उपभोग करने में बाधा उत्पन्न करते हैं तथा समुचित सुधारकारी उपायों की सिफारिश करेगा;

(ङ) दिव्यांगजनों के अधिकारों पर संधियों और अन्य अंतर्राष्ट्रीय लिखतों का अध्ययन करेगा और उनके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सिफारिशें करेगा;

(च) दिव्यांगजनों के अधिकारों के क्षेत्र में अनुसंधान करेगा और उसका संवर्धन करेगा;

(छ) दिव्यांगजनों के अधिकारों और उनके संरक्षण के लिए उपलब्ध सुरक्षापायों पर जागरूकता का संवर्धन करेगा;

(ज) दिव्यांगजनों के लिए आशयित इस अधिनियम के उपबंधों, स्कीमों और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की मानीटरी करेगा;

(झ) दिव्यांगजनों के फायदे के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा संवितरित निधियों के उपयोजन की मानीटरी करेगा; और

(ञ) ऐसे अन्य कृत्यों को करेगा, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा सौंपे जाएं।

(2) मुख्य आयुक्त, इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों का निर्वहन करते हुए किसी भी विषय पर आयुक्तों से परामर्श करेगा।”।

मुख्य आयुक्त की
सिफारिश पर
समुचित
प्राधिकारियों द्वारा
कार्रवाई।

76. जब भी मुख्य आयुक्त धारा 75 के खंड (ख) के अनुसरण में किसी प्राधिकारी को सिफारिश करता है तो वह प्राधिकारी उस पर आवश्यक कार्रवाई करेगा और सिफारिश प्राप्त होने की तारीख से तीन मास के भीतर की गई कार्रवाई से मुख्य आयुक्त को सूचित करेगा:

परन्तु जहां कोई प्राधिकारी किसी सिफारिश को स्वीकार नहीं करता है तो वह उसके स्वीकार न करने के कारणों को तीन मास की कालावधि के भीतर मुख्य आयुक्त को बताएगा और व्यथित व्यक्तियों को भी सूचित करेगा।

मुख्य आयुक्त की
शक्तियां।

77. (1) मुख्य आयुक्त को, इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों का निर्वहन करने के प्रयोजन के लिए वही शक्तियां होंगी, जो निम्नलिखित मामलों के संबंध में किसी वाद का विचारण करते समय सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन सिविल न्यायालय में निहित हैं, अर्थात्:—

1908 का 5

(क) किसी व्यक्ति को समन करना और उसे हाजिर कराना;

(ख) किन्हीं दस्तावेजों का प्रकटीकरण और पेश किए जाने की अपेक्षा करना;

(ग) किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रतियों की अध्यपेक्षा करना;

(घ) शपथपत्रों पर साक्ष्य ग्रहण करना; और

(ङ) किसी साक्षी या दस्तावेजों की परीक्षा के लिए कमीशन जारी करना।

(2) मुख्य आयुक्त के समक्ष प्रत्येक कार्यवाही भारतीय दंड संहिता की धारा 193 और धारा 228 के अर्थों में न्यायिक कार्यवाही होगी तथा मुख्य आयुक्त को दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 195 और अध्याय 26 के प्रयोजनों के लिए सिविल न्यायालय समझा जाएगा।

1860 का 45

1974 का 2

78. (1) मुख्य आयुक्त केन्द्रीय सरकार को एक वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा और किसी भी समय किसी विषय पर विशेष रिपोर्टें प्रस्तुत कर सकेगा जो उसकी राय में ऐसी अत्यावश्यकता या महत्ता का है कि उसे वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने तक आस्थगित नहीं किया जा सकता है।

मुख्य आयुक्त द्वारा वार्षिक और विशेष रिपोर्ट।

(2) केन्द्रीय सरकार, मुख्य आयुक्त की वार्षिक और विशेष रिपोर्टों को संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष उसकी सिफारिशों पर की गई कार्रवाई या किए जाने के लिए प्रस्तावित कार्रवाई और सिफारिशों को स्वीकार न करने के कारण, यदि कोई हों, पर एक ज्ञापन के साथ रखवाएगी।

(3) वार्षिक और विशेष रिपोर्टों को ऐसे प्ररूप और रीति में तैयार किया जाएगा तथा उनमें ऐसे ब्यौरे अंतर्विष्ट होंगे, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित किए जाएं।

79. (1) राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए दिव्यांगजनों के लिए एक राज्य आयुक्त (जिसे इसमें इसके पश्चात् “राज्य आयुक्त” कहा गया है) नियुक्त करेगी।

राज्यों में राज्य आयुक्त की नियुक्ति।

(2) कोई व्यक्ति राज्य आयुक्त के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए तब तक अर्हित नहीं होगा जब तक कि उसे पुनर्वास से संबंधित विषयों के संबंध में विशेष जानकारी या व्यावहारिक अनुभव न हो।

(3) राज्य आयुक्त को संदेय वेतन और भत्ते तथा सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें (जिसके अंतर्गत पेंशन, उपदान और अन्य सेवानिवृत्ति फायदे भी हैं) वे होंगे, जो राज्य सरकार द्वारा विहित किए जाएं।

(4) राज्य सरकार, राज्य आयुक्त की उसके कृत्यों के निर्वहन में सहायता करने के लिए अपेक्षित अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की प्रकृति तथा प्रवर्गों का अवधारण करेगी और राज्य आयुक्त को उतने ऐसे अधिकारी और अन्य कर्मचारी उपलब्ध कराएगी, जो वह ठीक समझे।

(5) राज्य आयुक्त को उपलब्ध कराए गए अधिकारी और कर्मचारी राज्य आयुक्त के साधारण अधीक्षण और नियन्त्रण के अधीन अपने कृत्यों का निर्वहन करेंगे।

(6) अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन और भत्ते तथा सेवा की अन्य शर्तें वे होंगी, जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाएं।

(7) राज्य आयुक्त की एक सलाहकार समिति द्वारा सहायता की जाएगी, जो विभिन्न दिव्यांगताओं के क्षेत्र से पांच से अन्यून सदस्यों से ऐसी रीति में, जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाए, मिलकर बनेगी।

80. राज्य आयुक्त,—

राज्य आयुक्त के कृत्य।

(क) स्वप्रेरणा से या अन्यथा किसी विधि के उपबंधों या नीति, कार्यक्रम और प्रक्रियाओं की पहचान करेगा, जो इस अधिनियम से असंगत हैं और आवश्यक सुधारकारी उपायों की सिफारिश करेगा;

(ख) स्वप्रेरणा से या अन्यथा दिव्यांगजनों को अधिकारों से वंचित करने और उन विषयों के संबंध में उन्हें उपलब्ध सुरक्षापायों की जांच करेगा जिनके लिए राज्य सरकार समुचित सरकार है और सुधारकारी कार्रवाई के लिए समुचित प्राधिकारियों के पास मामले को उठाएगा;

(ग) इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा दिव्यांगजनों के अधिकारों के संरक्षण के लिए उपलब्ध सुरक्षापायों का पुनर्विलोकन करेगा और उनके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए उपायों की सिफारिश करेगा;

(घ) उन कारकों का पुनर्विलोकन करेगा जो दिव्यांगजनों के अधिकारों का उपभोग करने में बाधा उत्पन्न करते हैं तथा समुचित सुधारकारी उपायों की सिफारिश करेगा;

(ङ) दिव्यांगजनों के अधिकारों के क्षेत्र में अनुसंधान करेगा और उसका संवर्धन करेगा;

(च) दिव्यांगजनों के अधिकारों और उनके संरक्षण के लिए उपलब्ध सुरक्षापायों पर जागरूकता का संवर्धन करेगा;

(छ) दिव्यांगजनों के लिए आशयित इस अधिनियम के उपबंधों और स्कीमों, कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की मानीटरी करेगा;

(ज) दिव्यांगजनों के फायदे के लिए राज्य सरकार द्वारा संवितरित निधियों के उपयोजन की मानीटरी करेगा; और

(झ) ऐसे अन्य कृत्यों को करेगा, जो राज्य सरकार द्वारा सौंपे जाएं।

राज्य आयुक्त की सिफारिश पर समुचित प्राधिकारियों द्वारा कार्रवाई।

81. जब भी राज्य आयुक्त धारा 80 के खंड (ख) के अनुसरण में किसी प्राधिकारी को सिफारिश करता है तो वह प्राधिकारी उस पर आवश्यक कार्रवाई करेगा और सिफारिश प्राप्त होने की तारीख से तीन मास के भीतर की गई कार्रवाई से राज्य आयुक्त को सूचित करेगा:

परंतु जहां कोई प्राधिकारी किसी सिफारिश को स्वीकार नहीं करता है तो वह उसके स्वीकार न करने के कारणों को तीन मास की कालावधि के भीतर दिव्यांगजन राज्य आयुक्त को बताएगा और व्यथित व्यक्ति को भी सूचित करेगा।

राज्य आयुक्त की शक्तियां।

82. (1) राज्य आयुक्त को, इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों का निर्वहन करने के प्रयोजन के लिए वही शक्तियां होंगी, जो निम्नलिखित मामलों के संबंध में किसी वाद का विचारण करते समय सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन सिविल न्यायालय में निहित हैं, अर्थात्:—

1908 का 5

(क) किसी व्यक्ति को समन करना और उसे हाजिर कराना;

(ख) किन्हीं दस्तावेजों का प्रकटीकरण और पेश किया जाना;

(ग) किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रतियों की अध्यपेक्षा करना;

(घ) शपथपत्रों पर साक्ष्य ग्रहण करना; और

(ङ) किसी साक्षी या दस्तावेजों की परीक्षा के लिए कमीशन जारी करना।

(2) राज्य आयुक्त के समक्ष प्रत्येक कार्यवाही भारतीय दंड संहिता की धारा 193 और धारा 228 के अर्थों में न्यायिक कार्यवाही होगी तथा मुख्य आयुक्त को और दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 195 और अध्याय 26 के प्रयोजनों के लिए सिविल न्यायालय समझा जाएगा।

1860 का 45

1974 का 2

राज्य आयुक्त द्वारा वार्षिक और विशेष रिपोर्टें।

83. (1) राज्य आयुक्त, राज्य सरकार को एक वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा और किसी भी समय किसी विषय पर विशेष रिपोर्टें प्रस्तुत कर सकेगा, जो उसकी राय में ऐसी अत्यावश्यकता या महत्ता की है कि उसे वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने तक आस्थगित नहीं किया जा सकता है।

(2) राज्य सरकार राज्य आयुक्त की वार्षिक और विशेष रिपोर्टों को राज्य विधान-मंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष उसकी सिफारिशों पर की गई कार्रवाई या किए जाने के लिए प्रस्तावित कार्रवाई और सिफारिशों को स्वीकार न करने के कारण, यदि कोई हों, पर एक ज्ञापन के साथ रखवाएगी।

(3) वार्षिक और विशेष रिपोर्टों को ऐसे प्ररूप और रीति में तैयार किया जाएगा तथा उनमें ऐसे ब्यौरे अंतर्विष्ट होंगे, जो राज्य सरकार द्वारा विहित किए जाएं।

अध्याय 13

विशेष न्यायालय

विशेष न्यायालय।

84. त्वरित विचारण प्रदान करने के प्रयोजन के लिए, राज्य सरकार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति की सहमति से, अधिसूचना द्वारा प्रत्येक जिले के लिए एक सेशन न्यायालय को इस अधिनियम के अधीन अपराधों के विचारण के लिए विशेष न्यायालय के रूप में विनिर्दिष्ट करेगी।

विशेष लोक अभियोजक।

85. राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा प्रत्येक विशेष न्यायालय के लिए उस न्यायालय में मामलों के संचालन के प्रयोजन के लिए विशेष लोक अभियोजक के रूप में एक लोक अभियोजक विनिर्दिष्ट करेगी या किसी ऐसे अधिवक्ता की नियुक्ति करेगी जो सात वर्ष से अन्यून अवधि के लिए अधिवक्ता के रूप में व्यवसाय कर रहा हो।

(2) उपधारा (1) के अधीन नियुक्त विशेष लोक अभियोजक ऐसी फीस या पारिश्रमिक प्राप्त करने का हकदार होगा जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाए।

अध्याय 14

दिव्यांगजनों के लिए राष्ट्रीय निधि

86. (1) दिव्यांगजनों के लिए राष्ट्रीय निधि नामक एक निधि का गठन किया जाएगा जिसमें निम्नलिखित दिव्यांगजनों के लिए जमा किया जाएगा— राष्ट्रीय निधि।

1890 का 6

(क) अधिसूचना सं० का०आ० 573(अ), तारीख 11 अगस्त, 1983 द्वारा गठित दिव्यांगजनों के लिए निधि और पूर्त विन्यास अधिनियम, 1890 के अधीन अधिसूचना सं०का०आ० 30-03/2004-डीडीII, तारीख 21 नवंबर, 2006 द्वारा गठित दिव्यांगजन सशक्तिकरण न्यास निधि के अधीन उपलब्ध सभी राशियां;

(ख) 2000 की सिविल अपील सं० 4655 और 5218 में तारीख 16 अप्रैल, 2004 को माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसरण में बैंकों, निगमों, वित्तीय संस्थाओं द्वारा संदेय सभी राशियां;

(ग) अनुदान, दानों, संदानों, उपकृतियों, वसीयतों या अंतरणों के माध्यम से प्राप्त सभी राशियां;

(घ) केन्द्रीय सरकार से प्राप्त सभी राशियां जिनके अंतर्गत सहायता अनुदान भी हैं;

(ङ) अन्य ऐसे स्रोतों से, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिश्चित किए जाएं, सभी राशियां।

(2) दिव्यांगजनों के लिए निधि का उपयोग और प्रबंध ऐसी रीति में किया जाएगा जो विहित की जाए।

87. (1) केन्द्रीय सरकार, उचित लेखाओं और अन्य सुसंगत अभिलेखों को रखेगी और भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के परामर्श से ऐसे प्ररूप में जो विहित किया जाए, निधि के लेखाओं का वार्षिक विवरण जिसके अंतर्गत आय और व्यय लेखा भी है, तैयार करेगी। लेखा और संपरीक्षा।

(2) निधि के लेखे भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक द्वारा ऐसे अंतरालों पर संपरीक्षित किए जाएंगे जो उसके द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं और ऐसी संपरीक्षा के संबंध में उसके द्वारा उपगत किसी भी व्यय का संदाय भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक को निधि से किया जाएगा।

(3) भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक और निधि के लेखाओं की संपरीक्षा करने के संबंध में उसके द्वारा नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति को ऐसी संपरीक्षा के संबंध में वही अधिकार, विशेषाधिकार और प्राधिकार प्राप्त होंगे जो सरकारी लेखाओं की संपरीक्षा के संबंध में साधारणतया भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक को प्राप्त होते हैं और विशिष्टतया लेखा बहियों, संबद्ध वाउचरों और अन्य दस्तावेजों तथा कागज-पत्रों को पेश करने की मांग करने तथा निधि के किसी कार्यालय का निरीक्षण करने का अधिकार होगा।

(4) भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक या इस निमित्त नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा यथाप्रमाणित निधि के लेखे, उन पर संपरीक्षा रिपोर्ट सहित केन्द्रीय सरकार द्वारा संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखे जाएंगे।

अध्याय 15

दिव्यांगजनों के लिए राज्य निधि

88. (1) राज्य सरकार द्वारा दिव्यांगजनों के लिए राज्य निधि नामक एक निधि का ऐसी रीति में, जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाए, गठन किया जाएगा। दिव्यांगजनों के लिए राज्य निधि।

(2) दिव्यांगजनों के लिए राज्य निधि का उपयोग और प्रबंध ऐसी रीति में किया जाएगा, जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाए।

(3) प्रत्येक राज्य सरकार दिव्यांगजनों के लिए निधि, जिसके अंतर्गत आय और व्यय लेखे भी हैं, के उचित लेखे और अन्य सुसंगत अभिलेख ऐसी रीति में रखेगी, जो राज्य सरकार द्वारा भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के परामर्श से विहित किए जाएं।

(4) दिव्यांगजनों के लिए राज्य निधि के लेखाओं की संपरीक्षा भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक द्वारा ऐसे अंतरालों पर की जाएगी, जो उसके द्वारा विहित किए जाएं और ऐसी संपरीक्षा के संबंध में उसके द्वारा उपगत व्यय का संदाय भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक को राज्य निधि से किया जाएगा।

(5) भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक और दिव्यांगजनों के लिए राज्य निधि के लेखाओं की संपरीक्षा के संबंध में उसके द्वारा नियुक्त किए गए किसी व्यक्ति को उस संपरीक्षा के संबंध में वही अधिकार, विशेषाधिकार और प्राधिकार होंगे, जो सरकारी लेखाओं की संपरीक्षा के संबंध में भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक को प्राप्त होते हैं और विशेष रूप से लेखा बहियों, संबंधित वाऊचरों तथा अन्य दस्तावेजों और कागज-पत्र पेश करने की मांग करने तथा राज्य निधि के कार्यालयों का निरीक्षण करने का अधिकार होगा।

(6) भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक या दिव्यांगजनों के लिए राज्य निधि के लेखाओं की संपरीक्षा के संबंध में उसके द्वारा नियुक्त किए गए किसी अन्य व्यक्ति द्वारा यथा प्रमाणित राज्य निधि के लेखे उस पर संपरीक्षा रिपोर्ट के साथ राज्य विधान-मंडल के प्रत्येक सदन के, जहां वह दो सदनों से मिलकर बना है या जहां ऐसे विधान-मंडल में एक सदन है, उस सदन के समक्ष रखे जाएंगे।

अध्याय 16

अपराध और शास्त्रियां

अधिनियम या
इसके अधीन बनाए
गए नियमों या
विनियमों के उपबंधों
के उल्लंघन के
लिए दंड।

89. (1) कोई व्यक्ति, जो इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए किसी नियम के उपबंधों का उल्लंघन करता है, पहले उल्लंघन के लिए जुर्माने से जो दस हजार रुपए तक का हो सकेगा और किसी पश्चात्पूर्व उल्लंघन के लिए जुर्माने से, जो पचास हजार रुपए से कम नहीं होगा किंतु जो पांच लाख रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा।

कंपनियों द्वारा
अपराध।

90. (1) जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कंपनी द्वारा किया गया है, वहां ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जो उस अपराध के किए जाने के समय कंपनी के कारबार के संचालन के लिए उस कंपनी का भारसाधक था और कंपनी के प्रति उत्तरदायी था और साथ ही वह कंपनी भी ऐसे अपराध के लिए दोषी समझे जाएंगे और अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और तदनुसार दंडित किए जाने के भागी होंगे:

परंतु इस उपधारा की कोई बात इस अधिनियम में उपबंधित किसी दंड के लिए किसी ऐसे व्यक्ति को भागी नहीं बनाएगी, यदि वह यह साबित कर देता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने अपराध के निवारण के लिए सब सम्यक् तत्परता बरती थी।

(2) उपधारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां इस अधिनियम के अधीन दंडनीय कोई अपराध किसी कंपनी द्वारा किया गया है और यह साबित हो जाता है कि अपराध कंपनी के किसी निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी की सम्मति या मौनानुकूलता से किया गया है, या उस अपराध का किया जाना उसकी किसी उपेक्षा का कारण माना जा सकता है वहां ऐसा निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी भी उस अपराध का दोषी समझा जाएगा और तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने का भागी होगा।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए—

(क) “कंपनी” से कोई निगमित निकाय अभिप्रेत है और इसमें कोई फर्म या व्यष्टियों का कोई अन्य संगम सम्मिलित है; और

(ख) फर्म के संबंध में “निदेशक” से उस फर्म का कोई भागीदार अभिप्रेत है।

संदर्भित दिव्यांगजनों
के लिए आशयित
किसी फायदे को
कपटपूर्वक लेने के
लिए दंड।

91. जो कोई कपटपूर्वक संदर्भित दिव्यांगजनों के लिए आशयित किसी फायदे को लेता है या लेने का प्रयत्न करता है, वह कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से दंडनीय होगा।

अत्याचारों के
अपराधों के लिए
दंड।

92. जो कोई—

(क) किसी लोक दृष्टिगोचर स्थान में दिव्यांगजन को साशय अपमानित करता है या अपमान करने के आशय से अभिन्नस्त करता है;

(ख) किसी दिव्यांगजन पर, उसका अनादर के आशय से हमला करता है या बल प्रयोग करता है या दिव्यांग महिला की लज्जा भंग करता है;

(ग) किसी दिव्यांगजन पर वास्तविक प्रभार या नियंत्रण रखते हुए, स्वेच्छया या जानते हुए उसे भोजन या तरल पदार्थ देने से इन्कार करता है;

(घ) किसी दिव्यांग बालक या महिला की इच्छा को अधिशासित करने की स्थिति में होते हुए और उस स्थिति का उपयोग उनका लैंगिक रूप से शोषण करने के लिए करता है;

(ङ) किसी दिव्यांगजन के किसी अंग या इंद्रिय या सहायक युक्ति के उपयोग में स्वेच्छया क्षति, नुकसान पहुंचाता है, या बाधा डालता है;

(च) किसी दिव्यांग महिला पर कोई चिकित्सीय प्रक्रिया करता है, उसका संचालन करता है, किए जाने के लिए या निदेश करता है जिससे उसकी अभिव्यक्त सम्मति के बिना गर्भावस्था की समाप्ति होती है या समाप्त होने की संभावना है, सिवाय उन मामलों में जहां रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायियों की राय लेकर दिव्यांगता के गंभीर मामलों में गर्भावस्था के समापन के लिए और दिव्यांग महिला के संरक्षक की सहमति से भी चिकित्सीय प्रक्रिया की गई है,

ऐसे कारावास से जिसकी अवधि छह मास से कम की नहीं होगी किन्तु जो पांच वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से दंडनीय होगा।

93. जो कोई इस अधिनियम या इसके अधीन किए गए किसी आदेश, या निदेश के अधीन पुस्तिका, लेखा या अन्य दस्तावेज पेश करने में या कोई विवरणी, जानकारी या विशिष्टियां इस अधिनियम या इसके अधीन किए गए किसी आदेश या निदेश के उपबंधों के अनुसरण में पेश करने या देने या किए गए किसी प्रश्न का उत्तर देने के लिए कर्तव्यबद्ध है, को पेश करने में असफल रहता है वह प्रत्येक अपराध की बाबत जुर्माने से दंडनीय होगा जो पच्चीस हजार रुपए तक का हो सकेगा और चालू असफलता या इंकार की दशा में अतिरिक्त जुर्माने से जो जुर्माने के दंड के अधिरोपण के मूल आदेश की तारीख के पश्चात् चालू असफलता या इंकार के लिए प्रत्येक दिन के लिए एक हजार रुपए तक हो सकेगा, दंडनीय होगा।

जानकारी प्रस्तुत करने में असफल रहने के लिए दंड।

94. कोई न्यायालय समुचित सरकार के पूर्वानुमोदन या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा फाइल किए गए किसी परिवाद के सिवाय, इस अध्याय के अधीन समुचित सरकार के किसी कर्मचारी द्वारा किए जाने के लिए अभिकथित किसी अपराध का संज्ञान नहीं लेगा।

समुचित सरकार का पूर्वानुमोदन।

95. जहां इस अधिनियम के अधीन और किसी अन्य केन्द्रीय या राज्य अधिनियम के भी अधीन कोई कार्य या लोप किसी अपराध को गठित करता है तब तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, ऐसे अपराध के लिए दोषी पाया गया अपराधी केवल ऐसे अधिनियम के दंड के लिए भागी होगा जो ऐसे दंड के लिए उपबंध करता है, जो कि डिग्री में अधिक है।

अनुकल्पी दंड।

अध्याय 17

प्रकीर्ण

96. इस अधिनियम के उपबंध, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अतिरिक्त होंगे न कि अल्पीकरण में।

अन्य विधियों का लागू होना, वर्जित न होना।

97. इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाहियां समुचित सरकार या समुचित सरकार के किसी अधिकारी या मुख्य आयुक्त या राज्य आयुक्त के किसी अधिकारी या कर्मचारी के विरुद्ध नहीं होगी।

सद्भावपूर्वक की गई कार्यवाही के लिए संरक्षण।

98. (1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो केन्द्रीय सरकार राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा ऐसे उपबंध कर सकेगी या ऐसे निदेश दे सकेगी जो कठिनाई दूर करने के लिए आवश्यक या समीचीन प्रतीत होते हों, जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हो:

कठिनाइयां दूर करने की शक्ति।

परंतु इस धारा के अधीन ऐसा कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारंभ होने की तारीख से दो वर्ष तक की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, इसके किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा।

अनुसूची का संशोधन करने की शक्ति।

99. (1) समुचित सरकार द्वारा की गई सिफारिशों पर या अन्यथा यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, तो वह अधिसूचना द्वारा अनुसूची का संशोधन कर सकेगी और ऐसी अधिसूचना के जारी किए जाने पर अनुसूची तदनुसार संशोधित की गई समझी जाएगी।

(2) प्रत्येक ऐसी अधिसूचना इसके जारी किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जाएगी।

केन्द्रीय सरकार की नियम बनाने की शक्ति।

100. (1) केन्द्रीय सरकार, पूर्व प्रकाशन की शर्त के अध्वधीन अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के उपबंधों के क्रियान्वयन के लिए नियम बना सकेगी।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियम, निम्नलिखित विषयों में से सभी या किसी विषय के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात्:—

(क) धारा 6 की उपधारा (2) के अधीन दिव्यांगता अनुसंधान समिति के गठन की रीति;

(ख) धारा 21 की उपधारा (1) के अधीन समान अवसर नीति अधिसूचित करने की रीति;

(ग) धारा 22 की उपधारा (1) के अधीन प्रत्येक स्थापन द्वारा अभिलेखों के अनुरक्षण का प्ररूप और रीति;

(घ) धारा 23 की उपधारा (3) के अधीन शिकायत अनुतोष अधिकारी द्वारा शिकायतों के रजिस्टर के अनुरक्षण की रीति;

(ङ) धारा 36 के अधीन विशेष रोजगार कार्यालय के लिए स्थापन द्वारा जानकारी और विवरणी प्रस्तुत करने की रीति;

(च) धारा 38 की उपधारा (2) के अधीन निर्धारण बोर्ड की संरचना और उपधारा (3) के अधीन निर्धारण बोर्ड द्वारा किए जाने वाले निर्धारण की रीति;

(छ) धारा 40 के अधीन दिव्यांगजनों की पहुंच के लिए मानक अधिकथित करने के लिए नियम;

(ज) धारा 58 की उपधारा (1) के अधीन दिव्यांगता प्रमाणपत्र के जारी किए जाने के लिए आवेदन की रीति और उपधारा (2) के अधीन दिव्यांगता के प्रमाणपत्र का प्ररूप;

(झ) धारा 61 की उपधारा (6) के अधीन केंद्रीय सलाहकार बोर्ड के नामनिर्दिष्ट सदस्यों को संदत्त किए जाने वाले भत्ते;

(ञ) धारा 64 के अधीन केंद्रीय सलाहकार बोर्ड की बैठकों में कारबार के संव्यवहार के लिए प्रक्रिया के नियम;

(ट) धारा 73 की उपधारा (4) के अधीन मुख्य आयुक्त और आयुक्तों के वेतन और भत्ते तथा सेवा की अन्य शर्तें;

(ठ) धारा 74 की उपधारा (7) के अधीन मुख्य आयुक्त के अधिकारियों और कर्मचारिवृंद के वेतन और भत्ते और सेवा की शर्तें;

(ड) धारा 74 की उपधारा (8) के अधीन सलाहकार समिति की संरचना और विशेषज्ञों की नियुक्ति की रीति;

(ढ) धारा 78 की उपधारा (3) के अधीन मुख्य आयुक्त द्वारा तैयार की जाने वाली और प्रस्तुत की जाने वाली वार्षिक रिपोर्ट का प्ररूप, रीति और अंतर्वस्तु;

(ण) धारा 86 की उपधारा (2) के अधीन प्रक्रिया, निधि का उपयोग और प्रबंध की प्रक्रिया, रीति;

(त) धारा 87 की उपधारा (1) के अधीन निधि के लेखाओं की तैयारी के लिए प्ररूप।

(3) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा। यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी। यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा। यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा। किंतु नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

101. (1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा पूर्व प्रकाशन की शर्त के अध्वधीन इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से छह मास से अनधिक की अवधि के अपश्चात् इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी।

राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियम निम्नलिखित सभी विषयों या किसी विषय के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात्:—

(क) धारा 5 की उपधारा (2) के अधीन दिव्यांगता अनुसंधान के लिए समिति के गठन की रीति;

(ख) धारा 14 की उपधारा (1) के अधीन किसी सीमित संरक्षक की सहायता उपलब्ध कराने की रीति;

(ग) धारा 51 की उपधारा (1) के अधीन रजिस्ट्रीकरण के प्रमाणपत्र के लिए किसी आवेदन को करने का प्ररूप और रीति;

(घ) धारा 51 की उपधारा (3) के अधीन रजिस्ट्रीकरण के प्रमाणपत्र की मंजूरी के लिए संस्थान द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं और पूरे किए जाने वाले मानक;

(ङ) धारा 51 की उपधारा (4) के अधीन रजिस्ट्रीकरण के प्रमाणपत्र की विधिमान्यता, रजिस्ट्रीकरण के प्रमाणपत्र से संलग्न प्ररूप और शर्तें;

(च) धारा 51 की उपधारा (7) के अधीन रजिस्ट्रीकरण के प्रमाणपत्र के लिए आवेदन के निपटान की अवधि;

(छ) वह अवधि जिसके भीतर धारा 53 की उपधारा (1) के अधीन अपील की जाएगी;

(ज) धारा 59 की उपधारा (1) के अधीन प्रमाणकर्ता प्राधिकारी के आदेश के विरुद्ध अपील का समय और रीति और उपधारा (2) के अधीन ऐसी अपील के निपटान की रीति;

(झ) धारा 67 की उपधारा (6) के अधीन राज्य सलाहकार बोर्ड के नामनिर्दिष्ट सदस्यों को संदत्त किए जाने वाले भत्ते;

(ञ) धारा 70 के अधीन राज्य सलाहकार बोर्ड की बैठकों में कारबार के संव्यवहार के लिए प्रक्रिया के नियम;

(ट) धारा 72 के अधीन जिला स्तर समिति की संरचना और कृत्य;

(ठ) धारा 79 की उपधारा (3) के अधीन राज्य आयुक्त का वेतन, भत्ते तथा सेवा की अन्य शर्तें;

(ड) धारा 79 की उपधारा (3) के अधीन राज्य आयुक्त के अधिकारियों और कर्मचारिवृंद के वेतन, भत्ते तथा सेवा की शर्तें;

(ढ) धारा 79 की उपधारा (7) के अधीन सलाहकार समिति की संरचना और विशेषज्ञों की नियुक्ति की रीति;

(ण) धारा 83 की उपधारा (3) के अधीन राज्य आयुक्त द्वारा तैयार की जाने वाली और प्रस्तुत की जाने वाली वार्षिक और विशेष रिपोर्टों का प्ररूप, रीति और अंतर्वस्तु;

(त) धारा 85 की उपधारा (2) के अधीन विशेष लोक अभियोजक को संदत्त की जाने वाली फीस या पारिश्रमिक;

(थ) धारा 88 की उपधारा (1) के अधीन दिव्यांगजनों के लिए राज्य निधि के गठन की रीति और उपधारा (2) के अधीन राज्य निधि के उपयोग और प्रबंध की रीति;

(द) धारा 88 की उपधारा (3) के अधीन दिव्यांगजनों के लिए राज्य निधि के खातों को तैयार करने के लिए प्ररूप।

(3) इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम इसके बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र राज्य विधान-मंडल के समक्ष जहां दो सदन हैं, वहां प्रत्येक सदन के समक्ष और जहां राज्य विधान-मंडल का एक सदन है, उस सदन के समक्ष रखा जाएगा।

निरसन और
व्यावृत्ति।

102. (1) निशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 1996 का 1
इसके द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) उक्त अधिनियम के ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अधिनियम के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई समझी जाएगी।

‘अनुसूची

[धारा 2 का खंड (य ग) देखिए।]

विनिर्दिष्ट दिव्यांगता

1. शारीरिक दिव्यांगता—

(अ) गतिविषयक दिव्यांगता (सुनिश्चित गतिविधियों को करने में किसी व्यक्ति की असमर्थता जो स्वयं और वस्तुओं की गतिशीलता से सहबद्ध है जिसका परिणाम पेशीकंकाल और तंत्रिका प्रणाली या दोनों में पीड़ा है), जिसके अंतर्गत—

(क) “कुष्ठ रोगमुक्त व्यक्ति” से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो कुष्ठ से रोगमुक्त हो गया है किंतु निम्नलिखित से पीड़ित है—

(i) हाथ या पैरों में सुग्राहीकरण का ह्रास के साथ-साथ आंख और पलक में सुग्राहीकरण का ह्रास और आंशिक घात किंतु व्यक्ति विरूपता नहीं है;

(ii) व्यक्ति विरूपता और आंशिक घात किंतु उसके हाथों और पैरों में पर्याप्त गतिशीलता है जिससे वह सामान्य व्यावसायिक क्रियाकलापों में लगे रहने के लिए सक्षम है;

(iii) अत्यंत शारीरिक विरूपता के साथ-साथ वृद्ध जो उसे कोई लाभप्रद व्यवसाय करने से निवारित करती है और “कुष्ठ रोगमुक्त व्यक्ति” पद का तदनुसार अर्थ लगाया जाएगा;

(ख) “प्रमस्तिष्क घात” से कोई गैर-प्रगामी तंत्रिका स्थिति का समूह अभिप्रेत है जो शरीर के संचलन को और पेशियों के समन्वयन को प्रभावित करती है, जो मस्तिष्क के एक या अधिक विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में क्षति के कारण उत्पन्न होता है जो साधारणतः जन्म से पूर्व, जन्म के दौरान या जन्म के तुरंत पश्चात् होता है;

(ग) “बौनापन” से कोई चिकित्सीय या आनुवांशिक दशा अभिप्रेत है जिसके परिणामस्वरूप किसी वयस्क व्यक्ति की लंबाई चार फीट दस इंच (147 सेमी) या उससे कम रह जाती है;

(घ) “पेशीयदुष्पोषण” से वंशानुगत, आनुवांशिक पेशी रोग का समूह अभिप्रेत है जो मानव शरीर को संचलित करने वाली पेशियों को कमजोर कर देता है और बहुदुष्पोषण के रोगी व्यक्तियों के जीन में वह सूचना अशुद्ध होती है या नहीं होती है जो उन्हें उस प्रोटीन को बनाने से निवारित करती है जिसकी उन्हें स्वस्थ पेशियों के लिए आवश्यकता होती है, इसकी विशेषता प्रगामी कंकाल पेशी की कमजोरी, पेशी प्रोटीनों में त्रुटि और पेशी कोशिकाओं और टिशुओं की मृत्यु है;

(ङ) “तेजाबी आक्रमण पीड़ित” से तेजाब या समान संक्षारित पदार्थ को फेंककर किए गए हिंसक हमले के कारण विदूषित कोई व्यक्ति अभिप्रेत है;

(आ) दृष्टिगत ह्रास—

(क) “अंधता” से ऐसी दशा अभिप्रेत है जिसमें सर्वोत्तम सुधार के पश्चात् व्यक्ति में निम्नलिखित स्थितियों में से कोई एक स्थिति विद्यमान होती है,—

(i) दृष्टि का पूर्णतया अभाव; या

(ii) सर्वाधिक संभव सुधार के साथ बेहतर आंख में दृष्टि सुतीक्ष्णता 3/60 से कम या 10/200 (स्नेलन) से कम; या

(iii) 10 डिग्री से कम के किसी कोण पर कक्षांतरित दृश्य क्षेत्र की परिसीमा;

(ख) “निम्न दृष्टि” से ऐसी स्थिति अभिप्रेत है जिसमें व्यक्ति की निम्नलिखित में से कोई एक स्थिति होती है, अर्थात्:—

(i) बेहतर आंख में सर्वाधिक संभव सुधार के साथ 6/18 से अनधिक या 20/60 से कम से 3/60 तक या 10/200 (स्नेलन) तक दृश्य सुतीक्ष्णता; या

(ii) 40 डिग्री से कम से 10 डिग्री तक की कक्षांतरित दृष्टि की क्षेत्र परिसीमा;

(इ) “श्रवण शक्ति का ह्रास”—

(क) “बधिर” से दोनों कानों में संवाद आवृत्तियों में 70 डेसिबिल श्रव्य ह्रास वाले व्यक्ति अभिप्रेत हैं;

(ख) “ऊंचा सुनने वाला व्यक्ति” से दोनों कानों से संवाद आवृत्तियों में 60 डेसिबिल से 70 डेसिबिल श्रव्य ह्रास वाला व्यक्ति अभिप्रेत है;

(ई) “वाक् और भाषा दिव्यांगता” से लेराइनजेक्टोमी या अफेलिया जैसी स्थितियों से उद्भूत स्थायी दिव्यांगता अभिप्रेत है जो कार्बनिक या तंत्रिका संबंधी कारणों के कारण वाक् और भाषा के एक या अधिक संघटकों को प्रभावित करती है।

2. “बौद्धिक दिव्यांगता” से ऐसी स्थिति, जिसकी विशेषता बौद्धिक कार्य (तार्किक, शिक्षण, समस्या, समाधान) और अनुकूलित व्यवहार, दोनों में महत्वपूर्ण कमी होना है, जिसके अंतर्गत दैनिक सामाजिक और व्यवहार्य कोशलों की रेंज है, जिसके अंतर्गत—

(क) “विनिर्दिष्ट विद्या दिव्यांगताओं” से स्थितियों का एक ऐसा विजातीय समूह अभिप्रेत है जिसमें भाषा को बोलने या लिखने की प्रक्रिया द्वारा आलेखन करने की कमी विद्यमान होती है जो समझने, बोलने, पढ़ने, लिखने, अर्थ निकालने या गणितीय गणना करने में कमी के रूप में सामने आती है और इसके अंतर्गत बोधक दिव्यांगता डायसेलेक्सिया, डायसग्राफिया, डायसकेलकुलिया, डायसप्रेसिया और विकासात्मक अफेसिया जैसी स्थितियां भी हैं;

(ख) “स्वपरायणता स्पैक्ट्रम विकार” से एक ऐसी तंत्रिका विकास की स्थिति अभिप्रेत है जो विशिष्टतः जीवन के पहले तीन वर्ष में उत्पन्न होती है, जो व्यक्ति की संपर्क करने की, संबंधों को समझने की और दूसरों से संबंधित होने की क्षमता को अत्यधिक प्रभावित करती है और आमतौर पर यह अप्रायिक या घिसे-पिटे कर्मकांडों या व्यवहार से सहबद्ध होता है।

3. मानसिक व्यवहार,—

“मानसिक रुग्णता” से चिंतन, मनोदशा, बोध, अभिसंस्करण या स्मरणशक्ति का अत्यधिक विकार अभिप्रेत है जो जीवन की साधारण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समग्र रूप से निर्णय, व्यवहार, वास्तविकता की पहचान करने की क्षमता या योग्यता को प्रभावित करता है किंतु जिसके अंतर्गत मानसिक मंदता नहीं है जो किसी व्यक्ति के मस्तिष्क का विकास रुकने या अपूर्ण होने की स्थिति है, विशेषकर जिसकी विशिष्टता बुद्धिमत्ता का सामान्य से कम होना है।

4. निम्नलिखित के कारण दिव्यांगता—

(क) चिरकारी तंत्रिका दशाएं, जैसे—

(i) “बहु-स्केलेरोसिक” से प्रवाहक, तंत्रिका प्रणाली रोग अभिप्रेत है जिसमें मस्तिष्क की तंत्रिका कोशिकाओं के अक्ष तंतुओं के चारों ओर रीढ़ की हड्डी की मायलिन सीथ क्षतिग्रस्त हो जाती है जिससे डिमायलीनेशन होता है और मस्तिष्क में तंत्रिका कोशिकाओं और रीढ़ की हड्डी की कोशिकाओं की एक-दूसरे के साथ संपर्क करने की क्षमता प्रभावित होती है;

(ii) “पार्किंसन रोग” से कोई तंत्रिका प्रणाली का प्रगामी रोग अभिप्रेत है, जो कम्प, पेशी कठोरता और धीमा, कठिन संचलन द्वारा चिन्हांकित होता है जो मुख्यतया मस्तिष्क के आधारीय गंडिका के अद्यपतन तथा तंत्रिका संचलन डोपामई के ह्रास से संबद्ध मध्य आयु और वृद्ध व्यक्तियों को प्रभावित करता है;

(ख) रक्त विकृति—

(i) “हेमोफीलिया” से एक आनुवंशिकीय रोग अभिप्रेत है जो प्रायः पुरुषों को ही प्रभावित करता है किंतु इसे महिला द्वारा अपने नर बालकों को संचारित किया जाता है, इसकी विशेषता रक्त के थक्का जमने की साधारण क्षमता का नुकसान होना है जिससे छोटे से घाव का परिणाम भी घातक रक्तस्राव हो सकता है;

(ii) “थेलेसीमिया” से वंशानुगत विकृतियों का एक समूह अभिप्रेत है जिसकी विशेषता हिमोग्लोबिन की कमी या अभाव है;

(iii) “सिक्कल कोशिका रोग” से होमोलेटिक विकृति अभिप्रेत है जो रक्त की अत्यंत कमी, पीड़ादायक घटनाओं और जो सहबद्ध टिशुओं और अंगों को नुकसान से विभिन्न जटिलताओं में परिलक्षित होता है; “हेमोलेटिक” लाल रक्त कोशिकाओं की कोशिका झिल्ली के नुकसान को निर्दिष्ट करता है जिसका परिणाम हिमोग्लोबिन का निकलना होता है।

5. बहुदिव्यांगता(उपर्युक्त एक या एक से अधिक विनिर्दिष्ट दिव्यांगताएं) जिसके अंतर्गत बधिरता, अंधता, जिससे कोई ऐसी दशा जिसमें किसी व्यक्ति के श्रव्य और दृश्य के सम्मिलित ह्रास के कारण गंभीर संप्रेषण, विकास और शिक्षण संबंधी गंभीर दशाएं अभिप्रेत हैं।

6. कोई अन्य प्रवर्ग जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किए जाएं।’।

विनिर्दिष्ट बैंक नोट (दायित्वों की समाप्ति) अधिनियम, 2017

(2017 का अधिनियम संख्यांक 2)

[27 फरवरी, 2017]

लोकहित में विनिर्दिष्ट बैंक नोटों पर दायित्वों की
समाप्ति के लिए और उससे संबंधित
या उसके आनुषंगिक विषयों का
उपबंध करने के लिए
अधिनियम

भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम विनिर्दिष्ट बैंक नोट (दायित्वों की समाप्ति) अधिनियम, 2017 है। संक्षिप्त नाम और प्रारंभ।
(2) यह 31 दिसम्बर, 2016 को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा।
2. (1) इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—
(क) “नियत दिन” से 31 दिसम्बर, 2016 अभिप्रेत है; परिभाषा।

(ख) “अनुग्रह अवधि” से केन्द्रीय सरकार द्वारा, अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट की जाने वाली ऐसी अवधि अभिप्रेत है, जिसके दौरान विनिर्दिष्ट बैंक नोट, इस अधिनियम के अनुसार निक्षिप्त किए जा सकते हैं;

(ग) “अधिसूचना” से राजपत्र में प्रकाशित कोई सूचना अभिप्रेत है;

(घ) “रिजर्व बैंक” से केन्द्रीय सरकार द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 3 के अधीन गठित भारतीय रिजर्व बैंक अभिप्रेत है; 1934 का 2

(ङ) “विनिर्दिष्ट बैंक नोट” से 8 नवम्बर, 2016 को या उससे पूर्व विद्यमान क्रम के पांच सौ रुपए या एक हजार रुपए की श्रृंखला के अंकित मूल्य का कोई बैंक नोट अभिप्रेत है;

(2) उन शब्दों और पदों के जो इस अधिनियम में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं, किन्तु भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 या बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो उन अधिनियमों में उनके हैं। 1934 का 2
1949 का 10

विनिर्दिष्ट बैंक नोटों के प्रति रिजर्व बैंक या केन्द्रीय सरकार का दायित्व न होना।

3. भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी नियत तारीख से ही भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 26 की उपधारा (2) के अधीन जारी भारत सरकार के वित्त मंत्रालय की अधिसूचना सं० का०आ० 3407(अ), तारीख 8 नवम्बर, 2016 को ध्यान में रखते हुए विनिर्दिष्ट बैंक नोट, जिनकी वैध निविदा नहीं है, धारा 34 के अधीन रिजर्व बैंक का दायित्व नहीं होंगे और उक्त अधिनियम की धारा 26 की उपधारा (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार की प्रत्याभूति नहीं होंगे। 1934 का 2

विनिर्दिष्ट बैंक नोटों का विनियमन।

4. (1) धारा 3 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी 8 नवम्बर, 2016 को या उससे पूर्व विनिर्दिष्ट बैंक नोट रखने वाले निम्नलिखित व्यक्ति अनुग्रह अवधि के भीतर ऐसी घोषणाओं या कथनों सहित रिजर्व बैंक के ऐसे कार्यालयों में या ऐसी अन्य रीति में, जो उसके द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, निविदत्त करने के हकदार होंगे, अर्थात्:—

(i) भारत का कोई नागरिक, ऐसी शर्तों, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा, अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, के अधीन यह घोषणा करता है कि वह 9 नवम्बर, 2016 से 30 दिसम्बर, 2016 के बीच भारत से बाहर था; या

(ii) व्यक्तियों का ऐसा वर्ग और ऐसे कारणों से जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं।

(2) रिजर्व बैंक, ऐसे सत्यापन करने के पश्चात्, जो वह आवश्यक समझे, यदि यह समाधान हो जाता है कि धारा 3 में निर्दिष्ट अधिसूचना में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर नोटों को निक्षिप्त करने में विफलता के लिए कारण वास्तविक हैं, उसके, नोटों के मूल्य को अपने ग्राहक को जानिए अनुपालक बैंक खाते में ऐसी रीति से, जो उसके द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, जमा कर सकेगा।

(3) उपधारा (2) के अधीन रिजर्व बैंक द्वारा नोटों के मूल्य को जमा किए जाने से इंकार करने से व्यथित कोई व्यक्ति, उसको ऐसी इंकारी की संसूचना के चौदह दिन के भीतर रिजर्व बैंक के केन्द्रीय बोर्ड को अभ्यावेदन कर सकेगा।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए “अपने ग्राहक को जानिए अनुपालक बैंक खाता” से ऐसा खाता अभिप्रेत है जो बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के अधीन रिजर्व बैंक द्वारा बनाए गए विनियमों में विनिर्दिष्ट शर्तों का पालन करता है। 1949 का 10

विनिर्दिष्ट बैंक नोट धारण करने, अंतरित करने या प्राप्त करने पर प्रतिषेध।

5. कोई व्यक्ति, नियत दिन से ही, जानते हुए या स्वेच्छया किसी विनिर्दिष्ट बैंक नोट को धारण, अंतरित या प्राप्त नहीं करेगा:

परंतु इस धारा में अंतर्विष्ट कोई बात—

(क) किसी व्यक्ति द्वारा—

(i) अनुग्रह अवधि की समाप्ति तक; या

(ii) अनुग्रह अवधि की समाप्ति के पश्चात्,—

(अ) अंकित मूल्य का विचार किए बिना कुल दस नोटों से अनधिक; या

(आ) अध्ययन, अनुसंधान या मुद्राशास्त्र के प्रयोजनों के लिए पच्चीस नोटों से अनधिक।

(ख) रिजर्व बैंक या उसके अधिकरणों द्वारा, या रिजर्व बैंक द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति द्वारा;

(ग) न्यायालय में लंबित किसी मामले के संबंध में किसी न्यायालय के निदेश पर किसी व्यक्ति द्वारा,

विनिर्दिष्ट बैंक नोट धारण करने को प्रतिषिद्ध नहीं करेगी।

6. जो कोई, जानते हुए या जानबूझकर, धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट कोई ऐसी घोषणा या कथन करेगा, जो तात्त्विक विशिष्टियों में मिथ्या है या कोई तात्त्विक कथन करने में लोप करेगा या कोई ऐसा कथन करेगा जिसके सत्य होने पर वह विश्वास नहीं करता है वह जुर्माने से, जो पचास हजार रुपये तक या निविदित विनिर्दिष्ट बैंक नोटों के अंकित मूल्य की रकम के पांच गुना तक का, इनमें से जो भी उच्चतर हो, हो सकेगा, से दंडनीय होगा।

धारा 4 के उल्लंघन के लिए शास्ति।

7. जो कोई धारा 5 के उपबंधों का उल्लंघन करेगा वह जुर्माने से, जो दस हजार रुपये तक या उल्लंघन में अंतर्वर्तित विनिर्दिष्ट बैंक नोटों के अंकित मूल्य की रकम के पांच गुना तक का, इनमें से जो भी उच्चतर हो, हो सकेगा, से दंडनीय होगा।

धारा 5 के उल्लंघन के लिए शास्ति।

8. (1) जहां धारा 6 या धारा 7 में निर्दिष्ट कोई उल्लंघन या व्यतिक्रम को करने वाला कोई व्यक्ति एक कंपनी है, वहां ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जो उल्लंघन या व्यतिक्रम किए जाने के समय उस कंपनी के कारबार के संचालन के लिए उस कंपनी का भारसाधक और उसके प्रति उत्तरदायी था, और साथ ही वह कंपनी भी ऐसे उल्लंघन या व्यतिक्रम के दोषी समझे जाएंगे और तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने के भागी होंगे:

कंपनियों द्वारा अपराध।

परंतु इस उपधारा में अंतर्विष्ट कोई बात किसी ऐसे व्यक्ति को दंड का भागी नहीं बनाएगी यदि वह साबित कर देता है कि उल्लंघन या व्यतिक्रम उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने उल्लंघन या व्यतिक्रम किए जाने का निवारण करने के लिए सभी सम्यक् तत्परता बरती थी।

(2) उपधारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कंपनी द्वारा किया गया है और यह साबित हो जाता है कि वह अपराध कंपनी के किसी निदेशक, प्रबंधक, सचिव या कंपनी के किसी अन्य अधिकारी या कर्मचारी की सहमति या मौनानुकूलता से किया गया है या उस अपराध का किया जाना उसकी किसी उपेक्षा के कारण माना जा सकता है, वहां ऐसा निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी या कर्मचारी भी उस अपराध का दोषी समझा जाएगा और तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने का भागी होगा।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजन के लिए—

(क) “कोई कंपनी” से कोई निगमित निकाय अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत कोई फर्म, कोई न्यास, कोई सहकारी सोसाइटी और व्यष्टियों का अन्य संगम भी है;

(ख) किसी फर्म या न्यास के संबंध में “निदेशक” से उस फर्म का कोई भागीदार या न्यास में का कोई हिताधिकारी अभिप्रेत है।

1974 का 2

9. दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 29 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी इस अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन के लिए प्रथम श्रेणी के किसी मजिस्ट्रेट का न्यायालय या किसी महानगर मजिस्ट्रेट का कोई न्यायालय जुर्माना अधिरोपित कर सकेगा।

अपराधों के संबंध में विशेष उपबंध।

10. इस अधिनियम के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही सरकार, रिजर्व बैंक या उनके किसी अधिकारी के विरुद्ध नहीं होगी।

सद्भावपूर्वक की गई कार्यवाही के लिए संरक्षण।

11. (1) केन्द्रीय सरकार इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए अधिसूचना द्वारा नियम बना सकेगी।

नियम बनाने की शक्ति।

(2) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा। यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी। यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा। यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा। किन्तु नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति।

12. (1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा ऐसे उपबंध कर सकेगी, जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हो और जो उसे उस कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो:

परन्तु इस धारा के अधीन ऐसा कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारंभ से दो वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा।

निरसन और व्यावृत्तियां।

13. (1) विनिर्दिष्ट बैंक नोट (उत्तरदायित्व का समाप्त होना) अध्यादेश, 2016 इसके द्वारा निरसित किया जाता है।

2016 का अध्यादेश संख्यांक 10

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई समझी जाएगी।

प्रसूति प्रसुविधा (संशोधन) अधिनियम, 2017

(2017 का अधिनियम संख्यांक 6)

[27 मार्च, 2017]

प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961
का और संशोधन
करने के लिए
अधिनियम

भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम प्रसूति प्रसुविधा (संशोधन) अधिनियम, 2017 है।

संक्षिप्त नाम और
प्रारंभ।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे:

परंतु इस अधिनियम के भिन्न-भिन्न उपबंधों के लिए भिन्न-भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी और ऐसे किसी उपबंध में इस अधिनियम के प्रारंभ के प्रति किसी निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह उस उपबंध के प्रवृत्त होने के प्रति निर्देश है।

1961 का 53

2. प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 में खंड (ख) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

धारा 3 का
संशोधन।

‘(खक) “अधिकृत माता” से ऐसी जैविक माता अभिप्रेत है, जो किसी अन्य स्त्री में रोपित भ्रूण को पैदा करने के लिए अपने अंडाणु का उपयोग करती है;’।

धारा 5 का
संशोधन।

3. मूल अधिनियम की धारा 5 में,—

(अ) उपधारा (3) में,—

(i) “बारह सप्ताह होगी, जिसमें से छह सप्ताह से अनधिक” शब्दों के स्थान पर,
“छब्बीस सप्ताह होगी, जिसमें से आठ सप्ताह से अनधिक” शब्द रखे जाएंगे;

(ii) उपधारा (3) के पश्चात् और पहले परन्तुक से पहले, निम्नलिखित परन्तुक
अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“परन्तु वह अधिकतम कालावधि जिसके लिए कोई ऐसी स्त्री, जिसके दो या
दो से अधिक बालक हैं, प्रसूति सुविधा की हकदार है, बारह सप्ताह होगी जिसमें से
छह सप्ताह से अनधिक उसके प्रसव की प्रत्याशित तारीख से पूर्व होगी।”;

(iii) पहले परन्तुक में “परन्तु” शब्द के स्थान पर, “परन्तु यह और कि” शब्द रखे
जाएंगे;

(iv) दूसरे परन्तुक में “परन्तु यह और कि” शब्दों के स्थान पर, “परन्तु यह भी
कि” शब्द रखे जाएंगे;

(आ) उपधारा (3) के पश्चात् निम्नलिखित उपधाराएं अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:—

“(4) कोई स्त्री, जो वैध रूप से तीन मास से कम आयु के शिशु का दत्तक ग्रहण
करती है या कोई अधिकृत माता, उस तारीख से, जिसको, यथास्थिति, दत्तक माता या
अधिकृत माता को शिशु सौंपा जाता है, बारह सप्ताह की अवधि के लिए प्रसूति प्रसुविधा
की हकदार होगी।

(5) उस दशा में, जहां किसी स्त्री को सौंपा गया कार्य ऐसी प्रकृति का है कि वह घर
से कार्य कर सकती है, वहां नियोजक उसे प्रसूति प्रसुविधा का उपभोग करने के पश्चात् ऐसी
अवधि के लिए और ऐसी शर्तों पर, जिन पर नियोजक और स्त्री की पारस्परिक सहमति हो,
ऐसा करने के लिए अनुज्ञात कर सकेगा।”।

नई धारा 11क का
अंतःस्थापन।

4. मूल अधिनियम की धारा 11 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

शिशु कक्ष सुविधा।

“11क. (1) पचास या अधिक कर्मचारियों वाले प्रत्येक स्थापन में, ऐसी दूरी के भीतर जो
विहित की जाए या जो पृथक्: या सामान्य सुविधाओं सहित शिशु कक्ष की सुविधा होगी:

परन्तु नियोजक, स्त्री द्वारा शिशु कक्ष में दिन में चार बार जाने की अनुज्ञा देगा, जिसके
अंतर्गत उसे अनुज्ञात विश्राम अंतराल भी होगा।

(2) प्रत्येक स्थापन, प्रत्येक स्त्री को लिखित रूप में या इलेक्ट्रॉनिक रूप से उसकी आरंभिक
नियुक्ति के समय इस अधिनियम के अधीन उपलब्ध प्रत्येक प्रसुविधा के संबंध में सूचित करेगा।”।

कर्मचारी प्रतिकर (संशोधन) अधिनियम, 2017

(2017 का अधिनियम संख्यांक 11)

[12 अप्रैल, 2017]

कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम, 1923
का और संशोधन
करने के लिए
अधिनियम

भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम कर्मचारी प्रतिकर (संशोधन) अधिनियम, 2017 है।
(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे।

संक्षिप्त नाम और
प्रारंभ।

1923 का 8

2. कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम, 1923 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

नई धारा 17क का
अंतःस्थापन।

“17क. प्रत्येक नियोजक, किसी कर्मचारी के नियोजन के समय तत्काल, कर्मचारी को इस अधिनियम के अधीन प्रतिकर संबंधी उसके अधिकारों की लिखित में और इलैक्ट्रॉनिक साधनों के माध्यम से अंग्रेजी या हिन्दी में या नियोजन के क्षेत्र की राजभाषा में, जो कर्मचारी समझता हो, जानकारी देगा।”।

नियोजक का
कर्मचारी को उसके
अधिकारों की
जानकारी देने का
कर्तव्य।

धारा 18क का
संशोधन।

3. मूल अधिनियम की धारा 18क की उपधारा (1) में,—

(i) खंड (घ) में, “के अधीन अपेक्षित है” शब्दों के स्थान पर “के अधीन अपेक्षित है, या” शब्द रखे जाएंगे;

(ii) खंड (घ) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“(ड) कर्मचारी को ऐसे प्रतिकर संबंधी उसके अधिकारों की जानकारी देने में असफल रहेगा जो धारा 17क के अधीन अपेक्षित है,”;

(iii) दीर्घ पंक्ति में “जो पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा” शब्दों के स्थान पर “जो पचास हजार रुपए से कम का नहीं होगा किन्तु जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा” शब्द रखे जाएंगे;

धारा 30 का
संशोधन।

4. मूल अधिनियम की धारा 30 की उपधारा (1) के पहले परन्तुक में “तीन सौ रुपए” शब्दों के स्थान पर “दस हजार रुपए या ऐसी उच्चतर रकम जो केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे” शब्द रखे जाएंगे।

धारा 30क का
संशोधन।

5. मूल अधिनियम की धारा 30क का लोप किया जाएगा।

एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017

(2017 का अधिनियम संख्यांक 13)

[12 अप्रैल, 2017]

केंद्रीय सरकार द्वारा माल या सेवाओं या दोनों की अंतरराज्यिक पूर्ति पर कर के
उद्ग्रहण और संग्रहण के लिए उपबंध करने के लिए तथा उससे
संबंधित या उसके आनुषंगिक
विषयों के लिए
अधिनियम

भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

अध्याय 1

प्रारंभिक

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 है।
- (2) इसका विस्तार जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत पर होगा।
- (3) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे:

संक्षिप्त नाम,
विस्तार और
प्रारंभ।

परन्तु इस अधिनियम के भिन्न-भिन्न उपबंधों के लिए भिन्न-भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी तथा इस अधिनियम के प्रारंभ के प्रति ऐसे किसी उपबंध में किसी निर्देश का अर्थ उस उपबंध के प्रवृत्त होने के प्रति निर्देश के रूप में लगाया जाएगा।

परिभाषाएं।

2. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(1) “केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम” से केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 अभिप्रेत है;

(2) “केन्द्रीय कर” से केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम के अधीन उद्गृहीत और संगृहीत कर अभिप्रेत है;

(3) “निरंतर यात्रा” से ऐसी यात्रा अभिप्रेत है, जिसके लिए या तो सेवा के एकल पूर्तिकार द्वारा या सेवा के एक पूर्तिकार से अधिक की और से कार्य करने वाले किसी अभिकर्ता के माध्यम से एक ही समय एक या एक से अधिक टिकट या बीजक जारी किया गया है और जिसमें उस यात्रा की, जिसके लिए एक या अधिक अलग टिकट या बीजक जारी किए गए हैं, किन्हीं मंजिलों के बीच कोई मध्य विश्राम अंतर्वर्तित नहीं है।

स्पष्टीकरण—इस खंड के प्रयोजनों के लिए, “मध्य विश्राम” पद से ऐसा स्थान अभिप्रेत है, जहां कोई यात्री या तो दूसरे वाहन में स्थानांतरण के लिए या कतिपय अवधि के लिए अपनी यात्रा को किसी पश्चात्पूर्व समय बिन्दु पर पुनः प्रारंभ करने हेतु रुकने के लिए उतर सकता है।

(4) “भारत की सीमाशुल्क सरहद” से सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 2 में यथा 1962 का 52 परिभाषित सीमाशुल्क क्षेत्र की सीमाएं अभिप्रेत हैं;

(5) “माल का निर्यात” से उसके व्याकरणिक रूपभेदों और सजातीय पदों के साथ भारत से माल को भारत के बाहर किसी स्थान पर ले जाना अभिप्रेत है;

(6) “निर्यात सेवाओं” से किसी सेवा का ऐसा प्रदाय अभिप्रेत है, जब,—

(i) सेवा का पूर्तिकार भारत में अवस्थित है;

(ii) सेवा का प्राप्तिकर्ता भारत के बाहर अवस्थित है;

(iii) सेवा की पूर्ति का स्थान भारत के बाहर है;

(iv) सेवा के पूर्तिकार द्वारा ऐसी सेवा के लिए संदाय संपरिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में प्राप्त किया गया है; और

(v) सेवा का पूर्तिकार और सेवा का प्राप्तिकर्ता धारा 8 के स्पष्टीकरण के अनुसार मात्र किसी विशेष व्यक्ति के स्थापन नहीं हैं।

(7) “स्थिर स्थापन” से ऐसा स्थान (कारबार के रजिस्ट्रीकृत स्थान से भिन्न) अभिप्रेत है, जिसे सेवाओं की पूर्ति के लिए या अपने स्वयं की आवश्यकताओं के लिए सेवाएं प्राप्त करने और उनका उपयोग करने के लिए मानव और तकनीकी संसाधनों के रूप में स्थायित्व की पर्याप्त मात्रा और उपयुक्त संरचना द्वारा विशिष्टता का वर्णन किया गया है;

(8) “माल और सेवा कर (राज्यों को प्रतिकर) अधिनियम” से माल और सेवा कर (राज्यों को प्रतिकर) अधिनियम, 2017 अभिप्रेत है;

(9) “सरकार” से केन्द्रीय सरकार अभिप्रेत है;

(10) “माल का आयात” से उसके व्याकरणिक रूपभेदों और सजातीय पदों के साथ भारत के बाहर किसी स्थान से भारत में माल लाना अभिप्रेत है;

(11) “सेवाओं का आयात” से किसी सेवा की पूर्ति अभिप्रेत है, जहां,—

(i) सेवा का पूर्तिकार भारत के बाहर अवस्थित है;

(ii) सेवा का प्राप्तिकर्ता भारत में अवस्थित है;

(iii) सेवा की पूर्ति का स्थान भारत में है;

(12) “एकीकृत कर” से इस अधिनियम के अधीन उद्गृहीत एकीकृत माल और सेवा कर अभिप्रेत है;

(13) “मध्यवर्ती” से कोई दलाल, कोई अभिकर्ता या कोई अन्य व्यक्ति, जिस भी नाम से ज्ञात हो, अभिप्रेत है, जो दो या अधिक व्यक्तियों के बीच माल या सेवाओं या दोनों की या प्रतिभूतियों की पूर्ति का इंतजाम करता है या उसे सुकर बनाता है किन्तु इसके अंतर्गत ऐसा व्यक्ति नहीं है, जो ऐसे माल या सेवाओं या दोनों की या प्रतिभूतियों की पूर्ति अपने वास्ते करता है;

(14) “सेवाओं के प्राप्तिकर्ता का अवस्थान” से निम्नलिखित अभिप्रेत है,—

(क) जहां कोई पूर्ति, कारबार के ऐसे स्थान पर प्राप्त की जाती है, जिसके लिए रजिस्ट्रीकरण अभिप्राप्त किया गया है, ऐसे कारबार के स्थान का अवस्थान;

(ख) जहां पूर्ति, कारबार के ऐसे स्थान से भिन्न किसी स्थान पर प्राप्त की जाती है, जिसके लिए रजिस्ट्रीकरण अभिप्राप्त किया गया है (अन्यत्र कोई स्थिर स्थापन), ऐसे स्थिर स्थापन का अवस्थान;

(ग) जहां पूर्ति, एक से अधिक स्थापन पर प्राप्त की जाती है, चाहे वह कारबार का स्थान हो या स्थिर स्थापन, पूर्ति की प्राप्ति के संबंध में सर्वाधिक प्रत्यक्ष स्थापन का अवस्थान; और

(घ) ऐसे स्थानों के अभाव में, प्राप्तिकर्ता के निवास के मामूली स्थान का अवस्थान।

(15) “सेवाओं के पूर्तिकार का अवस्थान” से अभिप्रेत है,—

(क) जहां कोई पूर्ति, कारबार के ऐसे स्थान पर की जाती है, जिसके लिए रजिस्ट्रीकरण अभिप्राप्त किया गया है, ऐसे कारबार के स्थान का अवस्थान;

(ख) जहां पूर्ति, कारबार के ऐसे स्थान से भिन्न किसी स्थान पर की जाती है, जिसके लिए रजिस्ट्रीकरण अभिप्राप्त किया गया है (अन्यत्र कोई स्थिर स्थापन), ऐसे स्थिर स्थापन का अवस्थान;

(ग) जहां पूर्ति, एक से अधिक स्थापन पर की जाती है, चाहे वह कारबार का स्थान हो या स्थिर स्थापन, पूर्ति के प्रदान किए जाने के संबंध में सर्वाधिक प्रत्यक्ष स्थापन का अवस्थान; और

(घ) ऐसे स्थानों के अभाव में, पूर्तिकार के निवास के मामूली स्थान का अवस्थान।

(16) “गैर-कराधेय आनलाइन प्राप्तिकर्ता” से कोई ऐसी सरकार, ऐसा कोई स्थानीय प्राधिकारी, सरकारी प्राधिकरण, व्यक्ति या अन्य व्यक्ति अभिप्रेत है, जो रजिस्ट्रीकृत नहीं है और कराधेय राज्यक्षेत्र में अवस्थित वाणिज्य, उद्योग या किसी अन्य कारबार या वृत्ति से भिन्न किसी प्रयोजन के संबंध में आनलाइन सूचना और डाटाबेस पहुंच या सुधार सेवाओं को प्राप्त करता है।

स्पष्टीकरण — इस खंड के प्रयोजनों के लिए, “सरकारी प्राधिकरण” पद से,—

(i) संसद् या किसी राज्य विधान-मंडल के किसी अधिनियम द्वारा स्थापित; या

(ii) किसी सरकार द्वारा स्थापित,

कोई प्राधिकरण या कोई बोर्ड या कोई भी अन्य निकाय अभिप्रेत है, जिसके पास संविधान के अनुच्छेद 243ब के अधीन किसी नगरपालिका को सौंपे गए किसी कृत्य को कार्यान्वित करने के लिए साधारण शेयर या नियंत्रण के माध्यम से नब्बे प्रतिशत या उससे अधिक की भागीदारी है;

(17) “आनलाइन सूचना और डाटाबेस पहुंच या सुधार सेवाओं” से ऐसी सेवाएं अभिप्रेत हैं, जिनका परिदान इंटरनेट पर सूचना प्रौद्योगिकी या किसी इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क के माध्यम से किया जाता है और जिसकी प्रकृति उनकी पूर्ति को आवश्यक रूप से स्वचालित कर देती है और जिसमें न्यूनतम मानव मध्यक्षेप है और जिसे सूचना प्रौद्योगिकी के अभाव में सुनिश्चित करना असंभव है तथा जिसके अंतर्गत ऐसी इलेक्ट्रॉनिक सेवाएं आती हैं, जैसे,—

(i) इंटरनेट पर विज्ञापन देना;

- (ii) समूह सेवाएं प्रदान करना;
- (iii) दूरसंचार नेटवर्कों या इंटरनेट के माध्यम से ई-पुस्तकें, चलचित्र, संगीत, साफ्टवेयर और अन्य अमूर्त चीजें प्रदान करना;
- (iv) कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से किसी व्यक्ति को इलेक्ट्रॉनिक रूप में सुधार्य या अन्यथा डाय या सूचना प्रदान करना;
- (v) डिजिटल अंतर्वस्तु (चलचित्र, दूरदर्शन कार्यक्रम, संगीत इत्यादि) की आनलाइन पूर्ति करना;
- (vi) डिजिटल डाय भंडारण; और
- (vii) आनलाइन गेम खेलना;

(18) किसी कराधेय व्यक्ति के संबंध में “आउट पुट कर” से इस अधिनियम के अधीन प्रभाय एकीकृत कर या उसके द्वारा अथवा उसके अधिकर्ता द्वारा माल या सेवाओं या दोनों की कराधेय पूर्ति अभिप्रेत है किन्तु इसके अंतर्गत उसके द्वारा प्रतिलोम प्रभार आधार पर संदेय कर नहीं है;

(19) “विशेष आर्थिक जोन” का वही अर्थ होगा जो विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 की धारा 2 के खंड (यक) में है; 2005 का 28

(20) “विशेष आर्थिक जोन विकासकर्ता” का वही अर्थ होगा जो विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 की धारा 2 के खंड (ज) में है और इसके अंतर्गत उक्त अधिनियम की धारा 2 के खंड (घ) में यथा परिभाषित कोई प्राधिकरण और खंड (च) में यथा परिभाषित कोई सह-विकासकर्ता भी है; 2005 का 28

(21) “पूर्ति” का वही अर्थ होगा जो केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 7 में है;

(22) “कराधेय राज्यक्षेत्र” से ऐसा राज्यक्षेत्र अभिप्रेत है, जिसको इस अधिनियम के उपबंध लागू होते हैं;

(23) “शून्य-दर पूर्ति” का वह अर्थ होगा जो धारा 16 में है;

(24) उन शब्दों और पदों के, जो इस अधिनियम में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं किन्तु केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, माल और सेवा कर (राज्यों को प्रतिकर) अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो उन अधिनियमों में हैं;

(25) इस अधिनियम में किसी ऐसी विधि, जो जम्मू-कश्मीर राज्य में प्रवृत्त नहीं है, के प्रतिनिर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह उस राज्य के संबंध में उस राज्य में प्रवृत्त तत्स्थानी विधि, यदि कोई हो, के प्रति निर्देश है।

अध्याय 2

प्रशासन

अधिकारियों की नियुक्ति।

3. बोर्ड, इस अधिनियम के अधीन शक्तियों का प्रयोग करने के लिए ऐसे केन्द्रीय कर अधिकारियों को नियुक्त कर सकेगा, जो वह ठीक समझे।

राज्य कर या संघ राज्यक्षेत्र कर के अधिकारियों का कतिपय परिस्थितियों में समुचित अधिकारी के रूप में प्राधिकार।

4. इस अधिनियम के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, राज्य माल और सेवा कर अधिनियम अथवा संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम के अधीन नियुक्त अधिकारी, ऐसे अपवादों और शर्तों के अधीन, जो सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करेगी, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए समुचित अधिकारी होने के लिए प्राधिकृत हैं।

अध्याय 3

कर का उद्ग्रहण और संग्रहण

5. (1) उपधारा (2) के उपबंधों के अध्वधीन, केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 15 के अधीन अवधारित मूल्य पर मानव उपभोग के लिए मद्यसारिक पान की पूर्ति के सिवाय माल या सेवा या दोनों की समस्त अंतरराज्यिक पूर्तियों पर एकीकृत माल और सेवा कर नामक कर उद्ग्रहीत किया जाएगा और जो चालीस प्रतिशत से अनधिक की ऐसी दर पर होगा, जो परिषद् की सिफारिशों पर सरकार द्वारा अधिसूचित की जाए और उसे ऐसी रीति में संगृहीत किया जाएगा, जो विहित की जाए और उसे कराधेय व्यक्ति द्वारा संदत्त किया जाएगा:

कर का उद्ग्रहण और संग्रहण।

1975 का 51

परन्तु भारत में आयातित माल पर एकीकृत कर सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 3 के उपबंधों के अनुसार उक्त अधिनियम के अधीन यथा अवधारित मूल्य पर उस बिन्दु पर उद्ग्रहीत और संगृहीत किया जाएगा, जब सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 12 के अधीन उक्त माल पर सीमाशुल्क उद्ग्रहीत किया जाता है।

1962 का 52

(2) अपरिष्कृत पेट्रोलियम, उच्च गति डीजल, मोटर स्प्रीट (सामान्यतया पेट्रोल के रूप में ज्ञात), प्राकृतिक गैस और विमानन टर्बाइन ईंधन की पूर्ति पर एकीकृत कर ऐसी तारीख से उद्ग्रहीत किया जाएगा, जो सरकार द्वारा परिषद् की सिफारिशों पर अधिसूचित की जाए।

(3) सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर अधिसूचना द्वारा माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति के ऐसे प्रवर्ग विनिर्दिष्ट कर सकेगी, जिस पर कर ऐसे माल या सेवाओं या दोनों के प्राप्तिकर्ता द्वारा प्रतिलोम प्रभार आधार पर संदत्त किया जाएगा और इस अधिनियम के सभी उपबंध ऐसे प्राप्तिकर्ता पर इस प्रकार लागू होंगे, मानो वह ऐसे माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति के संबंध में कर का संदाय करने के लिए दायी व्यक्ति हो।

(4) कराधेय माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति के संबंध में एकीकृत कर ऐसे पूर्तिकार द्वारा, जो रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के पास रजिस्ट्रीकृत नहीं है, ऐसे व्यक्ति द्वारा प्रतिलोम प्रभार आधार पर प्राप्तिकर्ता के रूप में संदत्त किया जाएगा और इस अधिनियम के सभी उपबंध ऐसे प्राप्तिकर्ता पर इस प्रकार लागू होंगे, मानो वह ऐसे माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति के संबंध में कर का संदाय करने के लिए दायी व्यक्ति हो।

(5) सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा सेवाओं के प्रवर्ग, अंतरराज्यिक पूर्ति पर कर विनिर्दिष्ट कर सकेगी, जो इलेक्ट्रानिक वाणिज्य आपरेटर द्वारा संदत्त किया जाएगा, यदि ऐसी सेवा की पूर्ति उसके माध्यम से की जाती है और इस अधिनियम के सभी उपबंध ऐसे इलेक्ट्रानिक वाणिज्य आपरेटर पर इस प्रकार लागू होंगे, मानो वह ऐसी सेवाओं की पूर्ति के संबंध में कर का संदाय करने के लिए दायी पूर्तिकार हो:

परन्तु जहां कोई इलेक्ट्रानिक वाणिज्य आपरेटर कराधेय राज्यक्षेत्र में स्वयं उपस्थित नहीं है, वहां कराधेय राज्यक्षेत्र में किसी भी प्रयोजन के लिए ऐसे इलेक्ट्रानिक वाणिज्य आपरेटर का प्रतिनिधित्व करने वाला कोई भी व्यक्ति कर का संदाय करने के लिए दायी होगा:

परन्तु यह और कि जहां इलेक्ट्रानिक वाणिज्य आपरेटर कराधेय राज्यक्षेत्र में स्वयं उपस्थित नहीं है और उक्त राज्यक्षेत्र में उसका कोई प्रतिनिधि भी नहीं है, वहां ऐसा इलेक्ट्रानिक वाणिज्य आपरेटर कर का संदाय करने के प्रयोजन के लिए दायी होगा, कराधेय राज्यक्षेत्र में किसी व्यक्ति को नियुक्त करेगा और ऐसा व्यक्ति कर का संदाय करने के लिए दायी होगा।

6. (1) जहां सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक है, वहां वह, परिषद् की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा, साधारणतया या तो आत्यंतिक रूप से या ऐसी शर्तों के अध्वधीन, जो उसमें विनिर्दिष्ट की जाएं, किसी विनिर्दिष्ट प्रकार के माल या सेवा या दोनों को उस पर उद्ग्रहणीय संपूर्ण कर या उसके भाग से, ऐसी तारीख से, जो ऐसी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए, छूट प्रदान कर सकेगी।

कर से छूट प्रदान करने की शक्ति।

(2) जहां सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक है, वहां वह, परिषद् की सिफारिशों पर प्रत्येक मामले पर विशेष आदेश द्वारा, उस आदेश में कथन की जाने वाली किसी आपवादिक परिस्थितियों में किसी भी माल या सेवा या दोनों पर, जिस पर कर उद्ग्रहणीय है, कर के संदाय से छूट प्रदान कर सकेगी।

(3) सरकार, यदि उपधारा (1) के अधीन जारी किसी अधिसूचना या उपधारा (2) के अधीन जारी आदेश के क्षेत्र या लागू होने को स्पष्ट करने के प्रयोजन के लिए ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझती है, तो उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना के जारी किए जाने या उपधारा (2) के अधीन आदेश के एक वर्ष के भीतर किसी भी समय अधिसूचना द्वारा यथास्थिति, ऐसी अधिसूचना या आदेश में कोई स्पष्टीकरण अंतःस्थापित कर सकेगी और ऐसा प्रत्येक स्पष्टीकरण इस प्रकार प्रभावी होगा, मानो वह सदैव, यथास्थिति, ऐसी पहली अधिसूचना या आदेश का भाग था।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, जहां किसी माल या सेवा या दोनों की बाबत उस पर उद्ग्रहणीय संपूर्ण कर या उसके भाग से आत्यंतिक रूप से छूट प्रदान की गई है, वहां ऐसे माल या सेवा या दोनों की पूर्ति करने वाला रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, माल या सेवा या दोनों की ऐसी पूर्ति पर प्रभावी दर से अधिक कर संगृहीत नहीं करेगा।

अध्याय 4

पूर्ति की प्रकृति का अवधारण

अंतरराज्यिक पूर्ति।

7. (1) धारा 10 के उपबंधों के अध्यधीन, जहां पूर्तिकार का अवस्थान और पूर्ति का स्थान—

- (क) दो भिन्न-भिन्न राज्यों में है;
- (ख) दो भिन्न-भिन्न संघ राज्यक्षेत्रों में है; या
- (ग) एक राज्य में और एक संघ राज्यक्षेत्र में है,

वहां माल की पूर्ति को अंतरराज्यिक व्यापार या वाणिज्य के अनुक्रम में माल की पूर्ति के रूप में समझा जाएगा।

(2) भारत के राज्यक्षेत्र में आयातित माल की पूर्ति को, जब तक वह भारत की सीमाशुल्क सरहद को पार करता है, अंतरराज्यिक व्यापार या वाणिज्य के अनुक्रम में माल की पूर्ति होना समझा जाएगा।

(3) धारा 12 के उपबंधों के अध्यधीन, जहां पूर्तिकार का अवस्थान और पूर्ति का स्थान—

- (क) दो भिन्न-भिन्न राज्यों में है;
- (ख) दो भिन्न-भिन्न संघ राज्यक्षेत्रों में है; या
- (ग) एक राज्य में और एक संघ राज्यक्षेत्र में है,

वहां सेवाओं की पूर्ति को अंतरराज्यिक व्यापार या वाणिज्य के अनुक्रम में सेवाओं की पूर्ति के रूप में समझा जाएगा।

(4) भारत के राज्यक्षेत्र में आयातित सेवाओं की पूर्ति को अंतरराज्यिक व्यापार या वाणिज्य के अनुक्रम में सेवाओं की पूर्ति होना समझा जाएगा।

(5) माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति को—

- (क) जब पूर्तिकार भारत में अवस्थित है और पूर्ति का स्थान भारत के बाहर है;
- (ख) किसी विशेष आर्थिक जोन विकासकर्ता या किसी विशेष आर्थिक जोन इकाई को या उसके द्वारा है; या
- (ग) कराधेय राज्यक्षेत्र में है, जो कोई अंतरराज्यिक पूर्ति नहीं है और इस धारा में अन्यत्र समाविष्ट नहीं है,

अंतरराज्यिक व्यापार या वाणिज्य के अनुक्रम में माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति के रूप में समझा जाएगा।

राज्य के भीतर पूर्ति।

8. (1) धारा 10 के उपबंधों के अध्यधीन माल की पूर्ति को, जहां पूर्तिकार की अवस्थिति और माल की पूर्ति का स्थान उसी राज्य में या उसी संघ राज्यक्षेत्र में है, राज्य के भीतर पूर्ति के रूप में समझा जाएगा:

परंतु माल की निम्नलिखित पूर्ति को राज्य के भीतर पूर्ति के रूप में नहीं समझा जाएगा, अर्थात्:—

- (i) किसी विशेष आर्थिक जोन विकासकर्ता या किसी विशेष आर्थिक जोन इकाई को या उसके द्वारा माल की पूर्ति;

(ii) भारत के राज्यक्षेत्र में आयातित माल, जब तक वह भारत की सीमाशुल्क सरहद को पार करता है;

(iii) धारा 15 में निर्दिष्ट किसी पर्यटक को की गई पूर्तियां।

(2) धारा 12 के उपबंधों के अध्वधीन, सेवाओं की पूर्ति को, जहां पूर्तिकार की अवस्थिति और सेवा की पूर्ति का स्थान उसी राज्य में या उसी संघ राज्यक्षेत्र में है, राज्य के भीतर पूर्ति के रूप में समझा जाएगा:

परंतु सेवाओं की राज्य के भीतर पूर्ति के अंतर्गत किसी आर्थिक जोन विकासकर्ता या किसी विशेष आर्थिक जोन इकाई को या उसके द्वारा सेवा की पूर्ति नहीं आएगी।

स्पष्टीकरण 1—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, जहां किसी व्यक्ति के पास,—

(i) भारत में कोई स्थापन है और भारत से बाहर कोई अन्य स्थापन है;

(ii) किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में कोई स्थापन है और उस राज्य के बाहर कोई अन्य स्थापन है;

(iii) किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में कोई स्थापन है और कोई अन्य स्थापन, जो कारबार शीर्ष है, उस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के भीतर रजिस्ट्रीकृत है,

तो ऐसे स्थापनों को विभिन्न व्यक्तियों के स्थापनों के रूप में समझा जाएगा।

स्पष्टीकरण 2—किसी राज्यक्षेत्र में किसी शाखा या किसी अभिकरण या किसी प्रतिनिधि कार्यालय के माध्यम से कारबार चलाने वाले व्यक्ति को उस राज्यक्षेत्र में स्थापन रखने वाले के रूप में समझा जाएगा।

9. इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी,—

राज्यक्षेत्रीय सागर
खंड में पूर्तियां।

(क) जहां पूर्तिकार की अवस्थिति राज्यक्षेत्रीय सागर खंड में है, वहां ऐसे पूर्तिकार की अवस्थिति को; या

(ख) जहां पूर्ति का स्थान राज्यक्षेत्रीय सागर खंड में है, वहां ऐसी पूर्ति के स्थान को,

इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, उस तटीय राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में समझा जाएगा, जहां समुचित आधार रेखा का निकटतम बिंदु अवस्थित है।

अध्याय 5

माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति का स्थान

10. (1) भारत में आयातित या भारत से निर्यातित माल की पूर्ति से भिन्न माल की पूर्ति का स्थान निम्नलिखित रूप में होगा:—

भारत में आयातित
या भारत से
निर्यातित माल की
पूर्ति से भिन्न माल
की पूर्ति का
स्थान।

(क) जहां पूर्ति में माल का संचलन अंतर्वलित है, चाहे वह पूर्तिकार द्वारा या प्राप्तिकर्ता द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा हो, ऐसे माल की पूर्ति का स्थान उस समय माल का अवस्थान होगा, जब माल का संचलन, प्राप्तिकर्ता को परिदान के लिए समाप्त होता है;

(ख) जहां माल का परिदान, पूर्तिकार द्वारा किसी प्राप्तिकर्ता या किसी अन्य व्यक्ति को किसी तीसरे व्यक्ति के निदेश पर, चाहे वह अभिकर्ता के रूप में या अन्यथा कार्य कर रहा हो, माल के संचलन से पहले या उसके दौरान या तो माल के हक के दस्तावेज के अंतरण के रूप में या अन्यथा किया जाता है, वहां यह समझा जाएगा कि उक्त तीसरे व्यक्ति ने माल प्राप्त किया है और ऐसे माल की पूर्ति का स्थान ऐसे व्यक्ति के कारबार का मूल स्थान होगा;

(ग) जहां पूर्ति में माल का संचलन अंतर्वलित नहीं है, चाहे वह पूर्तिकार द्वारा हो या प्राप्तिकर्ता द्वारा, वहां पूर्ति का स्थान प्राप्तिकर्ता को परिदान के समय ऐसे माल का अवस्थान होगा;

(घ) जहां माल का समंजन या संस्थापन किसी स्थल पर किया जाता है, वहां पूर्ति का स्थान ऐसे संस्थापन या समंजन का स्थान होगा;

(ड) जहां माल की पूर्ति किसी वाहन के फलक पर की जाती है, जिसके अंतर्गत कोई जलयान, कोई वायुयान, कोई ट्रेन या कोई मोटरयान भी है, वहां पूर्ति का स्थान वह अवस्थान होगा, जिस पर ऐसा माल फलक पर लिया जाता है।

(2) जहां माल की पूर्ति के स्थान का अवधारण नहीं किया जा सकता, वहां पूर्ति का स्थान ऐसी रीति में अवधारित किया जाएगा, जो विहित की जाए।

भारत में आयातित
या भारत से
निर्यातित माल की
पूर्ति का स्थान।

11. माल की पूर्ति का स्थान—

- (क) भारत में आयातित है, तो आयातकर्ता का अवस्थान होगा;
- (ख) भारत से निर्यातित है, तो भारत के बाहर का अवस्थान होगा।

सेवाओं की पूर्ति
का स्थान, जहां
पूर्तिकर्ता और
प्राप्तिकर्ता का
अवस्थान भारत में
है।

12. (1) इस धारा के उपबंध सेवाओं की पूर्ति के स्थान को अवधारित करने के लिए वहां लागू होंगे, जहां सेवाओं की पूर्तिकर्ता का अवस्थान और सेवाओं के प्राप्तिकर्ता का अवस्थान भारत में है।

(2) उपधारा (3) से उपधारा (14) में विनिर्दिष्ट सेवाओं के सिवाय सेवाओं की पूर्ति का स्थान,—

- (क) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को की गई है, तो ऐसे व्यक्ति का अवस्थान होगा;
- (ख) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति से भिन्न किसी भी व्यक्ति को की गई है तो,—

(i) प्राप्तिकर्ता का अवस्थान होगा, जहां अभिलेख पर पता विद्यमान है; और

(ii) अन्य मामलों में सेवाओं की पूर्तिकर्ता का अवस्थान होगा।

(3) (क) किसी स्थावर संपत्ति के संबंध में प्रत्यक्षतः सेवाओं की पूर्ति का स्थान, जिसके अंतर्गत वास्तुविद, आंतरिक सज्जाकार, सर्वेक्षक, इंजीनियर और अन्य संबंधित विशेषज्ञ या संपदा अभिकर्ता द्वारा प्रदान की गई सेवाएं भी हैं, स्थावर संपत्ति के उपयोग का अधिकार प्रदान करने के रूप में दी गई या संनिर्माण कार्य को करने या उसे समन्वित करने के लिए किसी सेवा का स्थान; या

(ख) किसी होटल, सराय, अतिथि-गृह, गृह-निवास, क्लब या शिविर स्थान द्वारा चाहे जिस नाम से ज्ञात हो, जिसके अंतर्गत हाउस बोट या कोई अन्य जलयान भी है, वास-सुविधा के रूप में सेवाओं की पूर्ति का स्थान; या

(ग) कोई विवाह या स्वागत समारोह या उससे संबंधित मामलों को आयोजित करने के लिए, शासकीय, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक या कारबार समारोह, जिसके अंतर्गत ऐसी संपत्ति पर ऐसे समारोह के संबंध में दी गई सेवाएं भी हैं, के लिए किसी स्थावर संपत्ति में वास-सुविधा के रूप में सेवाओं की पूर्ति का स्थान; या

(घ) खंड (क), खंड (ख) और खंड (ग) में निर्दिष्ट सेवाओं की अनुषंगी किन्हीं सेवाओं की पूर्ति का स्थान,

वह अवस्थान होगा, जिस पर, यथास्थिति, स्थावर संपत्ति या नौका या जलयान अवस्थित है या अवस्थित होना आशयित है:

परंतु यदि स्थावर संपत्ति या नौका या जलयान का अवस्थान भारत से बाहर अवस्थित है या अवस्थित होना आशयित है, तो पूर्ति का स्थान प्राप्तिकर्ता का अवस्थान होगा।

स्पष्टीकरण — जहां स्थावर संपत्ति या नौका या जलयान एक से अधिक राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में अवस्थित है, वहां सेवाओं की पूर्ति को प्रत्येक क्रमिक राज्य या संघ राज्यक्षेत्रों में इस बाबत की गई संविदा या करार के निबंधनानुसार सेवाओं के लिए पृथक्तः संगृहीत या अवधारित मूल्य के अनुपात में किया गया समझा जाएगा या ऐसी संविदा या करार के अभाव में ऐसे अन्य आधार पर किया गया समझा जाएगा, जो विहित किया जाए।

(4) रेस्त्रां और खानपान सेवाओं, व्यक्तिगत श्रृंगार, स्वस्थता, सौन्दर्य उपचार, स्वास्थ्य सेवा, जिसके अंतर्गत प्रसाधन सामग्री और प्लास्टिक शल्यक्रिया भी है, की पूर्ति का स्थान वह अवस्थान होगा, जहां सेवाएं वास्तविक रूप से दी जाती हैं।

(5) (क) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को प्रशिक्षण और कार्य-निष्पादन के मूल्यांकन से संबंधित सेवाओं की पूर्ति का स्थान ऐसे व्यक्ति का अवस्थान होगा;

(ख) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति से भिन्न किसी व्यक्ति को प्रशिक्षण और कार्य-निष्पादन के मूल्यांकन से संबंधित सेवाओं की पूर्ति का स्थान वह अवस्थान होगा, जहां सेवाएं वास्तविक रूप से दी जाती हैं।

(6) किसी सांस्कृतिक, कलात्मक, खेलकूद, वैज्ञानिक, शैक्षणिक, मनोरंजन समारोह या आमोद-प्रमोद बाड़ा या किसी अन्य स्थान में प्रवेश के रूप में दी गई सेवाओं और उसकी सहायक सेवाओं की पूर्ति का स्थान, वह स्थान होगा, जहां वास्तविक रूप से समारोह आयोजित किया जाता है या जहां पर बाड़ा या ऐसा अन्य स्थान अवस्थित है।

(7) (क) किसी सांस्कृतिक, कलात्मक, खेलकूद, वैज्ञानिक, शैक्षणिक या मनोरंजन समारोह के आयोजन के रूप में दी गई सेवाओं की पूर्ति का स्थान, जिसके अंतर्गत किसी सम्मेलन, मेला, प्रदर्शनी, अनुष्ठान या इसी प्रकार के समारोहों के संबंध में सेवाओं की पूर्ति भी है, ऐसे व्यक्ति का अवस्थान होगा; या

(ख) किसी समारोह को आयोजित करने के लिए अनुषंगी सेवाएं या खंड (क) में निर्दिष्ट सेवाएं या ऐसे समारोहों के प्रायोजन का समनुदेशन,—

(i) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को किया जाता है तो ऐसे व्यक्ति का अवस्थान होगा;

(ii) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति से भिन्न किसी व्यक्ति को किया जाता है तो वह स्थान होगा, जहां समारोह वास्तविक रूप से आयोजित किया जाता है और यदि समारोह भारत के बाहर आयोजित किया जाता है, तो पूर्ति का स्थान प्राप्तकर्ता का अवस्थान होगा।

स्पष्टीकरण — जहां समारोह एक से अधिक राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में आयोजित किया जाता है और ऐसे समारोह से संबंधित सेवाओं की पूर्ति के लिए संचित रकम प्रभारित की जाती है तो ऐसी सेवाओं के स्थान को इस बाबत की गई संविदा या करार के निबंधनानुसार सेवाओं के लिए पृथक्: संगृहीत या अवधारित मूल्य के अनुपात में प्रत्येक क्रमिक राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में होने के रूप में लिया जाएगा।

(8) (क) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को माल के परिवहन, जिसके अंतर्गत मेल या कुरिअर द्वारा भी आते हैं, के रूप में सेवाओं की पूर्ति का स्थान ऐसे व्यक्ति का अवस्थान होगा;

(ख) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति से भिन्न व्यक्ति को माल के परिवहन, जिसके अंतर्गत मेल या कुरिअर द्वारा भी आते हैं, के रूप में सेवाओं की पूर्ति का स्थान वह अवस्थान होगा, जिस पर ऐसा माल उसके परिवहन के लिए सौंपा जाता है;

(9) (क) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को यात्री परिवहन सेवा की पूर्ति का स्थान, ऐसे व्यक्ति का अवस्थान होगा;

(ख) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति से भिन्न व्यक्ति को यात्री परिवहन सेवा की पूर्ति का स्थान, वह स्थान होगा, जहां यात्री निरंतर यात्रा के लिए वाहन पर चढ़ता है;

परंतु जहां मार्गाधिकार किसी भावी उपयोग के लिए दिया गया है और चढ़ने का बिन्दु मार्गाधिकार जारी करने के समय ज्ञात नहीं है तो ऐसी सेवा की पूर्ति का स्थान उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार अवधारित किया जाएगा।

स्पष्टीकरण — इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, वापसी यात्रा को एक पृथक् यात्रा के रूप में समझा जाएगा, चाहे आगे की और वापसी यात्रा का मार्गाधिकार एक ही समय जारी किया गया हो।

(10) किसी वाहन के फलक पर, जिसके अंतर्गत कोई जलयान, कोई वायुयान, कोई ट्रेन या कोई मोटर यान भी है, सेवा की पूर्ति का स्थान यात्रा के लिए उस वाहन के प्रस्थान के पहले अनुसूचित बिन्दु का अवस्थान होगा।

(11) किसी व्यक्ति को दूरसंचार सेवाओं की, जिसके अंतर्गत डाटा ट्रांसफर, प्रसारण, केबल और डायरेक्ट टू होम दूरदर्शन सेवा भी है, पूर्ति का स्थान—

(क) स्थिर दूरसंचार लाइन, लीज्ड सर्किट, इंटरनेट लीज्ड सर्किट, केबल या डिश एन्टिना के रूप में सेवाओं की दशा में वह अवस्थान होगा, जहां दूरसंचार लाइन, लीज्ड सर्किट या केबल कनेक्शन या डिश एन्टिना सेवाओं की प्राप्ति के लिए संस्थापित किया जाता है;

(ख) पश्च संदाय आधार पर प्रदान की गई दूरसंचार और इंटरनेट सेवाओं के लिए मोबाइल कनेक्शन की दशा में सेवाओं के पूर्तिकर्ता के अभिलेख पर सेवाओं के प्राप्तिकर्ता के बिलिंग पते का स्थान होगा;

(ग) उन मामलों में, जहां दूरसंचार के लिए मोबाइल कनेक्शन, इंटरनेट सेवा और डायरेक्ट टू होम दूरदर्शन सेवाएं, किसी वाउचर या किसी अन्य साधन के माध्यम से पूर्व संदाय आधार पर,—

(i) किसी विक्रय अभिकर्ता या किसी पुनःविक्रेता या सब्सक्राइबर आईडेंटिटी मोड्यूल कार्ड या रिचार्ज वाउचर के वितरक के माध्यम से प्रदान की जाती है, वहां पूर्ति के समय पूर्तिकर्ता के अभिलेख के अनुसार विक्रय अभिकर्ता या पुनः विक्रेता या वितरक के पते का स्थान होगा;

(ii) अंतिम सब्सक्राइबर को किसी व्यक्ति द्वारा प्रदान की जाती है, वहां वह अवस्थान होगा, जहां ऐसा पूर्व संदाय प्राप्त किया गया है या ऐसे वाउचर बेचे गए हैं;

(घ) अन्य दशाओं में, सेवाओं के पूर्तिकार के अभिलेख के अनुसार प्राप्तिकर्ता का पता होगा और जहां ऐसा पता उपलब्ध नहीं है, वहां सेवाओं के पूर्तिकार का अवस्थान पूर्ति का स्थान होगा:

परंतु जहां सेवाओं के पूर्तिकार के अभिलेख के अनुसार प्राप्तिकर्ता का पता उपलब्ध नहीं है, वहां सेवाओं के पूर्तिकार का अवस्थान पूर्ति का स्थान होगा:

परंतु यह और कि यदि इंटरनेट बैंकिंग या संदाय के अन्य इलेक्ट्रॉनिक पद्धति के माध्यम से ऐसी पूर्व संदाय सेवा प्राप्त की जाती है या रिचार्ज किया जाता है, तो सेवाओं के पूर्तिकार के अभिलेख में सेवाओं के प्राप्तिकर्ता का अवस्थान ऐसी सेवाओं की पूर्ति का स्थान होगा।

स्पष्टीकरण — जहां लीज्ड सर्किट को एक से अधिक राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में संस्थापित किया गया और ऐसी सर्किट के संबंध में सेवाओं की पूर्ति के लिए संचित रकम प्रभारित की जाती है, वहां ऐसी सेवाओं की पूर्ति के स्थान को इस बाबत की गई संविदा या करार के निबंधनानुसार सेवाओं के लिए पृथक्: संगृहीत या अवधारित मूल्य के अनुपात में प्रत्येक क्रमिक राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में होने के रूप में, या ऐसी संविदा या करार के अभाव में ऐसे अन्य आधार पर, जो विहित किया जाए, लिया जाएगा।

(12) बैंककारी और अन्य वित्तीय सेवाओं की पूर्ति का स्थान, जिसके अंतर्गत किसी व्यक्ति को स्टॉक ब्रोकिंग सेवाएं भी हैं, सेवाओं के पूर्तिकार के अभिलेख में सेवाओं के प्राप्तिकर्ता का अवस्थान होगा:

परंतु यदि सेवाओं के प्राप्तिकर्ता का अवस्थान पूर्तिकार के अभिलेख में नहीं है, तो पूर्ति का स्थान पूर्तिकार का स्थान होगा।

(13) बीमा सेवाओं की,—

(क) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को पूर्ति का स्थान ऐसे व्यक्ति का अवस्थान होगा;

(ख) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति से भिन्न किसी व्यक्ति को पूर्ति का स्थान सेवाओं के पूर्तिकार के अभिलेख में सेवाओं के प्राप्तिकर्ता का अवस्थान होगा।

(14) केन्द्रीय सरकार, किसी राज्य सरकार, किसी कानूनी निकाय या किसी स्थानीय प्राधिकरण को संविदा या करार में परिलक्षित राज्यों या संघ राज्यक्षेत्रों के लिए आशयित विज्ञापन सेवाओं की पूर्ति के स्थान को ऐसे प्रत्येक राज्य या संघ राज्यक्षेत्र होने के रूप में लिया जाएगा और प्रत्येक राज्य या संघ राज्यक्षेत्र को ऐसी विनिर्दिष्ट पूर्ति का मूल्य इस बाबत की गई संविदा या करार के निबंधनानुसार यथा अवधारित क्रमिक राज्यों या संघ राज्यक्षेत्रों में प्रसार के रूप में दी गई सेवाओं के कारण दी गई रकम के अनुपात में होगा या ऐसे संविदा या करार के अभाव में ऐसे अन्य आधार पर, जो विहित किया जाए, होगा।

13. (1) इस धारा के उपबंध सेवाओं की पूर्ति का स्थान अवधारित करने के लिए वहां लागू होंगे, जहां सेवाओं के पूर्तिकार का अवस्थान या सेवाओं के प्राप्तिकर्ता का स्थान भारत से बाहर है।

(2) उपधारा (3) से उपधारा (13) में विनिर्दिष्ट सेवाओं के सिवाय सेवाओं की पूर्ति का स्थान सेवाओं के प्राप्तिकर्ता का अवस्थान होगा:

परंतु जहां सेवाओं के प्राप्तिकर्ता का अवस्थान कारबार के सामान्य अनुक्रम में उपलब्ध नहीं है, वहां पूर्ति का स्थान सेवाओं के पूर्तिकार का अवस्थान होगा।

(3) निम्नलिखित सेवाओं की पूर्ति का स्थान वह अवस्थान होगा, जहां वास्तविक रूप से सेवाएं प्रदान की जाती हैं, अर्थात्:—

(क) ऐसे माल की बाबत पूर्ति की गई सेवाएं, जिसमें सेवाओं के प्राप्तिकर्ता द्वारा सेवाएं प्रदान किए जाने के लिए, सेवाओं के पूर्तिकार या सेवाओं के पूर्तिकार की ओर से कार्य करने वाले किसी व्यक्ति के पास वस्तुतः उपलब्ध होना अपेक्षित है:

परंतु जब ऐसी सेवाएं इलेक्ट्रॉनिक साधनों के रूप में दूरस्थ अवस्थान से प्रदान की जाती हैं, तब पूर्ति का स्थान वह अवस्थान होगा, जहां माल सेवा की पूर्ति के समय स्थित है:

परंतु यह और कि इस खंड में अंतर्विष्ट कोई बात माल की बाबत पूर्ति की गई ऐसी सेवाओं की दशा में लागू नहीं होगी, जो भारत में मरम्मत के लिए अस्थायी रूप से आयात की गई है और ऐसी मरम्मत के लिए जो अपेक्षित है, उससे भिन्न भारत में किसी अन्य उपयोग में लिए बिना मरम्मत के पश्चात् निर्यात कर दी जाती है;

(ख) किसी व्यक्ति को पूर्ति की गई सेवाएं, जो या तो सेवाओं के प्राप्तिकर्ता के रूप में या प्राप्तिकर्ता की ओर से कार्य करने वाले व्यक्ति के रूप में प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें सेवाओं की पूर्ति के लिए पूर्तिकर्ता के साथ प्राप्तिकर्ता या उसकी ओर से कार्य करने वाले व्यक्ति की वस्तुतः उपस्थिति अपेक्षित है।

(4) किसी स्थावर संपत्ति के संबंध में पूर्ति, जिसके अंतर्गत विशेषज्ञों और संपदा अधिकर्ताओं द्वारा इस संबंध में पूर्ति की गई सेवाएं भी हैं, किसी होटल, सराय, अतिथि-गृह, क्लब या शिविर स्थल, जिस भी नाम से ज्ञात हो, में वास-सुविधा की पूर्ति, स्थावर संपत्ति के उपयोग के अधिकार को प्रदान किए जाने का, संनिर्माण कार्य, जिसके अंतर्गत वास्तुविद या आंतरिक सज्जाकार भी हैं, को कार्यान्वित करने या उसका समन्वय करने के लिए सेवाओं की पूर्ति के संबंध में प्रत्यक्षतः पूर्ति की गई सेवाओं की पूर्ति का स्थान वह स्थान होगा, जहां स्थावर संपत्ति अवस्थित है या अवस्थित होनी आशयित है।

(5) किसी सांस्कृतिक, कलात्मक, खेलकूद, वैज्ञानिक, शैक्षणिक या मनोरंजन समारोह या अनुष्ठान या सम्मेलन, मेला, प्रदर्शनी या उसी प्रकार के समारोहों में प्रवेश के रूप में पूर्ति की गई सेवाओं और ऐसे प्रवेश या संगठन की सहायक सेवाओं की पूर्ति का स्थान, वह स्थान होगा, जहां वास्तविक रूप से समारोह आयोजित किया जाता है।

(6) जहां उपधारा (3) उपधारा (4) और उपधारा (5) में निर्दिष्ट किन्हीं सेवाओं की पूर्ति एक से अधिक अवस्थानों पर की जाती है, जिसके अंतर्गत कराधेय राज्यक्षेत्र में अवस्थान भी है, उनकी पूर्ति का स्थान, कराधेय राज्यक्षेत्र में अवस्थान होगा।

(7) जहां उपधारा (3), उपधारा (4) और उपधारा (5) में निर्दिष्ट सेवाओं की पूर्ति एक से अधिक राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में की जाती है, वहां ऐसी सेवाओं की पूर्ति के स्थान को ऐसे प्रत्येक राज्य या संघ राज्यक्षेत्र होने के रूप में लिया जाएगा और प्रत्येक राज्य या संघ राज्यक्षेत्र को ऐसी विनिर्दिष्ट पूर्ति का मूल्य इस बाबत की गई संविदा या करार के निबंधनानुसार सेवाओं के लिए पृथक्: संगृहीत या अवधारित मूल्य के अनुपात में प्रत्येक क्रमिक राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में होने के रूप में, या ऐसी संविदा या करार के अभाव में ऐसे अन्य आधार पर, जो विहित किया जाए, लिया जाएगा।

सेवाओं की पूर्ति का स्थान, जहां पूर्तिकार का अवस्थान या प्राप्तिकर्ता का अवस्थान भारत से बाहर है।

(8) निम्नलिखित सेवाओं की पूर्ति का स्थान सेवाओं के पूर्तिकार का अवस्थान होगा, अर्थात्:—

(क) किसी बैंककारी कंपनी या किसी वित्तीय संस्था या किसी गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनी द्वारा खाता धारकों को पूर्ति की गई सेवाएं;

(ख) मध्यवर्ती सेवाएं;

(ग) ऐसी सेवाएं, जिसमें परिवहन के साधनों को एक मास की अवधि तक के लिए किराए पर लेना सम्मिलित है, जिसके अंतर्गत नौका भी है, किन्तु जिसके अंतर्गत वायुयान और जलयान नहीं हैं;

स्पष्टीकरण — इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए,—

(क) “खाता” पद से जमाकर्ता को ब्याज देने वाला कोई खाता अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत कोई अनिवासी विदेशी खाता और कोई अनिवासी साधारण खाता भी है;

(ख) “बैंककारी कंपनी” पद का वही अर्थ होगा, जो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45क के खंड (क) में है; 1934 का 2

(ग) “वित्तीय संस्था” पद का वही अर्थ होगा, जो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 51झ के खंड (ग) में है; 1934 का 2

(घ) “गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनी” पद से निम्नलिखित अभिप्रेत हैं, —

(i) कोई वित्तीय संस्था, जो कोई कंपनी है;

(ii) कोई गैर-बैंककारी संस्था, जो कोई कंपनी है और जिसका मुख्य कारबार, किसी स्कीम या ठहराव या किसी अन्य रीति के अधीन निक्षेप प्राप्त करना या किसी रीति में उधार देना है; या

(iii) ऐसी अन्य गैर-बैंककारी संस्था या ऐसी संस्थाओं का वर्ग, जो भारतीय रिजर्व बैंक, केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे।

(9) मेल या कुरिअर के रूप में माल के परिवहन से भिन्न माल के परिवहन की सेवाओं की पूर्ति का स्थान ऐसे माल का गंतव्य स्थान होगा।

(10) यात्री परिवहन सेवाओं की बाबत पूर्ति का स्थान, वह स्थान होगा, जहां यात्री निरंतर यात्रा के लिए वाहन पर चढ़ता है।

(11) किसी यात्री परिवहन प्रचालन के प्रक्रम के दौरान वाहन के फलक पर प्रदान की गई सेवाओं की पूर्ति का स्थान, जिसके अंतर्गत फलक पर रहते पूर्णतः या सारतः उपभोग किए जाने के लिए आशयित सेवाएं भी हैं, यात्रा के लिए उस वाहन के प्रस्थान का प्रथम अनुसूचित बिन्दु होगा।

(12) आनलाइन सूचना और डाटाबेस पहुंच या सुधार सेवाओं की पूर्ति का स्थान सेवाओं के प्राप्तिकर्ता का अवस्थान होगा।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, ऐसी सेवाओं को प्राप्त करने वाला व्यक्ति कराधेय राज्यक्षेत्र से अवस्थित होना समझा जाएगा यदि निम्नलिखित में से कोई दो गैर-विरोधात्मक शर्तों को पूरा किया जाता है, अर्थात्:—

(क) इंटरनेट के माध्यम से सेवाओं के प्राप्तिकर्ता द्वारा प्रस्तुत किए गए पते का अवस्थान कराधेय राज्यक्षेत्र में है;

(ख) क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड या स्टोर वैल्यू कार्ड या चार्ज कार्ड या स्मार्ट कार्ड या कोई अन्य कार्ड, जिसके द्वारा सेवाओं का प्राप्तिकर्ता संदाय का परिनिर्धारण करता है, कराधेय राज्यक्षेत्र में जारी किया गया है;

(ग) सेवाओं के प्राप्तिकर्ता का बिलिंग पता कराधेय राज्यक्षेत्र में है;

(घ) सेवाओं के प्राप्तिकर्ता द्वारा प्रयोग किए गए यंत्र का इंटरनेट प्रोटोकाल पता कराधेय राज्यक्षेत्र में है;

(ङ) सेवाओं के प्राप्तिकर्ता का बैंक, जिसमें वह संदाय के लिए प्रयोग किया गया खाता रखता है, कराधेय राज्यक्षेत्र में है;

(च) सेवाओं के प्राप्तिकर्ता द्वारा प्रयोग किया गया सब्सक्राइबर आईडेंटिटी माड्यूल कार्ड का कंट्री कोड कराधेय राज्यक्षेत्र में है;

(छ) उस स्थिर लैंड लाइन का अवस्थान, जिसके माध्यम से प्राप्तिकर्ता द्वारा सेवा प्राप्त की जाती है, कराधेय राज्यक्षेत्र में है।

(13) किसी सेवा की पूर्ति के दोहरे कराधान या गैर-कराधान के निवारण के लिए या नियमों के एकरूपता से लागू होने के लिए सरकार को सेवाओं के किसी प्रकार को या परिस्थितियों को अधिसूचित करने की शक्ति होगी, जिसमें पूर्ति का स्थान सेवा के प्रभावी उपयोग और सेवा के उपभोग का स्थान होगा।

14. (1) किसी गैर-कराधेय राज्यक्षेत्र में अवस्थित किसी व्यक्ति द्वारा आनलाइन सूचना और डाटाबेस पहुंच या सुधार सेवाओं की पूर्ति पर और जो गैर-कराधेय आनलाइन प्राप्तिकर्ता द्वारा प्राप्त की जाती है, किसी गैर-कराधेय राज्यक्षेत्र में अवस्थित सेवाओं का पूर्तिकार वह व्यक्ति होगा, जो सेवाओं की ऐसी पूर्ति पर एकीकृत कर के संदाय के लिए दायी होगा:

पूर्तिकार द्वारा
आनलाइन सूचना
और डाटाबेस
पहुंच या सुधार
सेवाओं के कर
का संदाय करने
का विशेष उपबंध।

परंतु गैर-कराधेय राज्यक्षेत्र में अवस्थित किसी व्यक्ति द्वारा आनलाइन सूचना और डाटाबेस पहुंच या सुधार सेवाओं की पूर्ति और जो गैर-कराधेय आनलाइन प्राप्तिकर्ता द्वारा प्राप्त की जाती है, की दशा में गैर-कराधेय राज्यक्षेत्र में अवस्थित ऐसे मध्यवर्ती को, जो ऐसी सेवाओं की पूर्ति का प्रबंध करता है या उसको सुकर बनाता है, गैर-कराधेय राज्यक्षेत्र में सेवाओं के पूर्तिकार और गैर-कराधेय आनलाइन प्राप्तिकर्ता को ऐसी सेवाओं की पूर्ति करने से ऐसी सेवाओं को प्राप्तिकर्ता समझा जाएगा सिवाय जब ऐसा मध्यवर्ती निम्नलिखित शर्तों को पूरा करता है, अर्थात्:—

(क) पूर्ति में भाग लेने वाले ऐसे मध्यवर्ती द्वारा बीजक, ग्राहक के बिल या जारी या उपलब्ध कराई गई रसीद में प्रश्नगत सेवा और उसके पूर्तिकार को गैर-कराधेय राज्यक्षेत्र में स्पष्टतः परिलक्षित किया गया है;

(ख) पूर्ति में सम्मिलित मध्यवर्ती ग्राहक के प्रभार को प्राधिकृत नहीं करता है या उसके प्रभार में भाग नहीं लेता है, जो मध्यवर्ती न तो किसी भी रीति में संदाय को संगृहीत करता है या उस पर कार्रवाई करता है, न ही गैर-कराधेय आनलाइन प्राप्तिकर्ता और ऐसी पूर्ति के पूर्तिकार के बीच संदाय के लिए उत्तरदायी है;

(ग) पूर्ति में सम्मिलित मध्यवर्ती परिदान को प्राधिकृत नहीं करता है; और

(घ) पूर्ति के साधारण निबंधन और शर्तें, पूर्ति में सम्मिलित मध्यवर्ती द्वारा नहीं बल्कि सेवाओं के पूर्तिकार द्वारा निश्चित की जाती हैं।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट आनलाइन सूचना और डाटाबेस पहुंच या सुधार सेवाओं का पूर्तिकार एकीकृत करके संदाय के लिए सरकार द्वारा अधिसूचित की जाने वाली सरलीकृत रजिस्ट्रीकरण स्कीम के अधीन एकल रजिस्ट्रीकरण लेता है:

परंतु कराधेय राज्यक्षेत्र में किसी प्रयोजन के लिए ऐसे पूर्तिकार का प्रतिनिधित्व करने वाला कराधेय राज्यक्षेत्र में अवस्थित कोई भी व्यक्ति स्वयं को रजिस्ट्रीकृत कराएगा और पूर्तिकार की ओर से एकीकृत कर का संदाय करेगा:

परंतु यह और कि यदि ऐसा पूर्तिकार कराधेय राज्यक्षेत्र में वस्तुतः उपस्थित नहीं है या किसी प्रयोजन के लिए कोई प्रतिनिधि नहीं रखता है, तो वह एकीकृत कर का संदाय करने के प्रयोजन के लिए कराधेय राज्यक्षेत्र में किसी व्यक्ति को नियुक्त कर सकेगा और ऐसा व्यक्ति ऐसे कर के संदाय के लिए दायी होगा।

अध्याय 6

अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक को एकीकृत कर का प्रतिदाय

भारत छोड़ने वाले पर्यटक को माल की पूर्ति पर संदत्त एकीकृत कर का प्रतिदाय।

15. भारत छोड़ने वाले पर्यटक द्वारा भारत के बाहर उसके द्वारा ले जाए गए माल की किसी पूर्ति पर संदत्त एकीकृत कर का प्रतिदाय, ऐसी रीति में और ऐसी शर्तों और रक्षोपायों के अध्वधीन, जो विहित किए जाएं, किया जाएगा।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, “पर्यटक” पद से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो भारत में सामान्यतः निवासी नहीं है, जो विधि सम्मत गैर-अप्रवास प्रयोजनों के लिए छह मास से अनधिक रुकने के लिए भारत में प्रवेश करता है।

अध्याय 7

शून्य दर पूर्ति

शून्य दर पूर्ति।

16. (1) “शून्य दर पूर्ति” से माल या सेवाओं या दोनों की निम्नलिखित कराधेय पूर्तियां अभिप्रेत हैं, अर्थात्:—

(क) माल या सेवा या दोनों का निर्यात; या

(ख) किसी विशेष आर्थिक जोन विकासकर्ता या किसी विशेष आर्थिक जोन इकाई को माल या सेवाएं या दोनों की पूर्ति।

(2) केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (5) के उपबंधों के अध्वधीन शून्य दर पूर्तियां करने के लिए इनपुट कर का प्रत्यय इस बात के होते हुए भी प्राप्त किया जा सकेगा कि ऐसी पूर्ति कोई छूट प्राप्त पूर्ति हो सकेगी।

(3) माल या सेवा या दोनों का निर्यात करने वाला रजिस्ट्रीकृत कोई व्यक्ति केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 54 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार निम्नलिखित विकल्पों में किसी के अधीन प्रतिदाय का दावा करने का पात्र होगा, अर्थात्:—

(क) वह एकीकृत कर के संदाय बिना ऐसी शर्तों रक्षापायों और प्रक्रिया के अध्वधीन, जो विहित किए जाएं, बंधपत्र या वचनबंध पत्र के अधीन माल या सेवाओं या दोनों का निर्यात कर सकेगा और अनुपयोजित इनपुट कर प्रत्यय के प्रतिदाय का दावा कर सकेगा; या

(ख) वह पूर्ति किए गए माल या सेवाओं या दोनों पर एकीकृत कर के संदाय पर ऐसी शर्तों, रक्षापायों और प्रक्रिया के अध्वधीन, जो विहित की जाएं, माल या सेवा या दोनों की पूर्ति कर सकेगा और ऐसे संदत्त कर के प्रतिदाय का दावा कर सकेगा।

अध्याय 8

कर का प्रभाजन और निधियों का व्यवस्थापन

कर का प्रभाजन और निधियों का व्यवस्थापन।

17. (1) केन्द्रीय सरकार को संदत्त किए गए एकीकृत कर में से,—

(क) केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 10 के अधीन कर का संदाय करने वाले किसी अरजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को या किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को माल या सेवाओं या दोनों की अंतरराज्यिक पूर्ति की बाबत;

(ख) माल या सेवाओं या दोनों की अंतरराज्यिक पूर्ति की बाबत, जहां रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति इनपुट कर प्रत्यय के लिए पात्र नहीं है;

(ग) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को किसी वित्तीय वर्ष में माल या सेवा या दोनों की, की गई अंतरराज्यिक पूर्ति की बाबत, जहां वह विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर इनपुट कर प्रत्यय को प्राप्त नहीं करता है और इस प्रकार ऐसे वर्ष के लिए, जिसमें पूर्ति की गई थी, वार्षिक विवरणी देने के लिए देय तारीख के अवसान के पश्चात् एकीकृत कर खाते में बना रहता है;

(घ) केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 10 के अधीन कर का संदाय करने वाले किसी अरजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा या रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा माल या सेवाओं या दोनों के आयात की बाबत;

(ङ) माल या सेवाओं या दोनों की आयात की बाबत, जहां रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति इनपुट कर प्रत्यय के लिए पात्र नहीं है;

(च) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा किसी वित्तीय वर्ष में माल या सेवाओं या दोनों के किए गए आयात की बाबत, जहां वह विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर उक्त प्रत्यय को प्राप्त नहीं करता है और इस प्रकार ऐसे वर्ष के लिए, जिसमें पूर्ति प्राप्त की गई थी, वार्षिक विवरणी देने के लिए देय तारीख के अवसान के पश्चात् एकीकृत कर खाते में बना रहता है,

उसी प्रकार की राज्य के भीतर पूर्ति कर केन्द्रीय कर के समतुल्य दर पर संगणित कर की रकम केन्द्रीय सरकार को प्रभाजित की जाएगी।

(2) उस पूर्ति की बाबत, जिसके लिए केन्द्रीय सरकार को उपधारा (1) के अधीन प्रभाजन किया गया है, एकीकृत कर खाते में शेष एकीकृत कर की अतिशेष रकम का प्रभाजन,—

(क) ऐसे राज्य को किया जाएगा, जहां ऐसी पूर्ति की जाती है; और

(ख) केन्द्रीय सरकार को किया जाएगा, जहां ऐसी पूर्ति किसी संघ राज्यक्षेत्र में की जाती है:

परंतु जहां किसी कराधेय व्यक्ति द्वारा की गई ऐसी पूर्ति का स्थान पृथकतः अवधारित नहीं किया जा सकता, वहां उक्त अतिशेष रकम का प्रभाजन,—

(क) प्रत्येक राज्य को; और

(ख) संघ राज्यक्षेत्रों के संबंध में केन्द्रीय सरकार को,

किसी वित्तीय वर्ष में, यथास्थिति, प्रत्येक ऐसे राज्य या संघ राज्यक्षेत्रों को ऐसे कराधेय व्यक्ति द्वारा की गई कुल पूर्तियों के अनुपात में किया जाएगा:

परंतु यह और कि जहां ऐसी पूर्तियां करने वाला कराधेय व्यक्ति पहचान योग्य नहीं है, वहां उक्त अतिशेष रकम का प्रभाजन, ठीक पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान, यथास्थिति, अपने-अपने राज्य द्वारा या केन्द्रीय सरकार द्वारा यथास्थिति, राज्य कर या संघ राज्य कर के रूप में संगृहीत रकम के अनुपात में सभी राज्यों और केन्द्रीय सरकार को किया जाएगा।

(3) एकीकृत कर के प्रभाजन से संबंधित उपधारा (1) और उपधारा (2) के उपबंध यथावश्यक परिवर्तनों सहित इस प्रकार प्रभाजित कर के संबंध में वसूल किए गए ब्याज, शास्ति और शमन की गई रकम के प्रभाजन को लागू होंगे।

(4) जहां किसी रकम का प्रभाजन उपधारा (1), उपधारा (2) और उपधारा (3) के अधीन केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार को किया गया है, वहां एकीकृत कर के रूप में संगृहीत रकम में से इस प्रकार प्रभाजित रकम के बराबर रकम को घटा दिया जाएगा और केन्द्रीय सरकार, ऐसी रीति में और ऐसे समय के भीतर, जो विहित किए जाएं, केन्द्रीय सरकार को प्रभाजित क्रमिक रकम के बराबर रकम को केन्द्रीय कर खाते या संघ राज्यक्षेत्र कर खाते में अंतरित कर देगी और उस राज्य को प्रभाजित रकम के बराबर रकम को क्रमिक राज्य के राज्य कर खाते में अंतरित कर देगी।

(5) किसी संघ राज्यक्षेत्र के मद्दे, यथास्थिति, किसी राज्य या केन्द्रीय सरकार को प्रभाजित कोई भी एकीकृत कर, यदि तत्पश्चात् किसी व्यक्ति को प्रतिदेय पाया जाए और ऐसे व्यक्ति को उसका प्रतिदाय कर दिया जाए, तो इस धारा के अधीन ऐसे राज्य या केन्द्रीय सरकार को ऐसे संघ राज्यक्षेत्र के मद्दे प्रभाजित की जाने वाली रकम में से, ऐसी रीति में और ऐसे समय के भीतर, जो विहित की जाए, घटा दिया जाएगा।

इनपुट कर प्रत्यय का अंतरण।

18. इस अधिनियम के अधीन,—

(क) केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 49 की उपधारा (5) के उपबंधों के अनुसार केन्द्रीय कर के संदाय के लिए प्राप्त किए गए एकीकृत कर के प्रत्यय के उपयोग पर, एकीकृत कर के रूप में संगृहीत रकम में से इस प्रकार उपयोग किए गए प्रत्यय के बराबर रकम घटा दी जाएगी और केन्द्रीय सरकार एकीकृत कर खाते से इस प्रकार घटी हुई रकम के बराबर रकम को, ऐसी रीति में और ऐसे समय के भीतर, जो विहित किया जाए, केन्द्रीय कर खाते में अंतरित कर देगी;

(ख) संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 9 के अनुसार संघ राज्यक्षेत्र कर के संदाय के लिए प्राप्त किए गए एकीकृत कर के प्रत्यय के उपयोग पर, एकीकृत कर के रूप में संगृहीत रकम में से इस प्रकार उपयोग किए गए प्रत्यय के बराबर रकम घटा दी जाएगी और केन्द्रीय सरकार एकीकृत कर खाते से इस प्रकार घटी हुई रकम के बराबर रकम को ऐसी रीति में और ऐसे समय के भीतर, जो विहित किया जाए, संघ राज्यक्षेत्र कर खाते में अंतरित कर देगी;

(ग) क्रमिक राज्य माल और सेवा कर अधिनियम के उपबंधों के अनुसार राज्य कर के संदाय के लिए प्राप्त किए गए एकीकृत कर के प्रत्यय के उपयोग पर, एकीकृत कर के रूप में संगृहीत रकम में से इस प्रकार उपयोग किए गए प्रत्यय के बराबर रकम घटा दी जाएगी और उसे समुचित राज्य सरकार को प्रभाजित कर दिया जाएगा तथा केन्द्रीय सरकार इस प्रकार प्रभाजित रकम को, ऐसी रीति में और ऐसे समय के भीतर, जो विहित किया जाए, समुचित राज्य सरकार के कर खाते में अंतरित कर देगी।

स्पष्टीकरण — इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए, कराधेय व्यक्ति के संबंध में “समुचित राज्य से” ऐसा राज्य या संघ राज्यक्षेत्र अभिप्रेत है, जहां वह रजिस्ट्रीकृत है या केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम के उपबंधों के अधीन रजिस्ट्रीकृत किए जाने के लिए दायी है।

सदोष संगृहीत और केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार को संदत्त कर।

19.(1) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिसने उसके द्वारा कोई अंतरराज्यिक पूर्ति होना समझी गई पूर्ति पर एकीकृत कर संदत्त कर दिया है, किंतु जिसे तत्पश्चात् राज्य के भीतर ही पूर्ति अभिनिर्धारित किया गया है, तो उसे ऐसी रीति में और ऐसी शर्तों के अध्वधीन, जो विहित की जाएं, इस प्रकार संदत्त एकीकृत कर की रकम का प्रतिदाय मंजूर किया जाएगा।

(2) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिसने उसके द्वारा कोई राज्य के भीतर पूर्ति होना समझे गए किसी संव्यवहार पर, यथास्थिति, केन्द्रीय कर और राज्य कर या संघ राज्यक्षेत्र कर संदत्त कर दिया है किंतु तत्पश्चात् उसे अंतरराज्यिक पूर्ति अभिनिर्धारित कर दिया गया है तो उससे संदेय एकीकृत रकम पर किसी ब्याज के संदाय की अपेक्षा नहीं की जाएगी।

अध्याय 9

प्रकीर्ण

केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम के उपबंधों का लागू होना।

20. इस अधिनियम के उपबंधों और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अध्वधीन केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम के उपबंध निम्नलिखित को, जहां तक हो सके, यथावश्यक परिवर्तनों सहित, एकीकृत कर के संबंध में, लागू होंगे, जैसे वे केन्द्रीय कर के संबंध में ऐसे लागू होते हैं, मानों वे इस अधिनियम के अधीन अधिनियमित किए गए हैं,—

- (i) पूर्ति का क्षेत्र;
- (ii) सामूहिक पूर्ति और मिश्रित पूर्ति;
- (iii) पूर्ति का समय और मूल्य;
- (iv) इनपुट कर प्रत्यय;
- (v) रजिस्ट्रीकरण;
- (vi) कर बीजक, जमापत्र और नामे नोट;
- (vii) लेखे और अभिलेख;

- (viii) विलंब शुल्क से भिन्न विवरणी;
- (ix) कर का संदाय;
- (x) स्रोत पर कर की कटौती;
- (xi) स्रोत पर कर का संग्रहण;
- (xii) निर्धारण;
- (xiii) प्रतिदाय;
- (xiv) संपरीक्षा;
- (xv) निरीक्षण, तलाशी, अभिग्रहण और गिरफ्तारी;
- (xvi) मांग और वसूली;
- (xvii) कतिपय मामलों में संदाय करने का दायित्व;
- (xviii) अग्रिम विनिर्णय;
- (xix) अपील और पुनरीक्षण;
- (xx) दस्तावेजों के बारे में उपधारणा;
- (xxi) अपराध और शास्तियां;
- (xxii) छुटपुट कार्य;
- (xxiii) इलेक्ट्रानिक वाणिज्य;
- (xxiv) संक्रमणकालीन उपबंध; और
- (xxv) प्रकीर्ण उपबंध, जिसके अंतर्गत ब्याज और शास्ति के अधिरोपण से संबंधित उपबंध भी हैं:

परंतु स्रोत पर कटौती किए गए कर की दशा में कटौतीकर्ता, पूर्तिकार को किए गए संदाय या जमा रकम से दो प्रतिशत की दर से कर की कटौती करेगा:

परंतु यह और कि स्रोत पर संगृहीत कर की दशा में, आपरेटर, कराधेय पूर्तियों के शुद्ध मूल्य के दो प्रतिशत से अनधिक की ऐसी दर पर कर संगृहीत करेगा, जो परिषद् की सिफारिशों पर अधिसूचित की जाए:

परंतु यह भी कि इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, किसी पूर्ति के मूल्य के अंतर्गत इस अधिनियम से भिन्न तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन तथा माल और सेवा कर (राज्यों को प्रतिकर) अधिनियम के अधीन उद्ग्रहीत कोई भी कर, शुल्क, उपकर, फीस और प्रभार भी होंगे, यदि वे पूर्तिकार द्वारा अलग से प्रभारित किए गए हैं:

परंतु यह भी कि उस दशा में, जहां शास्ति केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम और राज्य माल और सेवा कर अधिनियम (या संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम) के अधीन शास्ति उद्ग्रहणीय है, वहां इस अधिनियम के अधीन उद्ग्रहणीय शास्ति उक्त शास्तियों की कुल राशि होगी।

21. नियत दिन को या उसके पश्चात् की गई सेवाओं का आयात, इस बात पर ध्यान दिए बिना कि सेवाओं के ऐसे आयात का संव्यवहार नियत दिन से पहले प्रारंभ कर दिया गया था, इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन कर के दायित्वाधीन होगा:

नियत दिन को या उसके पश्चात् की गई सेवाओं का आयात।

परंतु यदि सेवाओं के ऐसे आयात पर कर, विद्यमान विधि के अधीन पूर्णतः संदत्त कर दिया गया था, तो इस अधिनियम के अधीन ऐसे आयात पर कोई कर संदेय नहीं होगा:

परंतु यह और कि यदि सेवाओं के ऐसे आयात पर कर, विद्यमान विधि के अधीन भागतः संदत्त किया गया था, तो इस अधिनियम के अधीन ऐसे आयात पर कर की अतिशेष रकम संदेय होगी।

स्पष्टीकरण — इस धारा के प्रयोजनों के लिए, किसी संव्यवहार को नियत दिन से पहले प्रारंभ किया गया समझा जाएगा, यदि या तो ऐसी पूर्ति से संबंधित बीजक या संदाय, या तो पूर्णतः या भागतः नियत दिन से पहले प्राप्त कर लिया गया है या किया गया है।

नियम बनाने की शक्ति।

22. (1) सरकार परिषद् की सिफारिशों पर इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए अधिसूचना द्वारा नियम बना सकेगी।

(2) उपधारा (1) के उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, सरकार ऐसे सभी या किन्हीं विषयों के लिए नियम बना सकेगी, जो इस अधिनियम द्वारा विहित किए जाने अपेक्षित हों या विहित किए जाएं या जिनके संबंध में उपबंध नियमों द्वारा बनाए जाने हैं या बनाए जाएं।

(3) इस धारा द्वारा प्रदत्त नियम बनाने की शक्ति के अंतर्गत, उस तारीख से, जिसको इस अधिनियम के उपबंध प्रवृत्त होते हैं, अपूर्व किसी तारीख से, नियमों या उनमें से किसी नियम को भूतलक्षी प्रभाव देने की शक्ति भी है।

(4) उपधारा (1) के अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों में यह उपबंध किया जा सकेगा कि उनका उल्लंघन दस हजार रुपए से अनधिक की शास्ति के दायित्वाधीन होगा।

विनियम बनाने की शक्ति।

23. बोर्ड, इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए नियमों से संगत विनियम बना सकेगा।

नियमों, विनियमों और अधिसूचनाओं का रखा जाना।

24. सरकार द्वारा इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, बोर्ड द्वारा बनाया गया प्रत्येक विनियम तथा सरकार द्वारा जारी की गई प्रत्येक अधिसूचना को बनाए जाने या जारी किए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा। यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी। यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम, विनियम या अधिसूचना में कोई उपांतरण करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे उपांतरित रूप में ही प्रभावी होगा। यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम, विनियम नहीं बनाया जाना चाहिए या अधिसूचना जारी नहीं की जानी चाहिए, तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा, तथापि नियम, विनियम या अधिसूचना के ऐसे उपांतरित या निष्प्रभाव होने से, यथास्थिति, नियम, विनियम या अधिसूचना के अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

कठिनाइयों को दूर करना।

25. (1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर राजपत्र में प्रकाशित साधारण या विशेष आदेश द्वारा, ऐसे उपबंध कर सकेगी, जो इस अधिनियम के उपबंधों या उसके अधीन बनाए गए नियमों अथवा विनियमों से असंगत न हों, जो उक्त कठिनाई को दूर करने के प्रयोजन के लिए आवश्यक या समीचीन हो:

परंतु ऐसा कोई भी आदेश इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से तीन वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा।

(2) इस धारा के अधीन बनाया गया प्रत्येक आदेश उसके बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा।

माल और सेवा कर (राज्यों को प्रतिकर) अधिनियम, 2017

(2017 का अधिनियम संख्यांक 15)

[12 अप्रैल, 2017]

संविधान (एक सौ एकवां संशोधन) अधिनियम, 2016 के उपबंधों
के अनुसरण में माल और सेवा कर के क्रियान्वयन के मद्दे
उद्भूत होने वाली राजस्व की हानि के लिए राज्यों हेतु
प्रतिकर का उपबंध करने के लिए
अधिनियम

भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम माल और सेवा कर (राज्यों को प्रतिकर) अधिनियम, 2017 है। संक्षिप्त नाम,
(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण भारत पर है। विस्तार और प्रारंभ।
- (3) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे।

परिभाषाएं।

2. (1) इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) “केंद्रीय कर” से केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम के अधीन उद्गृहीत और संगृहीत केन्द्रीय माल और सेवा कर अभिप्रेत है;

(ख) “केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम” से केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 अभिप्रेत है;

(ग) “उपकर” से धारा 8 के अधीन उद्गृहीत माल और सेवा कर प्रतिकर उपकर अभिप्रेत है;

(घ) “प्रतिकर” से धारा 7 के अधीन माल और सेवा कर प्रतिकर के रूप में यथा अवधारित कोई रकम अभिप्रेत है;

(ङ) “परिषद्” से संविधान के अनुच्छेद 279क के उपबंधों के अधीन गठित माल और सेवा कर परिषद् अभिप्रेत है;

(च) “निधि” से धारा 10 में निर्दिष्ट माल और सेवा कर प्रतिकर निधि अभिप्रेत है;

(छ) किसी कराधेय व्यक्ति के संबंध में “इन्पुट टैक्स” से निम्नलिखित अभिप्रेत है,—

(i) उसे किए गए मालों या सेवाओं या दोनों की किसी पूर्ति पर प्रभारित उपकर;

(ii) मालों के आयात पर प्रभारित उपकर और इसके अंतर्गत प्रतिलोम प्रभार के आधार पर संदेय उपकर भी है;

(ज) “एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम” से एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 अभिप्रेत है;

(झ) “एकीकृत कर” से एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम के अधीन उद्गृहीत और संगृहीत एकीकृत माल और सेवा कर अभिप्रेत है;

(ञ) “विहित” से इस अधिनियम के अधीन परिषद् की सिफारिशों पर बनाए गए नियमों द्वारा विहित किया गया अभिप्रेत है;

(ट) “अनुमानित विकास दर” से धारा 3 के अनुसार संक्रमणकालीन अवधि के लिए विकास की अनुमानित दर अभिप्रेत है;

(ठ) “अनुसूची” से इस अधिनियम से उपाबद्ध अनुसूची अभिप्रेत है;

(ड) “राज्य” से,—

(i) धारा 3, धारा 4, धारा 5, धारा 6 और धारा 7 के प्रयोजनों के लिए केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम के अधीन यथा परिभाषित राज्य अभिप्रेत है; और

(ii) धारा 8, धारा 9, धारा 10, धारा 11, धारा 12, धारा 13 और धारा 14 के प्रयोजनों के लिए केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम के अधीन यथा परिभाषित राज्य और संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम के अधीन यथा परिभाषित संघ राज्यक्षेत्र अभिप्रेत है;

(ढ) “राज्य कर” से अपने-अपने राज्य माल और सेवा कर अधिनियम के अधीन उद्गृहीत और संगृहीत राज्य माल और सेवा कर अभिप्रेत है;

(ण) “राज्य माल और सेवा कर अधिनियम” से संबद्ध राज्य द्वारा माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति पर कर के उद्ग्रहण और संग्रहण के लिए राज्य विधानमंडल द्वारा बनाई गई कोई विधि अभिप्रेत है;

(त) “कराधेय पूर्ति” से माल या सेवाओं या दोनों की ऐसी पूर्ति अभिप्रेत है, जो इस अधिनियम के अधीन उपकर से प्रभार्य है;

(थ) किसी राज्य के संबंध में “संक्रमण तारीख” से वह तारीख अभिप्रेत है, जिसको संबद्ध राज्य में राज्य माल और सेवा कर अधिनियम प्रवृत्त होता है;

(द) “संक्रमण अवधि” से संक्रमण तारीख से पांच वर्ष की अवधि अभिप्रेत है; और

(ध) “संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम” से संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 अभिप्रेत है।

(2) ऐसे शब्दों और पदों का, जो इस अधिनियम में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं, किन्तु केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम और एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उन अधिनियमों में क्रमशः उनका है।

3. संक्रमण अवधि के दौरान किसी राज्य के लिए सम्मिलित की गई राजस्व की अनुमानित अभिहित विकास दर चौदह प्रतिशत प्रतिवर्ष होगी। अनुमानित विकास दर।

4. संक्रमण अवधि के दौरान किसी वित्तीय वर्ष में संदेय प्रतिकर की रकम की संगणना करने के प्रयोजन के लिए, 31 मार्च, 2016 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष को आधार वर्ष के रूप में लिया जाएगा। आधार वर्ष।

5. (1) उपधारा (2), उपधारा (3), उपधारा (4), उपधारा (5) और उपधारा (6) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, किसी राज्य के लिए आधार वर्ष राजस्व, राज्य और स्थानीय निकायों द्वारा आधार वर्ष के दौरान, संबद्ध राज्य या संघ द्वारा उद्गृहीत करों के मद्दे संगृहीत राजस्व और क्रमिक राज्य या संघ द्वारा अधिरोपित निम्नलिखित करों, जिन्हें माल और सेवा कर में सम्मिलित कर लिया गया है, के संबंध में शुद्ध प्रतिदायों का योग होगा, अर्थात्:— आधार वर्ष राजस्व।

संविधान (एक सौ एकवां संशोधन) अधिनियम, 2016 के उपबन्धों के प्रारंभ से पूर्व,—

(क) मूल्य वर्धित कर, विक्रय कर, क्रय कर, संकर्म संविदा पर संगृहीत कर या संबद्ध राज्य द्वारा संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-2 (राज्यसूची) की तत्कालीन प्रविष्टि 54 के अधीन उद्गृहीत कोई अन्य कर;

1956 का 74

(ख) केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 के अधीन उद्गृहीत केन्द्रीय विक्रय कर;

(ग) संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-2 (राज्य सूची) की तत्कालीन प्रविष्टि 52 के अधीन सम्बद्ध राज्य द्वारा उद्गृहीत प्रवेश कर, चुंगी कर, स्थानीय निकाय कर या कोई अन्य कर;

(घ) संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-2 (राज्य सूची) की तत्कालीन प्रविष्टि 62 के अधीन क्रमिक राज्य द्वारा उद्गृहीत भोग-विलास की वस्तुओं पर कर, जिसके अन्तर्गत मनोरंजन, आमोद-प्रमोद, दाव लगाने और जुआ खेलने पर कर, या कोई अन्य कर भी हैं;

(ङ) संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-2 (राज्य सूची) की तत्कालीन प्रविष्टि 55 के अधीन सम्बद्ध राज्य द्वारा उद्गृहीत विज्ञापन पर कर या कोई अन्य कर;

(च) संविधान के तत्कालीन अनुच्छेद 268 के अधीन औषधीय और प्रसाधन निर्मितियों पर संघ द्वारा उद्गृहीत किन्तु सम्बद्ध राज्य सरकार द्वारा संगृहीत और प्रतिधारित उत्पाद शुल्क;

(छ) उपधारा (4) के अधीन अधिसूचित किसी अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची 2 की प्रविष्टि 52, 54, 55 और 62 के साथ पठित प्रविष्टि 66 के अधीन उद्ग्रहणीय कोई उपकर या अधिभार या फीस;

परंतु निम्नलिखित करों के अधीन, किसी राज्य में आधार वर्ष के दौरान, संगृहीत राजस्व, शुद्ध प्रतिदायों को उस राज्य के लिए आधार वर्ष राजस्व की संगणना में सम्मिलित नहीं किया जाएगा, अर्थात्:—

(क) संविधान (एक सौ एकवां संशोधन) अधिनियम, 2016 के उपबन्धों के प्रवृत्त होने से पूर्व संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-2 (राज्य सूची) की तत्कालीन प्रविष्टि 54 के अधीन अधिनियमित किसी अधिनियम के अधीन कच्चे पेट्रोलियम, उच्च गति डीजल, मोटर स्पिरिट (सामान्यतः पेट्रोल के रूप में ज्ञात), प्राकृतिक गैस, विमानन टरबाईन ईंधन और मानव उपभोग के लिए मद्यसारिक पान के विक्रय या क्रय पर उद्गृहीत कोई कर;

1956 का 74

(ख) केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 के अधीन कच्चे पेट्रोलियम, उच्च गति डीजल, मोटर स्पिरिट (सामान्यतः पेट्रोल के रूप में ज्ञात), प्राकृतिक गैस, विमानन टरबाईन ईंधन और मानव उपभोग के लिए मद्यसारिक पान के विक्रय या क्रय पर उद्गृहीत कर;

(ग) राज्य सरकार द्वारा कच्चे पेट्रोलियम, उच्च गति डीजल, मोटर स्पिरिट (सामान्यतः पेट्रोल के रूप में ज्ञात), प्राकृतिक गैस, विमानन टरबाइन ईंधन और मानव उपभोग के लिए मद्यसारिक पान के विक्रय या क्रय पर अधिरोपित कोई उपकर; और

(घ) संविधान (एक सौ एकवां संशोधन) अधिनियम, 2016 के उपबन्धों के प्रवृत्त होने से पूर्व संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-2 (राज्य सूची) की तत्कालीन प्रविष्टि 62 के अधीन अधिनियमित किसी अधिनियम के अधीन राज्य द्वारा उद्गृहीत, किन्तु स्थानीय निकायों द्वारा संगृहीत मनोरंजन कर।

(2) जम्मू-कश्मीर राज्य के सम्बन्ध में, आधार वर्ष राजस्व में आधार वर्ष के दौरान उक्त राज्य सरकार द्वारा सेवाओं के विक्रय पर संगृहीत कर की रकम सम्मिलित होगी।

(3) संविधान के अनुच्छेद 279क के खण्ड (4) के उपखण्ड (छ) में उल्लिखित राज्यों के सम्बन्ध में उपधारा (1) में निर्दिष्ट ऐसे विनिर्दिष्ट करों के सम्बन्ध में, राज्य में औद्योगिक विनिधान का संवर्धन करने के लिए उक्त राज्य सरकार द्वारा दी गई छूटों या परिहार के कारण छोड़ दिए गए राजस्व की रकम ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो विहित की जाएं, राज्य के कुल आधार वर्ष राजस्व में सम्मिलित की जाएंगी।

(4) केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों के ऐसे अधिनियम, जिनके अधीन विनिर्दिष्ट कर, माल और सेवा कर में सम्मिलित किए गए हैं, वे होंगे, जो अधिसूचित किए जाएं।

(5) आधार वर्ष राजस्व की संगणना, भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक द्वारा यथा संपरीक्षित उस वर्ष में संगृहीत राजस्व के आंकड़ों और दिए गए शुद्ध प्रतिदायों के आधार पर उपधारा (1), उपधारा (2), उपधारा (3) और उपधारा (4) के अनुसार की जाएगी।

(6) किसी राज्य के सम्बन्ध में, यदि उपधारा (1), उपधारा (2), उपधारा (3) और उपधारा (4) में उल्लिखित राजस्व का कोई भाग, सम्बन्धित राज्य की संचित निधि में जमा नहीं किया जाता है, तो वह ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो विहित की जाएं, राज्य के कुल आधार वर्ष राजस्व में सम्मिलित किया जाएगा।

किसी वर्ष के लिए अनुमानित राजस्व।

6. राज्य में किसी वर्ष के लिए अनुमानित राजस्व उस राज्य के आधार वर्ष राजस्व पर अनुमानित वृद्धि-दर को लागू करके संगणित किया जाएगा।

दृष्टान्त—यदि किसी सम्बद्ध राज्य के लिए 2015-16 के लिए धारा 5 के अनुसार संगणित आधार वर्ष राजस्व एक सौ रुपए है तो वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए अनुमानित राजस्व निम्नानुसार होगा:—

$$2018-19 \text{ के लिए अनुमानित राजस्व} = 100(1+14/100)^3$$

प्रतिकर की संगणना और उसका जारी किया जाना।

7. (1) इस अधिनियम के अधीन प्रतिकर संक्रमण अवधि के दौरान, किसी राज्य को संदेय होगा।

(2) राज्य को संदेय प्रतिकर प्रत्येक दो मास की अवधि की समाप्ति पर अनन्तिम रूप से संगणित और जारी किया जाएगा तथा भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक द्वारा यथा संपरीक्षित अंतिम राजस्व आंकड़ों की प्राप्ति के पश्चात् प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए अंतिम रूप से संगणित किया जाएगा:

परंतु यदि, संगृहीत राजस्व के संपरीक्षित आंकड़ों के अनुसार, संक्रमण अवधि के दौरान किसी वित्तीय वर्ष में किसी राज्य को प्रतिकर के रूप में कोई अतिरिक्त रकम जारी कर दी है तो इस प्रकार जारी की गई रकम पश्चात्वर्ती वित्तीय वर्ष में ऐसे राज्य को संदेय प्रतिकर की रकम के प्रति समायोजित की जाएगी।

(3) किसी राज्य को संक्रमण अवधि के दौरान किसी वित्तीय वर्ष के लिए संदेय कुल प्रतिकर निम्नलिखित रीति में संगणित किया जाएगा, अर्थात्:—

(क) संक्रमण अवधि के दौरान किसी वित्तीय वर्ष के लिए ऐसा अनुमानित राजस्व, जो माल और सेवा कर के अभाव में किसी राज्य को प्रोद्भूत हुआ हो, धारा 6 के अनुसार संगणित किया जाएगा;

(ख) संक्रमण अवधि के दौरान किसी वित्तीय वर्ष में राज्य द्वारा संगृहीत भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक द्वारा यथा प्रमाणित वास्तविक राजस्व निम्नलिखित होगा—

(i) राज्य द्वारा संगृहीत राज्य कर से वास्तविक राजस्व, राज्य माल और सेवा कर अधिनियम के अध्याय 11 और अध्याय 20 के अधीन उक्त राज्य द्वारा दिए गए शुद्ध प्रतिदाय;

(ii) उस राज्य को प्रभाजित एकीकृत माल और सेवा कर; और

(iii) धारा 5 की उपधारा (4) में विनिर्दिष्ट अधिनियमों के अधीन, क्रमिक राज्य द्वारा उद्गृहीत करों के मद्दे करों का कोई संग्रहण, ऐसे करों का शुद्ध प्रतिदाय;

(ग) किसी वित्तीय वर्ष में संदेय कुल प्रतिकर किसी वित्तीय वर्ष के लिए अनुमानित राजस्व और खण्ड (ख) में निर्दिष्ट राज्य द्वारा संगृहीत वास्तविक राजस्व के बीच का अन्तर होगा।

(4) संक्रमण अवधि के दौरान किसी राज्य के लिए किसी वर्ष में प्रत्येक दो मास की अवधि की समाप्ति पर राजस्व की हानि की संगणना उक्त अवधि की समाप्ति पर निम्नलिखित रीति में की जाएगी, अर्थात्:—

(क) अनुमानित राजस्व, जो क्रमिक वित्तीय वर्ष की सुसंगत दो मास की अवधि की समाप्ति तक माल और सेवा कर के अभाव में राज्य द्वारा उपार्जित किया गया होता, धारा 6 के अनुसार, संगणित संक्रमण अवधि के दौरान किसी वित्तीय वर्ष के लिए कुल अनुमानित राजस्व की प्रतिशतता के रूप में आनुपातिक आधार पर संगणित किया जाएगा।

दृष्टान्त—यदि किसी वर्ष के लिए धारा 6 के अनुसार, संगृहीत अनुमानित राजस्व, एक सौ रुपए है तो ऐसे अनुमानित राजस्व, जो इस उपधारा के प्रयोजन के लिए दस मास की अवधि की समाप्ति तक उपार्जित किया जा सकता है, की संगणना करने का सूत्र, $100 \times (5/6) = 83.33$ रुपए होगा;

(ख) किसी राज्य द्वारा संक्रमण अवधि के दौरान किसी वित्तीय वर्ष में सुसंगत दो मास की अवधि की समाप्ति तक संगृहीत वास्तविक राजस्व निम्नलिखित होगा —

(i) राज्य द्वारा संगृहीत राज्य कर से वास्तविक राजस्व, राज्य माल और सेवा कर अधिनियम के अध्याय 11 और अध्याय 20 के अधीन राज्य द्वारा दिए गए शुद्ध प्रतिदाय होगा;

(ii) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और सीमाशुल्क बोर्ड के प्रधान मुख्य लेखानियंत्रक द्वारा यथा प्रमाणित, उस राज्य के लिए प्रभाजित एकीकृत माल और सेवा कर होगा; और

(iii) धारा 5 की उपधारा (4) में विनिर्दिष्ट अधिनियमों के अधीन, उक्त राज्य द्वारा उद्गृहीत करों का कोई भी संग्रहण, ऐसे करों का शुद्ध प्रतिदाय होगा।

(ग) किसी वित्तीय वर्ष में सुसंगत दो मास की अवधि की समाप्ति पर किसी राज्य को संदेय अनन्तिम प्रतिकर खण्ड (क) के अनुसार, सुसंगत अवधि की समाप्ति तक अनुमानित राजस्व और खण्ड (ख) में यथा निर्दिष्ट उक्त अवधि में राज्य द्वारा संगृहीत वास्तविक राजस्व में से संक्रमण अवधि के दौरान उक्त वित्तीय वर्ष में पूर्व दो मास की अवधि की समाप्ति तक राज्य को संदत्त अनन्तिम प्रतिकर को घटा कर आए राजस्व के बीच का अन्तर ऐसा होगा।

(5) भारत का नियंत्रक महालेखापरीक्षक से संपरीक्षित राजस्व आंकड़ों की प्राप्ति पर उपधारा (3) के उपबन्धों के अनुसार, संगणित राज्य को संदेय अन्तिम प्रतिकर की रकम और उपधारा (4) के उपबन्धों के अनुसार, उक्त वित्तीय वर्ष में किसी राज्य को जारी कुल अनन्तिम प्रतिकर रकम, के बीच अंतर की दशा में उसे पश्चात्पूर्ति वित्तीय वर्ष में राज्य को प्रतिकर के जारी किए जाने के प्रति समायोजित किया जाएगा।

(6) जहां किसी वित्तीय वर्ष में कोई प्रतिकर जारी नहीं किया जाना है और यदि पूर्व वर्ष में किसी राज्य को कोई अतिरिक्त रकम जारी की गई है तो वहां यह रकम केन्द्रीय सरकार को राज्य द्वारा वापस लौटा दी जाएगी और ऐसी रकम ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, निधि में जमा की जाएगी।

8. (1) उस तारीख से, जिससे केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम के उपबन्ध प्रवृत्त होते हैं, पांच वर्ष की अवधि के लिए या ऐसी अवधि के लिए जो परिषद् की सिफारिश पर विहित की जाए, माल और सेवा कर के कार्यान्वयन के कारण उद्भूत होने वाली राजस्व की हानि के लिए राज्यों को प्रतिकर का उपबन्ध करने के प्रयोजनों के लिए केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 9 में यथा उपबंधित माल या सेवा या दोनों के राज्य के भीतर ऐसी पूर्तियों पर और एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 5 में यथा उपबंधित माल या सेवाओं या दोनों के ऐसी अन्तरराज्यिक पूर्तियों पर उपकर उद्गृहीत किया जाएगा और ऐसी रीति में जो परिषद् की सिफारिशों पर विहित की जाए, संगृहीत किया जाएगा:

उपकर का उद्ग्रहण और संग्रहण।

परंतु ऐसा कोई उपकर, ऐसे किसी कराधेय व्यक्ति द्वारा, जिसने केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 10 के अधीन संयुक्त उद्ग्रहण के लिए विकल्प लेने का विनिश्चय किया है, की गई पूर्ति पर उद्ग्रहणीय नहीं होगा।

(2) उपकर, माल और सेवाओं की ऐसी पूर्तियों पर, जो अनुसूची के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट हैं, मूल्य, मात्रा के आधार पर अथवा ऐसे आधार पर ऐसी दर से जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (4) में तत्स्थानी प्रविष्टि में उपवर्णित ऐसी दर से अधिक नहीं हो, जो केन्द्रीय सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे, उद्ग्रहीत किया जाएगा:

परंतु जहां उपकर, ऐसे प्रत्येक प्रदाय के लिए माल या सेवाओं या दोनों के किसी पूर्ति पर उनके मूल्य के प्रति निर्देश से प्रभार्य है, वहां ऐसी प्रत्येक पूर्ति पर मूल्य, माल या सेवाओं या दोनों की राज्य के भीतर की समस्त पूर्तियों और अन्तरराज्यिक पूर्तियों के लिए केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 15 के अधीन अवधारित किया जाएगा:

परंतु यह और कि भारत में आयातित माल पर उपकर सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 3 के उपबन्धों के अनुसार उस बिन्दु पर, जहां सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 12 के अधीन उक्त माल पर उद्ग्रहीत किया जाता है, सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अधीन अवधारित मूल्य पर उद्ग्रहीत और संगृहीत किया जाएगा।

1975 का 51

1962 का 52

विवरणियां, संदाय
और प्रतिदाय।

9. (1) माल या सेवाओं या दोनों की कराधेय पूर्ति करने वाला प्रत्येक कराधेय व्यक्ति —

(क) इस अधिनियम के अधीन यथा संदेय उपकर की रकम का संदाय ऐसी रीति में करेगा;

(ख) केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम के अधीन फाइल की जाने वाली विवरणियों के साथ ऐसी विवरणियां ऐसे प्ररूप में प्रस्तुत करेगा; और

(ग) ऐसे संदत्त उपकर के प्रतिदाय के लिए आवेदन ऐसे प्ररूप में करेगा,

जो विहित किया जाए।

(2) विवरणियों के प्रस्तुत किए जाने और प्रतिदायों का दावा करने के सभी प्रयोजनों के लिए, फाइल किए जाने वाले प्ररूप के सिवाय, केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों के उपबन्ध, यथाशक्य, माल या सेवाओं या दोनों की सभी कराधेय पूर्तियों पर धारा 8 के अधीन उद्ग्रहणीय उपकर के उद्ग्रहण और संग्रहण के संबंध में वैसे ही लागू होंगे जैसे वे उक्त अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के अधीन ऐसी पूर्तियों पर केन्द्रीय कर के उद्ग्रहण और संग्रहण के सम्बन्ध में लागू होते हैं।

उपकर के आगमों
का निधि में जमा
करना।

10. (1) धारा 8 के अधीन उद्ग्रहणीय उपकर के आगम और ऐसी अन्य रकम, जो परिषद्, द्वारा सिफारिश की जाए, माल और सेवा कर प्रतिकर निधि के रूप में ज्ञात गैर-व्यपगतीय निधि में जमा किए जाएंगे जो भारतीय लोक लेखा का भाग होंगे, और उनका उपयोग उक्त धारा में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए किया जाएगा।

(2) धारा 7 के अधीन राज्यों को संदेय समस्त रकम, निधि में से संदत्त की जाएगी।

(3) संक्रमण अवधि की समाप्ति पर निधि में से शेष बची अनुपयोजित पचास प्रतिशत रकम केन्द्र के हिस्से के रूप में भारत की संचित निधि में अन्तरित कर दी जाएगी और अतिशेष पचास प्रतिशत, संक्रमण अवधि के अन्तिम वर्ष में यथास्थिति, राज्य कर या संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर से राज्यों के कुल राजस्व के अनुपात में उनके बीच वितरित की जाएगी।

(4) निधि से सम्बन्धित लेखे भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक या उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति द्वारा ऐसे अन्तरालों पर, जो उसके द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं, संपरीक्षित किए जाएंगे और ऐसी संपरीक्षा के संबंध में कोई भी व्यय केन्द्रीय सरकार द्वारा भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक को संदेय होगा।

(5) भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक द्वारा या इस निमित्त उसके द्वारा नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा यथाप्रमाणित निधि के लेखे उन पर संपरीक्षा रिपोर्ट सहित संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखे जाएंगे।

उपकर से संबंधित
अन्य उपबन्ध।

11. (1) केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों के उपबन्ध, जिनके अन्तर्गत निर्धारण, इनपुट कर प्रत्यय, अनुद्ग्रहण, कम उद्ग्रहण, ब्याज, अपीलें, अपराधों और शास्तियों से सम्बन्धित उपबन्ध भी हैं, जहां तक हो सके, माल और सेवा की अन्तरराज्यिक पूर्ति पर धारा 8 के अधीन उद्ग्रहणीय उपकर के उद्ग्रहण और संग्रहण, के संबंध में आवश्यक परिवर्तनों सहित, वैसे ही लागू होंगे, जैसे वे

उक्त अधिनियम या तद्दीन बनाए गए नियमों के अधीन माल और सेवा के ऐसी अन्तरराज्यिक पूर्तियों पर केन्द्रीय कर के उद्ग्रहण और संग्रहण के संबंध में लागू होते हैं।

(2) एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम और तद्दीन बनाए गए नियमों के उपबन्ध, जिनके अन्तर्गत निर्धारण, इनपुट कर प्रत्यय अनुद्ग्रहण, कम उद्ग्रहण, ब्याज, अपीलें, अपराधों और शास्तियों से संबंधित उपबन्ध भी हैं, माल और सेवा की अन्तरराज्यिक पूर्ति पर धारा 8 के अधीन उद्ग्रहणीय उपकर के उद्ग्रहण और संग्रहण के संबंध में आवश्यक परिवर्तनों सहित, वैसे ही लागू होंगे, जैसे वे उक्त अधिनियम या तद्दीन बनाए गए नियमों के अधीन माल और सेवा की ऐसी अन्तरराज्यिक पूर्तियों पर एकीकृत कर के उद्ग्रहण और संग्रहण के सम्बन्ध में लागू होते हैं:

परंतु धारा 8 के अधीन उद्ग्रहणीय माल और सेवाओं की पूर्ति पर उपकर के सम्बन्ध में इनपुट कर प्रत्यय का उपयोग उक्त धारा के अधीन उद्ग्रहणीय माल और सेवाओं की पूर्ति पर उक्त उपकर के संदाय के लिए ही किया जाएगा।

12. (1) केन्द्रीय सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी। नियम बनाने की शक्ति।

(2) विशिष्टता और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबन्ध कर सकेंगे, अर्थात्:—

(क) ऐसी शर्तें, जो धारा 5 की उपधारा (3) के अधीन, संविधान के अनुच्छेद 279क के खण्ड (4) के उपखंड (छ) में निर्दिष्ट राज्यों के कुल आधार वर्ष राजस्व में सम्मिलित की गई थी;

(ख) ऐसी शर्तें, जिनके अधीन रहते हुए क्रमिक राज्य की संचित निधि में जमा नहीं किए गए राजस्वों का कोई भाग धारा 5 की उपधारा (6) के अधीन राज्य के कुल आधार वर्ष राजस्व में सम्मिलित किया जाएगा;

(ग) धारा 7 की उपधारा (6) के अधीन केन्द्रीय सरकार को राज्यों द्वारा प्रतिकर के प्रतिदाय की रीति;

(घ) धारा 8 की उपधारा (1) के अधीन कर के उद्ग्रहण और संग्रहण की रीति तथा उसके अधिरोपण की अवधि;

(ङ) धारा 9 की उपधारा (1) के अधीन उपकर के संदाय के लिए, विवरणियों के प्रस्तुत किए जाने के लिए तथा उपकर के प्रतिदाय के लिए रीति और प्ररूप; और

(च) ऐसा कोई अन्य विषय, जो इन नियमों द्वारा विहित किया जाना है या विहित किया जाए या जिसके सम्बन्ध में उपबन्ध किया जाना है।

13. इस अधिनियम के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम, उसे बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा। यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी। यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन, यथास्थिति, नियम में कोई उपांतरण करने पर सहमत हो जाते हैं या दोनों सदन इस बात के लिए सहमत हो जाते हैं कि ऐसा नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो, यथास्थिति, ऐसा नियम उसके पश्चात् केवल ऐसे उपांतरित रूप में ही प्रभावी होगा या प्रभावी नहीं होगा, तथापि, ऐसा कोई उपांतरण या बातिलकरण उस नियम के अधीन पूर्व में की गई किसी बात की विधि मान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा। संसद् के समक्ष नियमों का रखा जाना।

14. (1) यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केन्द्रीय सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा ऐसे उपबन्ध कर सकेगी, जो इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत नहीं हैं और कठिनाई को दूर करने के लिए उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत होते हैं: कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति।

परंतु इस धारा के अधीन कोई आदेश, इस अधिनियम के प्रारंभ से तीन वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, इसके किए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, रखा जाएगा।

अनुसूची

[धारा 8(2) देखिए]

1. इस अनुसूची में “टैरिफ मद”, “शीर्ष”, “उपशीर्ष” और “अध्याय” के प्रतिनिर्देश, जहां-जहां वे आते हैं का वही अर्थ होगा जो सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची में टैरिफ मद, शीर्ष, उपशीर्ष और अध्याय में क्रमशः उनका है।

2. सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची के निर्वचन के लिए नियम, भाग और अध्याय टिप्पण तथा पहली अनुसूची के साधारण स्पष्टीकारक टिप्पण, जहां तक हो सकें, इस अनुसूची के निर्वचन के लिए लागू होंगे,—

क्र०सं०	माल या सेवाओं की पूर्ति का वर्णन	टैरिफ मद, शीर्ष, उपशीर्ष, अध्याय या यथास्थिति, माल या सेवाओं की पूर्ति	वह अधिकतम दर जिस पर माल और सेवा कर प्रतिकर उपकर संगृहीत किया जा सकेगा
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	पान मसाला।	2106 90 20	एक सौ पैंतीस प्रतिशत मूल्यानुसार।
2.	तम्बाकू और विनिर्मित तम्बाकू अनुकल्प, जिसके अन्तर्गत तम्बाकू उत्पाद भी हैं।	24	चार हजार एक सौ सत्तर रुपए प्रति हजार यष्टि या मूल्यानुसार दो सौ नब्बे प्रतिशत या उसका समुच्चय, किन्तु मूल्यानुसार चार हजार एक सौ सत्तर रुपए प्रति हजार यष्टि जमा दो सौ नब्बे प्रतिशत से अधिक नहीं।
3.	कोयला, इष्टिकाओं, अण्डाभों और कोयला, लिग्नाइट, चाहे संपिण्डित है या नहीं, जिसके अन्तर्गत जैट नहीं हैं, पीट (जिसके अन्तर्गत पीट तृणशैल्या भी है) चाहे संपिण्डित है या नहीं, से विनिर्मित वैसे ही ठोस ईंधन।	2701, 2702 या 2703	चार सौ रुपए प्रति टन।
4.	वातित जल।	2202 10 10	मूल्यानुसार पंद्रह प्रतिशत।
5.	व्यक्तियों के परिवहन के लिए प्रमुखतः अभिकल्पित मोटर कार और अन्य मोटर यान (चालक सहित दस या अधिक व्यक्तियों के परिवहन के लिए मोटर से भिन्न), जिसके अन्तर्गत स्टेशन वैगन और दौड़ प्रतियोगिता वाली कार भी हैं।	8703	मूल्यानुसार पंद्रह प्रतिशत।
6.	कोई अन्य पूर्ति।		मूल्यानुसार पंद्रह प्रतिशत।

संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2017

(2017 का अधिनियम संख्यांक 17)

[28 अप्रैल, 2017]

संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश, 1950 का ओडिशा राज्य में अनुसूचित
जातियों की सूची को उपांतरित करने और संविधान (पांडिचेरी)
(अनुसूचित जातियां) आदेश, 1964
का और संशोधन
करने के लिए
अधिनियम

भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2017 संक्षिप्त नाम।
है।

सं आ 19

2. संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश, 1950 की अनुसूची के भाग 13 - ओडिशा में, प्रविष्टि 79 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात्:—
“79. सुबाखिया, सुआलगिरि, स्वालगिरि।”।

संविधान
(अनुसूचित
जातियां) आदेश,
1950 का
संशोधन।

सं आ 68

3. संविधान (पांडिचेरी) अनुसूचित जातियां आदेश 1964 में, “पांडिचेरी” शब्द के स्थान पर, दोनों स्थानों पर जहां वह आता है, “पुडुचेरी” शब्द रखा जाएगा।

संविधान
(पांडिचेरी)
अनुसूचित जातियां
आदेश, 1964 का
संशोधन।

कराधान विधि (संशोधन) अधिनियम, 2017

(2017 का अधिनियम संख्यांक 18)

[4 मई, 2017]

सीमाशुल्क अधिनियम, 1962, सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क
अधिनियम, 1944, केन्द्रीय विक्रय-कर अधिनियम, 1956, वित्त अधिनियम, 2001
और वित्त अधिनियम, 2005 का और संशोधन करने के लिए
तथा कतिपय अधिनियमितियों का निरसन
करने के लिए
अधिनियम

भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम कराधान विधि (संशोधन) अधिनियम, 2017 है।
- (2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे:

संक्षिप्त नाम और
प्रारंभ।

परंतु इस अधिनियम के भिन्न-भिन्न उपबंधों के लिए भिन्न-भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी तथा ऐसे किसी उपबंध में इस अधिनियम के प्रारंभ के प्रति किसी निर्देश का अर्थ उस उपबंध के प्रारंभ के प्रति निर्देश के रूप में लगाया जाएगा।

अध्याय 1

सीमाशुल्क

धारा 2 का संशोधन।	2. सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (जिसे इसमें इसके पश्चात् सीमाशुल्क अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 के खंड (11) में, “सीमाशुल्क स्टेशन” के पश्चात्, “या किसी भांडागार” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे।	1962 का 52
नई धारा 108क और धारा 108ख का अंतःस्थापन।	3. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 108 के पश्चात्, निम्नलिखित धाराएं अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:—	
सूचना देने की बाध्यता।	“108क. (1) कोई भी व्यक्ति, जो—	
	(क) कोई स्थानीय प्राधिकारी या अन्य लोक निकाय या संगम है; या	
	(ख) माल या सेवाओं से संबंधित मूल्य वर्धित कर या विक्रय कर या किसी अन्य कर के संग्रहण के लिए उत्तरदायी राज्य सरकार का कोई प्राधिकारी है; या	
	(ग) आय-कर अधिनियम, 1961 के उपबंधों के अधीन नियुक्त कोई आय-कर प्राधिकारी है; या	1961 का 43
	(घ) भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45क के खंड (क) के अर्थातर्गत कोई बैंककारी कंपनी है; या	1934 का 2
	(ङ) निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 की धारा 2 के खंड (घघ) के अर्थातर्गत कोई सहकारी बैंक है; या	1961 का 47
	(च) भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झ के खंड (ग) के अर्थातर्गत कोई वित्तीय संस्था है या खंड (च) के अर्थातर्गत कोई गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनी है; या	1934 का 2
	(छ) कोई राज्य विद्युत बोर्ड है या विद्युत अधिनियम, 2003 के अधीन विद्युत वितरण या पारेषण अनुज्ञप्तिधारी है या कोई अन्य ऐसा अस्तित्व है, जिसे यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा ऐसे कृत्य सौंपे गए हैं; या	2003 का 36
	(ज) रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 की धारा 6 के अधीन नियुक्त कोई रजिस्ट्रार या कोई उप रजिस्ट्रार है; या	1908 का 16
	(झ) कंपनी अधिनियम, 2013 के अर्थातर्गत कोई रजिस्ट्रार है; या	2013 का 18
	(ञ) मोटर यान अधिनियम, 1988 के अध्याय 4 के अधीन मोटर यानों को रजिस्ट्रीकृत करने के लिए सशक्त कोई रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी है; या	1988 का 59
	(ट) भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 3 के खंड (ग) में निर्दिष्ट कोई कलेक्टर है; या	2013 का 30
	(ठ) प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 2 के खंड (च) में निर्दिष्ट कोई मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज है; या	1956 का 42
	(ड) निक्षेपागार अधिनियम, 1996 की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (ड) में निर्दिष्ट कोई निक्षेपागार है; या	1996 का 22
	(ढ) भारतीय डाकघर अधिनियम, 1898 की धारा 2 के खंड (ज) के अर्थातर्गत कोई महाडाकपाल है; या	1898 का 6
	(ण) विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 2 के खंड (घ) के अर्थातर्गत कोई विदेशी व्यापार महानिदेशक है; या	1992 का 22

1989 का 24

(त) रेल अधिनियम, 1989 की धारा 2 के खंड (18) के अर्थातर्गत किसी क्षेत्रीय रेल का कोई महाप्रबंधक है; या

1934 का 2

(थ) भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 3 के अधीन गठित भारतीय रिजर्व बैंक का कोई अधिकारी है,

जो ऊपर विनिर्दिष्ट किसी अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य ऐसी विधि, जिसे इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए सुसंगत समझा गया है, के अधीन रजिस्ट्रीकरण या लेखा विवरण का अभिलेख रखने या कोई अन्य सूचना रखने के लिए उत्तरदायी है, समुचित अधिकारी को ऐसी सूचना ऐसी रीति में देगा, जो इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित की जाए।

(2) जहां समुचित अधिकारी यह समझता है कि उपधारा (1) के अधीन दी गई सूचना त्रुटिपूर्ण है, वहां वह त्रुटि को उस व्यक्ति को संसूचित कर सकेगा, जिसने ऐसी सूचना दी है और उसे ऐसी संसूचना की तारीख से सात दिन की अवधि के भीतर या ऐसी और अवधि के भीतर, जो इस निमित्त किए गए आवेदन पर समुचित अधिकारी अनुज्ञात करे, त्रुटि में सुधार करने का अवसर दे सकेगा और यदि उस त्रुटि में, यथास्थिति, सात दिन की उक्त अवधि या और ऐसी अवधि, जो अनुज्ञात की जाए, के भीतर सुधार नहीं किया जाता है तो उस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, ऐसी सूचना को, नहीं दी गई के रूप में समझा जाएगा और इस अधिनियम के उपबंध लागू होंगे।

(3) जहां किसी व्यक्ति ने, जिससे सूचना दी जानी अपेक्षित है, उपधारा (1) या उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट समय के भीतर उसे नहीं दिया है, वहां समुचित अधिकारी उस पर एक नोटिस की तामील कर सकेगा जिसके द्वारा उसे नोटिस की तामील की तारीख से तीस दिन से अनधिक की अवधि के भीतर ऐसी सूचना देने की अपेक्षा की जाएगी और ऐसा व्यक्ति ऐसी सूचना देगा।

108ख. जहां वह व्यक्ति, जिससे धारा 108क के अधीन सूचना देने की अपेक्षा की गई है, उसकी उपधारा (3) के अधीन जारी नोटिस में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर ऐसा करने में असफल रहता है, वहां समुचित अधिकारी ऐसे व्यक्ति को ऐसी अवधि के, जिसके दौरान ऐसी सूचना देने में असफलता जारी रहती है, प्रत्येक दिन के लिए एक सौ रुपए की राशि का शास्ति के रूप में संदाय करने का निदेश दे सकेगा।”।

सूचना विवरणी देने में असफलता के लिए शास्ति।

अध्याय 2

सीमाशुल्क टैरिफ

1975 का 51

4. सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 3 में,—

धारा 3 का संशोधन।

(क) उपधारा (2) में,—

(i) खंड (ii) में मद (क) के स्थान पर, निम्नलिखित मद रखी जाएगी, अर्थात्:—

“(क) उपधारा (1), उपधारा (3), उपधारा (5), उपधारा (7) और उपधारा (9) में निर्दिष्ट शुल्क;”;

(ii) परंतुक के उपखंड (ख) की मद (ii) का लोप किया जाएगा;

(ख) उपधारा (6) के खंड (ii) में, मद (क) के स्थान पर निम्नलिखित मद रखी जाएगी, अर्थात्:—

“(क) उपधारा (5), उपधारा (7) और उपधारा (9) में निर्दिष्ट शुल्क;”;

(ग) उपधारा (7) और उपधारा (8) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधाराएं रखी जाएंगी, अर्थात्:—

“(7) कोई भी वस्तु, जिसका भारत में आयात किया जाता है, चालीस प्रतिशत से अनधिक की ऐसी दर पर ऐसे अतिरिक्त एकीकृत कर के लिए दायी होगी, जो उपधारा (8) के अधीन यथा अवधारित आयातित वस्तु के मूल्य पर भारत में पूर्ति की गई उसी प्रकार की वस्तु पर एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 5 के अधीन उद्ग्रहणीय है।

(8) किसी आयातित वस्तु पर उपधारा (7) के अधीन एकीकृत कर की संगणना करने के प्रयोजनों के लिए, जहां ऐसा कर उसके मूल्य की किसी प्रतिशतता पर उद्ग्रहणीय है, वहां आयातित वस्तु का मूल्य, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 14 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी निम्नलिखित का योग होगा, अर्थात्:— 1962 का 52

(क) आयातित वस्तु का, यथास्थिति, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 14 की उपधारा (1) के अधीन अवधारित मूल्य या ऐसी वस्तु का, उस धारा की उपधारा (2) के अधीन नियत टैरिफ मूल्य; और 1962 का 52

(ख) सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 12 के अधीन उस वस्तु पर प्रभार्य कोई सीमाशुल्क और उस वस्तु पर तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन प्रभार्य किसी राशि, जो सीमाशुल्क के अतिरिक्त और उसी रीति में हो, किन्तु इसके अंतर्गत उपधारा (7) में निर्दिष्ट कर या उपधारा (9) में निर्दिष्ट उपकर नहीं है। 1962 का 52

(9) कोई भी वस्तु, जिसका भारत में आयात किया जाता है, ऐसी दर पर माल और सेवा कर प्रतिकर उपकर के लिए दायी होगी, जो उपधारा (10) के अधीन यथा अवधारित आयातित वस्तु के मूल्य पर भारत में पूर्ति की गई उसी प्रकार की वस्तु पर माल और सेवा कर (राज्यों को प्रतिकर) उपकर अधिनियम, 2017 की धारा 8 के अधीन उद्ग्रहणीय है।

(10) किसी आयातित वस्तु पर उपधारा (9) के अधीन माल और सेवा कर प्रतिकर उपकर की संगणना करने के प्रयोजनों के लिए, जहां ऐसा उपकर उसके मूल्य की किसी प्रतिशतता पर उद्ग्रहणीय है, वहां आयातित वस्तु का मूल्य सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 14 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी निम्नलिखित का योग होगा, अर्थात्:— 1962 का 52

(क) आयातित वस्तु का, यथास्थिति, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 14 की उपधारा (1) के अधीन अवधारित मूल्य या ऐसी वस्तु का, उस धारा की उपधारा (2) के अधीन नियत टैरिफ मूल्य; और 1962 का 52

(ख) सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 12 के अधीन उस वस्तु पर प्रभार्य कोई सीमाशुल्क और उस वस्तु पर तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन प्रभार्य किसी राशि, जो सीमाशुल्क के अतिरिक्त और उसी रीति में हो, किन्तु इसके अंतर्गत उपधारा (7) में निर्दिष्ट कर या उपधारा (9) में निर्दिष्ट उपकर नहीं है। 1962 का 52

(11) इस धारा के अधीन प्रभार्य, यथास्थिति, शुल्क या कर या उपकर इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन अधिरोपित, यथास्थिति, किसी अन्य शुल्क या कर या उपकर के अतिरिक्त होगा।

(12) सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 के उपबंध तथा उसके अधीन बनाए गए नियम और विनियम, जिसके अंतर्गत शुल्कों की वापसियां, प्रतिदाय और छूट से संबंधित नियम और विनियम भी हैं, जहां तक हो सके, इस धारा के अधीन प्रभार्य, यथास्थिति, शुल्क या कर या उपकर उसी प्रकार लागू होंगे जैसे वे इस अधिनियम के अधीन उद्ग्रहणीय शुल्कों के संबंध में लागू होते हैं।"। 1962 का 52

अध्याय 3

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

धारा 2 का संशोधन।

5. केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 (जिसे इसमें इसके पश्चात् केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम कहा गया है) की धारा (2) में,— 1944 का 1

(क) खंड (घ) में, "केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 की पहली अनुसूची और दूसरी अनुसूची" शब्दों के स्थान पर, "चौथी अनुसूची" शब्द रखे जाएंगे; 1986 का 5

(ख) खंड (ङ) में, "नमक से भिन्न" शब्दों का लोप किया जाएगा;

1986 का 5

(ग) खंड (च) के उपखंड (ii) में, “केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 की पहली अनुसूची” शब्दों के स्थान पर, “चौथी अनुसूची” शब्द रखे जाएंगे।

6. केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम में धारा 3 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

धारा 3 के स्थान पर नई धारा का रखा जाना।

“3. (1) ऐसे सभी उत्पाद-शुल्क्य माल (विशेष आर्थिक जोनों में उत्पादित या विनिर्मित माल को छोड़कर) पर, जिनका उत्पादन या विनिर्माण भारत में किया जाता है, ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, ऐसी दरों पर, जो चौथी अनुसूची में उपवर्णित हैं, केन्द्रीय मूल्य वर्धित कर (सैनवेट) नामक उत्पाद-शुल्क उद्ग्रहीत और संगृहीत किया जाएगा:

चौथी अनुसूची में विनिर्दिष्ट शुल्क का उद्ग्रहीत किया जाना।

1962 का 52

परंतु उत्पाद-शुल्क, जो ऐसे किसी शुल्क्य माल पर, जो किसी सौ प्रतिशत निर्यातोन्मुख उपक्रम द्वारा उत्पादित या विनिर्मित किया गया है और भारत में किसी अन्य स्थान में लाया गया है, उद्ग्रहीत और संगृहीत किया जाएगा, ऐसे सीमाशुल्कों के सकल योग के बराबर रकम होगी, जो सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन भारत से बाहर उत्पादित या विनिर्मित वैसे ही माल पर उद्ग्रहणीय होता, यदि भारत में उनका आयात किया जाता और जहां उक्त सीमाशुल्क उनके मूल्य के संदर्भ में प्रभार्य हैं, वहां ऐसे उत्पाद-शुल्क्य माल का मूल्य, इस अधिनियम के अन्य उपबंधों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 तथा सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के उपबंधों के अनुसार अवधारित किया जाएगा।

1975 का 51

स्पष्टीकरण 1—जहां उसी प्रकार के किसी भी माल की बाबत तत्समय प्रवृत्त उद्ग्रहणीय कोई सीमाशुल्क भिन्न-भिन्न दरों पर उद्ग्रहणीय है, वहां इस परंतुक के प्रयोजनों के लिए ऐसा शुल्क उन दरों में से उच्चतम दर पर उद्ग्रहणीय समझा जाएगा।

स्पष्टीकरण 2—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए,—

1951 का 65

(i) “सौ प्रतिशत निर्यातोन्मुख उपक्रम” से ऐसा उपक्रम अभिप्रेत है, जिसे केन्द्रीय सरकार द्वारा, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 की धारा 14 द्वारा तथा इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस निमित्त नियुक्त किए गए बोर्ड द्वारा सौ प्रतिशत निर्यातोन्मुख उपक्रम के रूप में अनुमोदित किया गया है;

2005 का 28

(ii) “विशेष आर्थिक जोन” का वही अर्थ होगा, जो विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 की धारा 2 के खंड (यक) में उसका है;

(2) उपधारा (1) के उपबंध ऐसे सभी उत्पाद-शुल्क्य माल की बाबत, जिनका उत्पादन या विनिर्माण सरकार द्वारा या उसकी ओर से भारत में किया जाता है, उसी प्रकार लागू होंगे जैसे वे ऐसे माल की बाबत लागू होते हैं, जिनका उत्पादन या विनिर्माण सरकार द्वारा नहीं किया जाता है।

(3) केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में, अधिसूचना द्वारा, उक्त शुल्क के उद्ग्रहण के प्रयोजनों के लिए या तो विनिर्दिष्टतया या साधारण शीर्षों के अधीन, चौथी अनुसूची में मूल्यानुसार शुल्क से प्रभार्य के रूप में प्रगणित किन्हीं वस्तुओं के टैरिफ मूल्य नियत कर सकेगी और तत्समय प्रवृत्त किन्हीं टैरिफ मूल्यों में परिवर्तन कर सकेगी।

(4) केन्द्रीय सरकार निम्नलिखित के लिए भिन्न-भिन्न टैरिफ मूल्य नियत कर सकेगी,—

(क) भिन्न-भिन्न वर्गों या वर्णनों के एक ही उत्पाद-शुल्क्य माल के लिए, या

(ख) एक ही वर्ग या वर्णन के उत्पाद-शुल्क्य माल के लिए—

(i) जो भिन्न-भिन्न वर्गों के उत्पादकों या विनिर्माताओं द्वारा उत्पादित या विनिर्मित हों; या

(ii) जिनका भिन्न-भिन्न वर्गों के क्रेताओं को विक्रय किया गया हो:

परंतु उपखंड (i) या उपखंड (ii) के अधीन आने वाले उत्पाद-शुल्क माल की बाबत भिन्न-भिन्न टैरिफ मूल्य नियत करने में, यथास्थिति, भिन्न-भिन्न वर्गों के उत्पादकों या विनिर्माताओं द्वारा प्रभारित विक्रय कीमतों या ऐसे माल के थोक व्यापार के सामान्य प्रचलन का ध्यान रखा जाएगा।”।

धारा 3क का संशोधन।

7. केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 3क के स्पष्टीकरण में, “केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 की पहली अनुसूची और दूसरी अनुसूची” शब्दों के स्थान पर, “चौथी अनुसूची” शब्द रखे जाएंगे।

नई धारा 3ख और धारा 3ग का अंतःस्थापन।

8. केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 3क के पश्चात्, निम्नलिखित धाराएं अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:—

उत्पाद-शुल्क बढ़ाने के लिए केन्द्रीय सरकार की आपात शक्ति।

“3ख. (1) जहां किसी माल की बाबत केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि धारा 3 के अधीन उस पर उद्ग्रणीय शुल्क बढ़ाया जाना चाहिए और यह कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं, जिससे तुरंत कार्रवाई करना आवश्यक है, वहां केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, चौथी अनुसूची को, ऐसे माल की बाबत उसमें विनिर्दिष्ट शुल्क की दर को प्रतिस्थापित करने के लिए निम्नलिखित रीति में संशोधित कर सकेगी, अर्थात्:—

(क) ऐसी दशा में, जहां अधिसूचना के जारी किए जाने से ठीक पहले चौथी अनुसूची में यथाविनिर्दिष्ट प्रवृत्त शुल्क की दर शून्य है, वहां शुल्क की दर किसी भी रूप या पद्धति में अभिव्यक्त मूल्यानुसार पचास प्रतिशत से अनधिक होगी;

(ख) किसी अन्य दशा में, शुल्क की दर चौथी अनुसूची में ऐसे माल की बाबत विनिर्दिष्ट शुल्क की ऐसी दर के दोगुने से अधिक नहीं होगी, जो उक्त अधिसूचना के जारी किए जाने से ठीक पहले प्रवृत्त है:

परंतु केन्द्रीय सरकार, इस उपधारा के अधीन उस सरकार द्वारा जारी की गई किसी पूर्व अधिसूचना द्वारा यथा विनिर्दिष्ट किसी माल की बाबत शुल्क की दर को प्रतिस्थापित करने के लिए इस उपधारा के अधीन कोई भी अधिसूचना, उपधारा (2) के अधीन उपांतरणों के साथ या उसके बिना, ऐसी पूर्व अधिसूचना के अनुमोदन से पहले जारी नहीं करेगी।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, उत्पाद-शुल्क की दर के संबंध में “रूप या पद्धति” से ऐसा आधार, जिसके अंतर्गत मूल्यांकन, भार, संख्या, लंबाई, क्षेत्र, परिमाण या कोई अन्य उपाय भी हैं, अभिप्रेत है, जिस पर शुल्क उद्गृहीत किया जा सकेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन जारी प्रत्येक अधिसूचना, अधिसूचना के जारी किए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, और यदि सत्र में न हो, तो उसके पुनः समवेत होने के सात दिन के भीतर रखी जाएगी और केन्द्रीय सरकार, उस दिन से, जिसको लोक सभा के समक्ष अधिसूचना इस प्रकार रखी जाती है, आरंभ होने वाले दिन से पंद्रह दिन की अवधि के भीतर किए गए संकल्प द्वारा अधिसूचना पर संसद् के अनुमोदन की मांग करेगी और यदि संसद् अधिसूचना में कोई उपांतरण करती है या यह निदेश देती है कि अधिसूचना प्रभावी नहीं रहनी चाहिए तो तत्पश्चात् अधिसूचना, यथास्थिति, उस उपांतरित रूप में ही प्रभावी होगी या प्रभावी नहीं रहेगी, किंतु ऐसा करने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(3) केन्द्रीय सरकार द्वारा, राजपत्र में अधिसूचना जारी करके, किसी भी समय, उपधारा (1) के अधीन जारी की गई कोई भी अधिसूचना, जिसके अंतर्गत उपधारा (2) के अधीन अनुमोदित या उपांतरित कोई अधिसूचना भी है, विखंडित की जा सकेगी।

केन्द्रीय सरकार की चौथी अनुसूची को संशोधित करने की शक्ति।

3ग. जहां केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है तो वह, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, चौथी अनुसूची को संशोधित कर सकेगी:

परंतु ऐसा कोई भी संशोधन, चौथी अनुसूची में विनिर्दिष्ट ऐसी दरों को, जिस पर उसमें विनिर्दिष्ट माल पर उत्पाद-शुल्क उद्ग्रहणीय है, किसी भी रीति में परिवर्तित या प्रभावित नहीं करेगा।”।

9. केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 38 में, “धारा 3क” शब्द, अंक और अक्षर के पश्चात् धारा 38 का संशोधन।
“धारा 3ग” शब्द, अंक और अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे।

10. केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 38क के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:— नई धारा 38ख का अंतःस्थापन।

1986 का 5

“38ख. केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 174 की उपधारा (1) द्वारा केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 के निरसन के होते हुए भी, उक्त अधिनियम की पहली अनुसूची में या उसके अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों या विनियमों में, या उसके अधीन जारी की गई किसी अधिसूचना, परिपत्र, आदेश या अनुदेश में, यथास्थिति, अध्याय, शीर्ष, उपशीर्ष या टैरिफ मद के प्रति किसी निर्देश का अर्थ चौथी अनुसूची में, यथास्थिति, अध्याय, शीर्ष, उपशीर्ष या टैरिफ मद के प्रति निर्देश होगा।”।

11. केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम में तीसरी अनुसूची के स्थान पर, पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट अनुसूची रखी जाएगी। तीसरी अनुसूची के स्थान पर नई अनुसूची का रखा जाना।

12. केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम में तीसरी अनुसूची के पश्चात्, दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट अनुसूची अंतःस्थापित की जाएगी। चौथी अनुसूची का अंतःस्थापन।

अध्याय 4

केन्द्रीय विक्रय-कर

1956 का 74

13. केन्द्रीय विक्रय-कर अधिनियम, 1956 (जिसे इसमें इसके पश्चात् केन्द्रीय विक्रय-कर अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 में,— धारा 2 का संशोधन।

(क) खंड (ग) का लोप किया जाएगा;

(ख) खंड (घ) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:—

‘(घ) “माल” से निम्नलिखित अभिप्रेत है—

(i) अपरिष्कृत पेट्रोलियम;

(ii) उच्च गति डीजल;

(iii) मोटर स्पिरिट (जो सामान्यतया पेट्रोल के नाम से ज्ञात है);

(iv) प्राकृतिक गैस;

(v) विमानन टर्बाइन ईंधन; और

(vi) मानव उपभोग के लिए अल्कोहली लिकर।’।

14. केन्द्रीय विक्रय-कर अधिनियम की धारा 14 का लोप किया जाएगा। धारा 14 का लोप।

15. केन्द्रीय विक्रय-कर अधिनियम की धारा 15 का लोप किया जाएगा। धारा 15 का लोप।

अध्याय 5

प्रकीर्ण

16. वित्त अधिनियम, 2001 की सातवीं अनुसूची में,—

(क) टैरिफ मद 2402 20 10, 2402 20 20, 2402 20 30, 2402 20 40, 2402 20 50, 2402

2001 के अधिनियम संख्यांक 14 की सातवीं अनुसूची का संशोधन।

20 90, 2402 90 10, 2403 11 10, 2403 19 10, 2403 19 21, 2403 19 29, 2403 19 90, 2403 91 00, 2403 99 10, 2403 99 20, 2403 99 30, 2403 99 40, 2403 99 50, 2403 99 60, 2403 99 90 और 2709 00 00 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के सिवाय, अन्य सभी शीर्ष, उपशीर्ष, टैरिफ मद और उनसे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;

(ख) टैरिफ मद 2709 00 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित मद और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:—

(1)	(2)	(3)	(4)
“2709 20 00	- अपरिष्कृत पेट्रोलियम	किं०ग्रा०	50 रु० प्रति टन”।

2005 के
अधिनियम
संख्यांक 18 की
सातवीं अनुसूची
का संशोधन।

17. वित्त अधिनियम, 2005 की सातवीं अनुसूची में, टैरिफ मद 2106 90 20 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा।

कतिपय
अधिनियमितियों
का निरसन और
व्यावृत्ति।

18. (1) तीसरी अनुसूची के तीसरे स्तंभ में विनिर्दिष्ट अधिनियमितियां, उसके चौथे स्तंभ में विनिर्दिष्ट अधिनियमितियों के विस्तार तक, निरसित की जाती हैं।

(2) उपधारा (1) के अधीन निरसन के होते हुए भी, ऐसा निरसन,—

(क) किसी ऐसी विधि को प्रभावित नहीं करेगा, जिसमें निरसित अधिनियमिति को लागू, निगमित या निर्दिष्ट किया गया है;

(ख) निरसित अधिनियमिति के अधीन पहले से ही की गई या हुई किसी बात की विधिमान्यता, अविधिमान्यता, प्रभाव या परिणाम को अथवा पहले से ही अर्जित, प्रोद्भूत या उपगत किसी भी अधिकार, हक, बाध्यता या दायित्व को अथवा उसकी बाबत किसी भी उपचार या कार्यवाही को अथवा किसी भी ऋण, शास्ति, बाध्यता, दायित्व, दावे या मांग की निर्मुक्ति या उससे निर्मोचन को अथवा पहले से ही प्रदान किए गए किसी संरक्षण को अथवा किसी पिछले कार्य या बात के सबूत को प्रभावित नहीं करेगा;

(ग) विधि के किसी सिद्धांत या शासन को, सिद्ध अधिकारिता को, अभिवचन के प्ररूप या प्रक्रम को, प्रचलन या प्रक्रिया को अथवा विद्यमान प्रथा, रूढ़ि, विशेषाधिकार, निर्बंधन, छूट, पद या नियुक्ति को इस बात के होते हुए भी प्रभावित नहीं करेगा कि उसे क्रमशः किसी निरसित अधिनियमिति द्वारा उसमें या उससे किसी भी रीति में अभिपुष्ट या मान्यताप्राप्त किया गया हो या वह उससे व्युत्पन्न हुई हो;

(घ) अब अविद्यमान या अप्रवृत्त किसी अधिकारिता, पद, रूढ़ि, दायित्व, अधिकार, हक, विशेषाधिकार, निर्बंधन, छूट, प्रथा, प्रचलन, प्रक्रिया या किसी अन्य विषय या बात को पुनःप्रवर्तित या प्रत्यावर्तित नहीं करेगा।

(3) निरसनों के प्रभाव के संबंध में उपधारा (1) में विशिष्ट विषयों के उल्लेख से यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि उससे साधारण खंड अधिनियम, 1897 की धारा 6 के साधारणतया लागू होने पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा या वह उसे प्रभावित करेगा। 1897 का 10

शुल्कों के बकाया
का संग्रहण और
संदाय।

19. तीसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट अधिनियमितियों के निरसन के होते हुए भी, धारा 1 की उपधारा (2) के अधीन नियत तारीख के ठीक पूर्व उक्त अधिनियमितियों के अधीन उद्गृहीत शुल्कों के आगम,—

(i) यदि संग्रहण अभिकरणों द्वारा संगृहीत किए गए हैं, किंतु भारतीय रिजर्व बैंक को संदत्त नहीं किए गए हैं; या

(ii) यदि संग्रहण अभिकरणों द्वारा संगृहीत नहीं किए गए हैं,

तो भारत की संचित निधि में जमा किए जाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक को, यथास्थिति, संदत्त या संगृहीत और संदत्त किए जाएंगे।

पहली अनुसूची

(धारा 11 देखिए)

‘तीसरी अनुसूची

[धारा 2 (च) (iii) देखिए]

टिप्पण

1. इस अनुसूची में, “शीर्ष”, “उपशीर्ष” और “टैरिफ मद” से चौथी अनुसूची में क्रमशः कोई शीर्ष, उपशीर्ष और टैरिफ मद अभिप्रेत है।

2. चौथी अनुसूची के निर्वचन के नियम, भाग, अध्याय टिप्पण और साधारण स्पष्टीकारक टिप्पण इस अनुसूची के निर्वचन को लागू होंगे।

क्रम सं०	शीर्ष, उपशीर्ष या टैरिफ मद	माल का विवरण
1.	2402 20 10 से 2402 20 90	समस्त माल
2.	2403 99 10, 2403 99 20, 2403 99 30	चबाने वाला तंबाकू और चबाने वाले तंबाकू वाली निर्मितियां
3.	2403 99 90	तंबाकू वाला पान मसाला।’।

दूसरी अनुसूची

(धारा 12 देखिए)

‘चौथी अनुसूची

[धारा 2(घ) और 2(च) (ii) देखिए]

इस अनुसूची के निर्वचन के लिए साधारण नियम

इस अनुसूची में माल का वर्गीकरण निम्नलिखित सिद्धांतों द्वारा शासित होगा:

1. केवल निर्देश की सुगमता के लिए भागों, अध्यायों और उप-अध्यायों के शीर्षक उपबंधित किए गए हैं; विधिक प्रयोजनों के लिए वर्गीकरण का अवधारण शीर्षों और किन्हीं संबंधित भागों या अध्याय टिप्पणों के पदों के अनुसार और निम्नलिखित उपबंधों के अनुसार किया जाएगा बशर्ते ऐसे शीर्षों या टिप्पणों से अन्यथा अपेक्षित नहीं है।

2. किसी शीर्ष में—

(क) किसी अनुच्छेद के प्रति किसी निर्देश को उस अपूर्ण या अधूरे अनुच्छेद के प्रति निर्देश को सम्मिलित करने के लिए लिया जाएगा परंतु ऐसा तब, जब यथा प्रस्तुत अपूर्ण या अधूरा अनुच्छेद उस अनुच्छेद को पूर्ण या पूरा करने का आवश्यक स्वरूप रखता है। इसे उस पूर्ण या पूरे अनुच्छेद के प्रति निर्देश को, सम्मिलित करने (या इस नियम के कारण पूर्ण या पूरे के रूप में वर्गीकृत होने के लिए आने वाले) के लिए भी लिया जाएगा;

(ख) किसी सामग्री या पदार्थ के प्रति निर्देश को अन्य सामग्रियों या पदार्थों के साथ उस सामग्री या पदार्थ के मिश्रण या संयोजन के प्रति निर्देश को सम्मिलित करने के लिए लिया जाएगा। किसी दी गई सामग्री या पदार्थ के माल के प्रति निर्देश को ऐसी सामग्री या पदार्थ से पूर्णतः या भागतः मिलकर बनने वाले माल के प्रति निर्देश को सम्मिलित करने के लिए लिया जाएगा। एक से अधिक सामग्री या पदार्थ से मिलकर बने माल का वर्गीकरण नियम 3 के सिद्धांत के अनुसार होगा।

3. जब नियम 2 के खंड (ख) के लागू होने से या किसी अन्य कारण से माल, प्रथमदृष्टया दो या अधिक शीर्षों के अधीन वर्गीकरणीय है, तो वर्गीकरण निम्नलिखित रूप में प्रभावी होगा—

(क) ऐसे शीर्ष को, जिसमें सर्वाधिक विनिर्दिष्ट विवरण उपबंधित है, अधिक साधारण विवरण का उपबंध करने वाले शीर्ष पर अधिमान दिया जाएगा। तथापि जब दो या अधिक शीर्ष, मिश्रित या सम्मिश्र माल वाली सामग्री या पदार्थ के केवल भाग के प्रति या किसी मद के केवल भाग के प्रति प्रत्येक निर्देश को खुदरा विक्रय के लिए समुच्चय में रखा जाता है, वहां उन शीर्षों को उस माल के संबंध में बराबर विनिर्दिष्ट के रूप में माना जाना है, चाहे उनमें से एक उस माल का अधिक पूर्ण या सुस्पष्ट विवरण देता है;

(ख) विभिन्न सामग्रियों से या विभिन्न संघटकों से मिलकर बना मिश्रण या सम्मिश्र माल और खुदरा विक्रय के लिए समुच्चय में रखा गया माल, जिसे खंड (क) के प्रति निर्देश द्वारा वर्गीकृत नहीं किया

जा सकता, उसे इस प्रकार वर्गीकृत किया जाएगा मानो वे ऐसी सामग्री या संघटक से मिलकर बने हैं, जो उसे आवश्यक स्वरूप देता है, जहां तक यह मानदंड लागू है;

(ग) जहां माल को खंड (क) या खंड (ख) के प्रति निर्देश द्वारा वर्गीकृत नहीं किया जा सकता, वहां उन्हें ऐसे शीर्ष के अधीन वर्गीकृत किया जाएगा, जो उस माल की संख्याओं के क्रम के अंत में आता है, जिन पर समान रूप से गुणाधारित विचार किया जाता है।

4. ऐसा माल, जिसका वर्गीकरण पूर्वोक्त नियमों के अनुसार नहीं किया जा सकता, ऐसे माल के समुचित शीर्ष के अधीन वर्गीकृत किया जाएगा, जिसके वह सर्वाधिक सदृश है।

5. विधिक प्रयोजनों के लिए किसी शीर्ष के उपशीर्षों में माल का वर्गीकरण उन उपशीर्षों और किसी अन्य संबंधित उपशीर्ष टिप्पण के पद और यथावश्यक परिवर्तनों सहित पूर्वोक्त नियम के अनुसार इस बोध पर अवधारित किया जाएगा कि केवल उसी स्तर के उपशीर्ष तुलनीय हैं। इस नियम के प्रयोजनों के लिए, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, संबंधित अध्याय टिप्पण भी लागू होते हैं।

साधारण स्पष्टीकारक टिप्पण

1. जहां इस अनुसूची के स्तंभ (2) में शीर्ष के अधीन किसी वस्तु या वस्तु के समूह का वर्णन “-” से पहले आता है, वहां उस वस्तु या वस्तुओं के समूह को उक्त शीर्ष के अंतर्गत आने वाली वस्तुओं के समूह का उप-वर्गीकरण होने के रूप में लिया जाएगा। तथापि जहां वस्तु या वस्तुओं के समूह का वर्णन “-” से पहले आता है, वहां उक्त वस्तु या वस्तुओं के समूह को ऐसी वस्तु या वस्तुओं के समूह के वर्णन से ठीक पहले के उपवर्गीकरण होने के रूप में लिया जाएगा, जिसमें “-” है। जहां कोई वस्तु या वस्तुओं का समूह “.....” या “.....” से पहले आता है, वहां उस वस्तु या वस्तुओं के समूह के ठीक पूर्ववर्ती वर्णन का वर्गीकरण होने के रूप में लिया जाएगा, जिसमें “.....” या “.....” है।

2. शुल्क की दर के संबंध में, इस अनुसूची के स्तंभ (4) में संक्षेपाक्षर “%” यह उपदर्शित करता है कि ऐसे माल पर शुल्क, जिससे प्रविष्टि संबंधित है, उस मूल्य के, जो उक्त स्तंभ में उपदर्शित है, ऐसे प्रतिशत के बराबर शुल्क होने के कारण, केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 3 की उपधारा (3) के साथ पठित उपधारा (2) या धारा 4 या धारा 4क के अधीन, यथास्थिति, नियत या परिभाषित या समझे गए मूल्य के आधार पर प्रभासित किया जाएगा।

1944 का 1

अतिरिक्त टिप्पण

इस अनुसूची में,—

(1) पद—

(क) माल के संबंध में “शीर्ष” से चार अंक की संख्या सहित टैरिफ उपबंधों की सूची में वर्णन अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत ऐसी सभी टैरिफ मदों के उपशीर्ष आते हैं, जिनके पहले चार अंक उस संख्या के समरूप हैं;

(ख) माल के संबंध में “उपशीर्ष” से छह अंक की संख्या सहित टैरिफ उपबंधों की सूची में वर्णन अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत ऐसी सभी टैरिफ मदों के उपशीर्ष आते हैं, जिनके पहले छह अंक उस संख्या के समरूप हैं;

(ग) माल के संबंध में “टैरिफ मद” से या तो आठ अंक की संख्या और उत्पाद-शुल्क की दर सहित टैरिफ उपबंधों की सूची में माल का वर्णन या शुल्क की दर के स्तंभ में रिक्त स्थान के साथ आठ अंक की संख्या अभिप्रेत है।

(2) टैरिफ उपबंधों की सूची को भागों, अध्यायों और उप-अध्यायों में विभाजित किया गया है।

(3) स्तंभ (3) में मात्रा की मानक इकाई, व्यापार सांख्यिकियों के संग्रहण, उनकी तुलना और विश्लेषण को सुकर बनाने के लिए प्रत्येक टैरिफ मद के लिए विनिर्दिष्ट की गई है।

(4) किसी माल के सामने “.....” इस बात का द्योतक है कि इस अनुसूची के अधीन केंद्रीय उत्पाद-शुल्क ऐसे माल पर उद्ग्रहणीय नहीं है।

प्रयुक्त संक्षेपाक्षरों की सूची

संक्षेपाक्षर	के लिए
1. कि०ग्रा०	किलोग्राम
2. टीयू	संख्या हजार में

भाग 4

तम्बाकू और विनिर्मित तम्बाकू अनुकल्प

टिप्पण

इस भाग में, “इकाई पात्र” पद से पूर्व अवधारित मात्रा या संख्या को रखने के लिए डिजाइन किया गया कोई पात्र, चाहे बड़ा हो या छोटा (उदाहरण के लिए टिन, कैन, बाक्स, जार, बोतल, बैग या कार्टन, ड्रम, बैरल या कनस्तर) अभिप्रेत है।

अध्याय 24

तम्बाकू या विनिर्मित तम्बाकू अनुकल्प

टिप्पण

1. इस अध्याय में, “ब्रांड नाम” से ऐसा कोई ब्रांड नाम, चाहे रजिस्ट्रीकृत हो या नहीं, अर्थात्, कोई नाम या चिह्न, जैसे कोई प्रतीक, मोनाग्राम, लेबल, संकेत, आविष्कृत शब्द या कोई लिखावट अभिप्रेत है, जो उत्पाद और किसी व्यक्ति की पहचान के किसी उपदर्शन सहित या उसके बिना ऐसे नाम का प्रयोग करने वाले किसी व्यक्ति के बीच व्यापार के प्रक्रम के दौरान संबंध को उपदर्शित करने के प्रयोजन के लिए या उपदर्शित करने के बारे में किसी उत्पाद के संबंध में प्रयुक्त किए गए हैं।

2. शीर्ष 2401 या 2402 या 2403 के उत्पादों के संबंध में पात्रों पर लेबल लगाना या पुनः लेबल लगाना, थोक पैकों से खुदरा पैकों में पुनः पैक करना, किसी उपभोक्ता के लिए विपणनीय उत्पाद बनाने के लिए किसी अन्य उपचार को अंगीकार करना, उसका “विनिर्माण” करने की कोटि में आएगा।

3. इस अध्याय में टैरिफ मद 2403 99 90 में सम्मिलित सामान्यतया “गुटका” के रूप में या किसी अन्य नाम से ज्ञात “तम्बाकू वाला पान मसाला” से पान-सुपारी और तम्बाकू और निम्नलिखित किसी एक या अधिक संघटक वाली कोई भी निर्मिति अभिप्रेत है, अर्थात्:—

(i) चूना; और

(ii) कत्था (कटेचू),

चाहे उसमें कोई अन्य संघटक हो या नहीं, जैसे इलायची, गरी और पोदीना का सत्।

उपशीर्ष टिप्पण

उपशीर्ष 2403 11 के प्रयोजनों के लिए “हुक्का तम्बाकू” से किसी हुक्का में धूम्रपान के लिए आशयित तम्बाकू अभिप्रेत है और जो तम्बाकू और ग्लिसरोल के मिश्रण से बना है, चाहे उसमें सुगंधित तेल या निष्कर्षण, चासनी या चीनी हो या नहीं और चाहे उसमें फल का सुवास है या नहीं। तथापि, किसी हुक्के में धूम्रपान के लिए आशयित तम्बाकू रहित उत्पादों को इस उपशीर्ष से अपवर्जित किया गया है।

अनुपूरक टिप्पण

इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए:

(1) “तम्बाकू” से तम्बाकू का कोई भी रूप अभिप्रेत है, चाहे संसाधित हो या असंसाधित और चाहे विनिर्मित हो या नहीं और इसके अंतर्गत तम्बाकू के पौधे की पत्ती, डंडी और तना भी आते हैं किन्तु इसके अंतर्गत तम्बाकू के पौधे का ऐसा कोई भाग नहीं आता, जो अभी भी भू-बध्य है।

(2) “कटी हुई तम्बाकू” से आकार में काटी हुई तैयार या प्रसंस्कृत तम्बाकू अभिप्रेत है, जो साधारणतया मशीन से बनाई गई सिगरेटों के विनिर्माण में वांछित मात्रा तक सम्मिश्रित या आद्र की जाती है।

(3) उपशीर्ष 2403 10 का “सिगारों और सिगरेटों के लिए धूम्रपान मिश्रण” के अंतर्गत “गुडाकू” नहीं आता है।

टैरिफ मद	माल का वर्णन	इकाई	शुल्क की दर
(1)	(2)	(3)	(4)
2401	अविनिर्मित तम्बाकू : तम्बाकू उच्छिष्ट	कि०ग्रा०	64 .
2401 10	— तम्बाकू, जो डंडी/शिरा सहित हैं:	कि०ग्रा०	64 .
2401 10 10	--- धूमताल उपचारित वर्जीनिया तम्बाकू	कि०ग्रा०	64 .
2401 10 20	--- धूप उपचारित देसी (नाटू) तम्बाकू	कि०ग्रा०	64 .
2401 10 30	--- धूप उपचारित वर्जीनिया तम्बाकू	कि०ग्रा०	64 .
2401 10 40	--- जौ तम्बाकू	कि०ग्रा०	64 .
2401 10 50	--- बीड़ियों के विनिर्माण के लिए तम्बाकू जिसमें डंडियां न हों	कि०ग्रा०	64 .
2401 10 60	--- चबाने वाले तम्बाकू के विनिर्माण के लिए तम्बाकू	कि०ग्रा०	64 .
2401 10 70	--- सिगार और चुर्रुट के विनिर्माण के लिए तम्बाकू	कि०ग्रा०	64 .
2401 10 80	--- हुक्का तम्बाकू के विनिर्माण के लिए तम्बाकू	कि०ग्रा०	64 .
2401 10 90	--- अन्य	कि०ग्रा०	64 .
2401 20	- तम्बाकू जो भागतः या संपूर्णतः डंडीयुक्त या झंगा हुआ:	कि०ग्रा०	64 .
2401 20 10	--- धूमताल उपचारित वर्जीनिया तम्बाकू	कि०ग्रा०	64 .
2401 20 20	--- धूप उपचारित देसी (नाटू) तम्बाकू	कि०ग्रा०	64 .
2401 20 30	--- धूप उपचारित वर्जीनिया तम्बाकू	कि०ग्रा०	64 .
2401 20 40	--- जौ तम्बाकू	कि०ग्रा०	64 .
2401 20 50	--- बीड़ियों के विनिर्माण के लिए तम्बाकू	कि०ग्रा०	64 .
2401 20 60	--- चबाने वाले तम्बाकू के विनिर्माण के लिए तम्बाकू	कि०ग्रा०	64 .
2401 20 70	--- सिगार और चुर्रुट के विनिर्माण के लिए तम्बाकू	कि०ग्रा०	64 .
2401 20 80	--- हुक्का तम्बाकू के विनिर्माण के लिए तम्बाकू	कि०ग्रा०	64 .
2401 20 90	--- अन्य	कि०ग्रा०	64 .
2401 30 00	- तम्बाकू उच्छिष्ट	कि०ग्रा०	50 .
2402	तम्बाकू या तम्बाकू अनुकल्प के सिगार, चुर्रुट, सिगरीला और सिगरेट		
2402 10	--- तम्बाकू युक्त सिगार, चुर्रुट और सिगरीला:		

(1)	(2)	(3)	(4)
2402 10 10	--- सिगार और चुर्रुट	संख्या हजार में	12.5. या 4006 रुपए प्रति हजार, जो भी अधिक हो
2402 10 20	--- सिगरीला	संख्या हजार में	12.5. या 4006 रुपए प्रति हजार, जो भी अधिक हो
2402 20	- तम्बाकू युक्त सिगरेट:		
2402 20 10	--- 65 मिलीमीटर से अनधिक लंबाई की फिल्टर वाली सिगरेटों से भिन्न	संख्या हजार में	1280 रुपए प्रति हजार
2402 20 20	--- 65 मिलीमीटर से अधिक किन्तु 70 मिलीमीटर से अनधिक लंबाई की फिल्टर वाली सिगरेट से भिन्न	संख्या हजार में	2335 रुपए प्रति हजार
2402 20 30	--- 65 मिलीमीटर से अनधिक की लंबाई की फिल्टर वाली सिगरेट (जिसके अन्तर्गत फिल्टर की लंबाई 11 मिलीमीटर या उसकी वास्तविक लम्बाई, इसमें से जो भी अधिक हो)	संख्या हजार में	1280 रुपए प्रति हजार
2402 20 40	--- 65 मिलीमीटर से अधिक किन्तु 70 मिलीमीटर से अनधिक लम्बाई की फिल्टर वाली सिगरेट (जिसमें फिल्टर की लम्बाई सम्मिलित है, फिल्टर की लंबाई 11 मिलीमीटर या इसकी वास्तविक लम्बाई, इसमें से जो भी अधिक हो)	संख्या हजार में	1740 रुपए प्रति हजार
2402 20 50	--- 70 मिलीमीटर से अधिक किन्तु 75 मिलीमीटर से अनधिक लम्बाई की फिल्टर वाली सिगरेट (जिसमें फिल्टर की लम्बाई सम्मिलित है, फिल्टर की लंबाई 11 मिलीमीटर या इसकी वास्तविक लम्बाई, इसमें से जो भी अधिक हो)	संख्या हजार में	2335 रुपए प्रति हजार
2402 20 90	--- अन्य	संख्या हजार में	3375 रुपए प्रति हजार
2402 90	- अन्य:		
2402 90 10	--- तम्बाकू अनुकल्पों की सिगरेट	संख्या हजार में	3375 रुपए प्रति हजार
2402 90 20	--- तम्बाकू अनुकल्पों की सिगरीला	संख्या हजार में	12.5. या 4006 रुपए प्रति हजार, जो भी अधिक हो
2402 90 90	--- अन्य	संख्या हजार में	12.5. या 4006 रुपए प्रति हजार, जो भी अधिक हो
2403	अन्य विनिर्मित तम्बाकू और विनिर्मित तम्बाकू अनुकल्प, “समांगीकृत” या “पुनर्रचित” तम्बाकू निष्कर्ष और सत - धूम्रपान तम्बाकू, चाहे उनमें से किसी भी अनुपात में तम्बाकू अनुकल्प हैं या नहीं:		

(1)	(2)	(3)	(4)
2403 11	-- इस अध्याय के उपशीर्ष टिप्पण 1 में विनिर्दिष्ट हुक्का तम्बाकू:		
2403 11 10	--- हुक्का और गुडाकू तम्बाकू	कि॰ग्रा॰	60.
2403 11 90	--- अन्य	कि॰ग्रा॰	60.
2403 19	-- अन्य		
2403 19 10	--- पाइपों और सिगरेटों के लिए धूम्रपान मिश्रण	कि॰ग्रा॰	360.
	--- बीड़ी:		
2403 19 21	---- कागज बेल्लित बीड़ियों से भिन्न, जो मशीन की सहायता के बिना विनिर्मित हो	संख्या हजार में	12 रुपए प्रति हजार
2403 19 29	---- अन्य	संख्या हजार में	80 रुपए प्रति हजार
2403 19 90	--- अन्य	कि॰ग्रा॰	40.
	- अन्य:		
2403 91 00	-- “समांगीकृत”/पुनर्रचित” तम्बाकू	कि॰ग्रा॰	60.
2403 99	-- अन्य		
2403 99 10	--- चबाने वाला तम्बाकू	कि॰ग्रा॰	81.
2403 99 20	--- चबाने वाले तम्बाकू वाली विनिर्मितियां	कि॰ग्रा॰	60.
2403 99 30	--- जर्दा सुगंधित तम्बाकू	कि॰ग्रा॰	81.
2403 99 40	--- नस्वार	कि॰ग्रा॰	60.
2403 99 50	--- नस्वार वाली निर्मितियां	कि॰ग्रा॰	60.
2403 99 60	--- तम्बाकू निष्कर्ष और सत	कि॰ग्रा॰	60.
2403 99 70	--- कटा हुआ तम्बाकू	कि॰ग्रा॰	70 रुपए प्रति कि॰ग्रा॰
2403 99 90	--- अन्य	कि॰ग्रा॰	81.

भाग 5

खनिज उत्पाद

अध्याय 27

खनिज ईंधन, खनिज तेल और उनके आसवन के उत्पाद; बिटुमनी पदार्थ; खनिज मोम

टिप्पण

1. शीर्ष 2710 में “पेट्रोलियम तेलों और बिटुमनी खनिजों से अभिप्राप्त तेलों” के प्रति निर्देशों के अंतर्गत केवल पेट्रोलियम और बिटुमनी खनिजों से अभिप्राप्त तेल ही नहीं हैं बल्कि वैसे ही और वे तेल भी हैं जो किसी भी प्रक्रिया द्वारा अभिप्राप्त, मुख्यतः मिश्र असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से मिलकर बनते हैं, परंतु यह तब जबकि अनैरोमैटिक संघटकों का भार ऐरोमैटिक संघटकों से अधिक है।

तथापि, उक्त निर्देशों के अंतर्गत ऐसे द्रव संश्लिष्ट पोलिओलेफिन नहीं हैं जिनका 1,013 मिलीबार में संपरिवर्तन के पश्चात् जब अपचयनित दाब आसवन पद्धति का प्रयोग किया जाता है, 60% मात्रा से कम का आसवन 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है।

2. शीर्ष 2710 के स्नेहक तेलों और स्नेहक निर्मितियों के संबंध में, पात्रों के लेबल लगाने या उन पर पुनः लेबल लगाने या परपुंज पैकों से फुटकर पैकों में पुनः पैकिंग करना या उपभोक्ता के लिए उत्पाद को विपणनीय बनाने हेतु किसी अन्य उपचार का अंगीकरण, “विनिर्माण” की कोटि में आएगा।

3. शीर्ष 2711 के अन्तर्गत आने वाली प्राकृतिक गैस के सम्बन्ध में इसे सम्पीडित प्राकृतिक गैस (सीएनजी) के रूप में विपणन के प्रयोजन के लिए, ईंधन के रूप में प्रयोग के लिए या अन्य किसी प्रयोजन के लिए प्राकृतिक गैस के संपीड़न की प्रक्रिया (भले ही इसमें द्रवीकरण अन्तर्वर्तित नहीं है), “विनिर्माण” की कोटि में आएगा।

उपशीर्ष टिप्पण

उपशीर्ष 2710 12 के प्रयोजनों के लिए, “हल्के तेल और निर्मितियाँ” वे हैं जिनका आयतन के अनुसार 210 डिग्री सेंटीग्रेड (ए०एस०टी०एम०डी० 86 प्रणाली) पर आसवन 90% या अधिक (जिसके अन्तर्गत हानियाँ भी हैं), आयतन के अनुसार होता है।

अनुपूरक टिप्पण

इस अध्याय में निम्नलिखित अभिव्यक्तियों के वही अर्थ हैं जो इसमें उनके हैं:—

(1) “मोटर स्पिरिट” से कोई ऐसा हाइड्रोकार्बन आयल (कच्चे खनिज तेल को छोड़कर) अभिप्रेत है जिसका प्रज्ज्वलन बिंदु 25 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे है और जो स्वयं या किसी अन्य द्रव्य के मिश्रण के रूप में स्फुलिंग ज्वलन इंजनों में ईंधन के रूप में प्रयोग करने हेतु उपयुक्त है। “विशेष क्वथनांक स्पिरिट (टैरिफ मद 2710 12 11, 2710 12 12 और उपशीर्ष 2710 12 13)” से उपशीर्ष टिप्पण 4 में यथापरिभाषित हल्का तेल अभिप्रेत है, जिसमें कोई एन्टीनाक निर्मितियाँ न हों और तापमानों के बीच 60 डिग्री सेंटीग्रेड से अनधिक के अंतर पर आयतन (हानियों सहित) द्वारा मात्रा में 5 प्रतिशत और 90 प्रतिशत आसवन हो।

(2) “प्राकृतिक गैसोलीन द्रव्य (एनजीएल)” एक निम्न क्वथन द्रव पेट्रोलियम उत्पाद है जिसे प्राकृतिक गैस से निकाला जाता है।

(3) “विमान टरबाईन ईंधन (एटीएफ)” से कोई ऐसा हाइड्रोकार्बन तेल अभिप्रेत है जो भारतीय मानक ब्यूरो के भारतीय मानक विनिर्देश आई एस : 1571:1992:2000 के अनुरूप हो।

(4) “उच्च गति डीजल (एचएसडी)” से कोई ऐसा हाइड्रोकार्बन तेल अभिप्रेत है जो भारतीय मानक ब्यूरो के भारतीय मानक विनिर्देश आई एस : 1460:2000 के अनुरूप हो।

(5) “इन अतिरिक्त टिप्पणों के प्रयोजनों के लिए विहित परीक्षणों का वही अर्थ है जो निम्नलिखित में उनका हैं:—

(क) “प्रज्ज्वलन बिंदु” का निर्धारण पेट्रोलियम अधिनियम, 1934 के अधीन बनाए गए 1934 का 30 नियमों में इस निमित्त विहित परीक्षणों के अनुसार किया जाएगा;

(ख) “धूम्रबिंदु” का अवधारण तत्समय प्रवृत्त भारतीय मानक संस्था विनिर्देश आई एस: 1448 (पृष्ठ 31)-1967 में निर्दिष्ट रीति से धूम्रबिन्दु लैम्प के रूप में ज्ञात उपस्कर में किया जाएगा;

(ग) “अंतिम क्वथनांक” का अवधारण तत्समय प्रवृत्त भारतीय मानक संस्था विनिर्देश आई एस: 1448 (पृष्ठ 18)-1967 में निर्दिष्ट रीति में किया जाएगा;

(घ) “कार्बन अपशिष्ट” का अवधारण तत्समय भारतीय मानक संस्था विनिर्देश आई एस: 1448 (पृष्ठ 8)-1967 में उपदर्शित रीति में रैम्सबोटम कार्बन अपशिष्ट उपस्कर के रूप में ज्ञात उपस्कर में किया जाएगा;

(ङ) “रंग तुलन परीक्षण” निम्नलिखित रीति में किया जाएगा, अर्थात्:—

(i) आसवित जल में सबसे पहले पोटेशियम आयोडीन (विश्लेषण अभिकर्मक क्वालिटी) का पांच प्रतिशत भार का आयतन घोल तैयार किया जाएगा;

(ii) इसमें ठीक 0.04 सामान्य आयोडीन घोल तैयार करने के लिए अपेक्षित मात्रा में आयोडीन (विश्लेषण अभिकर्मक क्वालिटी) मिलाई जाएगी;

(iii) इसके पश्चात्, इस प्रकार तैयार परीक्षणाधीन आयोडीन घोल की खनिज तेल के रंग से तुलना की जाएगी।

टैरिफ मद	माल का वर्णन	इकाई	शुल्क की दर
(1)	(2)	(3)	(4)
2709	पेट्रोलियम तेल और बिटुमनी खनिजों से अभिप्राप्त कच्चा तेल	कि॰ग्रा॰
2709 10 00	- पेट्रोलियम तेल और बिटुमनी खनिजों से अभिप्राप्त तेल	कि॰ग्रा॰
2709 20 00	- कच्चा पेट्रोलियम		शून्य
2710	पेट्रोलियम तेल तथा बिटुमनी खनिजों से अभिप्राप्त तेल, कच्चे तेल से भिन्न; ऐसी निर्मितियां जो अन्यत्र विनिर्दिष्ट या सम्मिलित नहीं हैं, जिनमें पेट्रोलियम तेल या बिटुमनी खनिजों से अभिप्राप्त तेल भार के आधार पर 70 प्रतिशत या उससे अधिक है, जब ये तेल उन निर्मितियों के मूल संघटक हैं, अवशिष्ट तेल		
	- पेट्रोलियम तेल तथा बिटुमनी खनिजों से अभिप्राप्त तेल (कच्चे तेल से भिन्न) और ऐसी निर्मितियां जो अन्यत्र विनिर्दिष्ट या सम्मिलित नहीं हैं, जिनमें पेट्रोलियम तेल या बिटुमनी खनिजों से अभिप्राप्त तेल भार के आधार पर 70 प्रतिशत या उससे अधिक है, जैविक डीजल अंतर्विष्ट करने वाले से भिन्न, जब ये तेल उन निर्मितियों के मूल संघटक हैं और अवशिष्ट तेल से भिन्न		
2710 12	-- हल्के तेल और निर्मितियां		
	--- मोटर स्पिरिट (सामान्यतः पेट्रोल के रूप में ज्ञात):		
2710 12 11	---- विशिष्ट क्वथनांक स्पिरिट (बैंजीन टुलूओल से भिन्न) नामीय क्वथनांक रेंज 55-115 डिग्री सेंटीग्रेड सहित	कि॰ग्रा॰	14.+ 15.00 रु॰ प्रतिलीटर
2710 12 12	---- विशिष्ट क्वथनांक स्पिरिट (बैंजीन, टुलीन और टुलूओल से भिन्न) नामीय क्वथनांक 63-70 डिग्री सेंटीग्रेड सहित	कि॰ग्रा॰	14.+ 15.00 रु॰ प्रतिलीटर
2710 12 13	---- अन्य विशेष क्वथनांक स्पिरिट(बैंजीन, बंजोल, टुलीन और टुलूओल से भिन्न)	कि॰ग्रा॰	14.+ 15.00 रु॰ प्रतिलीटर
2710 12 19	---- अन्य	कि॰ग्रा॰	14.+ 15.00 रु॰ प्रतिलीटर
2710 12 20	--- प्राकृतिक गैसोलीन द्रव्य (एन जी एल)	कि॰ग्रा॰	14.+ 15.00 रु॰ प्रतिलीटर
2710 12 90	--- अन्य	कि॰ग्रा॰	14.+ 15.00 रु॰ प्रतिलीटर
2710 19	-- अन्य		
2710 19 10	--- बेहतर मिट्टी का तेल (एस के ओ)	कि॰ग्रा॰
2710 19 20	--- विमानन टर्बाइन ईंधन (ए टी एफ)	कि॰ग्रा॰	14.
2710 19 30	--- उच्च गति डीजल (एच एस डी)	कि॰ग्रा॰	14.+ 15.00 रु॰ प्रतिलीटर
2710 19 40	--- हल्का डीजल तेल (एल डी ओ)	कि॰ग्रा॰
2710 19 50	--- ईंधन तेल	कि॰ग्रा॰

(1)	(2)	(3)	(4)
2710 19 60	--- बेस तेल	कि०ग्रा०
2710 19 70	--- जूट बैचिंग तेल और टेक्सटाइल तेल	कि०ग्रा०
2710 19 80	--- स्नेहक तेल	कि०ग्रा०
2710 19 90	--- अन्य	कि०ग्रा०
	--- अपशिष्ट तेल:	
2710 20 00	पेट्रोलियम तेल तथा बिटुमनी खनिजों से अभिप्राप्त तेल (कच्चे तेल से भिन्न) और ऐसी निर्मितियां, जो अन्यत्र विनिर्दिष्ट या सम्मिलित नहीं हैं, जिनमें पेट्रोलियम तेल या बिटुमनी खनिजों से अभिप्राप्त तेल, भार के आधार पर 70 प्रतिशत या उससे अधिक हैं, जब ये तेल उन निर्मितियों के मूल संघटक हैं, जिनमें जैविक डीजल हो, अवशिष्ट तेल से भिन्न	कि०ग्रा०
2710 91 00	-- तेल बहुक्लोरीनेटित बाइफिनाल (पीसीबी) बहुक्लोरीनेटित टर्फिनायल (पीसीटी) या बहुब्रोमिनेटित बाइफिनायल (पीबीबी)	कि०ग्रा०
2710 99 00	-- अन्य	कि०ग्रा०
2711	पेट्रोलियम गैस और अन्य गैसीय हाइड्रोकार्बन		
	- द्रवीकृत:		
2711 11 00	-- प्राकृतिक गैस	कि०ग्रा०	1 4 .
2711 12 00	-- प्रोपेन	कि० ग्रा०	...
2711 13 00	-- ब्यूटेन	कि० ग्रा०	...
2711 14 00	-- एथीलीन, प्रोपिलीन, बुटीलीन और बुटाडीन	कि० ग्रा०	...
2711 19 00	-- अन्य	कि० ग्रा०	...
	- गैसीय अवस्था में:		
2711 21 00	-- प्राकृतिक गैस	कि० ग्रा०	1 4 .
2711 29 00	-- अन्य	कि० ग्रा०	...

तीसरी अनुसूची

(धारा 15 देखिए)

वर्ष	सं०	अधिनियमितियों का संक्षिप्त नाम	निरसन का विस्तार
(1)	(2)	(3)	(4)
1947	24	रबड़ अधिनियम, 1947	धारा 9 की उपधारा (1) के खंड (ख) और धारा 12
1951	65	उद्योग (विकास विनियमन) अधिनियम, 1951	धारा 9
1953	29	चाय अधिनियम, 1953	धारा 3 का खंड (ग), धारा 25 और धारा 26 और धारा 27 की उपधारा (1) का खंड (क)
1974	28	कोयला खान (संरक्षण और विकास) अधिनियम, 1974	धारा 6, धारा 7 और धारा 8

(1)	(2)	(3)	(4)
1976	56	बीड़ी कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1976	संपूर्ण
1977	36	जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) उपकर अधिनियम, 1977	संपूर्ण
1982	3	चीनी उपकर अधिनियम, 1982	संपूर्ण
1982	4	चीनी विकास निधि अधिनियम, 1982	धारा 3 की उपधारा (2)
1983	28	जूट विनिर्माता उपकर अधिनियम, 1983	संपूर्ण
2004	23	वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 2004	धारा 93
2007	22	वित्त अधिनियम, 2007	धारा 138
2010	14	वित्त अधिनियम, 2010	अध्याय 7
2015	20	वित्त अधिनियम, 2015	अध्याय 6
2016	28	वित्त अधिनियम, 2016	अध्याय 6 और अध्याय 7

राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी, विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (संशोधन) अधिनियम, 2017

(2017 का अधिनियम संख्यांक 19)

[4 अगस्त, 2017]

राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी, विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान
अधिनियम, 2007 का और संशोधन
करने के लिए
अधिनियम

भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी, विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (संशोधन) अधिनियम, 2017 है। संक्षिप्त नाम और प्रारंभ।
- (2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जिसे केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे।

2007 के अधिनियम
संख्यांक 29 की
दूसरी अनुसूची का
संशोधन।

2. राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी, विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान अधिनियम, 2007 की दूसरी अनुसूची में, क्रम संख्यांक 5 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:—

(1)	(2)	(3)
“6	भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, तिरुपति सोसाइटी	भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, तिरुपति
7	भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, बेरहामपुर सोसाइटी	भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, बेरहामपुर।”।

सांख्यिकीय संग्रहण (संशोधन) अधिनियम, 2017

(2017 का अधिनियम संख्यांक 21)

[4 अगस्त, 2017]

सांख्यिकीय संग्रहण अधिनियम, 2008 का संशोधन
करने के लिए
अधिनियम

भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम सांख्यिकीय संग्रहण (संशोधन) अधिनियम, 2017 है।

संक्षिप्त नाम और
प्रारंभ।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे।

2009 का 7

2. सांख्यिकीय संग्रहण अधिनियम, 2008 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 1 की उपधारा (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

धारा 1 का
संशोधन।

“(2) इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है:

परंतु यह जम्मू-कश्मीर राज्य को वहां तक लागू होगा, जहां तक इसका संबंध संविधान की, उस राज्य को यथालागू सातवीं अनुसूची की, सूची-1 (संघ सूची) या सूची-3 (समवर्ती सूची) में विनिर्दिष्ट प्रविष्टियों में किसी के अंतर्गत आने वाले विषयों से संबंधित सांख्यिकी से है।”।

3. मूल अधिनियम की धारा 2 में, खंड (घ) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

धारा 2 का
संशोधन।

“(घक) “नोडल अधिकारी” से धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन नोडल अधिकारी के रूप में अभिहित अधिकारी अभिप्रेत है;”।

नई धारा 3क का
अंतःस्थापन।

नोडल अधिकारी।

4. मूल अधिनियम की धारा 3 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

“3क. (1) केंद्रीय सरकार या कोई राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन अपने अधिकारियों में से किसी को इस अधिनियम के अधीन सांख्यिकीय के प्रयोजनों के लिए नोडल अधिकारी के रूप में अभिहित करेगा।

(2) नोडल अधिकारी, यथास्थिति, केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन, जिसमें उसे अभिहित किया गया है, के ऐसे सांख्यिकीय कार्यकलापों का समन्वय और पर्यवेक्षण करेगा और ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग और ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करेगा, जो विहित किए जाएं।”।

धारा 9 का
संशोधन।

5. मूल अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

“(1) सांख्यिकी अधिकारी या इस अधिनियम के अधीन प्राधिकृत कोई भी व्यक्ति या अभिकरण सांख्यिकीय प्रयोजनों के लिए धारा 6 के अधीन दी गई सूचना का उपयोग ऐसी रीति में करेगा, जो विहित की जाए।”।

धारा 33 का
संशोधन।

6. मूल अधिनियम की धारा 33 में,—

(i) उपधारा (1) में, “केन्द्रीय सरकार” शब्दों के पश्चात्, “पूर्व प्रकाशन की शर्त के अधधीन” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(ii) उपधारा (2) में,—

(अ) खंड (क) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“(कक) नोडल अधिकारी द्वारा धारा 3क की उपधारा (2) के अधीन सांख्यिकीय क्रियाकलापों का समन्वयन और पर्यवेक्षण तथा नोडल अधिकारी की शक्तियां और कर्तव्य;”;

(आ) खंड (घ) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“(घक) धारा 9 की उपधारा (1) के अधीन सूचना के उपयोग की रीति;”।

भारत का राजपत्र, असाधारण, भाग 2, अनुभाग 1क संख्यांक 1, खंड LIII, तारीख 12 जनवरी, 2017 को प्रकाशित राजपत्र का शुद्धिपत्र:—

पृष्ठ सं०	धारा/अनुच्छेद	पंक्ति	के स्थान पर	पढ़ें
93	मार्जिन	1	1976 का 3	1976 का 13
181	मद (2) का खंड आ(ख)	15	(शीर्ष 9001 या 2016)	(शीर्ष 1900 या 2016)

डॉ० जी० नारायण राजू,
सचिव, भारत सरकार।